CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2
RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-G

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

10·1

अब क्या हो ?

वर्त्तमान राजनीतिक परिस्थिति का विशद विवेचन, राजनीतिक शतरंज की चालों का ठोस दिग्दर्शन कांग्रेस के स्वरूप एवं कार्य का विश्लेषण, प्राप्त आजादी की असलियत, किसान-मजदूरों के लिए खतरे और वामपक्षीय नेताओं के कर्त्तव्यों पर पूर्ण प्रकाश।

लेखक

स्वामी सहजानन्द सरस्वती

बिहटा, पटना (बिहार)

प्रकाशक—

हुंकार-पुस्तकमाला, पटना

प्रथम बार—१०००] :: [मूल्य—।)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रारम्भिक निवेदन

प्रस्तुत पुस्तिका और कुछ नहीं है, सिवाय मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के सर्वांग विवेचन के। मुल्क कहाँ है, जनता कहाँ है और जिस स्वराज्य का महोत्सव अभी – अभी मनाया गया है, वह दरअसल क्या चीज है, इसकी जानकारी इससे होती है। कमाने-वाली जनता—किसानों और मजदूरों—के लिये आज कौनसे नये खतरे खड़े हो गये हैं, यह बात इसमें बखूबी समझाई गई है। हमारा अपना दृष्टिकोण है और उसीके अनुसार राजनीति के हरेक पहलू को इसमें दिखाया गया है। संभव है, भाषा और शैली कहीं - कहीं किसीको न रुचे। मगर इससे इसके विषय का महत्त्व घट नहीं जाता। फलतः पाठकों का ध्यान उसी ओर जाना चाहिये।

कांग्रेस एक ऐतिहासिक संस्था है। उसका कार्य भी ऐतिहासिक है। उसने अपना फर्ज अदा किया और लक्ष्य प्राप्त किया है। उसके बनाने में देश के सभी वर्गों का पूरा हाथ रहा है। कांग्रेस के नेता भी महान् हैं और उनने अपना कर्त्तव्य पाला है। कांग्रेस के साथ अबतक जो उनका संबंध रहा है, वह भी अपनी जगह पर ठीक रहा है। इसमें हमें कुछ भी नहीं कहना है। मगर अब आगे कांग्रेस को घसीटने तथा बनाए रखने के जो भगीरथ प्रयत्न इन नेताओं की ओर से हो रहे हैं, उन्हींसे हमारा गहरा मतभेद है। इसमें हमें किसानों एवं मजदूरों के लिए खतरे-ही-खतरे नज़र आ रहे हैं, जिनकी ओर लोगोंका ध्यान इस पुस्तिका के द्वारा आकृष्ट करना हमने अपना कर्त्तव्य समझा है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि इन खतरों का सामना सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है। आशा है, विवेकी पाठकों के गंभीर विचार के लिए इसमें कुछ मसाला मिलेगा।

बिहटा, पटना
२४—८—४७

स्वामी सहजानंद सरस्वती

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रथम पर्व की समाप्ति

आजादी और स्वतंत्रता के लिए जो महाभारत मुल्क में युगों से चालू था उसका प्रथम पर्व पूरा हुआ, ऐसा कहा जाता है। कहनेवाले लोग दो तरह के हैं। एक तो वह हैं जो समाजवाद, साम्यवाद या किसान-मजदूर राज्य के नाम से ही अबतक नाक-भौं सिकोड़ते थे। उनके लिए पूर्ण स्वतंत्रता, स्वराज्य, आजादी आदि कहना ही पर्याप्त था। अधिक-से-अधिक वे इतना ही कहते थे कि भारतीयों का राज्य इस देश में आएगा। यहाँ के लोगों के हाथ में शासन-सूत्र आएगा। बस, इसके आगे जाना उन्हें बर्दाश्त न था। उनका यह भी कहना था कि समाजवाद या साम्यवाद की चर्चा आजादी की लड़ाई में बाधक होगी, इसे कमजोर बनाएगी; क्योंकि इसके करते मुल्क में विचार-विभिन्नता का प्रसार होने से पारस्परिक तनाव बढ़ेगा और हम आपस में ही उलझ पड़ेंगे। गोया न करने से विचार-ऐक्य हो गया था!

दूसरे वे हैं, जो सदा समाजवाद, साम्यवाद तथा किसान-मजदूर राज्य के नारे लगाते रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना है कि जब तक शासन सत्ता कमानेवाली जनता, संपत्ति को उत्पन्न करनेवाली जनता—किसानों एवं मजदूरों—के हाथ सोलहों आने नहीं चली जाती, जब तक वर्ग-चेतनामूलक राजनीतिक चेतना के आधार पर किसान और मजदूर समूची शासन-सत्ता को मुस्तैदी के साथ बलात् अपने हाथों में नहीं ले लेते, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता, जनता का कल्याण असंभव है। और ऐसी चेतना लाने के लिए युगों का संगठित प्रयत्न, सतत् क्रियाशीलता अपेक्षित है। यह यकायक या कुछ समय में आनेवाली नहीं है। इसीलिए मुद्दत पहले से उन्होंने इस चेतना के प्रसार की कोशिश शुरू की थी। पहले दलवाले इस कोशिश को फूटी आँखों भी देख न सकते थे। उनकी चले, तो ऐसे लोगों को शूली पर ही चढ़ा दें।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

फिर भी, दोनों ही मानते हैं कि राष्ट्रीय महाभारत का प्रथम पर्व पूरा हुआ। विदेशी आधिपत्य से आजाद होने के लिए होनेवाला संघर्ष सफल हुआ, यह दोनों ही मानते हैं; हालाँकि दूसरे दलवालों का बराबर यही कहना रहा है कि समझौते का रास्ता छोड़ सीधी लड़ाई और क्रांतिकारी उथल-पुथल के फलस्वरूप ही यह आजादी हासिल होनी चाहिए। इसमें उनलोगों का महत्त्वपूर्ण मतलब था बेशक। सीधी लड़ाई से जो क्रांति होती, उसके फलस्वरूप न तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ही प्रश्न उठता और न सांप्रदायिक कलह की ही गुंजायश रहती। ब्रिटिश शासन के साथ ही इन अनर्थों को पैदा करनेवाली शक्तियाँ भी क्रांति के तूफान में जड़-मूल से उठाकर फेंक दी जातीं। समस्त दकियानूस ताकतों को निर्मूल करना एवं धो बहाना ही तो क्रांति की लहर का एक बड़ा काम माना जाता है। इसीके साथ एक बड़ी बात यह होती कि विदेशी शासकों के स्थान पर जो भी स्वदेशी मालदार तथा पूँजीवादी गद्दीनशीन होते—क्योंकि राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई के फल-स्वरूप देश के धनियों के ही हाथ में शासन-सत्ता जाया करती है ऐसा इतिहास बताता है—वे चैन से रह न पाते, उनका शासन दृढ़ नहीं हो पाता, जैसा कि १९१७ की क्रांति के बाद रूसी पूँजीपतियों का शासन वहाँ डावाँडोल ही रहा। फलतः किसान-मजदूरों के एक ही जबर्दस्त धक्के में उनका सारा शासन-यंत्र चकनाचूर हो जाता और शासन-सूत्र किसानों एवं मजदूरों के हाथ में चला जाता। दूसरे दल ने जो इस संघर्ष और सीधी मुठभेड़ का मार्ग छोड़ा, उसका सीधा परिणाम यही हुआ है कि हम सांप्रदायिक दंगों एवं मुल्क के अंग-भंग के शिकार हो गए। साथ ही, किसान-मजदूरों के हाथ में सत्ता का जाना कठिन हो गया है। उस दल की आँखें खुली हैं और जो कुछ उसने किया है उसका नतीजा यही होगा, यह उसे अविदित था, यह कैसे कहा जाए? संसार का इतिहास तो हमें इसी नतीजे पर पहुँचने को बाध्य करता है कि जानबूझ कर ही यह समझौते का मार्ग

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उसने अपनाया है और उसके नतीजे के लिए वह पहले से ही तैयार है—वह यही चाहता ही है, बेअदबी माफ़ हो।

जनता के हाथ में सत्ता सौंपना

कहा जाने लगा है कि कांग्रेस का काम है अब किसानों तथा मजदूरों के हाथ में सत्ता सौंपना। मगर प्रश्न यह है कि वह सत्ता १५ अगस्त को ही क्यों न सौंपी गई? और अगर उसमें कोई दिक्कत थी, तो कौनसी? अगर श्री शंकरराव देव के कथनानुसार अब आगे चलकर कांग्रेस का लक्ष्य होगा मजदूरों एवं किसानों के हाथ में वही सत्ता सौंपना, तो अब तक क्या दिक्कत थी उसके सौंपने में? आज तो कांग्रेस के सभी चुने-चुनाए, महारथी ही गवर्नर के पद से लेकर केंद्र एवं प्रांतों के मंत्रियों की गद्दियों पर आसीन हैं। फिर भी किसान-मजदूरों के हाथ में सत्ता क्यों न आई? क्या वे किसानों के प्रतिनिधि या उनके अपने आदमी नहीं हैं? यदि हाँ, तो जब तक वे रहेंगे और उनकी प्रभुता कांग्रेस पर रहेगी, तब तक किसानों को आशा कैसे हो सकती है कि सत्ता उन्हें मिलेगी? यदि वे लीडर अब तक ऐसा होने न दे सके, तो आगे कैसे होने देंगे? तो क्या वे अब कांग्रेस से हट जाएँगे? यह तो असंभव है। वह तो दूसरों को ही हट जाने को कहते हैं। नहीं-नहीं, जो लोग किसान-मजदूर-राज्य की बातें करते हैं, उन्हें कांग्रेस से गर्दनियाँ देने की नोटिस भी वही दे चुके हैं। यदि श्री शंकरराव को दर्द है कि १५ अगस्त को किसानों के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी गई, तो क्या उन्होंने इसका प्रतिवाद किया था? उन्होंने क्यों नहीं साफ़-साफ़ कहा कि भारी अनर्थ हो रहा है कि किसान-मजदूर शासन-सत्ता से वंचित किए जा रहे हैं? उन्हें तो साफ़ कहना था कि सर्वत्र किसानों और मजदूरों को ही सत्ता सौंपी जाए और लीडर लोग उनका काम सँभालने में चौकीदारी तथा सहायता का काम करें। और अगर श्री देव ने या उनके साथी इन चोटी के लीडरों ने ऐसा नहीं किया, तो आगे उनसे क्या आशा की जा सकती है? लेकिन यदि ये लीडर सचमुच

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

किसान-मजदूरों के ही आदमी हैं और उन्हींके लिए मरे जाते है, तो फिर और बाकी क्या रहा, जिसके लिए कांग्रेस को जारी रखने में जमीन और आसमान को एक किया जा रहा है ? लक्ष्य सिद्ध हो जाने पर उसकी जरूरत क्या रही ?

कहा जाएगा कि किसान और मजदूर सत्ता के योग्य नहीं हैं उसके लिए अभी तैयार न थे ; तब सत्ता उन्हें सौंपी जाती कैसे लेकिन उन्हें तैयार न होने देने के अपराधी भी हैं कौन ? ये राष्ट्रीय नेता या दूसरे लोग ? दूसरे लोग तो बराबर चिल्लाते थे कि श्रमजीवियों को राजनीतिक चेतना दी जाए, वे तैयार किये जाएँ। लेकिन ऐसा सुनकर ये नेता ही छाती पीटते थे कि ऐसा होने पर सब चौपट होगा ! फिर वही नेता आज लोगोंको कैसे तैयार करेंगे ? और क्या यह तैयारी बात-की-बात में ही हो जाएगी ? उसके लिए तो युग लगेंगे। तब तक क्या शोषकगण हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहेंगे ? क्या वे अपनी तैयारी न करेंगे और बाजी मार न ले जाएँगे ? अगर रोके जाएँगे तो किस तरह, यह बात बताने के लिए क्या ये लीडर तैयार हैं ? जिनने अबतक कांग्रेस कमिटियों, असेंबलियों और बोर्डों में शोषकों एवं उनके पिट्ठुओं को जाने से न रोका; प्रत्युत जान-बूझकर भेजा, वही आज उन्हें रोकेंगे, यह विश्वास कौन करेगा ? और जब आज तक किसान-मजदूरों को तैयार न किया गया तो आगे किया जाएगा, यह कौन मानेगा ? तैयार करने का प्रोग्राम भी क्या है ? वर्ग-चेतना से तो आपलोग भागते हैं। दूसरा रास्ता हई नहीं, उसमें तो धोका ही धोका है। फलतः उनके हाथ में सत्ता सौंपने की बात प्रवंचना मात्र है, क्षमा हो।

शान्तिपूर्ण क्रान्ति ?

कहा जाता है कि भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक क्रांति हो गई, अब उसी प्रकार की सामाजिक क्रांति के लिए कांग्रेस का कायम रहना जरूरी है। परंतु इसीको यदि क्रांति कहें, तो सुधार किसे कहेंगे ? जिसमें बातचीत और सुलह-समझौते से काम लिया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जाए उसे सुधार कहते हैं, न कि क्रांति। हम इसे शांतिपूर्ण क्रांति तो तब कहते, जब अँगरेज लोग यकायक इस मुल्क को छोड़के भाग जाते और हमारे नेता आकर उनकी जगह बैठते तथा काम सँभालते। सौदा करने की जब हिम्मत भी अँगरेजों को न होती और जान लेकर भाग जाते, तो क्रांति की बात कही जा सकती थी। अँगरेजों का होश-हवास दुरुस्त न रहता और चुपचाप भाग जाने के अलावे उनके पास रास्ता रही न जाता, तो कहने का मौका आता कि शांतिपूर्ण क्रांति हो गई। मगर यहाँ तो उल्टी बात है। वे मौजूद हैं और दो बिल्लियों के बीच बंदर-बाँट कर रहे हैं! फिर भी यह क्रांति है? तब सुधार क्या होगा? याकि दोनों एक ही हैं? यों तो हरेक के पास दिमाग है, हाथ है और कागज, कलम, दावात भी हैं। फिर जो चाहे कह दे, लिख दे और दो-दो को मिलाकर पाँच कह दे। उसे कौन रोके? क्रांति तो एक को हटा या मिटाकर सुन-सान (Vacuum) छोड़ जाती है, जिसमें दूसरे आकर बैठते हैं। उसमें हटने-मिटनेवाले अपने विरोधियों को हाथ पकड़कर बैठाते नहीं। क्रांति के भय से ही तो लड़ने का रास्ता छोड़ा गया। फिर भी उसीका नाम!

उसी क्रांति से बचने के लिए किसान-मजदूर राज्य या साम्यवाद के नाम से भी इन लीडरों को बुखार चढ़ जाता था और बहाने करते थे कि मुल्क में वर्ग-विद्वेष पैदा हो जाएगा। तो क्या अब वह विद्वेष न पैदा होगा? और, क्या सचमुच भारत के जमींदार-मालदार इतने भोलेभाले और भले हैं कि उन्हें अपने वर्ग-स्वार्थ का ज्ञान अबतक था ही नहीं? गांधी टोपी, गाढ़ी खादी को पहनकर और जेल के भीतर कांग्रेस के नाम पर रहकर भी इन जमींदार-मालदारों ने किसानों और मजदूरों के खून पीने में जरा भी हिचक कभी नहीं दिखाई है। उन्हींके वोट से असेम्बलियों में जाकर भी उनका गला कुंद छुरी से पहले भी काटा है, आज भी काट रहे हैं। अपना वर्ग-स्वार्थ वे बखूबी समझते और तदनुसार ही मुस्तैदी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

से अमल करते हैं। यह उनका सनातन धर्म है। फिर भी किसानों को जानबूझकर उसी वर्ग-स्वार्थ की जानकारी जिन लीडरों ने आज तक न होने दी, वही जब शांतिपूर्ण क्रांति एवं सत्ता सौंपने की बात बोलते हैं, तो खून में आग लग जाती है। यदि हमारे लीडर शुरू से ही श्रमजीवी किसानों और मजदूरों को वर्ग-स्वार्थ की जानकारी कराते रहते, तो सचमुच ही आज क्रांति हो गई होती फिर चाहे वह शांतिपूर्ण ही क्यों न होती, और अँगरेजों के दुम दबाकर भाग जाने पर उनकी जगह जमींदार-मालदारों की हिम्मत ही न होती कि बैठें। उनके बिठाने के लिए ही तो यह सारा पँवारा रचा गया। तब क्रांति की क्या बात ? क्रांति तो सामुद्रिक तूफान की लहर है, जो अपने सामने किसी भी मंदिर, मस्जिद, महल, मकान, जंगल, पहाड़ को नहीं छोड़ती और सबोंको धो बहाती है। सभी भले-बुरे को, जो सीना ताने खड़ा हो, मिटा देती है।

कांग्रेस एक पार्टी है

कहा जाता है कि अब कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ही रहना है। उसके भीतर अब विरोधी दलों की गुंजायश नहीं रही। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से ही अब किसान सभा, मजदूर सभा आदि वर्ग-संस्थाओं का भी संगठन होगा! यह कथन उसके प्रधान मंत्री श्री शंकरराव देव का है। जहाँ महात्मा गांधी ने अभी-अभी स्पष्ट ही कहा है कि कांग्रेस यदि पार्टी बनेगी तो आत्महत्या कर लेगी, तहाँ उसके मंत्री का ऐसा फर्माना है। यह भी विचित्र बात है। क्योंकि गांधीजी और उनके सिद्धांत की दोहाई देकर ही कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। दर असल पहले भी कांग्रेस एक पार्टी ही रही है। मगर खुलके नहीं छिपे रुस्तम। तब इसीकी जरूरत थी। पार्टी कहनेसे किसान मजदूर भड़क जाते और अगर वे आते, तो अमीर भाग जाते। लड़ने-मरने का काम तो गरीब ही करते हैं। इसलिए उन्हें कांग्रेस में रखना जरूरी था। मगर मालदारों को भी रखना था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आखिर १५ अगस्त का स्वराज्य कौन लेता ; यदि अमीर न रहते ? श्रीयुत देव भी तो मानते ही हैं कि यह अमीरों का ही स्वराज्य है। तभी तो गरीबों को अभी स्वराज्य दिलाना बाकी ही है।

बेशक पहले उसपर नकाब थी, जो अब उतार फेंकी जा रही है। फिर भी कहा जा रहा है कि किसानों और मजदूरों का संगठन कांग्रेस की ओर से ही किया जाएगा। क्यों साहब, कांग्रेस की ओर से क्यों ? स्वतंत्र क्यों नहीं ? श्री देव कहते हैं कि, "कांग्रेस में इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, किसान कांग्रेस या इसी तरह की कांग्रेस के द्वारा पुनरपि संगठित वर्गसंस्थाओं के प्रतिनिधि भी लिए जाएँगे, ताकि वह जन-समूह की संस्था रहे।" इसका सीधा अर्थ यही है कि नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और किसान कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की मातहती में हैं—कांग्रेस के द्वारा संगठित हैं, और अगर कदाचित् वह कांग्रेस की मातहती से इनकार करें, तो कांग्रेस द्वारा वैसी दूसरी संस्थाएँ बनाई जा सकती हैं। मगर हाल में ही श्री गुलजारी लालजी नंदा ने इसकी सफाई देते हुए जो पुस्तिका 'आक्षेपों का उत्तर' (Criticisms Answered) छापी है, उसके चौथे पृष्ठ में लिखा है कि "नई नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक संस्था से स्वतंत्र है और रहेगी और उसकी स्वतंत्र हस्ती में कोई फर्क न होगा, वह कांग्रेसका पुछल्ला न बनेगी"—"the new organisation is and will remain independent of the Congress or any other political body···does not affect the independent status of the organisation or make it an appendage of the National Congress". अब प्रश्न होता ह कि दोनों परस्पर विरोधी बातें कैसे होंगी ? कांग्रेस के द्वारा संगठित होने पर उसका पुछल्ला बनना ही होगा। तभी श्री देव का कहना संगत होगा कि 'And in order to keep its mass basis it should include representatives of functional

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

organisations such as I. N. T. U. C. or Kisan Congress or such other organisations re-organised by the Congress for the purpose'. या कि श्रीयुत देव कांग्रेस की ओर से 'कुछ दूसरी ही और नई वर्ग-संस्थाएँ खड़ी करेंगे और उस काम के लिए नए वर्ग भी ढूँढ़ निकालेंगे ?

और, अगर वर्ग-संस्थाओं का स्वतंत्र संगठन करना ही है, तो पहले से संगठितों को ही प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता ? अब आप ऐसा करने चले हैं। लेकिन अब तक कौन-सी बाधा थी ? यदि पहले से ही यह काम करते रहते, तो क्या आसमान टूट पड़ता ? यदि वर्ग-युद्ध का खतरा था, तो अब भी है और आप उससे भड़कते हैं। जो लोग अब तक वर्ग-संस्थाओं को फूटी आँखों भी नहीं देख सकते थे, वही अब उनका संगठन करेंगे, यह भी निराली बात है। सचमुच संसार परिवर्त्तनशील है या कि केवल धोखे की टट्टी खड़ी की जायगी ? हम श्रीयुत देव से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि यदि हमें वह अपनी किसान संस्था के संगठन का इंचार्ज किसी भी शर्त्त पर बना दें, तो हम उसके लिए तैयार हैं। केवल हम एक ही आजादी चाहते हैं और वह यह कि कांग्रेसी जमींदारों की जमींदारियों में जाकर किसान-संगठन करने में कोई रुकावट न हो। तब उन्हें और दुनिया को पता चल जायगा कि कांग्रेस की ओर से किसानों का संगठन किस प्रकार किया जा सकता है।

मुल्क और कांग्रेस मालदारों के हाथ में

कांग्रेस के कर्णधारों की जो बातें अबतक कही गई हैं, उनसे स्पष्ट है कि कांग्रेस को वे भी मालदारों की संस्था मानते हैं, यद्यपि स्पष्टतः इसे स्वीकार नहीं करते। उसके प्रधान मंत्री का कहना है कि अनेक दलों के बनने से कांग्रेस की ताकत घटेगी। नतीजा यह होगा कि स्थायी स्वार्थवाले (पूँजीवादी) अपनी संगठित शक्ति को मजबूत बना लेंगे—'The vested interests will organise and consolidate their position'। लेकिन स्वतंत्र भारतीय सरकार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi.Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के रेलवे विभाग के मंत्री डा० जौन मथाई ने इसी अगस्त की ८ वीं तारीख को दिल्ली के रोटरी क्लब में जो भाषण दिया, उसे सही मानें या श्री देव की बात को ? वे तो कहते हैं कि 'गत डेढ़ सौ साल के राष्ट्रीय आंदोलनों की प्रगति का दारमदार उस देश के स्थायी स्वार्थ वालों के प्रभाव, साहाय्य और साधन-सामग्री पर ही रहता है। ये स्थायी स्वार्थ वाले इसे एक प्रकार का व्यापार या पूँजी लगाना ही मानते हैं और आंदोलन के दौरान में भी स्वदेशी आदि के प्रचार से लाभ उठाते हैं। लेकिन याद रखने की बात है कि जब इस तरह इनके ऊपर निर्भर रहने से उस आंदोलन को सफलता मिलती और देश आजाद होता हैं, तो मुल्क उनके चंगुल में पहले से भी ज्यादा फँस जाता हैं। भारत की यही दशा कुछ हद तक आज है। आजादी के कुछ मानी नहीं हैं, यदि स्थिर स्वार्थ वालों का यह चंगुल कम-से कम ढीला नहीं हो जाता, अगर खत्म न भी हो सके। इसके लिए लंबी मुद्दत तक सख्त और भारी लड़ाई लड़नी होगी। विदेशी सत्ता खत्म हो जाने पर भी राष्ट्रीयता की नकाब के भीतर जो स्वार्थपरायणता है, वह ठोस और निर्दय वस्तु है' —'If we examine the progress of national movements in any country since the beginning of the 19th century, you will find that a national movement, while it is in progress, is almost inspite of itself, made to depend on the influence, support and resources which it gets from the vested interests of the country.

It is a very good investment for those large organised vested interests, nationalism invariably has an economic side to it and, while being engaged in a national movement, it is possible for vested interests to secure a certain amount of shelter from the competition that comes from foreign interests.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

But the point to remember is that when you have established your national movement, when you have been able to achieve success as a result of being dependent to a large extent upon the support of vested interests, when you have achieved that victory, when you have come to the end of the struggle, you find you are more than ever in the grip of those vested interests on whom you had depended during the period of your struggle.

That to my mind, to some extent, is the stage that we have reached in India today and I think the main part of the task that remains before us today. If freedom is to find full expression, we should carry our fight forward that the grip that vested interests have been able to establish over our people is loosened if not eliminated. That is going to be a long, hard and strenuous fight.

Although the foreign domination had disappeared or had almost entirely disappeared, the kind of selfishness that lay behind nationalism was a hard and cruel one'

डा० मथाई ने जो कुछ कहा है, वह ठोस स्थिति का विश्लेषण-मात्र है। वह कोई अपनी निजी बात नहीं कहते हैं। उनने तो इतिहास के अनुभव को संक्षेप में बतला दिया है। उनके शब्दों में न सिर्फ कांग्रेस, प्रत्युत सारा मुल्क आज भारतीय मालदारों के चंगुल में है और जब इस चंगुल को ढीला करने की लड़ाई लंबी, सख्त और थका देनेवाली होगी, ऐसा वे खुद मानते हैं, तो फिर इस चंगुल को खत्म कर देने के लिए लड़ी जानेवाली लड़ाई कितनी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भयंकर और खूनी होगी, कौन बताएगा ? राष्ट्रीयता के पीछे कितना नीच स्वार्थ और कितनी हृदयहीनता है ! फिर भी, इसी राष्ट्रीयता और इसी कांग्रेस के बल पर हमारे पुराने लीडर जनता को देश की सत्ता सौंपने के सुखद स्वप्न देख रहे हैं ! मालदारों के हथकंडे के नीचे फली-फूली एवं तगड़ी बनी कांग्रेस उनके हाथ से कैसे निकलेगी ? यह तो असंभव है। चाहे चवनियाँ मेंबरी रखिए या खत्म कीजिए, चाहे हजार उपाय कीजिए। मगर उनका हथकंडा हटने के बजाय दिनोंदिन मजबूत होगा।

खूबी तो यह है कि उसी कांग्रेस के द्वारा अब वर्ग-संगठनों का पँवारा खड़ा किया जाएगा, धोके की टट्टी खड़ी की जाएगी। जमींदारों और मालदारों के पैसे से पालतू बहाल होंगे और किसान सभा एवं मजदूर सभा के नाम पर नकली संस्थाएँ खड़ी की जाएँगी। किसान सभा के नए स्वयंभू नेता मालदार-जमींदारों की मोटरों पर चढ़कर उनके पैसे के ही बल पर बुलाई गई किसान मीटिंगों में लेक्चर तो देंगे खासा, किसानों के लिए गला फाड़ेंगे और आँसू भी बहाएँगे; मगर काम करेंगे पैसा देनेवाले प्रभुओं का ही। यह एक भयंकर जाल तैयार होगा, बड़ा खतरा खड़ा होगा। पहले कांग्रेस की शुद्धि हो लेती और उसके ऊपर से मालदार जमींदारों का भूत उतर जाता, तो शायद किसान-मजदूर-संगठन कामलायक बन सकते। मगर यह भूत तो तभी उतरेगा, जब वर्ग-संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में हो, जब किसान सभा और मजदूर सभा के प्रतिनिधि कांग्रेस में स्वतंत्र रूप से लिए जाएँ और जब उसकी चवनियाँ मेंबरी हटाकर काम करनेवाले किसानों और मजदूरों के बालिग मताधिकार के आधार पर ही कांग्रेस क प्रतिनिधि चुने जाएँ। मगर श्रीयुत देव तो इसी से घबराते हैं। वे तो घोड़ के आगे गाड़ी खड़ी करके उसे खिंचवाना चाहते हैं ! उनकी 'जन-तांत्रिक समाजवाद' की आवाज, उसका नारा उनका अपना नहीं है। यह तो उन्हीं मालदारों की आवाज है, जिनका चंगुल कांग्रेस पर कसके जमा है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

अब यह राष्ट्रीयता कैसी ?

राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। फलतः उसे निर्वाण-मुक्ति का पूरा हक है। फिर भी, हमारे नेता उसे बरकरार रखना चाहते हैं। मगर इसमें कई अड़चनें हैं, कई खतरे हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने में, गुलामी को उखाड़ फेंकने की बगावत में राष्ट्रीयता अनिवार्य रूप से अपेक्षित थी। सारे राष्ट्र को एक साथ मिलकर लड़ना जो था। समूचे राष्ट्र को गुलामी की कोढ़ मिटानी जो थी। आजाद सभी होना चाहते थे, चाहे सभी वर्गों के अपने-अपने दृष्टिकोण इस मामले में अलग भले ही थे। आजादी का खयाल हरएक वर्ग का जुदा-जुदा था कि वह कैसी होगी और उसमें हमारे हक क्या होंगे। मगर गुलामी के खिलाफ लड़ना सभी चाहते थे, सबों को मिलकर लड़ने की जरूरत थी। इसलिए राष्ट्रीयता का भूत सबों पर सवार होना अनिवार्य था। परस्पर विरोधी वर्गों का कंधे-से-कंधा भिड़ाकर लड़ना दूसरे रूप में असंभव था। दूसरी शक्ति इन्हें मिला नहीं सकती थी, एक सूत्र में बाँध नहीं सकती थी।

जहाँ इस राष्ट्रीयता से यह फायदा था, तहाँ हानि भी कम न थी। किसान-जमींदार आदि परस्पर विरोधी वर्गों के स्वार्थ-विरोध की स्पष्टता नहीं हो पाती थी। वह विरोध धूमिल और कमजोर नजर आता था। कभी-कभी तो वह लापता-सा हो जाता था। उसपर एक गहरा पर्दा पड़ जाता था। चूहे और बिल्ली में या बाघ और बकरी में जो वर्ग-द्वेष है, जो स्पष्ट विरोध है, वह सदा स्पष्ट रहता है। कभी धूमिल या अस्पष्ट नहीं होता। मगर ऐसी हालत यहाँ नहीं होती। बाघ कितनी ही कंठी-माला पहने, टीका-चंदन लगाए, ध्यान धरे और खादी पहने; फिर भी बकरी उसपर विश्वास नहीं करती। उसके निकट नहीं जाती। लेकिन खादीधारी एवं जेलयात्री जमींदारों पर किसान का विश्वास हो जाता है कि वह उसकी भलाई करेंगे यह ठोस बात है और इसका एक बड़ा कारण राष्ट्रीयता है। बाघ और बकरी एक साथ मिलकर किसीसे लड़ते नहीं। वे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एक सभा में बैठकर प्रस्ताव भी नहीं करते और न लेक्चर देते हैं। मगर कांग्रेस में ये बातें होती हैं। वहाँ जाकर किसान और जमींदार दोनों ही ये बातें करते हैं और यह होता है राष्ट्रीयता के करते। जबतक यह रहती है, वर्ग - विद्वेष और वर्ग-संघर्ष के आधार पर बने आर्थिक प्रोग्राम चलने नहीं पाते। उनमें बाधा पड़ती है। आजादी की लड़ाई छिड़ी कि किसान-जमींदार के बीच चलनेवाला बकाश्त-संघर्ष खत्म हुआ, बंद हुआ। उसे बंद करना ही पड़ता था। इसीलिए विवेकी जन सदा कहते आए हैं कि आर्थिक दृष्टि से होने वाली मोर्चेबंदी के लिए यह राष्ट्रीयता महान् अभिशाप है। फलत: आजादी प्राप्त करके इस राष्ट्रीयता को मार डालने में ही, खत्म करने में ही शोषित-पीड़ित जनता का त्राण है, उद्धार है, कल्याण है।

लेकिन राष्ट्रीय नेता उसी राष्ट्रीयता को कायम रखने में आकाश-पाताल एक कर रहे हैं! इस 'मौर्फिया' को, मोहक मंत्र और जादू को बनाए रखने की कोशिशें भरपूर हो रही हैं। एक ओर डाक्टर मथाई इस राष्ट्रीयता के सूत्र में लोगों को बाँधे रखकर ही लोगों की गरीबी, बीमारी आदि के विरुद्ध जेहाद बोलना चाहते हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस के प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस के अभाव में अराजकता, अंधेरखाता और विश्रृंखलता का भूत देखते हुए इसी राष्ट्रीयता की शरण लेना और इसे दीर्घ जीवन-दान देना चाहते हैं, जिला रखना चाहते हैं।

मगर जब राष्ट्र के भीतर ही शोषकों के विरुद्ध शोषितों को युद्ध-घोषणा करके खून की नदी पार करनी है, तो यहाँ राष्ट्रीयता का अवसर कहाँ? उसकी गुंजायश कहाँ है? राष्ट्र के भीतर तो शोषक एवं शोषित दोनों ही आ जाते हैं। ऐसी हालत में आमने-सामने लड़नेवाली सेना का वर्गीकरण राष्ट्रीयता के आधार पर कैसे होगा? राष्ट्रीय कांग्रेस शोषकों की न होकर केवल शोषितों की कैसे होगी? शोषकों की जो छाप कांग्रेस पर लगी है। वह उतरेगी कैसे? मिटेगी कैसे? या कि राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो जनसाधारण के दिलों में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

सत्कार-सम्मान है, उससे अनुचित लाभ उठाने की तैयारी मात्र यह है ? लोगों का फांसकर और बड़ी-बड़ी आशाएँ दिलाकर कांग्रेस के साथ रखने की कोशिश के अलावे :यह और कुछ नहीं है। उचित तो था कि सरकार के समर्थकों की एक नई पार्टी बनती। या यों कहिए कि मालदारों की पार्टी बनती और अपना आर्थिक या समाज-सुधार का कार्यक्रम लोगों के सामने रखती, जिसके आधार पर इसकी परीक्षा जनता करती। मगर ऐसा होने मे जनता के भड़क जाने का भारी खतरा है। इसीलिए कांग्रेस को ही जिला रखने का भगीरथ प्रयत्न हो रहा है। किसान की भाषा में कह सकते हैं कि जो कांग्रेस आजतक तगड़े बैल के रूप में मौजूद थी, ऐसे बैल के रूप में, जिससे हल खींचने, गाड़ी चलाने और बोझा ढोने का काम लिया जा सकता था—उसे ही आज नांदिया या बसहा बैल के रूप में, रखने की कोशिश हो रही है और होगी। पहला काम तो इसके लिए असंभव है। अब तो यही कहा जाएगा कि यह मान्य है, पूज्य है; इसके सामने सर झुकाओ और इसे कुछ दो—वोट दो, चंदा दो। कांग्रेस के नाम पर चुनावों में वोट माँगना और समय-समय पर चंदे माँगना यही दो काम इसका रह जाएगा। लड़ने या और कोई ठोस काम तो इससे अब किसान-मजदूर आदि ले न सकेंगे। यह बात असंभव है।

कांग्रेस को खत्म होना चाहिए

कुछ समय पूर्व—राष्ट्रपति के आसन पर आसीन होने के पहले—आचार्य कृपलानी ने एक लेखमाला तैयार की थी, जो अँगरेजी अखबारों में छपी थी और जिसके अनुवाद भी छपे थे। अगर मेरी समझ मुझे धोखा नहीं दे रही है, तो उनन स्वीकार किया था कि आजादी मिलने के बाद कांग्रेस की जरूरत न रहेगी। मगर आज तो वह भी यह बात शायद नहीं मानते और उसे कायम रखना चाहते हैं। उनने तो यह भी माना था कि कांग्रेस के द्वारा समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। यह हैं उनके शब्द, 'For all

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

these reasons the congress cannot be an organisation for the establishment of socialism, not at least till Purna Swaraj is attained. And afterwords the Congress as Congress that is as an organisation that works and fights for Indian national independence ceases to exist. The old name may be appropriated by a reforming or reactonary or neutral group, but, it will not be the congress whose goal is complete independence of India or Purna Swaraj, for the simplereason that that has been achieved already'

इसका आशय यह है कि 'इन्हीं कारणों से समाजवाद की स्थापना करनेवाली संस्था कांग्रेस नहीं हो सकती, कम-से-कम पूर्ण स्वराज्य की स्थापना तक तो यह नहीं ही हो सकती। और, उसके बाद तो यह कांग्रेस कांग्रेस के रूप में या यों कहिए कि उस संस्था के रूप में, जो भारत की राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ती है, रही न जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई सुधारवादी, प्रतिक्रियावादी या उदासीन दल कांग्रेस के इस नाम का उपयोग भले ही कर ले। लेकिन यह वह कांग्रेस हर्गिज न होगी, जिसका लक्ष्य है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य और इसका सीधा कारण यही है कि वह लक्ष्य तो हासिल होई गया है।'

यहाँ आचार्य कृपलानी तीन बातें कहते हैं। पहली यह कि कांग्रेस के जरिए समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती; कम-से-कम पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति तक तो नहीं ही। दूसरी यह कि उसके बाद कांग्रेस रही न जाएगी, खत्म हो जाएगी। तीसरी यह कि केवल सुधारवादी या प्रतिक्रियावादी ही दल कांग्रेस के नाम का उपयोग पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति के बाद भी करना चाहेंगे, न कि क्रांतिकारी। इनमें पहली बात में जो अंत में यह पंख लगा दिया है कि कम-से-कम स्वराज्य-प्राप्ति तक तो नहीं ही, वह उनका निजी मत नहीं है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

क्योंकि उसके बाद तो वह कांग्रेस की निर्वाणमुक्ति या उसका खात्मा मानते हैं। फलतः वह कहना केवल उन लोगों की दृष्टि से है, जो कांग्रेस को बाद में भी ठीक उसी तरह घसीटे फिरना या उससे चिपके रहना चाहते हैं, जैसे बंदरिया अपने मरे बच्चे के साथ चिपकी रहती है और उसे छोड़ती नहीं।

अब हमारा सीधा सवाल उन लोगों से है जो कांग्रेस के द्वारा ही जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना चाहते हैं, कि पूर्ण स्वराज्य गत १५ अगस्त को मिला या नहीं ? यदि मिल गया, तो अपनी लक्ष्य-सिद्धि के बाद कांग्रेस खत्म हो गई, मुक्त हो गई, जैसा कि राष्ट्रपति ने खुद माना है। और, अगर वह नहीं मिला और उसकी स्थापना अभी बाकी ही है तो, उन्हीं के शब्दों में समाजवाद की स्थापना कांग्रेस के द्वारा तब तक नहीं हो सकती जबतक पूर्ण स्वराज्य स्थापित न हो ले। फलतः समाजवाद के रूप में कांग्रेस के लक्ष्य को बदलकर जो उसे आगे भी घसीटना और साथ ही क्रांतिकारी कहलाना चाहते हैं ऐसे लोग अपने भीतर ही पहले खुद तो निपट लें। यदि उसके प्रधान मंत्री श्री शंकरराव जी ऐसा चाहते हैं, तो राष्ट्रपति साफ कहते हैं कि नहीं-नहीं, यह तो असंभव है। आजादी मिलने के बाद तो कांग्रेस प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी और दकियानूसों की ही जमात हो सकती है, न कि क्रांतिकारियों की। यह तो केवल एक ही काम में क्रांतिकारी रह सकती है, क्रांतिकारियों की जमात रह सकती है, और वह है राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई, जिसमें सारा राष्ट्र लड़ता है। यही बात राष्ट्रपति उसी लेख में यों कहते हैं, 'It can afford revolutionary action only on one front and that is the notional front.'

जो लोग अब कांग्रेस के द्वारा ही समाजवाद की स्थापना का सब्ज.बाग दिखाकर जनता को फाँसना चाहते हैं, उन्हें आचार्य कृपलानी की स्पष्टोक्तियों को गौर से विचारना और अपना विचार बदलना उचित है। यदि वे कोई और ही कांग्रेस बनाकर उसके

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जरिए यह काम करना चाहें, तो बात दूसरी है। मगर गत ६२ साल से जिस कांग्रेस ने आजादी का संघर्ष चलाया है, यदि उसीसे उनका मतलब है, तो वे भूलते हैं, बेअदवी माफ हो। घरेलू मामले में उसने निरंतर वर्ग-सामंजस्य का पाठ पढ़ा है और सदा सुधारवादी रही है। वही अब बुढ़ापे में वर्ग विद्वेष और क्रांति का पाठ इसी मामले में पढ़ेगी, यह असम्भव है। बूढ़े तोते को रामनाम नहीं पढ़ाया जा सकता।

अच्छा, तो अब उसी लेखमाला में से कृपलानीजी के कुछ वचनों को सुनें। ये वचन यद्यपि उस बड़े लेख में जगह-जगह से लिये गए हैं, फिर भी इनका आशय गड़बड़ होने नहीं पाया है। वे यों हैं, 'The national movement must ever be anxious to eliminate internal conflicts and achieve unity of purpose. A national movement has, therefore, to strike a middle path. In removing internal injustices, whatever its theoretical beliefs and predilections, it must content itself with reformatory activity. Again, the origin and evolution of the Congress precludes it from being a purely class organisation. Socialism is based upon class antagonism, if not class hatred and class war. A national organisation is fundamentally based upon class collaboration. An organisation working for the establishment of socialism cannot include as its members zamindars, capitalists and what are generally called bourgeois classes. In the present context an organisation for the establishment of socialism can only be a sectional organisation."

अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन सदा फिक्रमंद रहता है

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

कि देश के भीतर संघर्ष होने न पाए और सभी लोगोंकी दृष्टि एक ही चीज (आजादी) पर हो। इसीलिए उसे मध्यमार्ग या वर्ग-समन्वय का रास्ता अपनाना होता है। चाहे उसके सैद्धांतिक विचार और झुकाव कुछ भी क्यों न हों, फिर भी मुल्क के भीतरी संघर्षों को मिटाने के लिए उसे सुधारवादी मार्ग का ही अनुसरण करना पड़ता है। कांग्रेस की उत्पत्ति तथा विकास भी इसे किसी वर्ग-विशेष की संस्था होने में बाधक हैं। समाजवाद का आधार यदि वर्ग-युद्ध एवं वर्गों की पारस्परिक घृणा न भी हो, तो उनके स्वार्थों का परस्पर विरोध तो उसका आधार हई। राष्ट्रीय संस्था का आधार बुनियादी तौर पर वर्गों का पारस्परिक सामंजस्य ही है। समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयत्नशील संस्था जमींदारों, पूँजीवादियों और आम-तौर से 'बुर्जुवा' नामधारियों को अपने मेंबर नहीं बना सकती। वर्त्तमान दशा में समाजवाद की स्थापना के लिए उद्योगशील संस्था राष्ट्रीय न होकर सिर्फ वर्गविशेष की ही हो सकती है।'

जो लोग सचमुच विश्वास रखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस को क्रांतिकारी जमात और समाजवाद की स्थापना का यंत्र बना लिया जा सकता है, उनके लिए भी ऊपर लिखे वचनों में काफी मसाला है, जिससे वे अपनी भूल सुधार सकते हैं। आजादी मिलने के बाद राष्ट्रीय संस्था प्रतिगामी बन जाती है, ऐसा मानने के लिए बुनि-यादी बातें ऊपर लिखी गई हैं। एक तो कांग्रेस का जन्मजात आधार ही इस बात का विरोधी है। तुर्रा यह कि बराबर ६२ वर्षों तक वही कायम रहके अभ्यस्त हो गया है, उसके रग-रग में प्रविष्ट कर गया है। फलतः वह बदला नहीं जा सकता। जो लोग उसे बदलने का यत्न करेंगे वे खुद बदल दिए जाएँगे, अब ऐसी ताकत उसमें आ गई है। इसलिए 'तजहु आस निज-निज गृह जाहू'। यह तो दर्या की धारा है, जिसके अनुकूल ही बवंडर भी बह रहा है। फिर भी उसके प्रतिकूल जाने का यत्न अपने-आपको डुबाने के लिए दुस्साहस मात्र है। इतना ही नहीं,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जनसाधारण में ऐसा विश्वास पैदा करके उनके लिए इस प्रकार भविष्य में भारी खतरा भी खड़ा कर दिया जाएगा, जिसमें वे आसानी से जा फँसेंगे। लगातार एक बड़ी मुद्दत तक कांग्रेस को मानने-जानने का जादू तो जनसाधारण पर चढ़ा ही है। उन्हें विश्वास भी है कि अब उनके ही हाथ में सत्ता आ जायगी। जनता भोली-भाली होती जो है। हमारा तो फर्ज है कि उस जनता के ऊपर से यह जादू हटाएँ और बताएँ कि यह विश्वास निराधार है, धोका है, खतरनाक है। न कि उसे और भी मजबूत कर दें और इस प्रकार नया जादू चढ़ने का मौका दें। आज हमारी ताकत इस वस्तुस्थिति के स्पष्टीकरण और नवीन मार्ग के निर्धारण में लगनी चाहिए, न कि इस भूलभुलैया को कायम रखने एवं स्थायी बनाने में। यह तो जनता के प्रति—किसानों एवं मजदूरों के प्रति—भारी विश्वासघात होगा, उन्हें ले डूबने की तैयारी होगी। इससे प्रतिगामियों को बड़ी ताकत मिलेगी।

लक्ष्य सिद्धि अपूर्ण या पूर्ण ?

कांग्रेस को कायम रखने के पक्षपाती कहते हैं कि उसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य अभी कहाँ स्थापित हुआ ? अभी तो सिर्फ गुलामी हटी है। असली स्वराज्य तो लाना बाकी ही है। कांग्रेस की लड़ाई के लक्ष्य के दो पहलू थे—गुलामी हटाना और जनता के हाथ में सत्ता सौंपना। इनमें एक पूरा हुआ। दूसरा तो बाकी ही है। फलतः उसके लिए कांग्रेस का रहना जरूरी है। उनका यह भी कथन है कि भारत दो भागों में विभक्त हो गया है, गो आजाद हुआ है। परंतु हमारा लक्ष्य तो अखंड भारत (United India) था। फलतः उसे प्राप्त करने के लिए भी कांग्रेस का रहना जरूरी है।

लेकिन इसका उत्तर एक प्रकार से पहले ही दे चुके हैं। १५ अगस्त को केवल गुलामी ही हटी थी, या सत्ता भी सौंपी गई थी ? सौंपी तो गई थी जरूर। हथियाई गई थी जरूर। तो फिर जनता को ही क्यों न अवसर दिया गया कि वही वह सत्ता हथिया ले ?

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

इसमें बाधा क्या थी ? और अगर कोई बाधा थी तो वह आपही लोगों की—नेताओं की—ही पैदा की हुई थी न ? दूसरे तो थे नहीं। आपही ने जनता को आगे आने से रोका। आपही ने अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए विधान-परिषद् बनाई-बनवाई, जिससे वास्तविक जनता कोसों दूर रहे, दूर है। फिर भी यदि नेता चाहते तो विधान परिषद् के सदस्य टोपी-टोपवाले बाबू न चुने जाकर धोती-लंगोटीधारी किसान-मजदूर ही चुने जा सकते थे। ऐसा होना कोई कठिन बात न थी। मगर ऐसा होने न दिया गया जानबूझकर ही। बाबुओं को लीडर, मिनिस्टर, गवर्नर, दूत, एलची आदि खुद बनना जो था, अपने दोस्त-अहबाबों को बनाना जो था। नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही बगावत जो हो जाती। क्या यह झूठ है ? क्या सभी लीडरों और उनके भाई-बंधुओं को अपनी शान और अपने स्वराज्य की धुन न थी ? क्या उनपर इसका भूत सवार न था ? फिर भी उन्हीं के बल पर ही, उन्हीं से बनी कांग्रेस के बल पर ही, उसी कांग्रेस के बल पर, जिसे जब चाहें ये बाबू लात मार दें, जनता को सत्ता सौंपने की बात क्या धोके से भरी नहीं है ? खतरनाक नहीं है ? क्या १५ अगस्त को जनता के हाथ में सत्ता सौंपने का मुहूर्त्त ही न था जो पीछे आएगा ? लंगोटी-धोतीधारियों को उस दिन गद्दीनशीन करके यदि ये नेता उनके सच्चे और ईमानदार सलाहकार बनने से ही संतुष्ट हो जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता। और अगर ऐसा न किया तो आगे भी न करेंगे यह ध्रुव सत्य है। अपने तथा अपनों के स्वार्थ के लिए अब कांग्रेस को कीचड़ में घसीटना तथा उसे नाहक बदनाम करना अच्छा नहीं। उसने शान से अपना काम कर दिया। अब शान से ही उसे मर जाने दीजिए और साफ-साफ बाबुओं की एक अलग पार्टी बना लीजिए। यकीन रखिए, जनता उसके भावी कारनामों से ही उसे अपनी या पराए की मानेगी। जिन किसान-मजदूरों ने आपको तख्त पर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिठाया उन्हें आगे गुमराह करना उचित नहीं। यह तो बुरी एहसान-फ़रामोशी होगी।

अधूरे लक्ष्य की बात तो यों ही है। आजादी का अर्थ ही माना जाता रहा है विदेशी शासन से छुटकारा। दूसरा अर्थ उसका रहा है नहीं, यही ईमानदारी की बात है। जब-जब यत्न किया गया कि आजादी या स्वराज्य का विधानात्मक पहलू क्या है, उसे स्पष्ट कर देना चाहिए, तब-तब छाती पीटी गई और हाय-तोबा मची कि ऐसा करने से आजादी की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आज उसका अर्थ बताया जाता है जनता को सत्ता सौंपना, जबकि मालदारों के हाथ में सत्ता जा चुकी है। भारत के मालदार क्या गधे हैं कि यही बात बहुत पहले स्पष्ट कह देने से वे भड़क जाते? वे तो जानते ही थे कि सत्ता किसे मिलती है। अगर लीडरों की नीयत यही रहती कि सत्ता मालदारों को ही मिले, तो सिर्फ इतना कह देने से ही कि जनता को मिलेगी, भारतीय पूँजीपति कभी बुरा न मानते। वह तो ऐसा कहने को नेताओं की निरी चाल समझकर खामोश रह जाते। वे खूब जानते थे और जानते हैं कि कह देने मात्र से सत्ता नहीं मिलती। उसे अपनाने के लिए जनता को तैयार करना जरूरी है और वही बात नहीं की गई। जो जनता तैयार न हो, जिसे वर्गचेतनामूलक राजनीति का पूरा ज्ञान न हो, उससे तो सत्ता कभी भी छीनी जा सकती है। फलत: असल काम है तैयार करना और जनता को सत्ता देंगे ऐसा कहने पर उसी तैयारी की मजबूरी हमारे नेताओं को हो जाती। फलत: उनने कहना ही रोक दिया। न कह के भी वे तैयारी में लग सकते थे। कम-से-कम उनके रास्ते में बाधक न होते जो एतदर्थ जनता को तैयार कर रहे थे। मगर उनने कुछ न किया। प्रत्युत हजार बाधाएँ डालीं और आज मालदारों के हाथ में सत्ता एवं कांग्रेस दोनों ही को सौंपकर जनता को तैयार करने के मंसूबे बाँधे जाने लगे हैं—उसके सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं! 'मसीहाई को

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

रख छोड़ें हमें बीमार रहने दें,' हमारा इतना ही निवेदन है। उनने सदा यही माना है कि कांग्रेस का काम है, उसका लक्ष्य है विदेशी शासन को खत्म कर देना। अबतक का लीडरों का रवैया, उनके लेख और भाषण और आचार्य कृपलानी की लेखमाला जिसका जिक्र पहले आया है इसी बात के पोषक हैं। कांग्रेस का लक्ष्य था केवल नकारात्मक, निषेधात्मक—गुलामी को खत्म करना और वह पूरा हो गया १५ अगस्त को ही। तब लक्ष्य के अपूर्ण रहने का क्या प्रश्न ?

रह गई संयुक्त या अखंड भारत की बात। सो तो अजीब है। जिन लोगों ने इस अंग-भंग की स्वयमेव अनुमति दी वही अब छाती पीटें और दोनों भागों को फिर से मिलाने के लिए कसमें खाएँ और मुहलत माँगें, तो कुछ जँचता नहीं। या कि उसपर मुहर केवल इसीलिए लगाई गई कि पीछे उसीके बहाने कांग्रेस और उसके द्वारा अपनी लीडरी बरकरार रखने का मौका मिलेगा ? यही अवसर माँगने के लिए ही तो ऐसा नहीं किया गया था ? इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी मुल्क के जो भाग राजनीतिक दाव-पेंच में पड़कर अलग हुए वह फिर नहीं मिलते, जबतक पूरा बलप्रयोग न किया जाए। जर्मनी के प्रशिया और रूमानिया के बेसराबिया का इतिहास बताता है कि बिस्मार्क या स्टालिन या ऐसे ही लोगों की आसुरी शक्ति ने फिर से बिछुड़ों को एकत्र किया। पोलैंड के कई भागों की भी यही बात है तथा दूसरे देशों की भी। आयर्लैंड का अल्स्टर आज २५ साल से बिछुड़ा ही है और बिना बलप्रयोग के मिस्टर डीवेलरा या कोई भी उसे मिला न सकेगा। तो क्या हमारे नेता ऐसा करने को तैयार हैं ? फिर गांधीजी का नाम कैसे लेंगे ? भारत के कटे अंग को जोड़ने की उनकी आशा चाहे पवित्र भले ही हो, मगर है वह दुराशामात्र। जिस कांग्रेस ने अलग होने की स्वीकृति दी, वही अब पुनरपि मिलन कराएगी, यह अक्ल के बाहर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की बात है। यदि यही था तो स्वीकृति ही क्यों दी ? यदि लाचार होकर ही, तो वह लाचारी और बढ़ेगी या मिटेगी ?

कांग्रेस की सरकार मजबूत होगी

श्रीयुत देव कहते हैं कि 'भारतीय इतिहास के इस अत्यंत नाजुक वक्त पर इस मुल्क को एक ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो धीरे-धीरे शांतिपूर्ण सर्वांगीण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति कराने में समर्थ हो, जो इतनी विस्तृत हो कि एक जबर्दस्त सरकार को कायम रख सके और संगठन में ऐसी जबर्दस्त हो कि अपना असर जनता पर कायम रख सके, और यह काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है'—'Besides, at this critical period in her history India required for its gradual and orderly political, social and economic all round progress, one big political party, large enough to guarantee stable government, and strong enough organisationally to maintain its hold and influence over the people. The Congress alone could answer all the requirements.'

लेकिन सवाल यह है कि ये सब बातें इसीलिए जरूरी हैं कि किसान-मजदूरों के हाथ में सत्ता जाए और वे सुखी-सम्पन्न हों। तो क्या कांग्रेस यह कर सकेगी ? अभी-अभी तो बता चुके हैं कि उसके लिए यह असंभव है। अंग्रेजी शासन भी खूब संगठित और मजबूत था और ये सभी बातें अपने ढंग से करवा सकता था। मगर हमनें उसे उठा फेंका। क्यों ? इसीलिए न, कि ये बातें हम अपने ढंग से करना चाहते थे, न कि शासकों के ढंग से ? ठीक वही बात फिर भी लागू है। किसान-मजदूरों के ढंग से और उनकी मर्जी के मुताबिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति कराने में कांग्रेस असमर्थ है। फलतः मजबूत सरकार बनाने या शांतिपूर्ण प्रगति का प्रलोभन बेकार है। जो बात हम अंग्रेजों से कहते थे कि तुम्हारे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

शासन की अपेक्षा हम अराजकता को पसन्द करेंगे वही बात कांग्रेस लीडरों से भी क्यों न कहें जब कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कांग्रेस से संभव नहीं, जैसा कि बता चुके हैं ?

कांग्रेस बदल जायगी ?

कहा जाता है कि "कांग्रेस ने अपने जीवन के इतिहास में सिद्ध कर दिया है कि बदलते हुए समय की जरूरत के अनुसार ही वह अपना कायाकल्प कर लेती है, अपने को ढाल लेती है। उसके सामने एक ताजा ऐतिहासिक काम आया है जिसे उसे लगातार पूरा करना ही होगा बिना विराम के ही" "The Congress has proved its capacity to adapt itself to the needs of the changing times. A fresh historic task has to be taken up without any break in the continuity of the life of the Congress"

लेकिन यहाँ भी कांग्रेस के इतिहास का या तो केवल तोड़-मरोड़ किया गया है, या उसकी बुनियादी बातें समझने में भूल की गई हैं। दुनियां की हर चीजें और हर संस्थाएँ कमबेश बदलती और अपने को नए सांचे में ढालती भी हैं। मगर सबों की एक मर्यादा होती है जिसके आगे वे इस मामले में जा नहीं सकती हैं। कांग्रेस की भी यही बात है। वह इस नियम का अपवाद नहीं हो सकती। कह चुके हैं कि कांग्रेस केवल आजादी के संग्राम में ही क्रान्तिकारी बन सकती थी। मगर श्रीयुत देव देश के भीतरी काम, घरेलू काम में भी इसे क्रान्तिकारी रखना और उसका पुराना स्वभाव बदलना चाहते हैं, जो असम्भव है। उनकी रचनात्मक क्रांति (Constructive revolution) केवल विदेशियों के हटाने में भले ही समर्थ हुई, वहीं उसकी गुंजायश रही हो। लेकिन मुल्क के भीतर आर्थिक या समाजिक मामलों में कांग्रेस के द्वारा वह असम्भव है। ऐसा करने पर वह राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी ही नहीं। लेकिन उनके जवाब में हम आचार्य कृपलानी जी की लेखमाला को ही उद्धृत कर देना उचित समझते

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हैं। वह कहते हैं, "It is true that the Congress has changed its form and shape often enough. It changed them after the leadership of Gandhiji. But the changes brought about under his leadership were comparatively conservative and in keeping with its natural evolution and its traditions. Even the non-violence of Gandhiji was in keeping with the traditions of the Congress. From constitutional agitation to non-violent direct action was not a sudden revolution, but an evolutionary revolution that did not change the nature of the Congress as a national organisation. But supposing Gandhiji had changed the Congress to violent and military organisation, such a change would have been too-revolutionary for the very safety and existence of the Congress as an open mass organisation. It would not have been in keeping with its origin, history, tradition and direction of growth. In the language of religion this would not have been its *Swa-Dharma*, but *Para-Dharma*, in which it would have perished."

इसका भाव यह कि है कि "बेशक कांग्रेस ने अपना आकार-प्रकार अकसर बदला है। यह बात गांधीजी के नेतृत्व के समय भी हुई। लेकिन उनके नेतृत्व में इसमें जो भी परिवर्त्तन हुए वे अपेक्षाकृत पुराने ढर्रे के ही थे जो इसके स्वाभाविक विकास एवं परम्परा के अनुकूल ही थे। यहाँ तक कि गाँधीजी की अहिंसा भी उसकी प्राचीन परंपरा के अनुसार ही थी। वैधानिक आन्दोलन तो अहिंसात्मक ही होता है। उसे बदलकर अहिंसात्मक सीधी लड़ाई के रूप में ला देना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

कोई यकायक क्रांति न होकर विकासात्मक क्रांति ही थी जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय संस्थात्मक रूप और स्वभाव को नहीं बदला। लेकिन यदि गांधीजी उसे हिंसात्मक फौजी संस्था बना देते तो यह बात कांग्रेस की प्रत्यक्ष जन-समूह की संस्था के रूप में होनेवाली सत्ता एवं उसकी रक्षा के लिये भयंकर क्रांतिकारी सिद्ध हो जाती। कांग्रेस की उत्पत्ति, इतिहास, परम्परा और विकास के विपरीत यह बात जा पड़ती। धार्मिक भाषा में यह स्वधर्म न होकर परधर्म हो जाता जिसके चलते वह खत्म हो जाती।" लेकिन श्रीयुत देव उसका स्वभाव ही बदल देना चाहते हैं। फिर भी इसे स्वाभाविक कहते हैं।

कांग्रेस का झंडा ही न रहा

और जब कांग्रेस का अपना झंडा भी जाता रहा, उसका त्याग कर दिया गया तो फिर वह जिन्दा रहेगी क्यों कर? उस पर से चर्खे का चिह्न हटकर चक्र का बन गया। कांग्रेसी झंडे के सामने मुस्लिम लीग वाले कभी न झुके। मगर इसके सामने झुके, इसका आदर किया। इस थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप वह झंडा बदल गया। पाकिस्तान में भी लीगी झंडे में जरा-सा परिवर्तन करके एलान कर दिया गया कि यह सरकार का, राष्ट्र का झंडा है, न कि लीग का। वही बात यहाँ भी हो गई। यह सरकारी झंडा हो गया। कांग्रेस का निजी झंडा कोई न रहा। फिर श्रीयुत देव के शब्दों में सामाजिक क्रांति (Social revolution) वह किस झंडे के नीचे करेगी? क्या सरकारी झंडे के हीं नीचे? तो क्या सरकार इसे होने देगी? क्या वह इसे बर्दाश्त भी कर सकती है? क्या भारत सरकार यह एलान करेगी कि वह जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति करना चाहती है? और क्या कांग्रेस और सरकार एक ही है

तब तो बला होगी और लोगों के गुस्से का ठिकाना न रहेगा। आज अन्न, वस्त्र, नमक, तेल, दवादारू, लोह-लक्कड़ के लाले पड़े हैं और जनसाधारण की वेदना का अंत नहीं है। घूसखोरी और चोरबाजारी से नाकोदम है। पुलिस की मनमानी घरजानी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आसमान छू रही है ! खून-खराबी, लूट-पाट जारी हैं। तो क्या इन सभी बातों के लिए जनता अपना क्रोध कांग्रेस पर ही निकाले ? मगर उस दशा में कांग्रेस सामाजिक क्रांति करने के बजाय आत्म-हत्या कर लेगी, उसे मर जाना होगा, उसका साथ देने को कोई तैयार न होगा ! और अगर दोनों एक ही हैं तो कई प्रांतों में प्रधान मंत्रियों के साथ कांग्रेस के अध्यक्षों की तनातनी क्यों चलती है ? यदि प्रधान मंत्री झंडे की सलामी लेना चाहता है तो प्रांतीय कांग्रेस के सभापति क्यों बुरा मानते और खुद सलामी लेने को दौड़ पड़ते हैं ? इसी तरह की सैकड़ों बातें चिल्ला चिल्ला के बताती हैं कि कांग्रेस और सरकार दो संस्थाएँ हैं। इसीलिए कांग्रेस चाहती है, जैसा कि श्री देव कहते हैं, कि सरकार जो अपनी, किसान-मजदूरों की नहीं है उनकी बन जाय। मगर झंडे के अभाव में उनकी चाह केवल पवित्र इच्छा (pious wish) मात्र है। वह कुछ कर नहीं सकती।

आर्थिक राजनीति और राजनीतिक अर्थनीति

तो क्या इस दिमागी कसरत और माथापच्ची के फलस्वरूप दक्षिणपंथी नेता लोग कांग्रेस को बख्श देंगे और आर्थिक कार्य-क्रम के आधार पर कोई दूसरी पार्टी बनायेंगे ? आर्थिक कार्यक्रम से हमारा यह मतलब है कि उस दल का मुख्य कार्यक्रम आर्थिक एवं सामाजिक मसलों को लक्ष्य करके ही बना हो। कांग्रेस का प्रधान कार्यक्रम राष्ट्रीय रहा है और आर्थिक बातें गौण रही हैं। जिसे हम अपनी भाषा में राजनीतिक अर्थनीति कहते हैं वही उसका असली कार्यक्रम रहा है। वह आर्थिक मसलों को भी समय-समय पर छेड़ती-उठाती रही है। मगर उन पर राजनीति की छाप और प्रधानता रही है। उन्हें वह राजनीतिक के आईने में ही देखती रही है। सारांश, राजनीति उसका साध्य और आर्थिक बातें साधन मात्र रही हैं। इसके साफ मानी होते हैं कि कांग्रेस में आर्थिक मसले मजबूरन उठाये जाते थे और उनका मतलब यही था कि उन मसलों में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

दिलचस्पी रखनेवाले किसान-मजदूर कांग्रेस के भक्त बने रहें, उसके अनुयायी रहें और मौके पर उसकी राजनीति में मददगार हों, चाहे वोट देकर, जेल जाकर या सदस्य बन कर। ऐसे मसले छेड़ने में खामखाह किसान-मजदूरों की स्वार्थसिद्धि कभी कांग्रेस का लक्ष्य नहीं रही। नहीं तो असेम्बलियों एवं बोर्डों में मालदार, जमींदार या उनके आदमी ही अधिकांश क्यों भेजे जाते रहे है? खांटी किसान मजदूरों को ही बहुसंख्या में क्यों न भेजा जाता रहा है ? इससे कांग्रेस की मुख्य दृष्टि राजनीतिक दांव पेच ही रहे हैं इसपर पूरा प्रकाश पड़ता है। फलत: वह राजनीतिक पार्टी है।

मगर हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता अब आर्थिक पार्टी बनाएँ और उसके द्वारा अपना काम चलाते हुए कांग्रेस का पिंड छोड़ें। इसका मतलब यही है कि अब वह राजनीतिक अर्थनीति को छोड़कर आर्थिक राजनीति का रास्ता अपनाएँ और इस प्रकार अब अपनी राजनीति को अर्थनीति या आर्थिक प्रश्नों के आईने में देखें। ऐसी दशा में अर्थनीति साध्य और राजनीति उसका साधन बन जायगी। गोलमाल बातों से काम नहीं चलने को है, चाहे इनसे जनता गुमराह भले ही और खतरे में पड़ जाए। मगर "उघरहिं अंत न होय निबाहू।" किसान-मजदूर देखना चाहते हैं कि ये नेता केवल "डपोरशंखोऽस्मिवदामि न ददाम्यहम्" को चरितार्थ करते हैं या सचमुच हमारे जटिल आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों को सुलझाते हैं। यह बात दो टूक होगी और वे इसमें धोके में पड़ न सकेंगे। नेताओं की जांच भी खरी होगी। ईमानदारी का तकाजा है कि यही किया जाय और प्राचीन महर्षियों की प्रतिष्ठा और उनके लिए जनता में विद्यमान आदर की ओट में जिस प्रकार आज के पंडे-पुजारी और साधु-महात्मा अपनी कमजोरियाँ छिपाते और उन्हींकी दोहाई देकर काम चलाते हैं वही बात कांग्रेस के नाम और उसकी दोहाई के पीछे ये हमारे नेता न करें। ये बहादुर हैं, मर्द हैं, धुनवाले हैं। फलत: यह द्रविड़-प्राणायाम उन्हें शोभा नहीं देता, यह लुकाचोरी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उनकी शान में बट्टा लगाती है। जिन नेताओं को हमने आज तक सर-आँखों चढ़ाया उनके बारे में यह चीज हम से बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी यह तमन्ना है, उनसे हमारी दस्तबस्ता अर्ज है।

मौके की ताक में

मगर हमें आशा नहीं कि वे ऐसा करेंगे। राजनीति बड़ी गंदी चीज है, बुरी है और उनकी राजनीति का यह तकाजा है कि ऐसा ही करें। वह तो मौके की ताक में थे ही और देखा कि वह आ गया है। फिर चूकने क्यों लगे? नई पार्टी बनाने में उसे जनसाधारण के सामने लाने और प्रसिद्ध करने में एक खासी मुद्दत लगेगी। तब तक क्या ये लोग दूसरों की मर्जी पर रहेंगे? दुनिया बेदर्द है। यहाँ किसी को कोई पूछता नहीं। बात की बात में पहले के सभी किए कराए को लोग भूल जाते और बड़े-बड़े तक को दूध की मक्खी की तरह उठा फेंकते हैं। तब ये नेता खतरा क्यों मोल लें? एक बात और भी है। कांग्रेस की बातें गोलमोल रही हैं और उसके बारे में लोगों की वैसी आदत भी पड़ गई है। फलत: ज्यादा पर्वा नहीं करते। अत: आगे भी उसी की पूँछ पकड़ना हमारे नेता सुरक्षित समझते हैं। लेकिन नई आर्थिक पार्टी बनाने के बाद तो वे लोग अपने आप को जनता की बेमुरव्वत समालोचना की तोप के मुँह पर खड़ा कर देंगे। तब तो उनकी हर बात की जांच पड़ताल वह बेदर्दी के के साथ करेगी। पुराने ऋषि-मुनियों के अनुयायी आज पाप भी करें तो लोग बर्दाश्त कर जाते हैं। मगर उनके विरुद्ध जानेवालों की एक भी बात सुनने को रवादार नहीं जबतक वह पुराने साँचे में ढली न हो। जनता की इस मनोवृत्ति को हमारे नेता खूब समझते हैं और इससे लाभ उठाना चाहते हैं।

नेता लोग यह भी देखते हैं कि चाहे कुछ लोग मेढ़कों की तरह टर्र-टर्र भले ही करते रहें। फिर भी संगठित रूप से आज ऐसी कोई भी आवाज नहीं उठ सकती, जो हमें रोक सके, हमारी इस

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

चातुरी का, इस कूटनीति का सफल भंडाफोड़ कर सके। वे स्पष्ट देखते हैं कि उनकी चाल के विरुद्ध पर्याप्त प्रचार करके जनता को उभाड़ने और इस तरह उन्हें रुक जाने को विवश करनेवाली कोई भी जबर्दस्त ताकत, संगठित शक्ति देश में रह नहीं गई है, और दर असल किसान-मजदूरों के लिए यह सब से बड़ा खतरा है। आज प्रायः सभी समाचारपत्र मालदारों के हाथ में होने से नेताओं की चाल का ही समर्थन करते हैं, करेंगे। रेडियो, सिनेमा और प्रेस उन्हीं के हाथ में हैं। सरकार की सारी मैशीनरी उन्हीं के साथ है, उन्हीं की दासी है। वे चाहे जितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं और "ऊँट बिलैया लेगई, तो हांजी हांजी कहना" को अक्षरशः चरितार्थ कर सकते हैं। चाहें तो अनन्त प्रचारक भर्ती कर के उनसे भाड़े के टट्टू का काम ले सकते हैं। जाब्ता फौजदारी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जेल, पुलिस की लाठी और फौज की गोली भी आज उन्हीं के हाथ में है जिसके द्वारा विरोधियों की आवाज को हजार बहाने करके आसानी से कुचला जा सकता है। पंडित, पुजारी, मौलवी और पादरी भी जरूरत होने पर उन्हींके इशारे पर नाच सकते हैं और दुर्भाग्य से इनका असर हमारे देश में बहुत ज्यादा है। फिर ऐसे मौके से ये लीडर चूकनेवाले कब हैं ?

बड़े से बड़ा खतरा

किसान-मजदूरों के लिए ये सभी खतरे तो हुई और ये ठोस हैं, जबर्दस्त हैं। मगर इन सबों से भी बढ़कर दो खतरे हैं। राजनीतिक उथल-पुथल और खासकर दो महायुद्धों के चलते जनता में राजनीतिक चेतना आई है जरूर और काफी आई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर उसमें एक बड़ी कमी है, खामी है। उसे कोई निश्चित आकार नहीं मिला है। वह यों ही गोलमाल है, vague है। फलतः उसे किसी भी रंग में रँगा जा सकता है, किसी ओर मोड़ा जा सकता है। जैसे गीली मिट्टी को घड़े, खपड़े, बर्त्तन, मूर्त्ति या किसी भी रूप में बदल सकते हैं। यह बड़ी खतरा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नाक चीज है। वे अपनी राजनीति को ठीक-ठीक समझ नहीं सकते। मुल्क की राजनीति का विश्लेषण, उसकी उधेड़बुन भी नहीं कर सकते। फलतः असानी से धोके में पड़ सकते हैं। जोई गर्म लेक्चर झाड़े और आँसू बहादे या जेल गया हो उसीपर जनसाधारण लट्टू हो सकते हैं, उसीके मुरीद और चेले मुड़े जा सकते हैं। नतीजा यह होगा कि आज तक जो लोग किसान सेवकों का बाना पहने हुए थे उन्हें भी दक्षिण पंथी लोग रुपए-पैसे, नौकरी - चाकरी, रोजगार-व्यापार आदि के जरिए खरीद कर भारी बला पैदा कर सकते हैं, बला पैदा करेंगे। जनता की आदत होती है बिना विचारे ही विश्वास कर लेना (Unthinking trustfulness)। लेनिन बार-बार ऐसा कहा करता था। खासकर राजनीतिक मामलों में तो इस नादानी के करते बड़ा खतरा पैदा हो जायगा। आजादी की लड़ाई के सिलसिले में पुराने नेताओं पर विश्वास होना स्वाभाविक ठहरा। क्योंकि वर्गचेतनामूलक राजनीतिक ज्ञान के अभाव का नतीजा दूसरा हो नहीं सकता। इसीके साथ पुराने किसान सेवक भी जब खरीद ही लिए गए तो फिर किसानों का खुदा ही हाफिज। ये उन-पर विश्वास करेंगे और इस तरह अपना गला कटायेंगे। यह हुआ एक खतरा।

दूसरा बड़ा खतरा यह है कि मुल्क में जितने भी प्रगतिशील विचार करनेवाले या वामपंथी हैं सबोंको अपनी - अपनी डफली, अपना अपना गीत है। कम से कम जितनी पार्टियों में ये लोग बंटे हैं उतने रास्ते तो इनके हई। आपस में इनका काम करना वैसा ही है, जैसा बाघ और बकरी का। एक दूसरे से बातें करने में भी इन्हें नफरत है। दक्षिणपंथी नेताओं की सब से बड़ी होशि-यारी यही रही कि उनने वामपंथियों में "तीन कनौजिया तेरह चूल्हा" कर दिया और एक दूसरे को हजार कोस दूर रखा। हमारी पार्टी सही, हमारी पालिसी दुरुस्त और हमारी पोलिटीकल थीसिस खरी है, इसी धुन में हरेक पार्टीवाला मस्त है। उसपर इसका

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

नशा सवार है। वह दक्षिणपंथियों से मिलने और बातें करने में जरा भी नहीं हिचकता। मगर क्या मजाल कि एक पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी के लीडर से बातें करे। कांग्रेस नेता सबों को कान पकड़ के एके बाद दीगरे नचाते हैं, नचाने की हिम्मत रखते हैं। उन्हें विश्वास है कि इन पार्टियों को जो भी चाहें खरीद सकते हैं। अब तक ऐसा होने नहीं दिया कि कोई पार्टी या सभी पार्टियाँ मिलकर भी उनका सफलता से सामना कर सकें। ऐसी हालत में उनके वर्त्तमान रवैये की असलियत जनता के सामने कौन रख सकता है? यदि आज वामपक्षीय एकता हो तभी उनका ठीक-ठीक जवाब मिल सकता है। जो लोग यहाँ तक कहने की हिम्मत करने लगे हैं कि किसान राज्य तो अब कायम होई गया उनके भी होश दुरुस्त तभी हो सकते हैं जब सभी प्रगतिशील या समाजवादी विचारवाले एक होकर काम करें। मगर आज इसी चीज का अभाव है और यही दूसरा बड़ा खतरा है।

आखिर हो क्या ?

तो क्या अब निराशा ही निराशा है? क्या शोषित-पीड़ितों के लिए अंधेरा ही अंधेरा है? क्या अब कुछ हो नहीं सकता? उत्तर सीधा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब कुछ निर्भर करता है कि शोषित-पीड़ितों की आवाज निरंतर उठाने वाले क्या करते हैं। जो लोग किसान-मजदूरों की ओर से बराबर चिल्लाते रहे हैं वह इस मौके पर क्या करते हैं? यह तो सभी मानते हैं कि इतिहास करवट ले रहा है—भारतीय आजादी की लड़ाई का इतिहास। वह इतिहास दक्षिण करवट ले इसकी पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है, इसका पूरा आयोजन है। दुनिया की ऐसी लड़ाइयों का इतिहास भी यही बताता है कि ऐसे मौके पर वह दाहिनी करवट बदलता है—Right about turn करता है और भारत उसका अपवाद न होगा। यह करवट थोड़ी देर बाद बाईं हो जाए, यह बात जुदी है—Left about turn हो जाए, से

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संभव है, जैसा कि रूस में हुआ था। मगर क्या रूस के जैसा लेनिन यहाँ कोई है? क्या उसके जैसा किसान-मजदूरों का मसीहा और क्रांति की कला का पारंगत कलाविद् यहाँ कोई है? अगर नहीं है, तो क्या हम हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहें? मगर इतिहास तो बैठा रहेगा नहीं, समय तो रुकेगा नहीं और किसान-मजदूरों के शत्रु तो इंतजार करेंगे नहीं। वे तो अपनी राह चले जाएँगे। तो क्या यह दाहिनी करवट यों ही बदलने दी जाए और हम कुछ न करें?

करना तो होगा ही। यदि खुद न करेंगे, तो मजबूरन करना पड़ेगा; मगर तब, जब बहुत देर हो चुकी रहेगी और करना-धरना बेकार सिद्ध होगा। यदि हममें, वामपक्षी होने के दावादारों में, जरा भी नेकनीयती और ईमानदारी होगी, जरा भी हया होगी, तो हमें कुछ-न-कुछ ठोस काम करना ही होगा, आगे कदम बढ़ाना होगा। १९३४ में हमारे इतिहास की एक मामूली करवट थी, तो वामपक्ष ने कदम बढ़ाया और सोशलिस्ट पार्टी बनी। फिर १९३९ में कुछ ऐसा ही मौका था, तो वामपक्षीय कमिटी (Left Consolidation Committee) और पीछे फारवर्ड ब्लाक का जन्म हुआ। मगर इस करवट के सामने वे दोनों कुछ न थीं। तब तो लड़ाई के एक ही पर्व के दरम्यान यह करवट थी। मगर अब तो वह पर्व खतम हुआ और दाहिनी करवट की जोरदार तैयारी है। फलतः हमें कुछ-न-कुछ ठोस कदम आगे बढ़ाना ही होगा। नहीं तो आनेवाली पीढ़ी हमें कोसेगी, धिक्कारेगी।

इस बार हमें कोई नई पार्टी न बनाकर मुस्तैदी से सभी दलों और पार्टियों का, जो वर्ग-विहीन समाज की स्थापना मार्क्सवादी ढंग से करने को तैयार हैं, एक संयुक्त मोर्चा या प्लैटफार्म बनाना है। इस काम के लिये चाहे कोई कमिटी बने या उसे एक पार्टी का ही रूप दिया जाय, यह बात दूसरी है। फ्रांस आदि देशों के संयुक्त मोर्चे की त्रुटियों से हम बचने का भी उपाय करें और कदम आगे बढ़ायें भी। इस काम के लिए एक केंद्रीय स्थान पर सभी दलों के प्रमुख व्यक्तियों की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

और ऐसे लोगोंकी भी, जो किसी पार्टी में नहीं हैं, मगर मार्क्सवा
विचार रखते हैं, एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाय। वह कई दिन
और सभी पहलुओं पर बखूबी गौर करके किसी नतीजे पर पहुँ
यह काम जल्द होना चाहिये। देर की गुंजाइश नहीं है।

उस मीटिंग में एक सम्मिलित कार्यक्रम तैयार किया जाय।
कार्यक्रम कम से कम या छोटे से छोटा हो। इसमें एक ही दो ब
रहें। मगर वे सर्वसम्मत हों और खुले दिल से सभी दलवाले उ
स्वीकार करें। दबी जबान और आधे दिलसे स्वीकृत बातें
प्रोग्राम में न रहें। दृष्टांत के लिए आज का दक्षिणपक्षी लीडरों
कांग्रेस संबंधी अगला कदम लेकर उसकी असलियत का प्रचार
ले सकते हैं। उसका क्या रहस्य है और इसमें क्या खतरे हैं, इस
प्रचार में किसीको आनाकानी नहीं हो सकती है। फलतः सुसंग
रूप से इसका मुस्तैदी से प्रचार होने की बात तय कर सकते
इसी तरह की दूसरी बातें भी ढूँढ़ी जा सकती हैं। मेरा अप
विचार है कि राष्ट्रीय आजादी के प्रश्न के एक करवट बैठ जाने
कारण अब किसी भी वामपक्षीय पार्टी के साथ दूसरी पार्टियों
के संयुक्त मोर्चा बनाने में कोई खास अड़चन नहीं होनी चाहि
मैं तो यह भी मानता हूँ कि सबों में मार्क्सवाद की इतनी
अपने लक्ष्य के प्रति इतनी ईमानदारी-वफादारी और अपने में इत
हया, इतनी लाज मौजूद है कि जरूर आगे बढ़ेंगे और अनायास
जानेवाली हाराकिरी से सबों को बचाएँगे। सबोंको अपनी प्रति
का, आत्मसम्मान का खयाल है और यह भी मालूम है कि कुछ
करने पर सबों पर एक के बाद दीगरे भींगे जूते पड़ने हैं। सबों की श
में बट्टा लगना है, बेइज्जती होनी है जो, गीता के शब्दों में मौत
भी बुरी है, "सम्भावितस्य चाकीर्त्तिमरणा दतिरिच्यते"।

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हमारे किसान सेवक

८ मई १९४७ से १७ मई १९४७ तक बिहटा में चलनेवाले बिहार प्रान्तीय किसान शिक्षणशिबिर का संक्षिप्त विवरण, उसमें आये हुए किसान सेवकों एवं सेविकाओं का साधारण परिचय और उसका आय - व्यय।

प्रकाशक :
हुंकार-पुस्तकमाला
बांकीपुर : पटना

मूल्य—आठ आना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शिक्षण शिबिर का संक्षिप्त विवरण

बिहार प्रान्तीय किसान शिक्षण शिबिर ८ मई १९४७ से १८ मई तक होने को था। मगर कई कारणों से १७ वीं को ही उसका कार्य पूरा हो गया। ८ वीं को भी बिहार प्रान्तीय किसान सभा की बैठक होने के कारण शिबिर का कार्य विशेष रूप से न हो सका। शेष ९ दिन उसका काम ठीक-ठीक चालू रहा। १४ वीं मई की शाम को और १५ वीं के प्रातः श्री हरद्वार सिंह के नायकत्व में लालवर्दीधारी ५० से अधिक किसान-सेवकों का जत्था बिहटा के चारों ओर के गावों घूमता और किसान सभा के नारों से उन्हें गुंजाता रहा। गांववालों ने किसान सेवकों को नाश्ता-पानी भी कराया।

शिक्षणशिबिर में सौ से अधिक किसान सेवक और सेविकाओं ने भाग लिया। इनमें ८ सेविकायें थीं जो एकमात्र सिनुआरी ग्राम, हसुवा थाना, नावादा सबडिविजन, जिला गया की थीं। इनने न सिर्फ वहां के किसान संघर्ष को सफलतापूर्वक चलाया था, बल्कि गत साम्प्रदायिक दंगे के समय भी पास-पड़ोस के मुसलमानों को अभय दान देकर उनकी रक्षा प्राणपन से की। वहां दंगे की लपट पहुँचने नहीं पाई। इनने किसान सेवा का व्रत लिया है और प्रतिज्ञा की है कि चाहे जहां रहें—पति के घर या पिता के यहां—सदा यह कार्य करेंगी। शेष ९० से अधिक किसान-सेवक थे जिनमें कुछ नये और शेष पुराने एवं तपे तपाये थे। यद्यपि विचार था दो सौ के बुलाने और शिक्षा देने का। तथापि विवाह लग्न की बड़ी तेजी और गर्मी की अधिकता के कारण उतने न आ सके। जिनके नाम आगे मिलेंगे उनके सिवाय दरभंगा, हजारीबाग आदि जिलों के श्री रामलोचन सिंह, श्री डा० रामप्रकाश शर्मा, श्री नारायण प्रसाद प्रभृति भी आये थे। मगर वे लोग अधिक दिन टिक न सके। कुछ जिले के लोगों को देहात में सूचना न मिलने या देर से मिलने से वे न

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

आ सके और उनने पीछे पश्चात्ताप जाहिर किया। फिर भी शिक्षणशिबिर का यह पहला संगठित प्रयत्न सफल ही रहा। एतदर्थ अन्न, धनादि से सहायता करनेवाले सज्जनों के सामने हम और शर्मा जी नत-मस्तक हैं।

जिले के हिसाब से गया से ४५, पटना से २४, शाहाबाद से १६ मुंगेर से ५, दरभंगे से ४, चम्पारन से २, सारन से २, और मुजफ्फरपुर से १ शिक्षार्थी शिबिर में शामिल हुए। आखिरी दिन उन्हें जो महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया गया उसका सारांश यही है कि (१) अपने आपमें, अपने लक्ष्य किसान-मजदूर राज्य में और किसानों में अटूट विश्वास रखें; (२) प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति मास किसान सभा का कम-से-कम कितना काम जरूर करेंगे इसका निश्चय कर लें और वह समय पूरा होने पर देखें कि उतना काम पूरा हुआ या नहीं; यदि नहीं, तो आगे पूरा करने का प्रण कर लें; (३) अपने नित्य के कामों की डायरी रखें और सुबह या शाम को उसे लिखें; (४) स्वामीजी के पास महीने में चार या दो पत्र जरूर लिखें; (५) समय और वचन की पाबन्दी बेमुरव्वती से करें; (६) किसान सेवा को साधना या तप समझ उसे अपवित्र न होने दें।

आगे शिक्षार्थियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जो भविष्य के लिए बड़े काम का होगा। शिबिर के कामों का ब्योरा संक्षेप में इस तरह है—

८ मई को सुबह की गाड़ी से प्रांतीय किसान सभा के प्रधान मंत्री पं० रामचन्द्र शर्मा तथा पं० यमुना कार्यी बिहटा पधारे। साथ-साथ पटना, गया, मुंगेर तथा दरभंगा जिले के बहुत-से शिक्षार्थी अपने-अपने बिस्तर एवं अन्य सामान के साथ झुंड के झुंड बिहटा स्टेशन पर पहुँचे। नेताओं तथा शिक्षार्थियों के स्वागत के लिए किसानों के कर्मठ नेता पं० यदुनन्दन शर्मा कई अन्य किसान-सेवकों के साथ पहले से ही बिहटा स्टेशन पर मौजूद थे। उसी समय शाहाबाद जिले के दर्जनों लालवर्दी धारी शिक्षार्थी पश्चिम की गाड़ी से उतरे।

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्टेशन से कार्यकर्त्ता श्री सीताराम आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में चहल-पहल थी। उस ८ मई की शाम तक प्रांत के कोने-कोने से लगभग एक सौ शिक्षार्थी इकट्ठे हो गए।

शिक्षण केंद्र का उद्‌घाटन करते हुए पं० यदुनन्दनशर्मा ने कहा कि दुनिया और हिंदुस्तान की हालत बड़ी तेजी से बदल रही है। ऐसी अवस्था में बिना राजनीतिक ज्ञान किए जनता में जागृति लाना कठिन है। अतएव जो शिक्षार्थी या किसान-सेवक यहां शिक्षा पाने के लिए आए उन्हें अच्छी तरह से अनुशासन पालन करना चाहिए। तदुपरांत जननायक स्वामी सहजानन्द सरस्वती का भाषण हुआ। आपने अपने सारगर्भित भाषण के सिलसिले में किसान सभा का उद्देश्य, अनुशासन, पार्टियों के साथ किसान सभा का संबंध तथा राजनीतिक दाव-पेंच इत्यादि विषयों का भली-भाँति दिग्दर्शन कराया।

उसी दिन नवनिर्वाचित बिहार प्रांतीय किसान सभा की भी बैठक हुई, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

९ मई को ७ बजे सुबह में २ घंटे तक स्वामीजी का राष्ट्रीय राजनीति पर भाषण हुआ। फिर जमींदारी प्रथा के खात्मा पर पं० यमुना कार्यी का भाषण हुआ। शाम को स्वामीजी इतिहास और राजनीति पर बोले और कार्यी जी जमींदारी के खात्मा पर।

शिविर के इंचार्य पं० यदुनन्दन शर्मा जी थे। कुएँ में पानी खींचने के लिए नल लगाया गया था और स्नान करने के लिए सिमेंट का एक बड़ा हौज बना दिया गया था, जिससे शिक्षार्थियों को बड़ी सुविधा मिलती थी। शिक्षार्थियों के लिए भोजन, जलपान तथा व्यायाम का उत्तम प्रबंध था। कैंप के इंचार्ज पं० यदुनन्दन शर्मा सब से पहले उठते थे और सबके बाद सोते थे। सभी शिक्षार्थियों की सुविधा का आप पूरा खयाल रखते थे।

पाँच बजे सुबह में घंटी बजती थी। उठने के बाद सर्वप्रथम सितुआरी सत्याग्रह की देवियों तथा किसान-सेवकों द्वारा भारत-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

वन्दना होती थी। शौचादि तथा स्नानादि से निवृत्त हो कर कैप्टेन हरद्वार सिंह के नेतृत्व में लालवर्दी धारी किसान-सेवकों की कवायद होती थी। ७ बजे बिगुल बजते ही जलपान से निवृत्त हो कर लोगों को क्लास में चला आना पड़ता था। स्वामीजी तथा अन्य अध्यापकों के पहुँचते ही शिक्षार्थी खड़े होकर 'जयहिन्द' कहने के बाद अपना आसन ग्रहण करते थे। इस प्रकार ८ से १७ मई तक स्वामीजी, पं० यमुना कार्यी, पं० यदुनन्दन शर्मा, प्रोफेसर परमानंद प्रसाद, प्रोफेसर रामस्वरूपनारायण सिंह तथा पं० रामचन्द्र शर्मा का सुबह-शाम भाषण होता रहा। खासकर स्वामीजी ने हिन्दुस्तान में पार्टियाँ, पाकिस्तान, मार्क्सवाद, बकाश्त की लड़ाई, किसान क्या करें, हिन्दुस्ताम की वर्तमान परिस्थिति, भाग्य और भगवान तथा किसान सभा कैसे चलाई जाए आदि कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर भाषण दिया, जिसका असर शिक्षार्थियों पर काफी पड़ा। प्रोफेसर परमानन्द प्रसाद ने अधिकार पर बड़ा ही ओजपूर्ण भाषण दिया और प्रोफेसर रामस्वरूपनारायण सिंह ने जनसंख्या पर काफी प्रकाश डाला।

१६ मई की रात में पं० खड्गधारी मिश्र के नायकत्व में शिक्षण-शिविर के विद्यार्थियों ने 'किसानों की दुनिया' नामक बड़ा ही रोमांचकारी तथा प्रभावशाली नाटक खेला, जिसे देखने के लिए दूर-दूर के गांवों से ४-५ हजार की तायदाद में किसान आए थे। १७ मई के सबेर में स्वामीजी और पं० यदुनन्दन शर्मा का आखिरी भाषण हुआ। स्वामीजी ने किसान-सेवकों को संकेत करते हुए कहा कि विपत्तियों से कभी न घबराएँ और वचन को पूरा करें। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को अपने में और अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। साथ ही प्रत्येक किसान-सेवक को अपने कार्यों की डायरी रखनी चाहिए और किसानों से लिए गए पैसे का साफ हिसाब रखना चाहिए। अंत में पं० यदुनन्दन शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन का वर्णन करते हुए रो पड़े, जिसका किसान-सेवकों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पर गहरा असर पड़ा। इसी प्रकार जिले-जिले और थाने-थाने में किसान-शिक्षण-शिविर खोलकर किसान-कार्यकर्त्ताओं को ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई।

१७ मई को दोपहर की गाड़ी से अधिकतर शिक्षार्थी अपने-अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए।

शिविर के आय-व्यय का व्योरा अन्त में दिया गया है।

संक्षिप्त परिचय

श्री शिवशरण प्रसाद :—घर कोलविगहा और उम्र २० वर्ष। बोलने-चालने में कंजूस, देखने में गंभीर तथा जवानी के अन्य कई गुणों से वंचित, माँ का प्यारा और सबसे छोटा बच्चा। १२ वर्ष की उम्र के पहले की घटना से एकदम अनभिज्ञ, खेलकूद तथा पढ़ने-लिखने की मामूली रुचि। शिक्षा मि० हिन्दी तक। घर की हालत साधारण, पक्के गृहस्थ। ४२ की क्रांति में देश सेवा की लग्न हुई और डाकखाने के जलाने में सहयोग। शिक्षण-शिबिर में आने के पूर्व किसान आंदोलन तथा किसानों की समस्या से अपरिचित। शिक्षण-शिविर से प्रभावित होकर आगे कुछ करने की इच्छा। पिता श्री गंगा प्रसाद, गांव कोलविगहा, पो० चंडी, जि० पटना।

श्री सुखनन्दन शर्मा :—घर दबौल, उम्र २६ वर्ष। माँ-बाप की दूसरी संतान, रंग श्यामला, चेहरे पर फुंसी। ५ वर्ष की उम्र से घटित घटनाओं का स्मरण। पढ़ने-लिखने की आरंभ से ही रुचि। परंतु शिक्षा आठवें क्लास तक ही। जमींदार से संघर्ष और पिता जी की मृत्यु के कारण आगे की शिक्षा से वंचित। १९३० से देश सेवा की ओर रुचि। पुलिस के अनुचित व्यवहार से रंज होकर उसे पीटना और जेल यात्रा। ४२ के आंदोलन के साथ सहानुभूति और सक्रिय सहयोग। सुखी-सम्पन्न किसान, नाममात्र की मिलकीयत, परंतु प्रधान जीविका का साधन खेती। किसान आंदोलन में अधिक से अधिक समय देने का विचार। पिता श्री परमेश्वर शर्म्मा, गांव दबौल, पो० हिलसा, जि० पटना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

ब्रह्मचारी रामाश्रय विशारद :—उम्र लगभग ४२ वर्ष, गोरे और लंबे कद का, पिता का ७वां पुत्र, समझ बूझकर ब्रह्मचारी और शिक्षक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षोत्तीर्ण, लँदफँद से स्वाभाविक घृणा तथा सार्वजनिक सेवा में अटूट श्रद्धा। बीसों वर्ष से शिक्षक की हैसियत से बच्चों को सर्व प्रकार से योग्य बनाने की कोशिश और पिछड़ी हुई दिहाती जनता को आगे बढ़ाने में समय का सदुपयोग। संगठन में अटूट विश्वास, ग्रामीणों की शिक्षा, सफाई दवा आदि की सुविधा के लिये 'ग्राम सुधार संघ' की स्थापना, उसका प्रचारादि। साथ ही किसान की सेवा, उसके हक की रक्षा में पूर्ण विश्वास। समय-समय पर पत्रों में अपना विचार देना। ग्राम-सुधार ही उन्नति तथा उद्धार का साधन। पिता श्री वजीर सिंह, गांव सतपरसा, पो० हजरत साईं, जि० पटना।

४ *श्री त्रिवेणी शर्म्मा*:—अट्ठारह वर्ष का नौजवान। राष्ट्रीय मनोवृत्ति का, विद्यार्थी-जीवन व्यतीत करते हुए विद्यार्थियों में राष्ट्रीय-भाव जागृत करना, पिता की दूसरी संतान। घर की आर्थिक स्थिति बढ़िया, किन्तु घर के परिवार से उपेक्षित, घर के परिवार में जमींदारी मनोवृत्ति। वर्त्तमान समय आश्रम का जीवन, अध्ययन की मनोवृति वाला, गरीबों की सेवा की उत्कट भावना। ४२ के आन्दोलन में भाग लिया हुआ। विद्यार्थी संगठन का अग्रदूत। गोरे रंग का सुदृढ़ शरीर। पिता श्री कैलाश शर्म्मा, गांव मझियावां, पो० कुर्था, जि० गया।

५ *श्री राम सुभग पांडे*:—५७ वर्ष का, सार्वजनिक क्षेत्र में तपेतपाये, १९२१ से ही सेवा का काम करते हुए ५, ६ बार जेल यात्रा की। कद के लंबे, गोरे, बाल में सफेदी। गंभीर विचार के मिड्ल ट्रेनिङ्ग की शिक्षा प्राप्त। १५ वर्ष से किसान आन्दोलन के पुजारी। साधारण किसान। पिता श्री कमलेश्वर पांडे, गाँव तथा पो० सिमरी, जि० शाहाबाद।

६ *श्री रामदर्श पांडे*:—६१ वर्षीय वृद्ध तथा तपातपाया जनसेवक,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

४, ५, बार सार्वजनिक सेवा में जेल यात्री, पुष्ट शरीर, लम्बे कद का गोरा, गंभीर, साधारण किसान, लटपट से दूर, मुकदमेबाजी से दूर। पिता श्री निरहू पांडे, गांव तथा पो० सिमरी, जि० शाहाबाद।

७ *श्री झगड़ू राय:*—४० वर्ष की उम्र का नौजवान। खादी धारी, लोअर क्लास तक की शिक्षा प्राप्त, आर्थिक स्थिति अच्छी, साधारण अच्छा किसान, ६ वर्षों से किसान सभा में भाग लेते हुए किसान आन्दोलन का प्रेमी। माता के बड़े पुत्र, १२, १३ आदमी के परिवार का आदमी। पिता श्री सुभग राय, गाँव तथा पो० सिमरी, जिला० शाहाबाद।

८ *श्री सीताराम पांडे:*—२१ वर्ष का नौजवान, मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त, गरीबों का हितैषी, ४२ के आन्दोलन में भरपूर भाग लेते हुये सार्वजनिक सेवा में दिलचस्पी, काँग्रेस तथा किसान सभा आन्दोलन का पुजारी। साधारण किसान। पतले, गोरे, तेज, सादगी का आदर्श। पिता श्री दीपन पांडे, गाँव तथा पो० सिमरी, जि० शाहाबाद।

९ *श्री शिवनाथ प्रसाद सिन्हा:*—२८ वर्ष का नौजवान, मेट्रिकुलेशन तक की शिक्षा प्राप्त, सार्वजनिक मनोवृत्ति का, तेज, कद लम्बा-गोरा, १९२८ से ही सार्वजनिक कामों का प्रेमी। ४० में डुमराँव में जंगल आन्दोलन में भाग लेता हुआ जभी पुकार हुई गरीबों की सेवा के लिए तत्पर। पिता श्री गोकुललाल, गाँव तथा पो० सिमरी, जि० शाहाबाद।

१० *श्री उदय प्रकाश मिश्र:*— ६८ वर्ष का वृद्ध, बाल सफेद, नाटे कद का गोरा शरीर, सुदृढ़, पिता का बड़ा पुत्र, एक अच्छा किसान, सार्वजनिक सेवा का प्रेमी, गरीबों का हितैषी, १९२१ से ही कांग्रेस तथा किसान सभा से प्रेम, समय-समय पर देश की पुकार पर सब प्रकार तैयार, जब भी कांग्रेस का आन्दोलन हुआ, उसे पूरा करने में सचेष्ट, २१, ३०, तथा ४२ के आन्दोलन में पूर्ण भाग लेने वाला। पिता श्री रामसुमेर मिश्र, गांव सोनवरसा, पो० उपाध्यापुर, जि० शाहाबाद।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

११ *श्री राम एकबाल तिवारी*:— २६ वर्ष की उम्र का नौजवान सार्वजनिक सेवा की मनोवृत्तिका, कद लम्बा, गोरे रंग का, पतला स्वस्थ शरीर,४० के डुमरांव के जंगल आन्दोलन का पक्का स्वयंसेवक ४२ के आंदोलन का पुजारी, माता का अकेला प्रिय पुत्र, एक अच्छा किसान। देश की पुकार पर सब प्रकार तैयार। १० वें क्लास तक की शिक्षा प्राप्त। पिता श्री राम सुभग तिवारी, गांव नेनुआ, पो० डुमरांव, जि० शाहाबाद।

१२ *श्री डोमन मिश्र*:— ६५ वर्ष की उम्र का, पिता का तीसरा पुत्र, एक साधारण किसान, गोरे लम्बे कद का, सुपुष्ट शरीर, शिक्षा स्कूली कुछ नहीं; किंतु प्रौढ़ होने पर अपने स्वाध्याय के बल से अपने काम भर पढ़ लिख लेने भर हिन्दी का आना, देश की सेवा की अपूर्व लग्न। बराबर गरीबों की सेवा में तत्पर। पहले जहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं था वहां हाई स्कूल की स्थापना में पूर्ण योग। चपरासी की जगह पर सर्विस में रहने पर भी कांग्रेस की पुकार पर सर्विस की पर्वाह न कर नौकरी से हटा। तीन बार का जेल यात्री दो बार सार्वजनिक सेवा के काम से और एक बार हैदराबाद में आर्य्य समाजियों के सत्याग्रह में। नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्कम राज्य आदि की यात्रा किया हुआ। मानसरोवर का स्नान, कैलाश का प्रदक्षिण। बकवादी, एक साधारण किसान। पिता श्री कमला पति मिश्र, गांव भरौली, पो० भरौली, जि० शाहाबाद।

१३ *श्री सन्त प्रकाश शर्मा*:— ४२ वर्ष की उम्र का पिता का बड़ा पुत्र, धार्मिक मनोवृत्ति का, साधारण अच्छा किसान, करीब १२ वर्षों से किसान सेवा कार्य्य में। साधारण हिन्दी लिखने पढ़ने का ज्ञान। गोरा, कद लम्बा, बदन ढीला, शांत प्रकृति का, सदैव सार्वजनिक सेवा का प्रेमी। पिता श्री हितलाल शर्म्मा, गांव सिनुआरी, पो० हसुआ, जि० गया।

१४ *श्री रामगोविन्द मिश्र*:— ५० वर्ष की उम्र का पिता का अकेला पुत्र। साधारण अच्छा किसान। संस्कृत की मध्यमा शिक्षा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राप्त, जब कभी देश की पुकार हुई सामने आया, ४२ के आन्दोलन में यथायोग्य सेवा की। सहायता की उत्कट इच्छा, लम्बा, गोरा, सात्विक प्रकृति का, दीनों की सेवा की श्रद्धा। पिता श्री राजपति मिश्र, गांव रुद्रनगर, पो० शाहपुर, जि० शाहाबाद।

१५ *श्री राघव दूबेः*— ३२ वर्ष की उम्र का, पिता का प्रथम पुत्र, लम्बे कद का, गोरा, तेज, ३० ई० से ही सार्वजनिक सेवा का पुजारी, साधारण अच्छा किसान। ४२ के आन्दोलन का जेल यात्री, ३० में पिकेटिंग का जेल यात्री, १९३२ में कपड़े की दूकान की पिकेटिंग में जेल यात्रा किया हुआ। अपर क्लास तक की शिक्षा प्राप्त। ४० में डुमरांव में जंगल सत्याग्रही। अर्थात् जब-जब पुकार हुई सब प्रकार तैयार। पिता श्री मेघवर्ण दूबे, गांव ढकाइच, पो० डुमरांव, जि० शाहाबाद।

१६ *श्री रामजीवन सिंहः*— २५ वर्ष का नौजवान, सेवा के लग्न से डूबा हुआ। शिक्षा की प्रवृत्ति से रहित, राष्ट्र के लिए सब तरह के बलिदान करने को तैयार, ३० के ही आन्दोलन से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में लगा हुआ। जेल के कठिन अनुभव से पूर्ण। मां-बाप का प्यारा एकलौता पुत्र, कई बार के जेल के अनुभव से पूर्ण, किसान की सेवा की पूर्ण लग्न। संसार यात्रा का कड़ा अनुभव प्राप्त, कद लम्बा, रंग श्यामला, बोलने की कला में प्रवीण। क्रान्तिकारी अनुभववाला। पहले का कम्युनिष्ट–पार्टी का अनुभव प्राप्त। पिता श्री मानकी सिंह, गांव रतनपुर, पो० बेगूसराय (मुंगेर)।

१७ *श्री शिववालक सिंहः*— २० वर्ष का नौजवान, कद लम्बा, रंग गोरा, वदन सुदृढ़, पिता की एकलौता संतान। आज तक विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी रहते हुये दुखियों की सेवा की लग्न। विद्यार्थियों के संगठन का अनुभव प्राप्त। ४२ के आन्दोलन में सक्रिय भाग के अनुभव से पूर्ण। साधारण गृहस्थ। जभी कांग्रेस की पुकार हुई, भाग लेने में पीछे नहीं। तेज विचार का। ४२

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

के जेल में २ महीने जेल-जीवन का अनुभव। ग्राम सेवक। पिता श्री बाबूजन सिंह, गांव रतनपुर, पो० बेगूसराय (मुंगेर)।

१८ *श्री जयनन्दन मिश्रः—* २० वर्ष का नौजवान, पिता की अंतिम संतान, गोरा बदन, सुदृढ़ शरीर, चेहरे पर चेचक का गहरा दाग। शिक्षण कार्य्य, मिडूल ट्रेनिङ्ग पास, सार्वजनिक सेवा की प्रवृत्ति, ४२ के आन्दोलन में भाग लिया हुआ, शांत विचार, कम्युनिष्ट पार्टी का अनुभव प्राप्त, किसान सभा के आगे बढ़ाने के लग्न से ओत-प्रोत। पिता श्री भद्रदेव मिश्र, गांव नागदह, पो० बेगूसराय (मुंगेर)।

१९ *श्री प्रसाद वर्माः—* ३० वर्ष का नौजवान, साधारण कद का, साँवले रंग का किसान, विगत ३० से सार्वजनिक सेवा का अनुभव प्राप्त, सत्याग्रह के सिलसिले में ६ बार और २ बार किसान सत्याग्रह के सिलसिले में जेल अनुभव वाला, साधारण हिन्दी पढ़-लिख लेने की योग्यता। पिता का छोटा और प्यारा पुत्र। एकदम छोटा किसान। नेयामतपुर आश्रम का जीवन व्यतीत करने वाला। स्वभाव से तेज। पिता श्री लक्ष्मण वर्मा, गांव कोहरा, हालमुकाम नेआमतपुर आश्रम, पो० बेलागंज जि० गया।

२० *श्रीरामबालक शर्माः—*४२ वर्ष की उम्र का नौजवान, लम्बे कद का, गोरे रंग का, पिता की सबसे बड़ी संतान। एक अच्छा किसान, १७ वर्षों के सार्वजनिक सेवा का अनुभवी, कांग्रेस तथा किसान सभा के कार्य्य के सिलसिले में ५ बार के जेल-जीवन के अनुभव से ओतप्रोत। सेवा की भावना से पूर्ण। मिडूल तक की शिक्षा प्राप्त। इसके अलावे हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की विशारद परीक्षा पास। किसान सेवा में पूर्ण सहानुभूति। पिता श्री लक्ष्मी शर्मा, गांव सतारपुर, पो० सरता, जि० गया।

२१ *श्री हरद्वार सिंहः—* ३२ वर्ष का नौजवान, पिता की सबसे बड़ी संतान, सेवा की लग्न में डूबा हुआ। अनुशासन प्रिय, सांवले रंग का, सुदृढ़, लम्बा, चौड़ा जवान। एक साधारण किसान। सेवा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के सिलसिले में १२ बार के जेल जीवन का अनुभव प्राप्त, सैनिक की उच्च शिक्षा प्राप्त। हिन्दी पढ़ने-लिखने का साधारण ज्ञान। पिता श्री बाबूराम सिंह, गांव तथा पोस्ट सरता, जि० गया।

२२ *श्रीमती विद्या देवी:—* १५ वर्ष की लड़की, अपनी मां की पांचवी संतान, एक अच्छे किसान घरकी, गोरी, कद में लम्बी। एक वर्ष से सेवा की भावना में पूर्ण। एक वर्ष पहले शर्मा जी श्री पं० यदुनन्दन शर्मा का गांव में किसानों की सहायता में आना। उनके उपदेश से सेवा का भाव जागृत होना। घर के लोगों में इस भावना से दुख, ससुराल के लोगों का भी विरोध। बच्चा सेवा की भावना से पूर्ण है और भविष्य में विरोध के होते हुए भी विचार की पूर्णता ही रहने की भावना। रोपने के समय खेत सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेना तथा सफलता पाना। विरोध में घर के कुछ ही लोगों का हाथ, स्वभाव से चंचला। साम्प्रदायिक दंगे की शांति में सहयोग। पिता श्री दृगपाल शर्मा, गांव सिनुआरी, पो० हसुवा, जि० गया।

२३ *श्रीमती सुन्दरी देवी:—* २५ की उम्र की, लम्बे कद की, गोरी, अपनी मां की बड़ी संतान। साधारण किसान की संतान। एक वर्ष से स्वयं-सेविका का कार्य करने वाली। शिक्षा से बंचित। श्री पं०यदु-नन्दन शर्म्मा के व्याख्यान से हृदय में सेवा की भावना का जागृत होना। किसानों के जमीन के सत्याग्रह में भाग लेने वाली। घर के कुछ लोगों का इस भावना से विरोध। ससुराल के लोगों को इस भावना से सहानुभूति नहीं है। विरोध की दशा में भी सेवा की भावना कायम रहेगी। शांत, गंभीर, साम्प्रदायिक दंगे की शांति में सहयोग। पिता श्री गोपाल सिंह, गौंव सिनुआरी, पो० हसुवा, जि० गया।

२४ *श्रीमती शांति देवी:—* लगभग २५ वर्ष की श्यामली, लंबी कद की, मां की सबसे छोटी संतान में से, साधारण किसान के घर की, लगभग एक वर्ष से सेवा की भावना, शर्म्मा जी की जागृति

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

दिलाने के फलस्वरूप वस्ती के किसान सत्याग्रह में भाग लेने वाले नैहर के कुछ लोग विचार से विरोध करते हैं; किन्तु स्वसुराल के आधुनिक विचार वाले का कोई विरोध नहीं। सम्प्रदायिक दंगे शांति में पूर्ण सहयोग। लोअर तक की शिक्षा प्राप्त, चंचला। पि श्री द्वारिका प्रसाद शर्म्मा, गांव सिनुआरी, पो० हसुआ, जि० गया

२५ *श्रीमती रुक्मिणी देवी:*— १६ वर्ष की उम्र की; गोरी, कद की, अपनी मां की दूसरी संतान, सेवा की भावना में नै तथा ससुराल के लोगों की पूर्ण सहानुभूति। एक वर्ष से ही से वृत्ति का पैदा होना। उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि। यह भावना जीवन बनी रहेगी। चंचला, हिन्दी पढ़ना-लिखना साधारण, साम्प्रदा दंगे की शांति में सहयोग। पिता श्री रामेश्वर शर्मा, सिनुआरी, पो० हसुआ, गया।

२६ *श्रीमती श्री देवी:*—१७ वर्ष की उम्र की अपने मां की दू संतान। अच्छे किसान के घर की। गोरी, लम्बे कद की, शि से बंचित, सेवा की भावना से पूर्ण, एक वर्ष से सेवा का अनु सेवा की भावना में नैहर तथा स्वसुराल के लोगों का विरोध न अपनी बस्ती में किसान सत्याग्रह में भाग लेने वाली। स्वभाव चंचला। पिता श्री ब्रह्मी शर्म्मा, गांव सिनुआरी।

२७ *श्री कुमारी मोती देवी:*—१२ वर्ष की उम्र की, गोरी, कद की, मां की दूसरी संतान, अच्छे किसान के घर की। हिन्दी सुन्दर ज्ञान। सेवा की भावना की पूर्णता। यह शर्म्मा जी की शि का फल। सेवा की भावना से घर के लोगों की सहानुभू सेवाका विचार और बढ़ेगा। स्वभाव की चंचला, साम्प्रदायिक की शांति में पूर्ण सहयोग। पिता श्री प्रकाश शर्मा, गांव सिनुआ

२८ *श्रीमती सोनमती देवी:*—११ वर्ष की उम्र की, माँ की दू संतान। साधारण अच्छे किसान के घर की, गोरी, लम्बी, स्व से चंचला, सेवा की भावना से पूर्ण, दिनों दिन सेवा के भावना विचार में वृद्धि की संभावना। इस विचार में घर के लोगों का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सहयोग । गाँव के किसान सत्याग्रह की सहयोगिनी । सेवाकी भावना का श्रेय पंडित यदुनन्दन शर्मा को । साम्प्रदायिक दंगे की शांति में पूर्ण सहयोग । पिता श्री भागीरथ शर्मा, गाँव सिनुआरी ।

२९ *श्रीमती कमला देवी:*–४० वर्ष के उम्र की, श्यामली, नाटे कदकी, स्वभाव से चंचला, सेवा की भावना से पूर्ण, सेवा की भावना का श्रेय शर्माजी को । एक वर्ष से सेवा के कार्य्य में संलग्न, सेवा भावना में लोगों का भी पूर्ण सहयोग । सेवा का विचार कायम रखने का दृढ़ निश्चय । हिन्दू मुसलमान दंगे की शांति में पूर्ण प्रयत्नशील । पिता श्री माधव शर्मा, गाँव सिनुआरी ।

३० *श्रीभागवत शर्मा:*–३५ वर्ष के नौजवान, पिता के दूसरे पुत्र, तेजस्वीभाव के । अच्छे किसान । गोरे, नाटे कदके, बदन से सुदृढ़, मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास । विगत तीन वर्षों से सेवा की भावना से पूर्ण । सेनुआरी सत्याग्रह संचालन में प्रधान । यह सेवा की भावना उत्तरोत्तर उन्नत होने की संभावना । हिन्दू मुसलमान दंगे में स्वयं सेविकाओं के साथ शांति कायम करने में पूर्ण योग । सेवा की उत्कट भावना, क्लर्क के पोष्ट से हटकर सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पहुँचने की उत्कट भावना । पिता श्री भमो शर्मा, गाँव नारायणपुर, पो० हसुआ, जि० गया ।

३१ *श्रीकिसुनदीन शर्मा:*–२० वर्ष का नौजवान, रंग श्यामला, दुबला पतला, बचपन में ही माता-पिता के सुख से वंचित, अभी विद्यार्थी जीवन, मैट्रिकुलेशन क्लास का अध्ययन, पढ़ने में गार्जियन की सहायता से वंचित, सार्वजनिक सेवा की उत्कट इच्छा, किसान सत्याग्रह में भाग लिया हुआ, साधारण अच्छा गृहस्थ । विगत एक वर्ष से किसान आन्दोलन का सहयोगी । शेष जीवन किसान सभा के लिये अर्पण । पिता श्री बलदेव शर्मा, गांव सिनुआरी ।

३२ *श्री रामधारी शर्मा:*–४२ वर्ष का नौजवान, लम्बा, पतला, गोरे शरीर का, पिता की अकेली संतान, साधारण अच्छे किसान, किसान सेवा की भावना । २८ से ही सार्वजनिक सेवा की वृत्ति । बली

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

रोकने के सत्याग्रह में भाग लेकर जेल गया हुआ। ४२ के आंदोल का सहयोगी। किसानों का हित चिंतक। किसान सत्याग्रह व प्रेमी। ग्राम पंचायत का पोषक, बोलने में कुशल। पिता श्री नन्दकुमार शर्मा, गाँव भतसेनी, पो० तुंगी, जि० गया।

३३ श्री चन्द्रेश्वर शर्मा:–१२ वर्ष का लड़का, ६ ठे क्लास तक की शिक्षा प्राप्त, रंग गोरा, बदन सुदृढ़, पिता की सब से बड़ी संतान, साधारण किसान का लड़का,माता-पिता का प्यारा,एक वर्ष से किसान स्वयं सेवक का काम करने का अनुभव प्राप्त, सेवा की उत्कट इच्छा। शर्मा जी के व्याख्यान के फल स्वरूप सेवा की लग्न। घरके लोगों का सहयोग प्राप्त। बीमारी के कारण शिक्षा का स्थगन, अध्ययन की भी इच्छा रखनेवाला। अगले वर्ष एडमीशन लेने की इच्छा। पिता श्री भागीरथ शर्मा, गाँव सिनुआरी।

३४ *श्री कैलाश शर्मा:*—२८ वर्ष के नौजवान, गोरे रंग का, लम्बा, अपर तक की शिक्षा प्राप्त, पिता का सबसे बड़ा पुत्र, गत एक वर्ष से सेवा की भावना, पहले भी सभा के काम की इच्छा, सेवा की भावना का श्रेय शर्मांजी को। अच्छे किसान की श्रेणी में। किसान सभा के कार्य्य की भावना भविष्य में भी। साधारण हिन्दी पढ़ लिख लेने का ज्ञान। चंचल प्रवृत्ति का। हिन्दू-मुसलमान दंगे की शांति में सहयोग। पिता श्री रासधारी शर्मा, गाँव सिनुआरी।

३५ *श्री यमुना शर्मा:*—१७ वर्ष की उम्र के नौजवान। कद में साधारण, बदन सुदृढ़। पिता के तृतीय पुत्र, विद्यार्थी जीवन, मैट्रिकुलेशन क्लास का अध्ययन। चार-पाँच वर्षों से सेवा की भावना। भविष्य में सेवा की उत्कट इच्छा। सेवा की भावना का श्रेय श्री स्वामीजी तथा शर्मा जी को है। घरके लोगों की ओर से भी सेवा भावना अनुमोदित। हिन्दू मुसलमान दंगा की शांति में पूर्ण सहयोग। पिता श्री हगपाल शर्मा, गांव सिनुआरी।

३६ *श्री राम बिलास शर्मा:*—२३ वर्ष का नौजवान। शरीर से सुपुष्ट और सुदृढ़, गोरे रंग का, साधारण ऊँचाई का। पिता का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तृतीय पुत्र, साधारण अच्छा किसान, ४ वर्षों से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, मिडूल तक की शिक्षा प्राप्त, स्वामी जी तथा शर्माजी के व्याख्यान से, सेवा की भावना उत्पन्न, किसान सत्याग्रह तथा हिन्दू मुसलमान दंगे की शांति में सहयोग, सेवा की भावना में उतरोत्तर जागृति। पिता श्री हारो शर्मा, गाँव सिनुआरी।

६७ *श्री शिवनन्दन प्रसाद शर्मा:*—१६ वर्ष का नौजवान, पिता का चौथा पुत्र, गोरा, लम्बा, चेहरे पर चेचक का गहरा दाग। छोटा किसान। विगत ५. ६ वर्षों से सेवा की भावना। ४२ के आन्दोलन में भाग लिया हुआ। किसान-सत्याग्रह का सहयोगी, बस्ती के कुछ लोगों में सेवा की भावना से इसमें भी जागृति। भविष्य में सेवा कार्य्य में वृद्धि। घरवाले सेवा के विचार में बाधक। पिता श्री मुसाफिर शर्मा, गाँव सिनुआरी।

३८ *श्री नारायण शर्मा:*—१२ वर्ष की उम्र का लड़का, रंग गोरा, लम्बा, पिता का पांचवां पुत्र। ३रे क्लास तक की शिक्षा प्राप्त। गत वर्ष से सेवा की भावना में जागृति जिसका श्रेय शर्माजी को। किसान सत्याग्रह का अनुभव प्राप्त, हिन्दू-मुसलमान दंगे में शांति कार्य्य में योग। घर के कुछ लोग सेवा कार्य्य से खुश और कुछ को रंजिश। पिताजी का सहयोग है। भविष्य में सेवा की भावना में वृद्धि। पिता श्री काशी शर्मा, गाँव सिनुआरी।

३६ *श्री ब्रह्मदेव शर्मा:*—४१ वर्ष की उम्र के जवान, पतले, लम्बे कद के, गोरे रंग के। छोटे किसान की श्रेणी में। पिता की चौथी संतान, हिन्दी-पढ़ने लिखने का ज्ञान। सदा से सार्वजनिक सेवा की भावना और यह सेवा भावना वंश परम्परागत। १६२१ से ही सेवा के क्षेत्र में। ४ बार के जेल जीवन का कटु अनुभव। किसान सत्याग्रह के सहयोगी। साम्प्रदायिक झगड़े की शांति में प्रथम भाग। १६४२ के आन्दोलन में भाग लिये हुये। सेवा की भावना अंतिम समय तक कायम रहने का विश्वास। पिता श्री रघुवीर शर्मा, गाँव दौलतपुरा, पो० हसुवा, जि० गया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

४० श्री *दृगपाल शर्मा*:—४६ वर्ष की उम्र के, पिता की एक ही संतान हिन्दी और उर्दू का ज्ञान। एक अच्छे किसान। गत एक वर्ष से किसान सेवा कार्य्य में। किसान सत्याग्रह के सहयोगी। अपने बस्ती के किसान सत्याग्रह के साथी। शेष समय सेवा की भावना से पूर्ण। घर के अन्य लोगों का भी सहयोग। पिता श्री जानकी शर्मा, गाँव सिनुआरी।

४१ श्री *हरिश्चन्द्र ठाकुर*:—२३ वर्ष की उम्र के, लम्बे कद के गोरे, बदन गठीला, सुदृढ़, पिता के प्रथम पुत्र, छोटे किसान, हिन्दी पढ़ने-लिखने का अच्छा ज्ञान। बदन से मजबूत, बोलने में कुशल तेज, ४२ के अन्दोलन में भाग लिये हुये। जेल का कटु अनुभव। सेवा की लग्न। भविष्य में सेवा-भाव में उन्नति। संगीत के प्रेमी। पिता श्री कुशेश्वर ठाकुर, गाँव कर्णपुर, पो० झंझारपुर जि० दरभंगा।

४२ श्री *वीरेन्द्र कुमार सिंह*:—२० वर्ष की उम्र के नौजवान श्यामले, लम्बे, बदन गठीला, सुदृढ़, पिता के चौथे पुत्र, एलेवन क्लास तक की शिक्षा प्राप्त, सेवा की ऊँची इच्छा, १९४२ के आन्दोलन से सार्वजनिक क्षेत्र में। संगीत का अच्छा ज्ञान, एक सुन्दर चित्रकार। पहले घर के लोगों की सहानुभूति से वंचित, किन्तु आजकल विरोध का अभाव। ४२ के आन्दोलन में एक सप्ताह का जेल-अनुभव, किसान आन्दोलन से पूर्ण सहानुभूति। भविष्य में सेवा के भाव में उन्नति की आशा। पिता श्री सुन्दर सिंह गांव तेजउल, पो० कटरा, जि० मुजफ्फरपुर।

४३ श्री *ब्रजबिहारी मिश्र*:—३५ वर्ष की उम्र के नौजवान। श्याम रंग के, नाटे कद के, पिता के सब से छोटे पुत्र, संस्कृत के प्रथमा तथा अंगरेजी के दसवें क्लास तक की शिक्षा। परिवार के सभी भाई सार्वजनिक सेवा के काम में। १९३७ से सार्वजनिक सेवा के काम में। सेवा के सिलसिले में उत्तरोत्तर वृद्धि की आशा। पिता श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, छपरा (मौना) छपरा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

४४ श्री भुवनेश्वर मिश्रः—२१ वर्ष के नौजवान, गोरे रंग के, नाटे कद के, संस्कृत की मध्यमा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा तक की शिक्षा। अपने पिता के तीसरे पुत्र। ४६ से किसान सभा का कार्य्य करते आ रहे हैं। घर के कुछ लोगों का सेवा कार्य्य में सहयोग। भविष्य में सेवा की भावना में वृद्धि की उमीद की जा सकती है। किसान-जमीन्दार संघर्ष में किसानों की सहायता किया करता है। एक छोटे किसान की श्रेणी के। पिता श्री रामसुदिष्ट मिश्र, गाँव पतौर, पो० आनन्दपुर, जि० दरभंगा।

४५ श्री रामचन्द्रझाः—२१ वर्ष के नौजवान। गोरा रंग, सुदृढ़ और गठीला बदन, नाटे कद के। मिड्ल क्लास तक की शिक्षा पाया हुआ। पिता का सब से बड़ा पुत्र, एक अच्छा किसान। सेवा के काम में घर के लोगों की सहानुभूति। इसी वर्ष से सेवा के क्षेत्र में आया हुआ। सेवा की भावना में वृद्धि की ही भावना। सारा समय सेवा में देनेवाला। दरभंगा के किसान संघर्ष में भाग लिया हुआ। पिता श्री हरिनन्दन झा, गाँव पौराम, पो० हयाघाट, जि० दरभंगा।

४६ श्री वासुदेव चौधरीः—५५ वर्ष के वृद्ध, गोरे रंग के, नाटे, शरीर सुदृढ़, पिता के बड़े पुत्र, मि० ट्रे० तक की शिक्षा, अच्छे किसान के श्रेणी के, किसान सभा के आदिकाल से सेवा कार्य्य। १९४२ की क्रांति के सहयोगी। भविष्य में उतरोत्तर सेवा कार्य्य में वृद्धि ही की आशा। पिता श्री रामावतार चौधरी, गांव सुलतानगंज उर्फ ऊंचाकेतुका, पो० मकेर, जि० सारन।

४७ श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह :—२५ वर्ष के नौजवान, गोरे, लम्बे कद के, ८ वें क्लास तक की शिक्षा प्राप्त, अच्छे किसान की श्रेणी में, १९४४ से सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष रूप से। किन्तु पहले अर्थात् विद्यार्थी जीवन से ही सेवा कार्य्य में सहयोग, पिता के एक ही पुत्र। घर के लोगों का सेवा कार्य्य से सहयोग। गांव एकाढ़ा, पो० चवारा, जि० मुंगेर।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

४८ *श्री रामनन्दनशर्मा* :—२० वर्ष के नौजवान, गोरे, लम्बे क के, पिता के सब से छोटे पुत्र, साधारण अच्छे गृहस्थ, संस्कृत मध्यमा तथा मि० ई० परीक्षा पास। इसी वर्ष से सार्वजनिक के में। घर के लोगों की सेवा कार्य्य से सहानुभूति। पिता श्री रामदे सिंह, गांव बड़ा टेंगरैला, पो० रामबक्स जैंतीपुर (पटना)।

४९ *श्री शुकदेव प्रसाद शर्मा* :—२५ वर्ष के नौजवान, गोरे त लम्बे कद के, शरीर सुदृढ़, पिता के दूसरे पुत्र, अपर तक की शि प्राप्त, १९३२ से ही सार्वजनिक सेवा का अनुभव प्राप्त, सारा परिवा राष्ट्रीय विचार वाला, साधारण अच्छा किसान। ३२ में ताड़ी दूकान पर धरना में गिरफ्तार, किन्तु उम्र में कमी के कारण छूटा ३८ में चीनी मिल मजदूर हरिनगर की हड़ताल में ५ बार गिरफ्ता कई बार बेंत की सजा, आखिरी बार तीन महीने की सजा, ४० समझौते के पुतले जलाने में ६ महीने की सजा प्राप्त। ४१ प्रोसेशन निकालने के अभियोग में ५० रु० जुर्माना नहीं देने डेढ़ महीने की सजा। ४२ आंदोलन का भी अनुभव प्राप्त। आपत्ति जनक सामान रखने के अभियोग में मुकदमा, १ वर्ष सजा, १०० जुर्माना नहीं देने पर ६ महीने की और सजा। पिताजी को १ व सजा, ५०) जुर्माना। अपील से १ महीना। पुनः अपील से रिहा। पि जी इसके पूर्व भी जेल गये। पिता श्री परीक्षण सिंह, गाव जसौ पो० भोपतपुर, जि० चम्पारन।

५० *श्री चमारी सिंह* :—३५ वर्ष की उम्र के नौजवान। गो नाटे कद के, शिक्षा से वंचित एक छोटे किसान। बीसों वर्ष सेवा कार्य्य का अनुभव प्राप्त। नमक बनाने, विदेशी कपड़े पिकेटिंग तथा किसान सत्याग्रह के सिलसिले में २ बार के जे अनुभव प्राप्त। ग्राम संगठन के कार्य्य से सहानुभूति। पिता श्री गौ सिंह, गांव सहवाजपुर, पो० रसलपुरा, जिला गया।

५१ *श्री रामलखन शर्मा* :— २६ वर्ष के नौजवान। श्यामले के, लम्बे कद के। हिन्दी पढ़ने लिखने की साधारण शिक्षा। एक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

छोटे किसान। पिता के दूसरे पुत्र। लगभग १० वर्षों से सार्वजनिक काम का अनुभव। विहटा मिल हड़ताल के सिलसिले का जेल यात्री। १९४२ के आंदोलन का अनुभव प्राप्त। जभी पुकार हुई सहयोगी बना। पिता श्रीकृष्ण कुमार सिंह, गांव कटारी, पो० बिक्रम, जि० पटना।

५२ *श्री अम्बिका राय* :—२२ वर्ष की उम्र के नौजवान। बदन गठीला, सुदृढ़, श्यामले रंग के, लम्बे कद के, मैट्रिकुलेशन शिक्षा प्राप्त, बहुत अच्छे किसान, पिता के अकेले पुत्र। घर के कुछ लोगों का सेवा कार्य्य से विरोध। विद्यार्थी-जीवन से ही सेवा की भावना। दो-तीन वर्षों से सेवा में विशेष सहानुभूति। पिता श्री रामावतार राय, गांव नाट, पो० उपाध्यापुर, जि० शाहाबाद।

५३ *श्री रामपाल शर्मा*:—५० वर्ष की उम्र, बदन सुदृढ़, लम्बे कद के, गोरे, संस्कृत की मध्यमा परीक्षा पास, सेवा की भावना से पूर्ण, आर्य्य-समाजी विचार धारा, एक साधारण किसान, पिता के अकेले पुत्र, तीन चचेरे भाई के साथ, किसान सभा के कार्य्य से पूर्ण सहानुभूति। पिता श्री योधा शर्म्मा, गांव अस्ता, पो० चंडी, जि० पटना।

५४ *श्री शिवदत्त शर्म्मा*:—३२ वर्ष का नौजवान। गोरे रंग का, साधारण कद का, बदन सुदृढ़, बड़े किसान घर का, पिता का तीसरा पुत्र। हिन्दी पढ़ने-लिखने का बढ़िया ज्ञान, अंगरेजी का साधारण। १२ वर्षों से सार्वजनिक सेवा का अनुभव प्राप्त। विद्यार्थी काल से ही सेवा की भावना। समय समय पर ग्रामीणों की सेवा बीमारी आदि की दशा में, जिससे अपने ग्राम के लोगों का पूर्ण सहयोग सेवा में। किसानों का संगठन कर मरी हुई नदी महाने को सरकार की सहायता से खुदवाना। अस्पताल, स्कूल बनवाकर सहायता दी। किसान सभा से पूर्ण सहानुभूति, बकास्त की लड़ाई बहुत सी लड़ी और सफल हुआ। पिता श्री तिलकधारी शर्म्मा, गांव सोनचरी, पो० परबलपुर, जिला पटना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

५५ *श्री जगेश्वर प्रसाद यादव:*—३२ वर्ष की उम्र के नौजवान श्यामले रंग के, साधारण कद के, मिड्ल तक की शिक्षा प्राप्त, पिता के बड़े पुत्र, जमींदारों से परिताड़ित, एक सुखी किसान। १२ वर्षों से सार्वजनिक सेवा का अनुभव। बकास्त की लड़ाई के सहयोगी। संगठन कार्य्य में दक्ष। १९४२ आंदोलन के जेल यात्री। पिता श्री रामकेश्वर यादव, गांव जानकी बिगहा, पो० एकंगरसराय जि० पटना।

५६ *श्री सीताराम सिंह:*—२१ वर्ष की उम्र का नौजवान। श्यामला नाटे कद का, मिड्ल तक की शिक्षा प्राप्त, पिता का बड़ा पुत्र, २ वर्ष से सार्वजनिक सेवा का अनुभव प्राप्त, किसान सभा के काम में विशेष सहानुभूति। परिवार के अन्य लोगों की पूर्ण सहानुभूति पंचायती से बस्ती की जमीन किसान को दिलवाया। पिता श्री देव नारायण सिंह, गांव खड़ी लोदीपुर, पो० कोसियावां, जि० पटना।

५७ *श्री भागीरथ शर्मा*:—२५ वर्ष की उम्र के नौजवान। गोरे गठीले बदन के, शरीर सुदृढ़। पिता के एक ही पुत्र, हिन्दी पढ़ने लिखने का अच्छा ज्ञान। साधारण अच्छे किसान, ६ वर्ष से सार्वजनिक सेवा के काम का अनुभव। किसान सेवा में विशेष सहानुभूति, हेरथु के बकास्त आंदोलन में सफल लड़ाई लड़नेवाला घर के लोगों से सहानुभति पाया हुआ। पिता श्री मथुरा सिंह, गांव परशुराय, पो० खुदागंज, जि० पटना।

५८ *श्री रामनाथ शर्मा:*—१८ वर्ष की उम्र के नौजवान, गोरे लम्बे कद के, पिता के छोटे पुत्र, अच्छे किसान के श्रेणी के, मिड्ल तक की शिक्षा प्राप्त, ४३ से सार्वजनिक सेवा के काम में। नाजायज धान वसूली में जेल यात्री। घर के लोगों की भी सहानुभूति। पिता श्री बलदेव शर्मा, गाँव बेला, पो० रामबक्स जैंतीपुर, जि० पटना।

५९ *श्री जगदीश शर्मा:*—२५ वर्ष के नवजवान, गोरे, पतले, लम्बे कद के, मिड्ल तक की शिक्षा प्राप्त, संस्कृत का भी थोड़ा ज्ञान, साधारण किसान। पिता के तीसरे पुत्र, ३५ से ही सार्वजनिक सेवा

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

क्षेत्र में, घर के लोगों का इस कार्य्य में पूर्ण सहानुभूति। धान की नाजायज वसूली का अनशन कर्त्ता। पिता श्री फौजदार शर्मा, गाँव छोटाटेंगरैला, पो० जैंतीपुर, जि० पटना।

६० *श्री अनूप सिंह यादव:*—१६ वर्ष की उम्र का जवान। श्यामला रंग तथा नाटा कद, पिता का बड़ा पुत्र, घरके लोगों की इस काम से अनिच्छा। २ वर्षों से सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में। सिनामा के किसान आंदोलनका सहयोगी। मिडूल पास, साधारण किसान। पिता श्री महावीर सिंह यादव, गाँव रेंहड़ापर, पो० परवलपुर, जि० पटना।

६१ *श्री विश्वनाथ राय:*—२४ वर्ष की उम्र का नौजवान। गोरा, नाटा, पतला, मैट्रिकुलेशन की शिक्षा प्राप्त, साधारण अच्छा किसान। स्कूली जीवन की दशा से ही सार्वजनिक सेवा से सहानुभूति। ४२ के आंदोलन का कटु अनुभव। घर के कुछ लोगों को सेवा कार्य्य से असंतोष तथा कुछ लोगों की सहानुभूति। भविष्य में सेवा की भावना में वृद्धि की आशा। पिता श्री रामसुन्दर राय, गाँव दुरासन, पो० डुमरी, जि० शाहाबाद।

६२:—*श्री फागूराय*, पिता श्री दीपन राय, मु० अभ्युदय प्रेस, बक्सर (शाहाबाद)

६३:—*श्री रामेश्वर राय*। पिता श्री राधा राय, गाँव जलालपुर, पो० धनसोई (शाहाबाद)

६४:—*श्री जगदम सिंह*, पिता श्री ब्रह्मदत्त सिंह, गाँव चाँदपाली, पो० मंझवारी, (शाहाबाद)

६५:—*श्री महेश्वरी शर्मा*, पिता श्री ब्रह्मदेव शर्मा, गाँव सिनुआरी, जि० गया।

६६:—*श्री सुखनंदन शर्मा*, पिता श्री तपेश्वर शर्मा, गाँव वेलौरा, पो० पालीगंज, जि० पटना।

६७:—*श्री शिवशंकर भारती*। ३०—३५ वर्ष के काले बाबा, किसान संघर्ष और कांग्रेस के लिए बहुत बार जेल गए। मौजी, स्वतंत्र-जीव। काफी समझदार, पढ़े-लिखे, गर्म वक्ता, जवान बेलगाम।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

६८:—श्री *अलखदेव सिंह*, पिता श्री सामरथ सिंह, गाँव मसौढ़ा
० राजीपुर (पटना)

६९:—श्री *शिवगोन्द मिश्र*, पिता श्री मेघनाथ मिश्र, गाँव उधुरा
पो० निमेज (शाहाबाद)

७० श्री *पं० खड्गधारी मिश्र*—५० वर्ष की उम्र् के, नाटे कद के श्यामला रंग, वदन सुदृढ़, लग्न के पक्के। एक साधारण अच्छे किसान पिता के सबसे बड़े पुत्र। संस्कृत के आचार्य प्रथम खण्ड। जीवन के पिछले दस वर्ष भगवद् भजन में, २ वर्ष गोसेवा। पश्चात् ३२ से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जिसमें मुख्य किसान की सेवा, किसान सभा से पूर्ण सहानुभूति। दो बार के जेल जीवन का कटु अनुभव। वकास्त संघर्ष में माली महाल में सफल प्रयत्न। इसके अलावे किसान सत्याग्रह का पूर्ण अनुभव। सम्पूर्ण समय किसान हित में। भविष्य में सेवा भावना में वृद्धि की ही आशा। पिता श्री राजकुमार मिश्र, गाँव बघोई, पो० दाऊद नगर, जि० गया।

७१ श्री *ब्रह्मदेव शर्मा*:—३२ वर्ष के नौजवान, रंग श्यामला, नाटे शरीर सुदृढ़। पिता का बड़ा पुत्र। साधारण किसान, हिन्दी पढ़ने लिखने का साधारण ज्ञान, किसान सभा में विशेष भक्ति। सिंदुआरी किसान सत्याग्रह का कटु अनुभव, वर्त्तमान समय में आश्रम का जीवन। इसके पूर्व नवादा आश्रम का जीवन, घर के लोगों का सेवा कार्य्य में विरोध। स्वाभाविक त्याग की भावना। सारा समय और सारी शक्ति किसान सभा के कार्य में अर्पण। पिता श्री जुल्म सिंह, गाँव ओरैना, पो० ओढ़नपुर जि० गया।

७२ श्री *नित्यानंद मिश्र*:—३५ वर्ष की उम्र् के, गोरे, नाटे कद के वदन पुष्ट, सुदृढ़, हिन्दी पढ़ने-लिखने का साधारण ज्ञान। साधारण अच्छे किसान। १९३० से सार्वजनिक सेवा का काम। किसान संगठन में खास विश्वास। ४२ के आंदोलन में गिरफ्तार। अरवल किसान सत्याग्रह के सहयोगी। पिता के दूसरे पुत्र। परिवार के

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लोगों का सहयोग सेवा कार्य्य में। ५ बार के जेल यात्री। पिता श्री गोपाल मिश्र, गाँव अरवल (रौजा) पो० अरवल, जि० गया।

७३ श्री *बालेश्वर सिंहः*—२४ वर्ष के नौजवान। गोरे, वदन सुदृढ़, लम्बे; हिन्दी पढ़ने-लिखने का साधारण ज्ञान। पिता का अकेला पुत्र। साधारण किसान। १० वर्ष से सार्वजनिक सेवा के काम में। अपने गाँव के किसान सत्याग्रह में भाग लिया हुआ। एक बार जेल का भी अनुभव। पिता श्री महावीर सिंह, गाँव रेवड़ा, पो० भट्टा, जि० गया।

७४ श्री *सुखदेव सिंहः*—२० वर्ष की अवस्था के जवान, श्यामले, वदन सुदृढ़, पिता के दूसरे पुत्र। एक साधारण किसान, ८ वर्ष से सार्वजनिक सेवा में। किसान आन्दोलन के हिमायती। किसान सत्याग्रह में भाग लिया। सेवावृत्ति धारण करने का श्रेय पं० यदुनन्दन शर्मा को है। घर के लोगों का भी सेवा कार्य में सहयोग। पिता श्री बेदूसिंह, गाँव रेवड़ा, पो० भट्टा, जिला गया।

७५ श्री *दयाल लालः*—३२ वर्ष के जवान। श्यामले, लम्बे, सुदृढ़ वदन के। पिता के दूसरे पुत्र, एक साधारण किसान। किसान आंदोलन के पोषक। किसान सत्याग्रह में भाग लिया। इस का श्रेय पं० यदुनंदन शर्मा को। घर के लोगों से सहयोग पाया भविष्य में सेवा भावना में जागृति की आशा। एकबार के जेल का अनुभव प्राप्त। पिता श्री प्रयाग लाल, गांव रेवड़ा, पो० भट्टा, जि० गया।

७६ श्री *गुरु सहाय महतोः*—१६ वर्ष के जवान। श्यामले, लम्बे कद के, वदन सुदृढ़। पिता के सबसे बड़े पुत्र। साधारण किसान, ८ वर्ष से सार्वजनिक सेवा में। सेवावृत्ति का श्रेय शर्मा जी को। सेवा की भावना में भविष्य में उन्नति होने की आशा। पिता श्री मंगर महतो, गाँव रेवड़ा, पो० भट्टा, जिला गया।

७७ श्री *झरी भगतः*—६० वर्ष की उम्र, बूढ़े, लम्बे, गोरे, साधारण किसान, शिक्षा से वंचित, इसी वर्ष से सेवा कार्य्य में। पिता श्री लोचन भगत, गाँव साबरचक, पो० सोरंगपुर, जिला पटना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

७८ श्री *मघेश्वर सिंहः*—२० वर्ष का जवान, रंग गोरा, लम्ब स्वभाव से तेज, मैट्रिकुलेशन परीक्षा दिया हुआ। पिता का सब छोटा पुत्र। ४२ के आंदोलन में जेल जीवन व्यतीत किया हुआ साधारण किसान। घरवाले का भी विचार सेवा के काम अच्छा। भविष्य में सेवा भावना में उन्नति की आशा। पिता लालजीत सिंह, गांव भतसेनी, पो० तुंगी, जि० गया।

७९ श्री *प्रभुनाथ सिंहः*—२१ वर्ष की उम्र के, श्यामले रंग बदन गठीला, सुदृढ़, पिता के दूसरे पुत्र, मैट्रिकुलेशन के विद्यार्थ गरीब किसान। पहले से सेवा की मनोवृत्ति, १९४६ के जून में सिनुआ किसान सत्याग्रह में भाग लिया। पिता श्री द्वारका सि गांव राजा बिगहा, पो० नरहट, जिला गया।

८० श्री *पं० प्रभुनारायण शास्त्रीः*—२५ वर्ष की उम्र के जवान गोरे, नाटे कद के, बदन सुदृढ़, गठीला, व्याकरण प्रथमा, आयुर्वे शास्त्री तक की शिक्षा प्राप्त, पिता के तृतीय पुत्र, अच्छे किसान १९३७ से ही सेवा कार्य्य का अनुभव प्राप्त। कई जगह के किसा सत्याग्रह का अनुभव प्राप्त, ४२ के आंदोलन में भाग लिया। हिन्दू मुसलमान दंगे के शांति कार्य्य में सहायक। पिता श्री रामसहा शर्मा, गाँव धिरौंध, पो० सिरदला, जि० गया।

८१ श्री *ब्रह्मदेव प्रसादः*—१३ वर्ष की उम्र का, गोरा, लम्बे क का, बदन सुदृढ़, अपर तक की शिक्षा प्राप्त, साधारण किसान, ए वर्ष से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। घर के लोगों से भी सहयोग पाय हुआ। पिता श्री दाहू महतो, गांव सलेमपुर, पो० रम्भेत, जि० गया।

८२ श्री *काली सिंहः*—१९ वर्ष का जवान, श्यामला, बद सुदृढ़, सुपुष्ट, शिक्षा से वंचित, पिता का एक ही पुत्र, छोटा किसान, किसान सेवा की लग्न इसी वर्ष से। इसका श्रेय शर्मा जी को। भविष्य में सेवा की भावना में उन्नति की ही आशा। पिता श्री बुद्धन सिंह, गाँव रेवड़ा, पो० भट्टा, जि० गया।

८३ श्री *वालेश्वर तिवारीः*—५० वर्ष की उम्र के, लम्बे, गोरे, बद

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सुदृढ़। हिन्दी लिखने-पढ़ने का थोड़ा ज्ञान, पिता के बड़े पुत्र। साधारण अच्छे किसान। १५ वर्षों से सेवा कार्य्य का अनुभव, सिपाही की हैसियत से सेवा-कार्य्य करते आये। डुमराँव किसान सत्याग्रह के सहयोगी। पिता श्री निहोरा तिवारी, गांव बड़ी नैनीजोर, पो० महुवार, जिला शाहाबाद।

८४ श्री *संत प्रसाद सिंह:*—२४ वर्षकी उम्र के, रंग गोरा, बदन सुदृढ़, पिता का अकेला पुत्र, मि० इ० की परीक्षा पास, साधारण किसान। १९३५ से ही सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। ४२ के आंदोलन का सहयोगी। एकबार का जेल अनुभव। घर के लोगों का सेवा कार्य में विरोध। किसान सभा के काम में विशेष दिलचस्पी। अनुचित धान वसूली के सिलसिले में अनशन सत्याग्रह का संचालक। पिता श्री नंकन सिंह, गांव आरोपुर, पो० नौबतपुर, जि० पटना।

८५ श्री *नन्दीपति प्रसाद:*—३१ वर्ष की उम्र के जवान, गोरे, नाटे कद के, मैट्रिकुलेशन परीक्षोत्तीर्ण। हिंदी की विशेष योग्यता प्राप्त। पिता के छोटे पुत्र, अच्छे किसान, १९३० से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। किसान-आंदोलन से विशेष सहानुभूति। परिवार भर को सेवा कार्य्य से सहानुभूति। १९३० में कांग्रेस के गैरकानूनी घोषित होने की दशा में अपना मकान औफिस-कार्य्य के लिये समर्पण। गांव अनन्तपुर, पो० नौबतपुर, जि० पटना।

८६ श्री *बुद्धन मेहता:*—३५ वर्ष की उम्र के, श्यामले, साधारण कद के, पिता के बड़े पुत्र, छोटे किसान। १९३० से सार्वजनिक सेवा के काम में, दो वार के जेल यात्री। किसान सभा के कार्य्य से विशेष सहानुभूति। मिड्ल ट्रेनिंग पास। पिता श्रीराम सहाय मेहता, गांव रसीदपुर, पो० अरवल, जि० गया।

८७ श्री *रामलोचन सिंह:*—२५ वर्ष का जवान। रंग श्यामला, वदन सुदृढ़, लम्बे कदका। मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास। १९३७ से सार्वजनिक सेवा में। एक पक्का सिपाही, किसान सभा से विशेष सहानुभूति। ५, ६ बार का जेल यात्री। सेवा की अटूट लग्न।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

किसान आन्दोलन का प्रेमी। पिता श्री सोनधारी सिंह, गाँ अन्दामा, पो० अन्दामा, जि० दरभंगा।

८८ *श्री गेंदा सिंह:*—६५ वर्ष के वृद्ध, बदन सुदृढ़, लम्बे कद के श्यामले रंग के। किसान सभा में अटूट श्रद्धा, १६२१ से ही सार्वजनिक सेवा का पूर्ण अनुभव प्राप्त। दो बार के जेल-यात्री। नम कानून भंग के साथी। ४२ के आन्दोलन में भाग लिया एक सच्चे कार्य्यकर्त्ता। पिता श्री काशी सिंह, गाँव राघवपुर, पो विक्रम, जि० पटना।

८६ *श्री मुन्शी गोप:*—१३ वर्ष की उम्र का लड़का, रंग गोरा लम्बा, तेज स्वभाव का, किसान सभा के काम से प्रेम, शिक्षा से वंचित, पढ़ने का विचार, छोटे किसान का लड़का, पिता का एक लौता पुत्र, किसान सत्याग्रह का प्रेमी। वकवादी। पिता श्री लील धारी गोप, गाँव लोहगढ़, पो० मखदुमपुर, जि० गया।

६० *धुरगू सिंह:*—४० वर्ष की उम्र का, गोरा, नाटे कदका, शिक्षा से बंचित, सार्वजनिक सेवा में १२ वर्षों से, किसान-सत्याग्रह का पूर्ण अनुभव प्राप्त, छोटा किसान, पिता का अकेला पुत्र, कई बार जेल का कटु अनुभव। गाँव जीअर, पो० अस्थामा, जि० पटना।

६१ *श्री रामवतार शर्मा:*—४५ वर्ष की उम्र का जवान, गोरा लम्बे कदका, पिता का दूसरा पुत्र, अच्छा किसान। १६२६ से ही सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। किसान सभा के काम से दिलचस्पी मिड्ल ट्रेनिङ्ग परीक्षापास, सेवा के कार्य्य में पूर्ण लग्न। पिता श्री ठाकुरप्रसाद सिंह, गाँव चपौर, पो० नदवाँ, जि० पटना।

६२ *श्री अम्बिका प्रसाद सिंह:*—४० वर्ष की उम्र का, गोरा, लम्बे कदका, साधारण हिन्दी पढ़ने-लिखने का ज्ञान, पिता की एक ही संतान। छोटा किसान। १६२६ से ही किसान सभा के साथ किसानों की सेवा में पूर्ण सहानुभूति। भविष्य में सेवा कार्य्य में वृद्धि की उमीद। पिता श्री बलदेव सिंह, गाँव गोपालपुर, पो० नौबतपुर, जि० पटना।

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

९३ *श्री रामबहादुर शर्मा:*—३४ वर्ष की उम्र का जवान, गोरा, लम्बे कदका, पिता का दूसरा पुत्र, साधारण अच्छा किसान। मिडल तक की शिक्षा प्राप्त, हिन्दी से प्रेम, १९३० से किसान सभा का समर्थक। किसान सत्याग्रह से सहानुभूति रखनेवाला, चंचल प्रकृति का। पिता श्री रामपाल शर्मा, गाँव सरिस्ताबाद (…बरचक), पो० नौबतपुर, जिला पटना।

९४ *श्री धनुषधारी सिंह:*—२८ वर्ष का जवान, गोरा, लम्बे कदका, मि० ट्रे० पास, हिन्दी की उच्च शिक्षा की प्रवृत्ति, अध्यापन कार्य्य करता हुआ सार्वजनिक सेवा की प्रवृत्ति। साधारण किसान। किसान सभा के काम से विशेष सहानुभूति। पिता का सब से बड़ा पुत्र, सेवावृत्ति में परिवार के लोग वाधक। किसान सत्याग्रह से विशेष सहानुभूति। भविष्य में सेवा कार्य्य में उन्नति की आशा। पिता श्री महावीर सिंह, गांव आंती, पो० कादिरगंज, जि० गया।

९५ *श्री अलखदेव सिंह:*—१५ वर्ष की उम्र का जवान। श्यामले रंग का, लम्बे कद का। वदन सुदृढ़, विद्यार्थी जीवन। आश्रम का जीवन। पं० यदुनन्दन शर्मा की विशेष सहायता। किसान सेवा की उच्च इच्छा। पिता का सबसे छोटा पुत्र। गरीब किसान। पिता श्री आमू सिंह, गांव चरौल, पो० पकड़ी बरावां, जिला गया।

९६ *श्री इन्द्रदेवशर्मा:*—२२ वर्ष की उम्र का जवान। गोरा, नाटे कद का, बदन सुदृढ़। साधारण किसान, आइ० ए० तक की शिक्षा प्राप्त, सार्वजनिक सेवा की मनोवृत्ति, खासकर किसानों का हितचिन्तक। चंचल, वोलने में कुशल। पिता श्री बलदेव शर्मा, गांव अस्ता, पो० चंडी, जि० पटना।

९७ श्री *डा० रामवृक्ष सिंह:*—गांव सिसवा पटना, पो० राजपुर, जि० चम्पारन। प्राय: ४० साल का, गोरा वदन, धुनी किसान सेवक, अत्यन्त नम्र, और लगनवाला, साधारण किसान।

९८ श्री *महन्त सियाराम दास:*—नारेपुर मठ, पो० बछवारा, जि०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

मुङ्गेर। प्रायः ५० साल से ज्यादा अवस्था, गोरा शरीर, माथे लम्बी जटा और टीका, पक्के सनातनी, पक्के कांग्रेसी और किसान सभावादी किसान सेवक। इसी सिलसिले में कितनी बार जेल गये। बछवारा में बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन प्रबन्धक और स्वागताध्यक्ष की हैसियत से बड़ी से बड़ी ताकतों विरोध में भी सम्मेलन को खूब ही शानदार बनाया, जिसमें लाखों ज्यादा किसान सम्मिलित हुए और जब एक मीटिंग में लाउडस्पीकर के सहायता से भी सबों तक आवाज न पहुँच सकी, तो कई मीटिंग करके लोगों को किसान सभा का संदेश सुनाया गया।

९९ श्री *शक्ति कुमार, एम० एल० ए०*:—गांव कसवां, पो० कु… जि० गया। २०-२० साल की उम्र, काला वदन, देश तथा किसान के लिये जेल यात्री। हरिजन कुल के बालक, उनके उद्धार के लिये दत्तचित्त, १९४२ के युद्ध में भाग लेनेवाले।

१०० श्री *अनिरुद्ध शर्मा*:—गांव सुरतांपुर, पो० धनसोई, जि० शाहाबाद। पक्के कांग्रेसी और सच्चे किसान सभावादी, बीसियों साल से इस काम में, कई बार जेल गये, सुखी किसान और अपने इलाके में बड़े प्रभावशाली। श्यामला शरीर।

१०१ श्री *केशवसिंह*:—गांव पिंजौर, पो० जहानाबाद, जि० गया। ४० साल से अधिक अवस्था, खांटी देश सेवक, और कट्टर किसान सभावादी, सुखिया किसान, तपेतपाये जन सेवक और जेल यात्री प्रबंध में दक्ष। सच्ची लगनवाले।

—:०:—

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

शिक्षण-शिबिर का आय-व्यय

रुपया-पैसा

आय		व्यय	
५०)	मार्फत पं० यमुना कार्यी	९६)	थाली २६,लोटा ५ (पीतल के)
२००)	श्री ठाकुरप्रसाद शर्म्मा,गोढ़ी (दरभंगा)	४०।≋)॥	तरकारी
२००)	श्री वसिष्ठनारायण, एडवोकेट, पटना	५४।≈)	दाल
२००)	रेवड़ा के किसान	४०)	घी
२००)	श्री मथुरा प्र० सिंह, सिरदला (गया)	३८)	तेल कड़वा
१००)	मार्फत श्रीप्रभुनाथशास्त्री, सलेमपुर (गया)	५५)	दही, दूध
१०१)	श्रीरामकृष्ण सिंह, सिमरी (गया)	६७।≈)	पम्प, हौज बनवाई वगैरह
३१)	मार्फत श्री रक्षा सिंह, मकनपुर (गया)	१०)	कपड़ा
१०१)	श्री सीताराम सिंह, बिहटा (पटना)	४॥≋)।	किरासन तेल
५०)	श्री कैलाश शर्म्मा ,,	१३।–)।	कोयला
५०)	श्री महन्थ जी ,,	२२)	राह खर्च
१००)	श्री सरयू सिंह ,,	९॥)	बत्ती
१७५)	श्री नन्दकुमार सिंह ,,	२५)	सीमेन्ट
१०)	श्री सूर्यनारायण सिंह, ओवरसियर, बिहटा	६)	नमक
१०)	श्री रामलखन सिंह, डाक्टर, बिहटा	२३।≈)	चीनी
२७)	श्री लालनारायण सिंह, तिसखोरा, पटना	३१॥≈)	छुहाड़ा
१०)	श्री दीपनारायण सिंह, भराप, पटना	१२)	मिट्टी का बर्तन
९०)	श्री विन्देश्वर सिंह, रतनपुर, दरभंगा	१५॥≋)	साबुन
५१)	श्री डा० रामप्रकाश शर्म्मा, बथुवा,दरभंगा	१७॥)	ताला पीतल ८
५५)	श्री भैरव सिंह, जहानाबाद, गया	१८)	लालटेन ३
१००)	श्री परमानन्द केजरीवाल, मुजफ्फरपुर	३९≋)॥	खुदरा
५०)	श्री चन्द्रदीप शर्म्मा, जहानाबाद, गया	१२३)	पेट्रोल

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

२५) श्री रघुवंश सिंह, बिहटा, पटना
६) श्री टिप्पण प्रसाद सिंह, बिहटा, पटना
२०) श्री बलभद्र नारायण सिंह, पतौना, पटना
१०) स्वामी वासुदेवाचार्य, तरेत मठ, पटना
५) तरेत गांव के किसान
५) श्री बसंतनारायण सिंह, तेलपा, पटना
४।≋) मार्फत श्री रामलखन शर्मा, कटारी, पटना
५) श्री लक्खू सिंह, चकिया, गया
३) गोपालपुर के किसान
१) श्री रामवचन सिंह, बभनलई, पटना
१) श्री डा० रामवृक्ष सिंह, चम्पारन
१) श्री अम्बिका पांडेय, बिन्दौल, पटना
६४।।।) गुड़ बिक्री ३।।।ऽ४।।।-
२५) पानी के पम्प की बिक्री

२१३७≋) कुल जमा

९३।।।=)। मोटर मरम्मत
४०) ड्राइवर का वेतन
४०) तिरपाल बाबत मोटर
२९) मजदूरी रसोइया वगैरा

९६५।।।)।।। कुल खर्च
११७१।≈)। नगद जमा रोकड़

२१३७≋) कुल खर्च

—::०::—

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

अन्न आदि का हिसाब

चावल	मन	सेर	छ०
मसौढ़ा	३	२	०
नत्थूपुर	१	१५	०
लाल बाबू	१	०	०
बलभद्र बाबू	१	०	०
दरियापुर	२	२१	०
तरेत मठ, तरेत गांव, हृदसपुरा, पाली	८	८	०
गोपालपुर (बिखर)	५	३७	८
श्रीरामदेव शर्मा, वीरपुर	१	५	०
श्री दीपनारायण बाबू	१	०	०
श्री हनुमत सिंह कंचनपुर	०	१०	०
श्रीवसन्तनारायण सिंह,तेलपा	०	३०	०
श्री रामलखन शर्मा कटारी	०	५	०
श्री रामजन्म शर्मा, दरियापुर	०	४	०
मार्फत श्री यज्ञनारायण पांडे वद्य, लई	१	५	०
टेंगरैला बड़ा	२	३०	०
सिरवर	३	०	०
बड़ा कोपा	३	१६	०
चावल कुल जमा	३६	२८	८

चना	मन	सेर	छ०
नत्थूपुर	१	२७	०
श्री यज्ञनारायण पांडे,लई	०	३२	०
मसौढ़ा	०	२०	०
नौबतपुर इलाका	०	२५	०
बड़ा कोपा	०	३४	८
चना कुल	४	१८	८

आलू	मन	सेर	छ०
लाल बाबू	०	२०	०
श्री यज्ञनारायण पांडे,लई	०	२१	०
बभनलई	०	५	०
दरियापुर	०	२	८
बड़ाकोपा	०	२०	०
कुल आलू	१	२८	८

गुड़	मन	सेर	छ०
बड़ा कोपा	०	३०	०
छोटा कोपा	दो चक्की		
श्री नगेंदासिंह	एक चक्की		
नत्थूपुर	०	१६	०
श्री यज्ञनारायण पांडे	०	१३	०
बभनलई	०	५	०

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

हरियापुर ० ७

गेहूं	मन	सेर	छ०	
राघवपुर भगत जी	०	३	८	गुड़ कुल ३ चक्को और १ ३१
श्री यज्ञनारायण पांडे, लई	०	१२	०	३ चक्को १ मन पौने बत्तीस से
एक और जगह से	०	११	८	
बड़ा कोपा	०	३	८	
कुल गेहूँ	०	३०	८	

नोटः—गुड़ में से कुछ खर्च हुआ और एक मन रखकर बाकी ३॥।)४॥/ बेच दिया गया ६४॥।) में, क्योंकि वर्षा में खराब हो जाता।

खेसारी बड़ा कोपा से	२७ सेर
खेसारी की दाल वहीं से	८ सेर
रहर श्री यज्ञनारानण पांडे	९ सेर

इसमें कुछ २६ मन चावल, तीन मन चना, सब रहर, सब खेसारी, थो जौ चना मिला हुआ बच गयो। बाकी चावल वगैरह खर्च है। हां, गेहूँ भी कु बच गया है।

श्री सीतारामाश्रम, बिहटा,
१२–६–४७

स्वामी सहजानन्द सरस्वती

—::०::—

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ओरिएंटप्रेस, पटना जौब न० २५३ ड० का० १६—२५०—१६-८-४५

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Abolition of Zamindari

How to achieve it ?

"The landlords became a functionless and parasitic class interested only in getting the maximum of rent from the peasants".

("The Indian Rural Problem". page 108)

SWAMI SAHAJANAND SARASWATI

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-G

First Edition
1000 Copies

May, 1946.

Price Six annas

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

Prefatory words.

The zamindari is a relic of the social and economic system that obtained once throughout the whole world, but has now been banished from the most parts of it. Even the countries that somehow or other tolerated it so far are now in a hot haste to liquidate it. We find this in the Balkan countries and China. India too must not lag behind in the matter. This is the simple meaning of the congress call, through its election manifesto, to abolish "intermediaries between the peasant and the State". This feudal system has naturally no place in this capitalist era. It is why the rising national bourgeoisie is ready to give it a decent burial.

The zamindari means absentee landlordism. It has created a parasitic class of rent-receivers under various disguises and names, whose only business is to feed fat on the sweated labour of the Kisans. The law guarantees them their rent howsoever inequitable and oppressive, and the law-courts are ever ready to come to their prompt assistance, if and when the peasant defaults even due to the reasons absolutely beyond his control. This security of the rent is at the root of the miseries of the Kisans and the brutalities and high-handedness of the zamindars.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Even the raiyatwari areas and provinces have not escaped this misfortune and there too an army of these intermediaries has sprung up. Call them Sahukars, Khots, Jagirdars, Talukdar, Jenmis or by whatever name you like. But they are there and suck the life-blood of the peasants. The entire land has passed over to them and the actual tillers of the soil have become either agricultural labourers or mere tenants-at-will. Hence the liquidation of zamindars or intermediaries will ever remain incomplete as long as there remains even the slightest scope and loop-hole for these intermediaries to re-appear. This abolition, therefore, implies a system of land-tenure which allows no room for the passing away of the land from the actual tillers of it and the falling of it into the hands of the individuals and bodies of persons who have got within themselves the fatal germ of rent-receiving and absentee landlordism. Unless and until this is done and guaranteed, mere abolition will prove simply a formality and cannot serve the purpose aimed at. The lines that follow simply seek to clear the way for that and do nothing more.

Bihta, Patna
May Day, 1946. } Swami Sahajanand Saraswati.

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

I. Isolation of Zamindars complete.

"The introduction of Mauzawari settlement will necessitate the abolition of the present 'vested interests', like the Zamindars. Taluqdars and Malguzars" (*Gandhian Plan, page 63*)

The zamindars in their belated attempt to save zamindari are now fighting a losing battle without any of their erstwhile supporters with them. There was a time when the British people and especially the high-ranking Englishmen were the greatest champions of zamindari or the Permanent Settlement. Rather this system was created in March 1793 as a bulwark and support of the British power and interest, as says the originator of the Permanent Settlement, Lord Cornwallis, in his minute of the 3rd February 1790, "A very material alteration in the principles of our system of management has, therefore, become indispensably necessary, in order to restore this country to a state of prosperity, and to enable it to continue to be a solid support to the British interest and power, in this part of the word".

Although here Lord Cornwallis mentions the prosperity of the country as one of the objectives of the zamindari system, the events have shown

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

unmistakably quite otherwise and it is a naked reality. This hard fact has been admitted by Sir Manilal Nanavati in "The Indian Rural Problem" quoted elsewhere. The real aim is stated in the tail end of the remarks quoted above. The zamindars were created to play a reactionary role in the country and work as a mainstay of the British rule in India.

But during the last 150 years of zamindari the situation has so completely changed and the zamindars have so thoroughly exposed themselves that the Land Revenue Commission, Bengal, presided over by an eminent Englishman of position, Sir Francis Floud, recommended the complete liquidation of zamindari in their report in March, 1940. The report says inter alia in para 57, "Until the Rent Act was passed the raiyats were undoubtedly left to the mercy of the zamindars, and failed to obtain from them the generous treatment which was enjoined by the Permanent Sattlement Regulations. They were described by the Government of India as having been rack-rented, impoverished and oppressed". The report proves beyond doubt not only the defects and evils of this zamindari, but also its absolute rottenness. The commission have examined it from every aspect and found it standing in the way of the people's

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

progress and the productivity of the land.

Sir Azizul Huque in "The. Man Behind the Plough", page 255 quotes thus the then Lt. Governor speaking before the Legislative Council in 1883, "In that interval of 66 years, that is, between 1793 and 1859, while the proprietory body grew in strength aud prospered in wealth, the village communities perished,. the parganah rates, by which the assessment of the resident cultivator's rent was limited, disappeared, and almost every vestige of the constitutional claims of the peasantry, if ever such existed beyond a small privileged class, was lost in usurpations and encroachments of the landlords".

This zamindari would have been finished in no time by its inherent defects and contradictions themselves, had not the lawless laws and bayonets of the British Government come to its timely rescue and succour. It is why scarcely within six years of its birth the zamindars and their pettiest employees had to be vested with wide and arbitrary powers under the notorious "Haptam", as Justice Field admits in his "Landholding", and as also the Floud Commission say in their report, paragraph 51, "The situation that developed led to the passing of the notorious "Haptam" (Regulation VII of 1799) by which the zamindars were vested with wide and arbi-

a Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

trary powers of distraint. To the Government of that time it was an administrative necessity to have a stringent law of distraint in order to safeguard their revenue". Under this notorious Regulation the zamindars and their Amlas could easily enter even the zenanas or women's quarters of the defaulting kisans and no formal orders or search warrants from the legal authorities or courts of law were needed. Properties, movable and otherwise, lying even at the doors of the neighbours of such Kisans, were seized on mere suspicions of their really belonging to the defaulters. It is such lawless laws that protected the zamindari and surely not the least merit in it.

These and the kindered evils and defects of it had become well-known to the British people as far back as 1830 when the Select Committee set up by the House of Commons "came to conclusion that the benevolent intentions of Lord Cornwallis had not been carried into practice". It is why the Floud Commission say in their report (para 55) that "they (the Select Committee) made the interesting suggestion that Government might acquire zamindari by private or public purchase, in order to protect the raiyats' rights". So this abolition of zamindari with compensation is an old idea, to which simply a seal has been set

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

by the Floud Commission.

But if there are people who still doubt the absolute rottenness and devilry of this zamindari, they are requested to peruse the Final Report of the Famine Inquiry Commission, commonly called the Woodhead Commission, and in particular its page 275. From that it is evident that even the civilian Governments of Bihar, Orissa and Madras as also of Assam have recommended the liquidation of zamindari. The words of the report are :—

"The Bihar Government hold the view that the permanently-settled estate system stands in the way of an increase in agricultural production and an improvement in the standard of life of the cultivating classes and that it is desirable that the "abolition of system should be seriously considered by the State". At the same time, they point out that "Government Khasmahals are not conspicuously superior to many private estates, nor is the standard of life of a raiyat in raiyatwari provinces much superior to that of a raiyat in permanently settled areas", and that it would be necessary to undertake "large scale re-organisation of agriculture including cooperative farming, large scale irrigation and intensive and widespread application of all the well-known methods of agricultural development,

e Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

besides providing outlets for surplus agricultural labour". The acquisition by the State of intermediate proprietory interests between the ryot and the State is conceived by the Bihar Government as a step which should be undertaken in order to facilitate these developments.

"The Government of Assam observe that under the zamindari system there is a general feeling of insecurity and, short of abolishing this outmoded system no other change will give the full result.

"The Madras Government remark that the zamindari system appears to have outlived such usefulness as it may once have possessed.

"The Government of Orissa express the view that though the ryotwari is preferable to the permanently-settled estate system, the "only possible remedy", namely the abolition of the latter "does not seem to be a practical proposition at least for many years to come".

But the isolation and helplessness of the zamindars do not end here simply with the hard fact that their orginators and benefactors themselves have now left them in the lurch and joined their enemies' camp. Being aliens and having realised that their unholy alliance with the zamindars, who themselves feel thoroughly demoralised in face of the surging tide of mass revolt against

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

foreign yoke, could now no more serve the political objective aimed at at the inception of the zamindari, they can naturally change their mind, it may be argued. But what of the Indian bourgeoisie and business-magnates ? Surely, they are not aliens. But they too stand for the liquidation of zamindari, as is evident from the second part of the "Bombay plan", prepared by Messrs Tata, Birla and Company. They say in paras 19 and 20 of the same, "The various Tenancy Acts have in effect deprived the zamindar of a considerable part of his proprietory right over the soil and rendered him to that extent a mere collector of rent.

"As a general proposition it is nevertheless true that under the zamindari system the land lord has largely become a mere rentier and that the system as such has ceased to serve any national interest. Nowhere in India the system has created a class of landlords willing to supply capital for the improvement of the land and the extension of cultivation as was expected of it. Although the ryotwari system is not altogether free from the evils commonly associated with the zamindari system, it has the great advantage of bringing the actual cultivator directly in contact with the State. This gives to the cultivator better status and awakens the State to its responsibilities

ai Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

in the matter of cooperative farming, irrigation, prevention of soil erosion etc. without which even under a ryotwari system no agricultural improvement could be possible. The Floud Commission, which recently reported on the land revenue system of Bengal, has, after a thorough examination of the question, recommended the introduction of ryotwari system in the place of the existing zamindari tenures. We suggest the application of this recommendation to the zamindari areas in the whole of India where the zamindar is not directly interested in the cultivation of the land he owns", So even the Indian capitalists have at long last realised the great harm done by the zamindari. Hence they prefer its abolition. So much about the Bombay Plan.

Let us now turn to the Gandhian Plan as prepared and amplified by Mr. S. N. Agarwal and approved by Mahatma Gandhi, and see if that also deals a severe kick at and death blow to the zamindari. Of this Plan Mahatmaji says in the foreword, "Nevertheless, I have read enough of it to be able to say that he has not misrepresented me in any place". Therefore whatever is written in the Plan has the sanction of Mahatmaji himself. And Mr. Agarwal says with regard to zamindari in the pages 62 and 63,

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

"The zamindari system is, more or less, a remnant of feudalism, and is, therefore, out of date".

"The introduction of Mouzawari settlement will necessitate the abolition of the present 'vested interests', like the Zamindars, Taluqdars, and Malguzars. In other words, the land will have to be nationalised, and there will be no middlemen between the peasants and the State. Land will be given on long leases by the State to those who actually till it. It will pass from father to son. It shall not be alienated except to one who undertakes to till himself. The absentee landlord will be out of the picture. Of course a reasonable period of transition will be allowed for the gradual abolition of the existing proprietorial rights. A reasonable compensation may also be paid to the title holders after minutely scrutinising their titles to land. Many plots of lands have gone over to the landlords owing to defective laws or callous usury. The present owners of such plots shall not deserve any remuneration. Land may also be nationalised by levying heavy inheritance taxes or death-duties. Any succession to a landed property must be liable to a tax not less than fifty per cent. of the capital value of such land. In this manner, private property in land will automatically be ended in about two generations".

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

So Gandhiji is more merciless to the zamindars than the Indian bourgeoisie and the national Congress. If the logical corollary of this Gandhian argument is admitted and its implications are accepted, the zamindars will simply be expropriated. But more about all this later on.

Lastly, there is the latest Congress Election Manifesto which has given the final blow to the zamindari. It lays down, "The reform of the land system, which is so urgently needed in India, involves the removal of intermediaries between the peasant and the State. The rights of such intermediaries should, therefore, be acquired on payment of equitable compensation".

The Kisan sabha and all the left parties have all these long years been demanding the complete liquidation of these intermediaries without compensation. Hence the isolation of the zamindars, absentee landlords and other rent-receivers is now full and complete and mere nomenclature of zamindari and ryotwari areas and provinces will deceive nobody. Rent-receivers are to be found every where and they are to be allowed no quarters. They must quit, 'Quit India' must be accompanied by 'Quit Zamindari'.

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

II. Abolition with compensation.

"From the financial point of view, therefore, it seems us likely that the abolition of the system cannot be carried within a relatively short time, without incurring financial commitments which might seriously restrict the resources of public borrowing available for other urgent schemes of development in the post-war period".

(Woodhead Commission, page 276).

All the materials collected so far bearing on the problem to wipe out the zamindari and the intermediate interests, favour abolition with equitable or reasonable compensation. Let us, therefore, examine the point a bit in detail.

The report of the Floud Commission with regard to Bengal alone says. "At the same time we desire to point out that on the basis of the present two-party settlement operations it would not be possible to carry out a scheme of State acquisition in less than 30 years" (para 134). "The revision of the record-of-rights would be an essential preliminary to a scheme of State acquisition" (para 103). And this revision of the record-of-rights is indeed bound to be a weary process extending over a pretty long period of decades.

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

The same commission have calculated the compensation to be paid to the rent-receivers at the rate of 10, 12 or 15 times their net profit and have thus fixed the amount at Rs. 98,113. 58 and 136. 95 crores respectively (para 128). They further say in paragraph 138. "We also realise that it would not be possible to carry out the scheme without reducing by half, or even more, the present income of the proprietors and tenure-holders and other receivers of rent according as the compensation is paid at 15, 12 or 10 times the net profit".

It is worth noting here that while calculating compensation for the intermediaries, the commission have left out of consideration the entire body of Bargadars, Adhiars or Share-croppers who are now mere tenants-at-will and who cultivate about one fifth of the land in Bengal as the report itself admits thus, "At present probably about one fifth of the land in Bengal is cultivated for zamindars, tenure-holders, raiyats or under-raiyats by the people most of whom themselves hold land" (para 142). And the main reason for leaving them out for the present has been the financial consideration. Because if the immediate landlords of these Bargadars or Bataidars are allowed compensation, a huge additional sum for that will have to be raised by the Govern-

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ment as admitted in the report. It says, "As approximately one fifth of the land in Bengal is believed to be cultivated under the Barga system, compensation would amount to such an enormous figure that it would render impossible any scheme of State acquisition" (para 112). As the grain prices these days are abnormally high, the shares of the landlords of these Bargadars must fetch a huge amount of money whose capitalisation is bound to reach enormous figures. Hence this avoidation.

There is another consideration too. The moment the landlords of these Bargadars are sought to be compensated for the lands held by the latter, the former in a body will evict the latter from such lands, thus rendering them resourceless beggars and vagabonds.

Hence the commission have advised to carry through "in the first instance the acquisition of all superior rights down to the lowest grade of cash-paying under raiyat" (para 114). And it is only after that that the question of Bargadars will have to be taken up seriously, and in order to reduce very considerably the additional amount of compensation to be paid to the immediate superiors of these Bargadars, "fair rents could be fixed for Bargadars and compensation would be based on the difference between the fair rent so fixed

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

and the rent paid per acre by the raiyat" (para 113).

It is, therefore, evident that to eliminate the entire group of intermediaries an additional period of at least 10 years will be needed over and above the minimum period of 30 years mentioned above, and the whole amount to be ultimately paid by way of compensation will come some where near full 200 crores of rupees for Bengal alone. And for the process to be completed throughout the whole of India more or less ten times the amount calculated for Bengal will be required to pay off all the rent-receivers in cash, and this payment in cash is preferred by the Floud Commission. While the entire land in Bengal is 49,258,000 acres, the same in British India comes to 510,032,000 acres. Hence there is no escape from the colossal sum of Rs. 2000 crores. And the Indian States possessing 147,000,000 acres will still remain untouched, or an additional amount of Rs. 600 crores will have to be raised to banish landlordism from them also.

Those who think in terms of paying compensation in bonds or otherwise would do well to remember the words of that commission in this respect. They are :—

"We have considered carefully whether it

ijGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

would be preferable to pay compensation in cash or bonds. We are agreed that in principle it would be better to pay compensation in cash, although we realise that this method of payment might involve greater financial difficulties. Our reasons for coming to this decision are that if the zamindari system is to be abolished, it would be better to pay off the zamindars and tenure-holders once for all, rather than to have a huge body of annuitants dependent on the Government for 60 years, which is the term we propose for the sinking fund. If bonds were issued, the market would operate to put a valuation on them, and it is possible that their face value might depreciate. In view of this consideration, some of our members are of opinion that if bonds are issued, they should be guaranteed by the Government of India. An even stronger objection is that the issue of bonds would involve serious administrative difficulties. An account would have to be maintained at each District treasury of the persons who are entitled to receive compensation. Every sale and every case of inheritance would have to be *mutated* and the work involved would be much greater than that of maintaining the registers for revenue-paying and revenue-free estates", (para 102).

Therefore the Woodhead Commission in

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

their Final Report conclude thus,' 'The land Revenue Commission, Bengal, estimated that, on the basis of compensation at 15 times the net profit, the total compensation payable to holders of proprietory rights would amount to Rs, 137 crores. They also calculated that if this sum could be raised at 4 per cent the additional net revenue accruing to the Government as a result of the acquisition would be just about sufficient to discharge the debt in 60 years. One hundred and thirty seven crores is a large sum of money very nearly equal to the total capital outlay on all irrigation works carried out in British India upto the end of the year 1932-33—and the sum represents only the cost of acquisition in one province. The cost of acquisition in all areas where permanently-settled estate system prevails, would be several times larger. From the financial point of view, therefore, it seems to us likely that abolition of the system cannot be carried out *within a relatively short time*, without incurring financial commitments which might seriously restrict the resources of public borrowing available for other urgent schemes of development in the post-war period. Priority in the allocation of available resources should be given to large schemes of irrigation or industrial; development which—unlike a scheme

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

designed to replace one land system by another -- are calculated directly to increase the productive resources of the country.

"It has been suggested that there are other modes of compensation besides those considered by the Land Revenue Commission, Bengal, which can be devised and given effect to without resorting to borrowing. Thus the capitalising of the net profit of proprietors might be avoided altogether and a system of annuity payments, to be made out of the additional revenue resources acquired, might be feasible. We have not had an opportunity to investigate the possibilities of these suggestions, and we note that it may not be possible to avoid capital payments in cash or bonds in many cases, such as small proprietors and creditors, and there would in any case have to be a guarantee by the State of the annuity payments. In these circumstances, we think we are right in assuming that a change in the mode of compensation visualised by the Land Revenue Commission, Bengal, may not materially alter the conclusion reached by that Commission that it would take 30 years to replace the present land system by a ryotwari system.

"Apart from financial, there is also an administrative aspect. The revision of the record-

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

of-rights is an assential preliminary to a scheme of State acquisition. The settlement operations necessary are of such a character that the Land Revenue Commission, Bengal, concluded that it would not be possible to carry out a scheme of State acquisition in less than thirty years". The Commission having taken into account both the financial and administrative aspects of their recommendation, expressed the opinion that the work should be undertaken district by district, and as the work in each district was completed and the compensation assessed, loans may be raised by "instalments of perhaps 4 crores for payment of compensation" (pages 276-277).

'Why not then expropriate the zamindars and rent-receivers and make the actual tillers the owners of the land without compensation', may be asked to get out of this puzzle and solve the problem. But the solution is nct so easy as looks at the first glance. The fact is, any legal procedure to abolish intermediaries must involve this knotty problem of compensation. Under the section 299 of the Government of India Act it is obligatory to adopt some principle for compensation to be paid for the transferance to public ownership of any land as also the amount of the same to be mentioned specifically. Hence

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

the expropriation of the zamindars through legislative measures is unthinkable. To achieve that end a revolutionary overthrow of the regime is urgently needed.

Of course there are people who still think seriously that the Permanent Settlement must ever remain a sacrosanct thing and nobody can touch it. The Floud Commission, therefore, had to discuss the matter threadbare and come to a definite conclusion. In para 97 of their report they observe in this connection, "But before doing so we desire to record our view that the Permanent Settlement can no longer be regarded as exempt from any modification that may be called for in the national interest. Whatever may have been the obligations of the British Government as successors to the East India Company, the grant of provincial autonomy has created a new situation, under which the Government of Bengal is free to consider the problem afresh and to propose any modifications which they may consider desirable under present conditions. Indeed the appointment of the commission itself and its terms of reference are evidence that there is no legal or constitutional bar to the reconsideration of the Permanent Settlement, or to its replacement by any other system which is better adopted to the conditions of the present time.

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

"The question was considered by the Joint Committee on Indian Constitutional Reforms, who stated in their report that it should not "be placed beyond the competence of an Indian Ministry responsible to an Indian Legislature, which is to be charged inter alia with the duty of regulating the land revenue system of the Province, to alter the enactments embodying the Permanent Settlement, which enactments, despite the promises of permanence which they contain, are legally subject (like any other Indian enactment) to repeal or alteration".

So there is no legal bar to this abolition which may be accomplished through legislative actions only after paying some compensation, and this is beset with difficulties as stated above, which are almost insurmountable. Indian peasantry are surely not going to wait for more or less full half a century to see landlordism abolished. They have almost been crushed to atoms under this cruel and heartless system and the process continues unabated. The system has given birth throughout the country, irrespective of the fact if it is a zamindari or ryotwari area, to an army of absentee landlords and rent-receivers including their henchmen whose only business is to suck, through various devices, the life blood of the Kisans. Their tortures and

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

agonies have reached the climax and an outburst may occur any day, finishing not only this accursed system, but also the entire body of these parasites and their hangers-on. No body was prepared for the volcanic eruptions after the 8th August 1942, and yet it did occur and all were taken unawares. Who can say the same history will not repeat one day with regard to the zamindari and the zamindars and engulf them ? Hence if that eventuality is to be avoided and the landlords and their henchmen are to be saved, the system must end soon, sooner than many imagine even. But this seems simply inconceivable if the orthodox method of assessing and paying off compensation is allowed to operate. We are really between the two horns of the dilemma. Without compensation this abolition cannot be legally effected and the problem of compensation is such as in effect negatives the actual aim of abolition. This is the puzzle. and a solution must be found out.

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

III. What to do then ?

"Many plots of lands have gone over to the landlords owing to defective laws or callous usury. The present owners of such plots shall not deserve any compensation".

(*"Gandhian plan", page 63*)

In trying to find out a solution of the abolition-puzzle let us examine the problem a bit further. We have seen the Gandhian Plan in this regard, but have not scrutinised it. The Bombay Plan too must be consulted further. But before doing all this I am reminded of one very recent action on the part of the Bihar Government with regard to "Malikana". This malikana is an amount paid annually by the Government to the zamindars whose rights of zamindari had previously been taken over by the Government. This amount is, we are informed, only one tenth of the rent realised by the zamindars at the time the Government took it over. During this interval of a pretty long period the zamindars in general have enhanced the rents payable to them by the tenantry. But this malikana remains static and there is no increase in it. If, therefore, we take into account this enhancement, the amonnt of malikana might in actual practice be

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

more or less one sixteenth of the actual income of the dispossessed zamindars.

Now the recent decision of the Bihar Government was to pay off these malikana holders once for all by allowing them, in a lump sum, sixteen times the amount of it paid every year. Notices have been issued accordingly to the owners of these malikanas. We are not concerned with the result of these notices or the further step adopted by the Government. What we are concerned with is the principle adhered to by them in paying compensation for these malikanas. And if all the facts narrated above are borne in mind, it may be stated without contradiction or exaggeration that the malikana holders have been offered, by way of compensation, more or less only the amount which they would have been realising every year had they remained in possession of the zamindaris and and realising rent themselves at present. Sixteen times of the one sixteenth means nothing more or less than the orginal sum. And if with regard to the same zamindari-right of rent-receiving in a limited form this principle has been accepted by the Government of Bihar, what is the objection in applying it on a broader and extensive scale ? Here we are not going to discuss the point whether the malikana-holders have accep-

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

ted the principle or not. They might not have accepted it as they are not ready to liquidate zamindari. But if the Congress Government is going to force it on them, it may equally force also this principle of compensation.

It may be argued here that it is very hard to allow simply one years's income as compensation to the zamindars and take over their zamindari rights for ever. Further, it may be stated that the bulk of the zamindars being petty ones, possessing only nominal or insignificant amount of rent incomes, they are bound to be thrown on the streets as a result of this sort of compensation.

But those who advance this argument of hardship forget the hardest fact that all these hundred and fifty years these very Zamindars have piled upon the kisans one hardship after the other. Says Sir Azizul Haque in 'The Man Behind the Plough", page 249' "One regulation followed another to help the land lords till one finds the breath taking regulation that ryots preferring litigation or Groundless complaints against Zamindars were to be punished with fines and imprisonment." At another place he quotes thus the speech of the Lt. Governor of Bengal in 1859, "Feudalism on the one hand and serfdom on the other, were the principal

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

characteristics of the land system of Bengal". Could hardship go further ?

And as regards the petty Zamindars, if they are just now not roaming as beggars and vagabonds, with their insignificant income which cannot support them, how can they be so after liquidation ? And who has taken the least care to turn his eyes towards the most pitiable conditions of the Kisans in lacs and crores ? But, suppose, these petty rent receivers are allowed compensation as the Floud Commission recommend. Even then a great majority of them are destined to be thrown on the streets. Because, the amount obtained by them will be spent only in a year or two and they will become resourceless.

But if the critics are so particular about the feared beggary overtaking the petty zamindars, here is another suggestion to avoid this eventuality not only in case of petty zamindars, but also the kisan and others. Expropriate all the zamindars and rent receivers, big and small, of their rights to receive rent, give them some work and guarantee a decent or tolerably descent living to all nationals. A national Government can and must do it and see that no individual is unemployed and falls prey to hunger. The money received from the income of all the zamindars may profitably be utilized to start thousands of

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

new undertakings and industries and thus to provide work for millions.

It is quite possible the word "expropriation" may alarm the critics and thus they may raise a hue and cry against this proposal. But a little reflection over the matter may automatically silence them. Even if they peruse the Floud Commission's recommendations they will find that this expropriation is to be found there. They have recommended by a majority that compensation should be paid at the rate of ten times the net profit, and have admitted that even at the rate of 15 times the income of the zamindars will be halved and it would be lesser than that if the rate is 12 or 10 times. Now, if it is not expropriation, what else is it ? Maybe it is partial expropriation and not wholesale. All the same it is there. And when we suggest a guarantee by the State of a decent living for the expropriated zamindars, we too donot allow wholesale expropriation. So it is a difference of mere degrees after all and nothing more. And as mentioned above, also the Bombay Planners have admitted that "the various Tenancy Acts have in effect deprived the zamindar of a considerable part of his proprietory rights over the soil". Hence there is no escape from this expropriation in any case.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

And the Gandhian Plan ? This is the greatest advocate of this expropriation if we peruse it a bit attentively. In the first instance it declares that, "A reasonable compensation may also be paid to the title-holders after minutely scrutinising their titles to land", and this scrutiny, if taken up in right earnest up to its logical conclusions, may deprive almost all the rent-receivers of their titles. Really speaking this scrutiny is a terrible thing for the present title-holders. The zamindars have taken undue advantage of the helplessness of the Kisans, thus have fleeced from them the last penny, and have deprived them of the land in the absence of that penny. The Gandhian plan itself admits it as noted here and in the beginning of this chapter. And this is expropriation pure and simple. But the Plan goes further and while demanding death duties at not less than fifty per cent of the land-value from its successors, it clears the way for wholesale expropriation almost within the same period as is neededi nevitably for payment of compensation. It is why it uses the word "may be" instead of "should be" as adopted by others including the Congress Manifesto and the Bombay Plan. Therefore if a decent living is guaranteed to the rent-receivers and thus they are saved from the humiliations of this most trying scrutiny, it is preferable.

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

Hence we are definitely of opinion that either of the two alternatives specified before must be adopted to liquidate zamindari in the interest of all concerned. All other methods are not only tiresome, but also fraught with various dangers.

But if our voice proves simply crying in the wilderness and the orthodox mode of compensation as outlined by the Floud Commission and others is ultimately adopted to liquidate landlordism, we suggest that the law regarding the court of wards must be modified immediately, in order to bring all the rent-receiving interests within its scope, and all these interests must be taken over by this court of wards without delay. We make no difference between the khas-mahal or court of wards. We simply mean that all such interests must be managed by the Government themselves. It is with this view that the Bihar Provincial Kisan Sabha has recently passed a resolution to the effect that pending the abolition of landlordism all rent-receiving interests be compulsorily taken over by the court of wards immediately. And if we refer to the Bombay Plan, there also we are glad to find some such thing when it says that "For the present the State should take over the landlord's functions and pay the landlord a

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

fair rent for the land, deducting therefrom the expenses incidental to the discharge of these duties. Later on when the State is in a better position, this may be converted into a lump sum payment and the landlord's claim finally extinguished. For the immediate present, the link between the landlord and the tenant should be broken". (para 20.)

The following correspondence appeared in the "Leader" of Allahabad of the 28th April 1946 (dak edition) which is more or less on the lines suggested above. From this it appears that others too are thinking on such lines. It is :—

"Liquidation of Zamindari

It cannot be gainsaid in 1946 that the zamindars as a class have proved themselves a reactionary element in the life of the nation and useless for its social economy.

The zamindar is only a parasite sucking the life-blood of the poor agricultural economy of the country. Despite repeated warnings for more than two decades, the zamindars have not mended their ways. It is not only they have not helped the tenantry to introduce improved methods of agriculture, they took the maximum advantage of the landhunger of the people by extorting as much as they could by

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

hook or crook from them. During the temporary absence of the Congress leaders from the public life, they did not let the grass grow under their feet, but mercilessly exploited to the utmost the lacunae unfortunately left in the tenancy law. They filled their coffers, and out of their ill-gotten gains subscribed liberally to different war subscriptions sponsored by the Adviser Government, so that their nefarious activities might be overlooked. They did succeed in that.

It is admitted that the total abolition of the zamindari system is a bit complicated business, hence it is bound to take considerable time. I suggest that in order to give immediate and speedy relief to a considerable number of sufferers, the Government should amend the Court of Wards Act by adding one more provision to the disqualifications of the proprietors to manage their property. If they are habitually absentee landlords or if they manage their estates in a manner prejudicial to the interest of their tenantry or are in the habit of taking undue advantage of their position as landlords or habitually take forced labour, illegal cesses or nazrana, in such cases the zamindari be taken over by the Court of Wards for a fixed term of years and in very bad cases for the life time of the proprietor.

We might at once begin to liquidate the

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

zamindari system by making it a rule and a policy of the Court of Wards to sell out rather than conserve the indebted estates under its charge, to the cultivators if necessary on the instalment system and thus create peasant proprietors.

The present Court of Wards is only a device to keep alive the zamindari system. It must be reformed and should have a different outlook. It should be a trustee not only of the zamindar proprietor, but also of the interest of the tenants. The Court of Wards should be presided over by a politician of nationalist view, preferebly of socialist outlook The proprietor may be given a maintenance allowance with no lien on the surplus income which should be utilised for schemes for the betterment for the peasantry and the land. This will greatly assist rural development

I commend the above proposal to our Revenue Minister and his secretary who had been a great champion of the cause of the tenants in the last Assembly.—Pro Bono Publico".

In addition to the advantages narrated above the system must be adopted for following benefits and gains to the Kisans and the Government both :—

1. It will establish direct contacts between

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

the Kisans and the Government.

2. It will eliminate all chances of illegal exactions, feudal levies, non-granting of receipts for rents realised and taking recourse to Danabandi instead of Batai.

3. It will banish all chances and reasons of the Bakasht clashes in Bihar and elsewhere, as the court of wards will not try to evade the Tenancy Law on the Bakasht lands and the settled raiyats. Because the zamindars, while getting their Bakasht lands cultivated by the settled ryots, never grant a receipt for the rent in cash or kind they receive. Hence that clash.

4. Crops in the fields and ready grains on the thrashing floors will no more be allowed to rot and perish due to the insistence of the zamindars not to grant receipts, divide their share of grains or allow the kisans to harvest the crops in time.

5. The legal flaws and defects in the "Private Irrigation Act" will not be taken advantage of and thus the full irrigation facilities will be provided for at the cost of the zamindars.

6. Activities and institutions for the welfare of the Kisans and their children will be encouraged and started with the help of the funds provided from the income of the zamindaris

7. Thousands of graduates and the educated

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

youngmen will have opportunities for employment in place of the cheap Patwaris, Gumashtas and Barahils, whose constant business is to suck the life blood of the Kisans. Thus the zamindari oppressions will end.

8. At present the zamindars try to evade the Agricultural Income Tax Act, and succeed to a large extent by submitting false returns of their incomes. That will be tolally eliminated and the Government income will thus increase.

9. The ground for the much needed and urgently called for record-of-rights will be well prepared and its process facilitated, as all the zamindari records will be kept uptodate and the chances for frauds and forgeries either on the part of the Kisans or the zamindars will be ruled out to a large extent. In this way the real foundation for calculating comepensations will be laid.

Thus even if the zamindari is liquidated late—very-late—due to the compensation procedure, some tangible relief will be granted soon to the Kisans and they will consequently heave a sigh of reliaf.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

ORIENT PRESS. PATNA.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

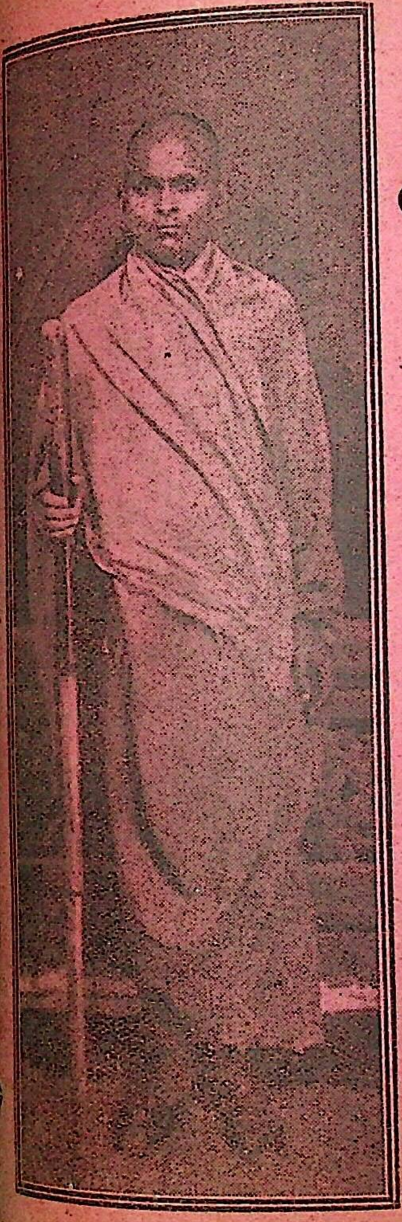

RENT REDUCTION IN BIHAR: HOW IT WORKS.

An exposure of the Government claim.

1939

BY
Swami
Sahjanand Saraswa

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

WHY AND WHEREFORE ?

When in October last Dr Rajendra Prasad issued a lengthy statement extolling in an unusual manner *inter-alia* the achievements of the Bihar Ministry regarding the rent-reduction affairs, I objected to it respectfully and elaborated my reasons in the booklet, "The other side of the Shield." But some people were still under the impression that I had exaggeratingly under-valued and minimised the ministerial gains in this respect and had sought to wilfully nullify them. But unfortunately for them there was held an All India Landholders' Conference at Lucknow in April last under the presidentship of Maharajadhiraj of Darbhanga where almost all the chosen landed magnates of Bihar actively participated, and which amply corroborated my contention. The conference after heated debates and discussions passed a resolution in favour of a talk and negotiation with the Congress High Command on behalf of the Zamindars of India with a view to arrive at an All India Congress-Zamindar Agreement on the lines of one already arrived at in Bihar. Speaking on that resolution Babus Chandreshwar Prasad Narayan Singh and Shyam Nandan Sahay, two big Zamindars of Bihar, admitted as follows :—

"The Government in Bihar too were very reasonable and some concessions were secured by the Zamindars in Bihar which no other Government would have allowed" (*C. P. N. Singh*).

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

"The Zamindars had not lost much by agreeing to reduction of rents enhanced after 1911, as such enhancements were really very small" (*S. N. Sahay*).

I naturally took this to be an excellent commentary on the ministerial policy between the Zamindars and the Kisans, coming as it did from the Zamindars themselves and consequently I thought the Government would keep quiet and not try to justify their high sounding policy regarding rent reduction by issuing press notes and communiques *ad nauseom* and by inflicting on the public at large a press-note in the end which puts forth claims that are totally untenable. In the pages that follow I have attempted to show vividly the hollowness of those claims.

The rent-reduction section of the B. T. Act bearing on the subject is appended in the end.

BIHTA (PATNA)
1-9-39
(A. I. K. Day)

Swami Sahajanand Saraswati.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Once more I am forced to examine closely and analyse ruthlessly, albeit reluctantly, the high claims advanced by the Bihar Ministry through a press-note issued from Ranchi on the 30th of July last, that "the essence and effect of tenancy legislations passed by the present Government have been to get a fair square deal for the tenants." I have previously scrutinized a bit mercilessly this general claim in a booklet, "The other side of the shield", written some eight months back, and have not come across even an attempted answer to the unassailable points raised therein. All the aspects of the "tenancy legislations passed by the present Government" have been thoroughly dealt with in that brochure and their true colours brought to light, and I respectfully still invite the Government to challenge a single fact related in it. The reader by going through it carefully will find how terribly exaggerated and baseless this claim of the Government is and how the tenants have been absolutely denied "a fair square deal" so often claimed by the present regime.

But the burden of the aforesaid press-note is not simply the tall claim put forth at the fag end of it, or there would have been no necessity for me to revert and reply to it afresh. The fact of the matter is that it deals wholly and solely with the rent-reduction affairs in the province, and attempts feebly to answer some of the criticisms levelled against the

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

procedure adopted from time to time by the Government in connection therewith and the net results thereof. Let me for convenience's sake reproduce here that note in extenso. It runs as under :—

"The attention of the Government has been drawn to an article published in a section of the press in which it is stated that the rent-reduction law is being administered to the disadvantage of the Kisans, and that Government have, in a recent circular, directed the rent-reduction officers that in granting reduction on the ground of submersion of the land under water, remission shall be allowed for such lands only as have recently gone under water, that no claim shall be entertained for the reduction of commuted rent to the level of the low rent of the adjoining land if the high rental had been fixed when the rent of the adjoining land was low, and that the power of the rent reduction officers to grant entire remission of rent on the ground of the land having become unfit for cultivation has been curtailed."

"No such circular or instructions have been issued by Government and all these statements are based on misinformation and misconception of the correct position. Relief under clause C.*i*) of section 112A of the B. T. Act is being freely given in such cases where it is established that there has been a temporary or permanent deterioration of the soil *since the existing rent first became payable*, and according to the extent of deterioration either the whole of the estimated rent of the holding is remitted, or in part".

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

"Secondly, as to the statement that no claim shall be entertained for the reduction of commuted rent to the level of the low rent of the adjoining land if the high rental had been fixed when the rent of the adjoining land was low, no such direction has been issued to the rent-reduction officers."

"Thirdly, as to the statement that the power of the rent-reduction officers to grant entire remission of rent on account of the land having become unfit for cultivation has been curtailed. this is wholly incorrect. The rent-reduction officers have *full discretion* in the matter. They can grant (*a*) complete, or (*b*) partial remission in proportion to the loss in productivity according to the facts proved, and it is wrong to say that *this statutory power has been* curtailed in any way by executive instructions."

"The essence and effect of tenancy legislations passed by the present Government have been to get a fair square deal for the tenants."

I need not mention at the very outset that I am no apologist of the article and the statement referred to repeatedly in the above press-note. In fact, I have not even seen them. What I am really concerned to deal with are certain facts stated in the note, and in so doing I shall have to examine critically and minutely the entire rent-reduction affair in the light of the whole of the section 112A of the B T. Act. Really speaking I am not aware of what are the bases of the statement in question and the subject matter of Government note. All the same, I find some stern

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

facts in it which can easily be proved and I shall do it justly.

But before proceeding further I must say that the contention of the writer of the article under criticism by the press-note, that "no claim shall be entertained for the reduction of commuted rent to the level of the low rent of the adjoining land, if the high rental had been fixed when the rent of the adjoining land was low", is thoroughly justified and it cannot be assailed. Even the note passes over it by simply saying that, "no such instruction has been issued to the rent reduction officers." There is no mention of such instructions in the contention as reproduced in the note itself, and one is taken aback by reading such a reply which is entirely besides the point. First of all the law itself on the point seems to be faulty as it does not take into account the rentals of the adjoining lands and relies instead solely on the prices of the stapple food crops, as is clear from the sub-sections (*b*) and (*d*) of the section 112 A (I) of the Bihar T. Act. So really there is no *prima facie* question of bringing the commuted rents to the level of the rental of the adjoining land.

But certainly there were some hopes of achieving the same, had the rent-reduction officers been left free hand and unlimited scope in the matter, of course, within the four corners of the law. It is but natural that the rent-reduction officers should have full freedom in applying one or more sub-sections of the section 112A (I) of the Act, when reducing

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

rent; and it was admitted by the government also, although by implication, when they issued instructions to these officers in the initial stages, as is clear from the paragraph 48 of the same, which runs :—

"In some cases it may happen that the application of the one or more of the clauses (*a*) to (*d*) leaves the rent still at an exorbitantly high figure. In all such cases it is open to the officer to report the case for action under clause (*e*)."

Then again paragraph 49 lays down further that, "certain cases may be of a mixed nature, *e. g.* where a rent fixed for a new settlement has subsequently been exhanced. In such cases the officer should cancel the enhancement and then deal with the case under the appropriate clause."

From the careful perusal of these two instructions issued by the Government it is clear that there may be ample scope for the application of all the sub-clauses of the section 112A (I) of the Bihar Tenancy Act, and that it might be necessary, with a view to do justice to the tenants, to apply sub-section (*d*) even after the application of (*a*) which cancels enhancements. It was probably sometime in 1938 when these instructions were issued. But when later on greater wisdom dawned upon the Government in early 1939, they passed circular No. 39 prohibiting the application of sub-section (*d*) in such cases. It runs :—

"Government have *now* decided that in any case in which a rent has been reduced under clause (*a*) or

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

under clause (*b*) of the section 112A (I) no further reduction should be allowed under clause (*d*). Rent-reduction officers should act accordingly" (12-3-1239). Mark here the word 'now'. And as though it is not enough clause (*e*) has not been applied at all by the Government up to the present. Not only this, instructions numbers 23 to 28 after enumerating the defects of the commutation and crop-cutting system therefor tell twice very clearly the rent reduction officers to report the case for notification and action under clause (*e*). But for the last two years the Government have slept snugly over the matter and have not thought it their worthwhile to move in the matter. And yet they make specious claims that the relief is freely given to the tenants and no instructions curtailing the discretionary powers of the rent-reduction officers have heen issued.

One more point in this respect and I shall proceed further. It is now the common experience of the rent-reduction officers that they could give formerly some tangible relief to the Kisans, as in accordance with the circular No. 17 the prices of only one stapple food crop, rice, were taken into consideration, though even then not much could be done and the Kisans could not really get a fair square deal. But of late a change for the worse has taken place and generally speaking this relief has ceased for all practical purposes. In this respect they point out to the circular No. 47 which speaks for itself and which is as follows :—

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

"The attention of the rent-reduction officers is invited to the paragraph 2 of the circular No. 17 Bihar in which it was directed that in applying clause (*b*) and (*d*) of section 112A (I) of the B. T. Act the price of only one stapple food crop, namely common rice, should be taken into account."

"Government have *now* considered the matter, and the previous direction is cancelled. Government have specified two crops as the stapple food crops of each local area. In applying the formula prescribed in clause (*b*) and (*d*) of section 112A (I) the prices of both the specified stapple food crops should be taken into consideration in the manner shown below." Mark again the word "now."

In the subsequent paragraph of the circular rice and barley have been exemplified and it has been shown by calculation that if the price of rice results in reducing the rent by, say, 25 per cent, the mean of the prices of barley and rice comes to only 18¾ per cent, meaning clearly one anna less. But it is a mere supposition. In actual practice nearly two annas per rupee have been lessened, making this clause practically dead. Still the Government go on repeating that they are serving the Kisans and not the Zamindars, that the rent-reduction officers enjoy the uncurtailed power within the law to reduce rents and their statutory powers have not been restricted in any way by any executive direction! But the deplomatic and the most cautious use of the language in their press-note will deceive none and it

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

won't be able to falsify and challenge the hard facts staring in their face.

Now I turn to other points raised in the said note. One of the charges levelled against the Government is that "the rent-reduction law is being administered to the disadvantage of the Kisans and the Government have, in a recent circular, directed the rent-reduction officers that in granting reduction on the ground of submersion of the land under water, remission shall be allowed for such lands only as have recently gone under water." It is curious indeed that instead of refuting straight away the accusation the press-note has sought to befool and hoodwink the uncanny public through a most shrewdly prepared phraseology, and thus, by implication, has pleaded guilty to the charge. I shall show it presently. The meaning of the charge in short is that the act provides, in clear terms, for the reduction of rents of all the lands whether permanently or temporarily under water or sand deposit or deteriorated by any other cause, sudden or gradual, as is evident from the clause C (*i*) appended in the end of this booklet. From the careful perusal of the same it is clear that for the application of this sub-clause C (*i*) it is not necessary that the land should become such either from before, or at the time when, or after, the existing rent became first payable. It is enough for the officer simply to find at the time of the application of that sub-clause that it is such. And if it is under water or sand-deposit

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

even from before the time the existing rent became first payable it becomes all the more necessary to reduce its rent, because it is quite probable and within commonsense that at the time of rent-settlement the deterioration had not been so complete and pronounced and that the rental had thus been fixed in the view of its productivity, though somewhat limited and also in the hope that the land might be redeemed fully in the near future.

But the circular No. 42 issued lately curtials awfully the scope of this clause by laying down that, "the Government desire that relief under clause C(*i*) of the section 112 A (I) should be given only where it is established that there has been a temporary or permanent deterioration of the soil since the existing rent became first payable."

"It is possible that some lands were habitually flooded for long periods and that in others there was a deposit of sand even at the time the existing rent first became payable. If this fact is satisfactorily established the existing rent should be assumed to have taken into account the habitual or occasional submersion of the land and the deposit of sand as the case many be and no remission should be given under clause C *i*)."

As already stated above, why should not the assumption be quite contrary to what is mentioned above in the circular and why should thus the Kisans be deprived of their rights by restricting arbitrarily the scope of the clause C (*i*) if and when the assump-

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

tion in the Circular does not tally with the hard facts ? And why this assumption at all ? Simply to limit the scope of the clause in the interest of the Zamindars ? If not, what is the meaning and necessity of this assumption if in reality "the essence and effect of the tenancy legislations passed by the present Government have been to get a fair square deal for the tenants ?" Most unpleasant truth is that the case of Government on this score is utterly untenable. Hence the press-note silently admits in other words the charge by saying, "relief under clause C (*i*) of section 112 A of B. T. Act is *being freely given* in such cases where it is established that there has been a temporary or permanent deterioration of the soil *since the existing rent first became payable.*" Being freely given forsooth ! Mark please this and the other italicised part "since etc".

One thing more. From the clause C (i) it is crystal clear that in addition to the submersion under water or sand deposit there may be "other specific causes, sudden or gradual," for deterioration and reduction should be granted on the basis thereof too. In fact some rent-reduction officers wanted to use their discretion in this respect. But they were indirectly stopped by the inspection remarks of Mr. R. A. E. Williams, the rent officer, which is to this effect, "The rent reduction officer is now considering the plea that some of the land has deteriorated because of the shade caste by some trees. I doubt whether clause C (i) covers such a case," (24-5-39). Is the

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

proudly and loudly advanced claim in the said note that "the rent-reduction officers have full discretion in the matter," justified yet ?

Next comes the clause C (*ii*) which has been for all intents and purposes nullified by the sheer executive fiat and I shall prove it upto the hilt. It is, "If the landlord of such holding has failed to carry out the arrangements in respect of irrigation which he is bound to maintain." Its chief aim is to reduce rent if the Zamindar has neglected irrigation. It has got a history of its own. During the last 12 long years the Kisan Sabha and the Kisans have had the bitterest experience of the Zamindars wilfully neglecting irrigation in its entirety, there being no legal means to compel them, the Private Irrigation Act having been invoked, but failed miserably for the purpose. The continued failures to maintain irrigation and its consequent desrepair beyond all proportions can not be remedied under that law. Hence the persistent cry on behalf of the Kisan Sabha from thousand of platforms to redress this standing wrong to the kisans resulted in incorporation of this subclause C (ii) in the tenancy legislation of the present Government. This was rightly considered to fulfil the longfelt need. It was therefore naturally expected that the Kisans will be compensated for this long and studied neglect on the part of the Zamindars to maintain irrigation by reduction of rent at least for the equal period with a view to cure the wound inflicted thus upon them by the Zamindars. This hope

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

was strengthened by the earlier directions issued by the Government to the rent-reduction officers. The 44 and 45 paragraphs of this are to the effect, "In deciding for what period the remission should be allowed, the officer should take into consideration the evidence before him, if any, as to the past conduct of the landlord. If failure to maintain the system is proved to be general and habitual, a period of ten years would be reasonable."

"Officer should ignore specious promises on the part of the landlords to repair their irrigation systems. The landlords' remedy is to put works into proper condition and then to apply for revision of the order under the proviso to this clause."

This was to a great extent in keeping with the spirit of the said clause But all this has been undone simply by one cruel stroke of the executive pen and the Kisans and their well-wishers stand aghast, finding no way out. The latest fiat of the Government, namely the circular No. 43 has verily acted like the butcher's knife in cutting the throats of the Kisans who had reposed their blind faith in the Ministry. It reads :—

"Before passing any order under section C (ii) the rent-reduction officer should direct the landlord to make good the specific defects which are found in the irrigation arrangement, and if within a reasonable time to be specified in the order, the landlord fails to comply with the directions, the order allowing remission of rent should be made final, and it should

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

take effect from such date after the filing of the tenant's application as the officer considers to be reasonable. Orders passed under clause (*c*) should not be given retrospective effect for a period prior to the date on which the application was filed."

This circular is significant from more than one point. It betrays clearly the change the Government outlook has undergone of late, as also the growing pro-zamindar tendency on their part. Otherwise what is the justification in allowing the Zamindars "a reasonable time" to make good the defects in irrigation when they must suffer and can be made to face the consequences of their terribly deliberate neglect in the irrigation works for decades together? Why should they be given at all such a facility and thus the innocent kisans be condemned to groan under the piled up tyrannies and caprices of the landlords for no fault of theirs? And why this sudden departure, pray, from the original stand taken by the Government themselves? Then again what is the "reasonable time" to be given to the landlords and who will decide it? The rent-reduction officer? Certainly not. Here once more his hands are sought to be tied up, though indirectly, by the executive action. Below are the inspection notes by Mr. R.A.E. Williams, the rent officer, which need no comment. He writes :—

Village Saguna (Dinapore P. S.)—These are fertile lands, but the landlords neglected the irrigation arrangements which they are found to maintain.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

The rent-reduction officer gave the landlords about 30 days to repair the Ahars and Pynes. I do not think that this period was sufficient or reasonable ....The attention of the rent reduction officer and the charge officer is drawn to the circular No. 43."

So, it is evident from this note that even 30 days are not enough for the sleepy landlords who are accustomed to pay no heed to their irrigational duties for decades and, who sat tight over the matter even after this clause had been passed some two years back ! Poor rent-reduction officers ! They have been tied hand and foot and delivered in a way to the landlords ! Really I pity their miserable plight ! They are again and again reminded, in this aforesaid inspection note, of the notorious circular No 43 quoted above, and yet we are told in all seriousness to believe that "they have full discretion in the matter."

An additional thing of importance in the above inspection note are the words "sufficient or reasonable time," and it has been sought to replace or explain away the original word 'reasonable' by deliberately using the word "sufficient" to connote its real meaning. And who will decide about this sufficiency ? Zamindars in the long run of course ! So the letters, which appeared time and again in the controlled press condemning the so-called tyrannies of the poor rent reduction officers by not allowing the asked for time to the Zamindars, have told at last and achieved desired results. Verily, the Government have invented a novel method for doing things by

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

backdoors and these circulars and inspection notes are unique illustrations of the same. And lest the rent reduction officers forget even after the repeated reminders in the paragraph 14 and 21 of the inspection note, the rent officer deems it neet and proper to devote the entire paragraph 18 of the note for the purpose, which runs :—

"Under the latest circular (No. 43) the defects in the irrigation system should be clearly specified and the landlords given an opportunity to remove them."

This is perhaps to save the Zamindars from the Zulums of the rent reduction officers! And again, is it a fact that atleast some rent-reduction officers have very recently been ordered to extend the period already allowed to 4, 5, 6 or more months? I pause here for an authoritative denial.

There is yet another sting in the tail of the above cited circular No. 43 which prohibits the retrospective effect of the remission order. It is merely to safeguard the interest of the Zamindars clearly at the cost of the Kisans and hence it seems a deliberate device. I shall make it a bit clear. In the first place there seems a plan to let no occasion arise for remission under this clause C (II) by allowing the landlords more and more time and latitude to repair irrigational systems. But if even then they unfortunately fail to prepare a show of repair, as no actual, solid and working system of irrigation can possibly be established and brought into being without a huge expenditure required for a carefully prepared plan of

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

the same by the experts, and these in their turn need ample time and test, the next move seems to be to allow the remission side by side with a hope and provision for the Zamindars to file a revision petition as soon after this remission as they can, and this is bound to be anulled without any delay and loss to them. It is with this view that the circular No. 48 has recently been issued which reads :—

" The rent-reduction officers should note that they are competent to exercise the powers of the Collector mentioned in the proviso to clause (*c*) of the section 112A (I) of the B. T. Act. They may revise any order *passed under sub-clause* (*II*) of the clause (*c*), if they are satified that the landlord has restored the condition of the irrigation which he is bound to maintain." Mark the italicised words and you will easily understand the meaning and the plan.

But this purpose can be achieved only if the order for reduction does not take a retrospective effect. In case of such an effect even after the revision by the same officer the Zamindar is destined to suffer some pecuniary loss, as a certain portion of arrears is then sure to be written off which cannot justifiably be realised after the revision even by the same agency, in as much as even after the repair of the irrigational systems by no stretch of imagination it can possibly be proved that the Kisans did not sustain a considerable loss of produce for want of irrigation. The restored systems of Ahars and pynes etc. cannot be so done for the past years too when they were actually

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

in a most delapidated state or had completely disappeared. Hence this safe course of not granting a retrospective effect to these remissions.

I am forcibly reminded of one more glaring fact at this stage. In the initial stages of this rent-reduction business a certain instruction No. 50 was brought out by the present Government directing the rent-reduction officers to pass orders for remissions to take effect from the following year. But, due to the threatening growth of the Kisan-movement perhaps, the Government, with a view to take the wind out of the sails of the Kisan-sabha, issued later on the circular No. 19 in December last which goes on to say :—

"In instruction No. 50 it is laid down that normally the date from which reduction is to take effect should be from the beginning of the following agricultural year. The Government have since decided that in case of Raiyats in arrears, the order with effect to the reduced rent should date from the year in which the arrears commenced."

The most welcome effect of this, so far as the Kisans were concerned, was that they had not now to apply separately for the reductions in arrears of rents according to the newly passed law for the purpose. They got the desired relief in this matter too through the rent reduction applications alone and were thus saved from much botherations and heavy expenditures. But this was too much for the Zamindars to tolerate and they raised a regular hue and cry

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

and brought pressure to bear upon the Government with the result that circular No. 44 was brought into being in the early April 1939 which speaks for itself and I cannot do more but to reproduce it verbatim. It is:—

"The rent-reduction officers are informed that the circular No. 19 of Bihar is cancelled, and that in future reduction of rent allowed under sec. 112A (I) of the B. T. Act should take effect from the beginning of the agricultural year in which the order is passed."

As if by way of adding insult to the injury the Zamindars have all along been filing rent suits for arrears even while the Kisans had already applied for the reduction. The irony is that the Civil Courts concerned went on uninterruptedly with their business of considering and decreeing these suits, notwithstanding the Kisans having informed them in the prescribed way of their application for reducing the very same arrears. Perhaps the court took the technical view of all these things and "our Government" had done nothing to force the courts to take notice of such applications for reducing the arrears of rents and stay the proceedings, although for the Zamindars they were as though in a hurry to issue circulars to safeguard their interests, as I have already shown and will show hereafter. And yet much ado has been and is still made of this very reduction in the arrears of rents. Need I enquire as to who is to benefit by this policy and by this circular

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

No. 44 in particular? Is it in the interests of the Zamindars or the Kisans? Is this the way to get a "fair square deal for the tenants?"

The matter does not end here. As if by way of making up deficiencies and giving still more protection to the Zamindars the circular No 20 had been issued restricting further more the scope of the rent-reduction law and curtailing further the powers of the rent-reduction officers in this respect. Here the law does make no difference between the fixed rate rents and others, and why should it do so? In fact it did not and could not occur to anyone at the time of the enactment of this section or for the matter of that the entire tenancy law amendments. The fact is, this distinction between the fixed rate rents and the others is simply ununderstandable. There are thousands of the Kisans who have to pay exorbitantly high rents at fixed rates just as there are lacs of others. The same were fixed equally when the prices of the stapple crops sored high. Therefore, it simply passes one's comprehension how and why these fixed rate Kisans should be debarred, I shall not tell deliberately, from this concession of rent-reduction. But this is actually what the Government have done, in the supreme height of their wisdom, through the circular No. 20 which says:—

"It has been *decided* by the Government that rents of the holdings, whose rents or rates of rents have been fixed in perpetuity, cannot be altered. There should, therefore, be no reduction of rent of this

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

class during the rent-reduction operations under section 112A (I) of the B. T. Act"

So it is not a mere interpretation of the law, but the "decision" of the Government—"it has been decided by the Government." A fair square deal for the Kisans forsooth!

I have previously referred to the circular No. 39 and have dilated upon it at some length. In this respect there is one more burning point which throws considerable light on the change in the policy of the Government, and proves beyond even a shadow of doubt that this change is deliberate and is meant to benefit the Zamindars. There is the paragraph 49 of the instructions issued at the very outset by the Government which has been quoted previously. According to that there might be ample justification to apply clause (*d*) even after the operation of the clause (*a*) or (*b*), with a view simply to mete out bare justice to the Kisans. This atleast is the admission of the Government themselves, though not in so many words. There can possibly be no other interpretation of that paragraph 49 and it is evident to anyone who goes a bit minutely through it But the same has been stopped by the Governmental order in the form of the circular No. 39!

Below I adduce additional facts to illustrate how the Government feel simply nervous when there is the slightest apprehension of the interests of the Zamindars being touched in favour of the Kisans. The circular No. 38 lays down that the evidence

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

tendered by the Zamindars must be considered and the order passed giving reasons for the acceptance or rejection of the same. It throws a burden on the rent reduction officers, as it is a common experience that to give reasons in writing, especially for rejection, is not an easy task. But the greatest harm that this order to the officers has done is a volume of fabricated and forged evidences and proofs produced by the Zamindars, who were encouraged by this order. It is an open secret and the Government have at least been forced to warn the rent reduction officers against these through perhaps circular No. 58 and otherwise. Then there is the circular No. 46 which betrays the aforesaid nervousness of the Government as nothing else does. It runs :—

"Under the existing rules a general notice is issued on the landlords and tenants of a village informing them that certain applications for the reduction of rent are to be considered on a certain date, and requesting their attendance. Sometimes the parties attend without further notice, and *where the landlords fail to attend* an individual notice has to be issued before any order reducing the rent can be passed. (And what, if the Kisans fail to attend ?)

"Under this proceedure it frequently happens that a landlord is not aware precisely of the particular holdings to which the applications refer.

"It is essential that the landlords should have precise information about the nature of the applica-

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

tions filed and the holdings and tenants to which they refer. Rent officers should, therefore, see that copies of the applications for reduction are sent to each landlord before the date of hearing. If the application is amended by the tenant at a later stage the landlords should be given time to consider the changes made".

Why this special care for the landlords only and not the Kisans? Why should not the special notice be issued to the Kisan also if he any how fails to attend? Of course when this open partiality was some how or the other brought to the notice of the Government, they, by way of mere face-saving, attempted to explain away this circular after about full two months by the circular No. 52 of June 7, which after referring to the said circular says, "Obviously the direction applies with equal force to the treatment of the tenants." But one is at a loss to understand how it is possible when there is no mention of tenants in that circular in this connection. This omission is impossible of being explained away as an act of oversight. It is but intentional, one is constrained to admit. Hence this explaining away to save face.

But no body for a moment should think that these charges against the present Government are based on mere arguments and abstract ideas and guesses and not on hard facts. To tell the truth it is the solid facts which have compelled us to find out the source and the real cause of this gradual whittling

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

down of the relief through rent-reduction and setting it almost at naught in the long run. When deterioration set in first in this rent-reduction relief the Kisans were bewildered and they were prone to blame merely the officers entrusted with this work who, according to them, spoiled everything of their own accord, being considered susceptible to all sorts of pressures and influences, as the Government could not easily be believed to do wire-pulling from behind the scenes. Consequently all sorts of wild charges were levelled against these officers in general. But to the piercing and discerning eyes the matter could not possibly rest there and investigations having been started these dirty things were unearthed as the actual causes for rendering this rent reduction affair a veritable farce to all intents and purposes. Nay, these officers themselves have narrated time and again, in private, how their hands have been tied down.

The Zamindars are accustomed to drag the Kisans in the intricate and ruinous course of litigation. By such devices alone, in addition of course to hundreds of illegal oppressions, they have so far been able to render these Kisans as so many galley slaves. Along with these Kisans we had been so long hoping that at least in this rent-reduction business they would be saved from this course to the maximum extent. But ours has been the hoping against hope. The Zamindars here too have marvellously succeeded in pursuading the Government to do

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

as they desired. This, in a nutshel, is the resultant sum total of these instructions and circulars issued by the Government from time to time during these two long years. This is the experience of the Kisans even in regard to their hard won partial success in remission. The protracted proceedings in this connection, first before the rent-reduction officers and then before the appeallate courts, have generally cost them ten to twenty years' savings by way of these remissions and they are consequently most annoyed.

But the Zamindars too are not happy despite all these, and how could they possibly be so during these abornal days of tremendous mass consciousness? Moreover, until and unless their rent-realisation continues unhampered seriously their glee and merry-making are bound to vanish in the thin air. They were calculating, of course childishly, that after having frustrated the Kisans thus in a round about way they would be able to realise the full and undiminished quota of their dues from them, surely with the help of the present Government. But here they were reckoning without their host. During past ten years of terrible depression accompanied by the unprecedented earthquake, repeatedly devastating floods and unceasing blood sucking policy of the Zamindars, money lenders and their allies, the Kisans have completely been ruined and thoroughly bled white. Hence no amount of coercion can succeed in squeezing out of them even half the amount formerly realised by

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

the Zamindars and others. Instead of realising this fact the Zamindars in their folly got angry at the Kisan Sabha, levelled all sorts of wild charges against it accused it right and left and petitioned for the Governmental help in realisation. This is the secret of the so-called public mass petitions by the Zamindars to the Premier which appeared sometime back in the press. But the Govt. too could not help them, realising as they did the acute distress among the peasantry, with the result that the Zamindars are now enraged at the Govt. also, though they cannot express this feeling of theirs publicly for various reasons. This is the secret of the confession by Dr. Rajendra Prasad before the B. P. C. C. and Mahatma Gandhi at Brindaban last summer that "the Zamindars are against us". But who are at fault for it ? Certainly neither the Kisans nor the Kisan sabha. Let he himself, his colleagues and the ministers thank themselves for creating such a situation fraught with dangerous possibilities inspite of ourselves—inspite of the Kisan sabha.

Therefore it is not a mere academic discussion, but a propagation and narration of hard facts which defy challenge and which are publicly by the Kisans, admitted in private by the rent reduction officers, corroborated by the Zamindars and borne out by the unassailable proofs in forms of circulars and instructions of the present Government. Here, now, I leave the matter to the intelligent readers and impartial observers to judge and pronounce their judgment on the claim of the present Government that

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

"The essence and effect of the tenancy legislations passed by the present Government have been to get a fair square deal for the tenants," that "This (rent reduction officer's) statutory power has not been curtailed in any way by any executive instructions," that "Rent-reduction officers have full discretion in the matter," and that "The relief under rent-reduction law is freely given."

Rent Reduction Section.

112A (1): The Collector may, on the application of an occupancy raiyat or a landlord made in the prescribed form, or, if the Governor by notification directs that a settlement of the rents of the occupancy holdings situated in any area or of any class or classes of occupancy holdings situated in any area shall be made under this section, on an application made as aforesaid or on his own motion;

(*a*) cancell all enhancements of the rents of occupancy holdings made under section 29 or under clauses (*a*), (*b*) or (*d*) of section 30 between the first day of January, 1911, and the thirty-first day of December, 1936,

(*b*) reduce the rent of an occupancy holding, the rent of which was commuted whether under section 40 or by agreement between the tenant and the landlord of such holding between the first day of January, 1911, and the thirty-first day of December, 1936, to such an extent that the reduced rent shall bear to the previous rent the same proportion as the current

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

prices bear to the average prices during the decennial period immediately preceeding the time when the rent was commuted;

(c) order the partial or entire remission, for such period as he considers reasonable in the circumstances, of the rent of an occupancy holding—

(i) if the soil of a portion or the whole of such holding has without the fault of the raiyat become temporarily or permanently deteriorated by a deposit of sand, by submersion under water or by any other specific cause, sudden or gradual;

(ii) if the landlord of such holding has failed to carry out the arrangements in respect of irrigation which he is bound to maintain;

Provided that the Collector may revise any order passed under sub clause (i) at any time before the expiry of the period fixed for such order if he is satisfied that the soil of the holding has become fit for cultivation, and may at any time revise any order passed under sub-clause (ii), if he is satisfied that the landlord has restored the arrangements in respect of irrigation which he is bound to maintain;

(d) reduce the rent of any occupancy holding, if there has been a fall not due to a temporary cause in the average local prices of staple food crops during the currency of the present rent to such an extent that the reduced rent shall bear to the previous rent the same proportion as the current prices bear to the prices prevailing—

(i) at the time when the previous rent first became payable, or

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

(*ii*) if the previous rent first became payable before the preparation of a record-of-rights under Chapter X and the landlord is unable to prove to the satisfaction of the Collector when the previous rent first became payable, at the time when a record-of-rights was first prepared in respect of the holding;

(*e*) settle a fair rent in such cases, or class of cases as may be specified in a notification issued for other sufficient reasons by the Governor in this behalf.

(2) No application shall be entertained under clause (*a*) or (*b*) of sub-section (1) unless it is filed within a period of one year from the date on which the Bihar Tenancy (*Amendment*) Act, 1937, comes into force.

(3) If the Governor by notification directs that there shall be commutation of rents of the occupancy holdings or any class of occupancy holdings situated in any area, the rent of which is paid in kind or in any of the other ways mentioned in sub-section (1) of section 40, the Collector may, on the application of the raiyat or landlord of any such holding, or on his own motion, determine the sum to be paid as money rent for such holding, and may order that the raiyat shall in lieu of paying his rent in kind or otherwise as aforesaid, pay the sum so determined.

(4) An order of the Collector under this section shall take effect from such date as may be specified in the order.

(5) The powers conferred on the Collector by this section, shall be exercised in accordance with the prescribed procedure.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

To be had of:—
Swami Sahjanand Saraswati,
P. O. Bihta, District Patna.
(Bihar)

Printed by
Ramesh Printing works.
Mithapur, Patna.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ALL INDIA KISAN SABHA

FOURTH SESSION

GAYA.

9th and 10th April 1939

ADDRESS OF THE CHAIRMAN, RECEPTION COMMITTEE.

Jadunandan Sharma.

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

COMRADES,

On behalf of the Kisans of Bihar I feel gratified to extend my hearty welcome to you all, who have assembled on the occassion of the forth session of the All India Kisan Sabha here at Gaya, the heart of Magadh.

Perhaps it is not unknown to you that today the peasants and workers of Bihar are engaged in their life-and-death struggle in order to re-achieve the great honour that the ancient history of India has assigned to Bihar and Magadh in the domain of fight for liberation and salvation. Therefore, it is but natural that shortcomings in matters of your reception are there, rather their absence should be surprising. Honestly speaking, those in the midst of struggle can prepare for one reception, and one alone: reception for assaults, for pillage and plunder, for fines and impositions, for imrisonment and transportation, for gallows and bullets, and finally, for death, all these beings rendered available by our adversaries. It is for others to judge whether we are actually busy with that preparation. We have no right to judge for

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

ourselves. It is a mere chance, as you all know, that I and my comrades who, only a few weeks back, had been kept behind the prison walls, and as such, never thought of our release, have the opportunity to receive you. All-round peaceful struggle is in progress and is hovering over my mind even when I am standing here. It is in this connection that the real friends of the down-trodden and world-renowned scholar Rev. Rahul Sankrityayan, together with his brave comrades, mostly kisans, is still lying behind prison bars at Chapra. Some of our Shahabad companions find themselves under similar conditions. Nearly two hundred Kisans and Kisan-sewaks of Champaran have only recently come out of jail. Our Darbhanga comrades have not been allowed even a minute's rest for years together. Conditions in the Patna and Muzaffarpur districts are almost identical. The valiant fighter of Barahiya Tal, lying in the immediate neighbourhood of Reora, and therefore, closely interlinked with us, Karyanand Sharma, who could render us immense help on this occasion, has been constantly kept occupied by class enemies of the Kisans, so much so that he has no time to breathe even. And so far as our Swamiji is concerned, he has been too

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

busy in running about from one place to another in order to look after and control the ceaseless and stormy struggles going on throughout the province. Therefore, I do not think we are at fault if you are to satisfy yourselves with what little we can afford under the circumstances.

Our Difficulties.

In addition to it, the extreme poverty of our Kisans has stood as an insurmountable rock in our way to your reception. Want of time prevented us from tapping other resources and the poor, famished and resourceless Kisans could not be expected to do much.

The measures adopted by the ministry relating to the kisans are often very highly talked of in and out of season. But in actual practice, these measures have wrought havoc to the kisans in general hitherto unknown. This can better be illustrated by the fact that in the Gaya district alone there are thousands of villages where ready-made paddy grains are lying and rotting on threshing floors even so late as the month of April. As the laws are so wretched and reactionary, the authorities so callous, and the Zamindars so heartless that

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

neither the Zamindars themselves accept their own shares nor do they allow the kisans to take theirs. Now, you can well imagine how the starving kisan can afford to contribute something towards your reception, and at the same time feed himself and his dependants. Nature, too, did not lag behind in adding insult to the injury. During the last two months, there have been repeated rainfalls for weeks consecutively accompanied, unfortunately, by terrible hailstorms, resulting in almost total destruction, not only of the crops lying in the fields and on the threshing floors, but also of the mango crops. This inclement weather has no less seriously impeded our movements.

So far as the Zamindars are concerned, they would not help us, nor would they allow the Kisans to do so. Whenever we approached the latter for contribution, they confronted us with tortures, insults and injuries inflicted upon them by the former. Under the circumstances how can we be expected to be so cruel and heartless as to add fuel to the fire by asking anything of them ? We will ever treasure the courage and fortitude displayed by our kisans,

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

together with what they have done, all these awfully adverse circumstances notwithstanding. What you see is the result of all that.

The Congress And The Kisan.

Whatever might have been the original character of our national movement, I feel constrained to opine that, with the progressive intensification of our struggle with British Imperialism, the Zamindars and other vested interests gradually began to slip away from the said struggle, while the kisans and other exploited masses took increasingly active part in it. This phenomenon reflected itself even during the last Assembly elections where it reached its culmination. Because while the moneyed people in general offered an open and organised opposition to the Congress, the kisans and other impoverished strata of our society strongly supported and gave victory to it in elections, keeping naturally implicit faith in the congress manifesto, simply because of the consideration that it was they who had given strength to it during Satyagrah. They could not imagine even that after the victorious game was over the table would be turned all on a sudden and

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

that their interests would be absolutely eclipsed by those of their enemies through the instrumentality of the congress ministry and leadership. But the bolt did fall from the blue ultimately, and the bewildered kisans stood aghast at the tragedy with a mixed feeling of surprise and indignation to find the erstwhile enemies of themselves and of the Congress shooting up overnight as so many of its virtual leaders and helpers with their fingers on their tightened moustache, bent upon wiping the kisans out of existence. The actions, policies and the utterances up-to-date of the congress ministries of different provinces, more or less, bear testimony to this naked truth. And the Bihar Ministry has undoubtedly played the pioneer in the game followed, of course, by Bombay, C. P., Madras and others in quick succession. If a ministry or two have done a bit better, it is not because they care even a whit more for the Election Manifesto than the rest, but solely because of the fact that the arrogance and strategical mistakes on the part of the zamindars accompanied by the majority of the Congress members of the Legislature had left them no option. Those who are desirous of having a peep into the doings of the Bihar Ministry in this respect

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

will do well to read Swamiji's booklet-'The other side of the shield.'

Although many of my comrades look upon the congress as the united peoples' front or at least think in the possibility of its being transformed into such an organ, yet we are chiefly concerned, in this respect, with the mentality of those who constitute the Congress High Command to day, and who maintain that it is a political party, not a political platform. This conviction has explicitly been expressed in the writings and public utterances of the General Secretary and other leaders of the Indian National Congress during the last two years. Events at Tripuri and after have made it still more clear. Under the citcumstances I am at a loss to understand the feasibility of the much-talked-of United Front. It is nowhere to be found that while one section of the so-called United Front calls it a party, the other a platform.

But what I mean to say here in this connection is that if the Congress High Command believes it to be really a political party, then it ought to act up to this principle. It is really curious

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

that a party which is based upon the strength and allegiance of about 95% oppressed masses and which comes into power through that very strength, should, at the eleventh hour, become oblivious of the initial promises in favour of their interests and proceed, on the contrary, on the basis of adjustment between their interests and those of their enemies. But really speaking, this is how the truth stands and this is the key-note to the Congress-Zamindar and Congress-Millowner agreements and pacts. I strongly believe that if the congress is a political party at all, it must be of the oppressed masses, and as such, their interest must constitute its first and foremost concern. If not, great danger lies in store for them. I am constrained to admit here that the last two years' experiences have driven us irresistibly to this bitter conclusion, bringing tears of blood into our eyes.

Why We Took To Satyagrah.

This is why after mature consideration and profound heart-searching we had no option left but come to the irresistible decision to launch Satyagrah in order to afford a satisfactory solution of the varied problems of the Kisans. After the Congress stepped into power in Bihar we left

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

no stone unturned to direct the attention of the Congress ministers and leaders to the fulfilment of the Election Manifesto, and that for years together; and the Bihar Provincial Kisan Sabha held meetings and organised demonstrations, thereby exhausting all constitutional methods to bring pressure to bear upon them, but to no avail. On the contrary, the Congress-Zamindar agreement was brought into being, dashing all our hopes to the ground and thus forcing us to to drink the cup of humiliation. The matter did not end here; the crocodile tears together with false alarm raised by the Zamindars in the district of Gaya, Monghyr and Patna at once moved the ministry into promptly sending, not only Gurkha and mounted force on the scene in order to terrify and crush the kisans, but also openly pro zamindar special officers were deputed who almost ruined them in every possible manner. This, too, we tolerated with a heavy heart. But this resulted in emboldening the Zamindars on the one hand and had a very bad repercussion on the minds of the authorities, more especially the police, so for as the interests of the kisans in relation to them was concerned, with the clear result that the Zamindars openly resorted to threats and organised goondaism.

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

going to the length of unresricted assaults and plunders in Barahiya Tal and in hundreds of other places. It looked as if land, crops, honour, life and property of the Kisans were all in danger. Again we raised our cry; but finding it all fruitless, the Bihar Provincial Kisan Sabha was ultimately obliged to take to peaceful Satyagrah, the only weapon of the helpless. At the outset our opponents simply tried to laugh it out and even threatened us with dire consequences. But unmindful of all these, we marched on and on with the result that they had to come to their senses. Now they have begun to realise and admit their mistakes, although not openly. At Reora in this district we have recently fought the Satyagrah battle with full vigour against our enemies who put in their entire resources to curb it. But ultimately we emerged triumphant, and the kisans became able to raise their head. Reora thus symbolised this struggle and served as a guide for the future. Amwari, Raghopur, Dekuli, Lagar, Muriyar and other places are proceeding on a similar plan of action, although many such individual fights have already been successfully fought here and there in the Gaya and other districts.

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Charge of Violence.

It has become a fashion with many to talk of non-violence in and out of season. Those who use violence at every step and whose very existence rests on violence simply excite laughter and create annoyance, when they come forward as apostles of non-violence with a charge of violence against us. The very foundation of the Zamindari and capitalist social system is an organised violence. And it is curious how such people as stand for these do not feel ashamed to teach the lessons of non-violence. It is wholesale anarchy, both in the sphere of law and morality, to try to prevent us from protecting our person and property, the life and honour of our mothers and sisters in the sacred name of non-violence, and to dream to transform, wholesale, the suffering humanity within a twinkling of eyes, into so many Dhruvas, Prahlads and Jesuses, as though through the swing of a magic wand. Those, who not only tolerate and support, but even order shootings and lathi charges on the helpless and armless kisans, simply excite laughter in us when they try to deprive us, in the name of Ahinsa, even of the simple right of self-defence provided by the I. P. C

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

This at once brings to our memory the well known saying-'Physician heal thyself.' May I enquire of them as to whether they or their Government have got repealed those sections of the Indian Penal Code, which provide for defensive violence in cases of private protection ? Or have they succeeded in turning, wholesale, the people into pucca Satyagrahis through the application of magic ? Are they ready to admit whether such Zamindars and their hirelings as break open the doors in broad day light and perforce enter the houses of the kisans, and attempt on their person and property and the honour of their womenfolk, are, in any way, better, if not worse than, ordinary criminals ? Are the sections of the I. P. C. not applicable to them ? And in order to correct such miscreants if we at all advocate a very very limited application of defensive violence, wherein lies the mistake ?

Then again, struggles there have been under the auspices of the Kisan Sabha within the last two to three years at so many places and during the course of all these struggles, the Zamindars and the police have been making cruel and ruthless use of violence without any

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

break whatsoever. Will our critics cite a single instance where any of the kisans and kisan workers have ever raised even a finger inspite of the atrocities perpetrated by these Zamindars? All the resources of our critics become exhausted no doubt in giving us moral lessons in Ahinsa. But, pray, what part of these do they really use to check the organised goondaism on the part of the Zamindars?

Let me be here a bit frank to these critics of ours. Circumstanced as we are, we have adopted peace and non-violence as a matter of policy, and not of creed, purposely taking into consideration the existing conditions of the kisans and the country. And we shall never miss its proper and opportune application. But we shall, in no case, allow it to be advocated and used as a mere cloak to conceal the weakness and impotence of the kisans, and as an instrument to suppress their growing power of resistance to oppression and tyranny.

Khet Mazdoors.

Apart from the charge of violence there is yet another allegation levelled against us. Our Kisan Sabha is treated as an institution of a

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

few upper and privileged communities with land and property, fighting for them alone. Consequently it cares, as they allege, very little, if at all, and does not stand for those who are either absolutely landless or possess little land. In a word it does not represent, they say, the interest of the Khet Mazdoors, and therefore the necessity for organising an independent Khet Mazdoor movement is pointed out.

But the manifesto of the Kisan Sabha, its resolutions and our activities in this respect give, in fact, a lie direct to it. After all what is our crusade against illpaid, unpaid and forced labour meant for? Our demand and activities to ensure minimum living wages to agricultural labourers and to raise their social status in order to enable them to live a respectable life, do point out in the same direction. Our extensive land struggle in Barahiya Tal concerns chiefly those who, although once really landed are being sought to be rendered almost landless through the diceit and artifices of the Zamindars. In fact this is the charge of these Zamindars against us who allege that the Kisan Sabhaites want to confiscate land from them and make it over to these landless agricultural

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

labourers in order to turn them into kisans. Recent press reports and notices broadcast by these Zamindars at Tripuri and else where clearly bear testimony to this fact.

A number of our brave comrades from the Senuwar side are still lying behind prison bars in the Shahabad District in connection with the fight for these very Khet Mazdoors. Some of our Muzafferpur companions came out of jail only the other day after having been kept confined there for years for the only fault that they fought for the Khet Mazdoors. At Reora, Amwari, Mangabigha and other places in the Gaya District alone we have fought a number of such battles only recently and our comrade Dr. Radhakrishna narrowly escaped death in connection with some such affair. Under the circumstances, it is really anomalous that such an allegation should have been and is being levelled against us for having disregarded the claims of the agricultural labourers.

We are not necessarily opposed even to their separate organisation. But what we actually want is the sympathetic co-operation with us in order to enable us to serve them better. The

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

third session of the All India Kisan Sabha held at Comilla has also passed a resolution to this effect which is a clear illustration of our policy in relation to them.

The Charge Of Irresponsibility.

We were painfully surprised to read from the pen of one of our leaders of the congress that "the Kisan Sabha leadership was astonishingly irresponsible." It is regrettable that he has not cited even a solitary example to substantiate the charge.

During the course of the last Satyagrah struggle of the Congress, the Kisan Sabha, by a specific resolution, postponed its own activities and actively participated in the former. By another resolution it declared that in matters political the Kisan Sabha should not oppose the congress. Further during the last Assembly elections it went to the length of openly supporting even the most tyrant Zamindar candidates set up on behalf of the Congress. Then again in the summer of 1937 the A. I. K. C. at Niyamatpur in the district of Gaya, by a resolution and statement enjoined upon all kisan workers and subordinate Kisan Sabhas not to do anything which might

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

conflict even the least with the fundamentals of the Congress and lower its tri-colour in the eyes of the people. Lastly, we took prompt and instantaneous step against any of our workers whenever any report reached us against them, and stopped their activities. Are all these and the like proofs of the astonishingly irresponsible character of the Kisan Sabha? The Kisan Sabhaites too are expected after all to possess some sense of propriety and responsibility, and they have identified themselves with its activities and also with the fight for freedom with due discretion, and certainly not under any influence or persuasion. They know their job well. They have also learnt what responsibility is, and therefore need no lesson in it from others.

Red Flag.

We notice some people are prejudiced to the extreme against the Red Flag bearing symbols of sickle and hammer. They can, in no way, tolerate this flag in the Kisan Sabha. They are afraid, lest it create confusion in the minds of the Kisans, so far as the congress and its struggle for freedom are concerned. We really appreciate their motive, no doubt, but pity their wisdom.

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

To my mind, politics and freedom are things certainly not meant for children. They are things done to order neither. To me, the herd mentality appears to be the greatest source of danger. In every country of the world it is the toiling masses who fought the battles of freedom. But nowhere, excepting Russia, could they achieve real freedom, bringing their exploitation to an end. What are the reasons therefor except that their leaders not only tolerated their habit of blind following, but even encouraged it in the realm of politics? This is why that great Saviour of the oppressed and usherer of the New Age, Lenin has laid great stress upon rooting out this dangerous tendency of blind following and unthinking trustfulness in the masses. It is his firm conviction that each and every kisan and mazdoor or any member of the oppressed community 'should follow, and participate in, every phase of polisics intelligently. When once we recognise this principle, where and how does arise the question of confusion being created, so far as Tri-colour and Red Flags are concerned?

In fact we are to explain the respective importance of both these flags and bring home

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

to the people the fact that while the one is the symbol of national solidarity and national revolution, the other reminds us and stands for the international solidarity of peasants and workers, and social revolution. Great danger lies in store for the social revolution if we do not prepare the people on the aforesaid lines from the very beginning, as that revolution will not drop from the heaven as a piece of commodity. We have got to prepare ground for it from now. It is impossible of achievement without the conscious class unity and solidarity of peasants and workers. And the Red Flag points out in that direction, although it is quite a different thing that as the social revolution cannot be imagined in absence of national revolution, it is incumbent upon us to lay primary stress on the latter.

We are afraid, however, that behind this bogey of intellectual and mental confusion, the religious method of Fatwa is being introduced imperceptibly into politics, resulting in the ultimate suppression of the independent thinking of the people. And if this trend is allowed to continue we shall have to bid go-by to the emancipation of the toiling and producing

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgac

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

masses. To maintain that the Sickle-Hammer-marked red flag represents the workers alone is simply not only to deceive oneself, but the people as well, is to fight shy of their actual struggle, and finally to move away from reality.

Our Task.

Those who think of the Kisan Sabha in terms of its being a branch of the Congress or attempt to make it such, simply delude themselves. The Kisan Sabha is an independent political class organisation and deems its duty to do all it can to fully democratise the congress and protect it form the influences of vested interests. In any case it seeks the formation of a United Front consisting of the Kisans, the Mazdoors, the youth, the students and others of the lower middle class to fight for the actual liberation of them. It is not meant for being in rivalry to any other organisation whatsoever. But its real objective is to co-operate with all such institutions as fight for the emancipation of the people, and to prepare the kisans therefor. It will therefore ever co-operate wholeheartedly with the congress in its struggle against British Imperialism, and the preparation for the same. In other matters, the cong-

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ress cannot of course expect this kind of co-operation from the Kisan Sabha; nay, as soon as we come to feel that the congress has, infact, given-up that fight, unfortunately, we will oppose it with all our might. How I wish there should not have been even temporary alliance between the congress and the British Government. But unfortunately this is so none-the-less, as Gandhiji himself clearly admits.

While on the one hand we consider the frittering away, in any way, of the forces of the country a political crime, we are the bitterest enemy of Gurudom in politics on the other. We believe in the principle of weighing everything on the criterion of popular welfare, and accept or reject accordingly. It is for this reason that we emphasize the economic aspect of the struggle of kisans. Our friends in the other camp see economics through politics while we are led to politics through economics. And this inevitably keeps us ever opposed to the policy of class collaboration, because this policy is absolutely incongruous with the interest of of the toilers. Herein lies the fundamental difference between our stand point and that of others.

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

To the kisans, whose land is being snatched away, whose crop is being ruined, who is groaning under the pressure of debts and black deeds of Sahukars and co-operative societies, whose starving naked familiies are verging on death for want of medicine and, finally, whose poor cottages are all without roofs, this empty talk of Swaraj and freedom is as inept as that of paradise and salvation, and simply adds insult to the injury. Therefore, we stress the importance of their agrarian struggle at the outset demanding inter alia restoration of land to them, cancellation of debts and arrears of rents, substantial reduction in rents, rates of interest and water rates, immediate provision for food, clothing and medicine and putting an end to various forms of tortures and tyrannies. To us this appears to be the only way to prepare fully the kisans and other exploited masses for the impending struggle for liberation.

We join issue with the kisans here that deliverance form foreign exploitation is not only pregnant with dangerous possibilities, but unthinkable, without that from exploitation at home. This is the lesson of the history of the world. He alone, I hold therefore, can be a true guide

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

and friend of the oppressed and exploited who pledges himself to end the indigenous exploitation simultaneously with or before the total extinction of foreign exploitation, and who puts himself heart and soul in achieving it. Nay, the actions and movements of even these leaders will have to be closely watched by the peasants and workers and they will have to take stock of them and their work without complaisance, or they, too, may fail them, let alone the others.

Here I crave forgiveness for putting it bluntly that to tolerate religious and moral influence in the popular fight for freedom, which, in fact is a fight for bread, will prove fatal in the long run, and those, talking in these terms, are sure to betray this cause. Because such leaders, I believe, are always retrograde and reactionary.

Rights Of Producers.

Irrespective of legal and social sanction, I maintain that to let the producers of wealth die silently of starvation for want of clothing and medicine, and to force them to live the life of humiliation, is absolutely barbarous and immoral. And it is up to us to efface it from the earth. Be as it may, let us declare

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

it openly to the world and take a vow that we are not going to clear off the dues of anybody aud allow ourselves to die of starvation, want of clothing and medicine.

Spot Of Strength And Of Debacle.

The starving millions are possessed of a weapon of which their enemies are devoid. And that is their immense capacity to produce. Their victory is guaranteed if only they realise the secret of this and how to use it collectively against their common foe. It is for this reason that we wish and require the Kisans to link themselves and co-ordinate their activities in a living organisation of their own in order to enable themselves to use efficiently and properly their numerical strengh in the fight for liberation.

There is, however, only one spot of danger for them, wherein their enemies, howsoever ostensibly complaisant, want to entrap them. That spot lies in the possibility of a display and use of violence on the part of the Kisans. Circumstanced as we are to day, every attempt will be made to excite us; but if we be cautious, maintain our equilibrium and try not to mete out violence by violence but by peace, collective

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

or otherwise, our troubles and miseries will melt away in to time. But, unfortunately, if we fail here, our cause will be ruined. This is the only criterion for me to judge the efficency of Kisan organisation and measure our strength.

Our Swami—A Dynamic Force.

Truly speaking, I am unable to measure the value of immensely active contribution of our Swámi to the growth and success of the Kisan movement in Bihar. I even call him the dynamo of this movement in the country at large. We find him working day in and day out in order to infuse a new life and spirit into the oppressed masses without caring a whit for personal comforts and conveniences. It is mostly due to him that the Kisa movement has shot up within the last few years from the stage of the loose, ill formed mass movement into a powerful and growing political organisation capable of shaking hands with its opponents. So for as I think, he is as much the saviour of the oppressed in India as Lenin was in Russia.

Concluson.

Finally, I crave your indulgence to forgive me for taking so much of your time and

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

transgressing the bounds of reception by unduly encroaching upon the duty and role of the president-lect, although my only duty is to accord you hearty reception and beg your forgiveness for my shortcomings. I, however, could not help it. Mad after the cause of the kisans as I have come to be, their interests and problems, and theirs alone, have perforce occupied my mind to the exclusion of others. It is under their influence that I went on dilating upon them, while welcoming you.

In the end I once more request you to overlook the deficiency in matters of your comforts and conveniences and hope and believe that you all, who have come over here to serve the kisans to the best of your abilities, and not to enjoy our hospitality, will kindly excuse us, through your large heartedness for our imperfections, begin the work of the session under the able guidarce of our president elect, Acharya Narendradeva and complete it successfully.

INQILAB ZJNDABAD.

Printed by Gopal Lal, Rajeshwari Perss, Gaya.

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

जंग और राष्ट्रीय लड़ाई

पिछली १२ फरवरी को नागपुर में हुई अखिल भारतीय
किसान सभा की केन्द्रीय किसान कौंसिल की बैठक में
"जंग और राष्ट्रीय लड़ाई" के सम्बन्ध में
पास हुआ ऐतिहासिक प्रस्ताव ।

स्वामी सहजानन्द सरस्वती

कीमत -)

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

जरूरी बातें

ता० १३-२-४२ को नागपुर में आल इंडिया किसान सभा की कार्यकारिणी—सेण्ट्रल किसान कौंसिल—ने लड़ाई और राष्ट्रीय मांगों के बारे में जो प्रस्ताव पास किया था, वह पूरा पूरा आगे लिखा है। उसकी पूरी जानकारी न होने से ही बहुत ढंग की गलतफहमियां फैली है, फैलाई गई हैं और फैलाई जा सकी हैं। करीब तीन साल से दुनियां में चलनेवाली खूंखार लड़ाई के बारे में हम हिन्दुस्तानियों का जो रुख पहले था वह अब ठीक नहीं, इसीलिये उसे हमें अब फौरन बदलना होगा, क्योंकि यह लड़ाई न सिर्फ हमारे दर्वाजे खटखटा रही है बल्कि अगर हमने मुस्तैदी के साथ मिलकर एक आवाज से सारी ताकत के साथ सभी तरह से इसका मुकाबिला फौरन से पेश्तर न किया तो फासिस्टों की राक्षसी ताकतें हमें मिटा के ही दम लेंगी। यही इस प्रस्ताव का मतलब है। फासिज्म की शैतानी शक्तियों के खिलाफ जी-जान से लड़नेवाले सोवियत रूस, चीन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिलिपाइन्स और हाल में ही गुलाम बनाये गये यूरोप और एशिया के दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ हमें कन्धे से कन्धा भिड़ा के लड़ना हीं होगा, अगर हम अपनी खैरियत चाहते हैं, यही बात यह प्रस्ताव बताता है। प्रस्ताव का यह भी मतलब है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस लड़ाई में पड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं है वह न सिर्फ खुद धोके में हैं, बल्कि औरों को भी धोका दे रहे हैं। अगर बदकिस्मती और नादानी से हमने ऐसा

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

किया तो कम से कम सैकड़ों साल के लिये आजादी की उम्मीद तो चली जायगी ही उसीके साथ हमारे खेत-बारी, घर-बार, पशु-मवेशी और भाई-बन्धु भी धूल में मिल जायंगे क्योंकि हमारी इंच इंच जमीन पर गोलेबारी होगी। सबसे पहले जापानियों की ओर से फिर उसका जवाब अंग्रेजी फौज भी उसी तरह देगी। नतीजा होगा कि दो चक्कियों के बीच में पड़े चने की तरह हम पिस जायगे।

यह समझना महज नादानी है कि जापानियों के हमले के बाद अंग्रेजी सरकार आसानी से यहां से हट जायगी और जापानियों का यहां कब्जा हो जायगा। जब मलाया, बर्मा वगैरह में ऐसा न हो सका तो यहां तो और भी न होगा। क्योंकि हिन्दुस्तान पर जापानियों और फासिस्टों का कब्जा होने के मानी हैं, चीन, रूस, अफ्रीका, इंगलैंड, आस्ट्रेलिया, अमेरीका वगैरह सभी देशों पर उनकी हुकूमत हो जायगी। इसीलिये ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के लोग और वहां की सरकार भी भरसक ऐसा न होने देगी और सारी ताकत लगा कर जी जान से यहां लड़ेगी। तो क्या हमें अपने घर-बार, खेत-बारी सभी कुछ को धूल में मिलने देना पसंद है? अगर नहीं है, तो जापान के खिलाफ सारी ताकत से लड़ने के अलावे दूसरा रास्ता है ही क्या? आखिर धूल में मिलाने का काम वही तो शुरू करेगा।

इसपर कुछ लोग कहते हैं कि हम निहत्थे आखिर लड़ेंगे कैसे? मगर ऐसा कहनेवाले भूल जाते हैं कि पिछले बीस बाईस साल से हम अंग्रेजी सरकार से आखिर निहत्थे ही तो लड़ते रहे हैं और उसमें हमें काफी कामयाबी भी हुई है। हमने सरकार को काफी परीशान और कमजोर कर डाला है; उस सरकार को जो यहां करीब दो सौ साल से जमी-

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

जमाई बैठी है। मगर जापानी शैतान तो अभी यहां आने की तैयारी ही कर रहे हैं। ऐसी हालत में अगर हमने मुल्क के एक छोर से दूसरे तक उनके खिलाफ एक ही आवाज उठाई कि खबरदार शैतानो, तुम्हारे लिये न तो यहां जगह है और न तुम्हारी गुजर ही हर्गिज हो सकेगी, तो उनके हौसले पर जरूर पानी फिर जायगा। जहां ऐसी आवाज न थी वहीं अबतक वे पहुँच पाये हैं और उनने हिम्मत की है, यह बात याद रखने की है। मुल्क भर में ऐसी एक ही आवाज उठे, इसीलिये तो यह प्रस्ताव कहता है कि कांग्रेस, मुस्लिमलीग, हिन्दू सभा, अछूत सभा, मजदूर सभा, किसान सभा, विद्यार्थी सभा वगैरह सभी दलों और जमातों में चाहे जैसे हो इस समय मेल और एका होना निहायत ही जरूरी है। उसके बिना काम नहीं चल सकता और एक आवाज हो नहीं सकती।

इतना ही नहीं। ऐसा एका हो जाने पर हम अंग्रेजी सरकार को भी मजबूर करके यहां राष्ट्रीय और कौमी सरकार—अपनी सरकार—भारत में और सभी सूबों में भी—आसानी से कायम कर सकेंगे क्योंकि वैसी हालत में हमारी मांगों को कबूल किये बिना सरकार के लिये कोई चारा रही न जायगा और ऐसा हो जाने पर हमलोग निहत्थे भी न रह जायंगे क्योंकि हमारी सरकार हमें फौजी तालीम के साथ ही काफी औजार-हथियार देने को खुद मजबूर होगी और मजबूर की जायगी। फिर तो हम सभी तरह से सिर्फ जापानियों और फासिस्ट दुश्मनों का ही नहीं, बल्कि दूसरे चोर डाकुओं का भी मुकाबिला करके उन्हें पछाड़ सकेंगे। बिना सभी दलों, कौमों और जातियों के मेल के यह बात होनेवाली नहीं। इसीलिये प्रस्ताव की नजर में सबसे जरूरी चीज यह एक ही है। बिना सरकार और जनता के बीच सहयोग और दिली मेलमिलाप के लड़ाई

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

की आफत से हम बच नहीं सकते और हमारे आपसी मेल के बिना सरकार से दिली मेल होना मुमकिन नहीं है।

जो लोग कहते हैं कि जापान हमें आज़ादी देगा वह भूल जाते हैं कि जो न सिर्फ कोरिया और फारमोसा को ही लगातार तीस चालीस वर्षों से मटियामेट कर रहा है और मंचूरिया वगैरह को बर्बाद किये बैठा है, बल्कि अपने देश के ही कमानेवालों को अच्छी तरह भरपेट खाने पीने और खुल के बोलने तक नहीं देता वह हमें ऐसा क्यों करने देगा। सिर्फ शान्ति के साथ ही जापान क मुकाबिला करने की बातें जो लोग सोचते और कहते हैं वह ऐसे खतरनाक वक्त पर हमें निरे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, ऐसा कहने के लिये हमें माफी दी जाय। अगर बेअदबी माफ हो तो हम साफ कहेंगे कि वे घुमा-फिरा के जापान को यहां नेवता देते हैं। चाहे अनजान में ही सही, जब वे इसी देश में हिन्दू-मुसलिम दंगों का और मार-पीट, चोरी, लूट-फसाद का मुकाबिला शान्ति के साथ अबतक न कर सके और लगातार यह बातें बढ़ती ही जा रही हैं, तो जापान की खूंखारी का सामना करेंगे ऐसा कहना दूर की कौड़ी लाना और लोगों को निरे बच्चे मानना है। ऐसा उपाय तो करना ही होगा जिसमें सभी लोगों की पूरी ताकत के साथ सरकार की और फौज की ताकत मिला के जापान का सामना किया जा सके। इसीलिये सर्वत्र—चारों ओर—एका चाहिये और इसीलिये अपनी सरकार भी चाहिये।

हर हालत में गांवों में सभी दलों, कौमों और धर्मों के लोगों की पंचायतें बनें और जनता में से ही स्वयंसेवक संगठित किये जायें जो बाहरी और भीतरी सभी तरह की आफतों से लोगों की हर तरह हिफाजत करें, यह बात भी प्रस्ताव में बताई गई है।

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

इस प्रस्ताव की तीन बातें बहुत ही अहम हैं। पहली यह कि हम किसी भी हालत में जापान को इस बात का जरा भी मौका देना नहीं चाहते कि अंग्रेजी सरकार के साथ हमारे मतभेद और मनमुटाव से नामुनासिब फायदा उठाके भारत पर हमला करने की हिम्मत करे। उसकी इस हिम्मत को पस्त करने के ही लिये ही तो अपनी सरकार यहां फौरन कायम करने की बात कही गई है। मगर चाहे यह बात हो या बदकिस्मती से न हो, हर हालत में न तो हम सरकार के रास्ते में रोड़े अटकायेंगे और न वह हमारे रास्ते में और दोनों ही चाहे मिल के या जुदा जुदा ही जापान का मुकाबिला डट के करेंगे; ताकि वह मुंह की खाये और हिम्मत हारे। जापान के खिलाफ जितनी भी कोशिशें हों हम उनका स्वागत करेंगे और जहां तक होगा उन्हें बढ़ावा देंगे। किसान सभा का विश्वास है कि जापान और फासिज्म को बखूबी पछाड़ने के साथ ही साथ साम्राज्यवाद की भी ताकतें तहस नहस हो जायंगी। इसके लिये अलग कोशिश की जरूरत न होगी।

इसकी दूसरी बात यह हैं कि जनता के दिल को लड़ाई के मामले में अपनी ओर अच्छी तरह से खींचना होगा। इसीलिये प्रस्ताव कहता है कि किसानों, मजदूरों और दूसरे लोगों की ऐसी मांगें फौरन पूरी की जायं जिनसे उन्हें विश्वास हो जाय कि सरकार हमारी है और इसे मदद देना हमारा फर्ज है। ये मांगें राष्ट्रीय मांगों के अलावे हैं। राष्ट्रीय मांगें तो सबों की हुईं। हिन्दुस्तान के लिये पूरी स्वतंत्रता का फौरन एलान करना, उसे खुद अपनी हुकूमत का ढांचा तैयार करने का पूरा हक दे देना और चटपट कौमी सरकार कायम करना, यही खास राष्ट्रीय मांगें हैं।

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

तीसरी बात है चीन और रूस की मदद करने की और जगह जगह सोवियत मित्रमंडल कायम करने की। इस बात से तो किसी को भी इनकार होई नहीं सकता है। इस प्रस्ताव में तो दर असल एक भी बात ऐसी नहीं है जिसपर उज्र हो सके। मगर अगर बाज लोग नासमझी, बे-जानकारी या हठ से ऐसा कर बैठते हैं तो हमारी मजबूरी है।

उम्मीद है, इस प्रस्ताव में लिखी बातों का इस छोटी सी किताब के जरिये काफी प्रचार होगा।

बिहटा (पटना)
ता: ७-५-४२ } स्वामी सहजानन्द सरस्वती

नागपुर-प्रस्ताव

पिछले साल लड़ाई में सोवियत रूस के शामिल हो जाने से दुनियां के सभी लोगों के लिये इस लड़ाई के महत्व और इसकी अहमियत में गहरी तबदीली हो गई है। जनतंत्र शासन, जमहूरियत और सोशलिज्म के जबर्दस्त गढ़ सोवियत रूस पर होनेवाले हमले का जो शानदार मुकाबिला वहां की लाल फौजें कर रही हैं उससे सभी लोगों में यह उम्मीद हो आई है कि फासिस्ट ताकतों के जड़ मूल से बर्बाद हो जाने पर एक निराली दुनियां बनेगी जिसमें साम्राज्यवाद, शाहंशाहियत की ताकतें नेस्तनाबूद हो जायंगी, न्याय और इन्साफ की बिना पर—उसी आधार पर—समाज और सोसायटी की बुनियाद शुरु की जायगी और

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

गुलाम लोगों की जंजीरें चकनाचूर हो जायंगी । तभी से फासिज्म के खिलाफ मिलके लड़नेवाले सभी मुल्कों के लोग सोवियत रूस को अगुआ बनाकर तेजी से आपस में मिलते जा रहे हैं ताकि मानव समाज और इन्सानों के सबसे बड़े दुश्मन को रत्ती-रत्ती तबाह करने के लिये एक साथ कोशिश की जा सके और दुनियां की आजादी हासिल हो सके। इससे हिटलर और उसके दोस्तों को ताज्जुब और घबराहट हो रही है।

एक हजार मील लम्बे मोर्चे पर रूसी फौजें और वहां के लोग जो लासानी लड़ाई लड़ रहे हैं वह मानवसमाज के इतिहास में हिम्मत और बहादुरी की एक निहायत ही आला और शानदार चीज है। यह तो सोशलिस्ट राष्ट्र और मुल्क के ही लोगों का काम है कि अपने मुल्क और अपनी जमीन पर अपना कब्जा बचाये रखने के लिये ऐसी अनोखी बहादुरी के साथ ऐसे खूनी हमलों का सामना कर सकें। खास कर रूसी किसानों, लुक छिप के लड़नेवालों, उनकी औरतों और यहां तक कि उनके बच्चों की भी यह हालत है कि अपनी कमाई को सोलहों आने खुद ही भोगते रहने की वजह से अपने मुल्क के लिये लड़नेवालों में वे सबसे बहादुर साबित हो रहे और शहीद बन रहे हैं। उनने जो गैर-मामूली करमातें की हैं, उनकी कहानियों से यहाँ के करोड़ों-करोड़ किसानों के खयालों में बिजली और दिलों में जोश दौड़ जाना चाहिये जिससे हमारे अपने मुल्क के सभी लोगों के साथ समाज और सोशायटी के भीतर इन्साफ हो और सबों की आजादी मिलने के लिये पूरी कोशिश की जा सके।

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

रूस पर होनेवाले हमले के कारण लड़ाई की मुसीबतें हिन्दुस्तान के भी दरवाजे खटखटाने लगी हैं। हिटलर के जो फासिस्ट गिरोह रूस में खून-खराबी और बर्बादी मचा रहे थे वे अभी अभी रोके जा सके हैं और सोवियत फौजों ने जो अपने शानदार हमले जारी किये हैं उनके चलते उन फासिस्ट फौजों को लेनिनग्राद, मास्को, रोस्तोक और सेवास्तोपोल के पड़ोस से पीछे भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिर भी काकेशस और ईरान में मिलनेवाले तेल की उसे बहुत ज्यादा जरूरत होने के कारण हिटलर की आँखें उस पर लगी हैं। यह भी कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के लोगों और यहां की सभी चीजों पर अड्डा जमाने के भी मंसूबे उसने बांध रक्खे हैं।

पूरब में लगातार चार साल की खूंखार लड़ाई के बाद भी जब जापान चीन के निराले मुकाबिले का जवाब न दे सका तो उसने दक्खिन-पूरब प्रशान्त सागर (पैसिफिक) के मुल्कों पर बेरहमी के साथ हमला शुरू करके एशिया और आस्ट्रेलिया पर अपनी हुकूमत जमाने की आखिरी बाजी लगाई है। हिन्दुस्तान के पड़ोसी मुल्कों पर दगाबाजी के साथ हमला करने से शुरू शुरू में जो कामयाबी उसे मिली है उससे लड़ाई की आफतें हमारे दरवाजे तक आ पहुँची हैं और लोगों में यह खौफ समा गया है कि हम कुछ कर-धर सकते ही नहीं!

एक ओर फौजी चाल और साम्राज्य की हिफाजत का खयाल और दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका की आजादी चाहनेवाले आम लोगों का दबाव, इन दोनों बातों के चलते मुल्कों को फासिस्टों के खिलाफ लड़ने के लिये रूस और चीन की कतार में खड़ा होना पड़ा है। इसलिये हालत ऐसी हो गयी है कि अबतक सोवियत रूस के मुतल्लिक

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-G

इंगलैण्ड और अमेरिका के इरादों के बारे में लोगों का जो शकशुभा था वह जाता रहा। इसका नतीजा यह हुआ है कि ब्रिटेन और अमेरिका की पूंजीवादी सरकारों ने अब रूस और चीन की आम जनता की सरकारों के साथ एक जबर्दस्त समझौता इसलिये किया है कि फासिज्म के उस शैतान का खात्मा किया जा सके जो स्पेन से लेकर काकेशस होके हिन्दुस्तान और अस्ट्रेलिया तक के लम्बे मोर्चे पर लड़ रहा है। सोवियत रूस की शानदार जीत और फौजी ताकत ने फासिस्टों के खिलाफ लड़नेवालों के बीच उसके लिये पक्की इज्जत की जगह हासिल कर ली है और यहां इस बात की गारंटी भी है कि आजादी, जमहूरियत और तरक्की चाहने वाली ताकतों की ही आखिरी जीत होगी।

ऐसी हालत में सेन्ट्रल किसान कौंसिल यह महसूस करती है कि अब लड़ाई और उसकी कोशिशों के मुतल्लिक अपने रुख को बदलना ही उसके लिये मुनासिब है। शान्ति और अमन की तरह लड़ाई भी टुकड़ों में बांटी जा सकती नहीं; इसलिये रूस और चीन की और उनके दोस्तों की, जो दुनिया भर से उन्हीं दोनों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लड़ाई में कोई बनावटी फर्क नहीं किया जा सकता है। इसीलिये भारत के किसानों पर रूस, चीन और उनसे मिली तरक्की पसन्द ताकतों और प्रगतिशील शक्तियों की कतार में खड़ा होने के लिये जोर देने और इस तरह फासिज्म के आखिरी खात्मे के लिये बेदर्दी के साथ लड़ाई चालू करने में इस कौंसिल को जरा भी हिचक नहीं है क्योंकि अगर नात्सी जर्मनी और उसके साथियों की जीत हो जाय तो भारत के किसानों और आम लोगों की आजादी, आर्थिक और माली तरक्की और हिफाजत

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जायंगी और उन पर भारी तवाही आ धमकेगी।

तानाशाह फासिस्ट मुल्कों के खिलाफ लड़ी जानेवाली यह अपने ढंग की जो निराली लड़ाई है वह तभी सफलता के साथ लड़ी जा सकती है जब कि खुशी-खुशी दिल खोल के सभी दलों और तबकों के लोग उसे सचमुच अपनी आजादी और भलाई के ही लिये लड़ें। जनता और आम लोगों की ऐसी ही लड़ाई बड़ी कामयाबी के साथ रूस और चीन में लड़ी जा रही है। इंगलैण्ड, अमेरिका और उनसे मिले दूसरे मुल्कों में भी यह लड़ाई तेजी के साथ जनता की आजादी की लड़ाई बनती जा रही है। उसी तरह यह लड़ाई हिन्दुस्तान के आम लोगों की लड़ाई तभी बखूबी बन सकती है जब कि इसे यहां की कौमी और राष्ट्रीय सरकार चलाये और जब उसमें चाह के साथ दिल खोल कर सभी लोग मदद करें।

इसीके साथ यह कौंसिल यह भी महसूस करती है कि मौजूदा हालत में भारत की अपार जन, धन, शक्ति और ताकत का इस्तेमाल इस लड़ाई को सफलता के साथ चलाने के लिये नहीं किया जा सकता है। स्वामी सहजानन्द सरस्वती, प्रो० रंगा, राहुल सांकृत्यायन और बाबा सोहन सिंह वगैरह किसान सभा के हजारों लीडर और कार्यकर्त्ता अभी भी आर्डिनेन्सी हकूमत के चलते जेलों में बन्द हैं। अमन और कानून के नाम पर सरकार नये नये हुक्म रोज जारी करती जा रही है जिनसे लोगों के रोज के काम में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। बहुत जगह फसलों के कमबेश खराब हो जाने, बहुत सी किराने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा गिर जाने और कारखाने की बनी चीजों के दाम बेहद बढ़ जाने

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

के कारण करोड़ों किसानों और मजदूरों में बहुत ज्यादा बेचैनी फैली हुई है। मुल्क के रोजगार-व्यापार करनेवाले लोग भी इसलिये रंज हैं कि जब जब उनने कलकारखाने खोल के मुल्क की माली हालत सुधारने की कोशिश की है तो सरकार ने अनगिनत रोड़े अटकाये हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि लड़ाई के बाद ही भारत आजाद हो जायगा इस बात की घोषणा और एलान अभी कर देने और फौरन यहाँ राष्ट्रीय सरकार कायम करने की जो मांग मुल्क ने पेश की है, उसके जवाब में सरकार ने एक तो गोलमोल बातें कही हैं; दूसरे वायसराय की कौंसिल में अपने मन से सिर्फ कुछ और मेम्बर बढ़ा दिये गये हैं और बहुत ही थोड़े राजनैतिक कैदी छोड़े गये हैं। यह कौंसिल महसूस करती है कि इस लड़ाई को सफलता के साथ चलाने और अपने मुल्क की रक्षा और हिफाजत करने के लिये भारत के करोड़ों लोगों को तैयार करने में आज जो सबसे बड़ी रुकावट है वह है भारतसरकार और सूबों की सरकारों के नाम से बनी हुई गैर-जिम्मेदार और अपनी मर्जी से हकूमत करनेवाली नौकरशाही, जिसके लिये इस मुल्क के करोड़ों आदमियों के दिलों में कोई माया-ममता नहीं है—जिससे उनका कोई भी दिली नाता नहीं है।

इसलिये हिन्दुस्तान की जनता अपनी आजादी को हासिल करने के अरमान और फासिज्म के खतरे को मिटा डालने की अपनी तमन्ना और ख्वाहिश को जिस तरह अमल में ला सकती है ठीक उसी बात का ख्याल कर के यह कौंसिल सरकार पर जोर देकर कहती है कि वह फौरन नीचे लिखे काम करे :—

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

(१) साफ शब्दों में यह एलान कर दे कि भारत को आजाद होने और लड़ाई के बाद फौरन ही अपनी हुकूमत का ढांचा (शासन-विधान) खुद बनाने का पूरा हक है।

(२) फौरन ही भारत में ऐसी राष्ट्रीय सरकार कायम करे जो असेम्बली और भारत की जनता के सामने जिम्मेवार हो।

(३) सूबों में जनता की वजारतें और मंत्रिमण्डल कायम करे।

(४) सभी राजनीतिक, किसान और मजदूर कैदियों और नजर बन्दों को छोड़ दे।

(५) लोगोंको अपने जायज कामों के करते रहने के लिये आजादी दे दे।

(६) ऐसी नीति और पालिसी अख्तियार करे जिससे तेजी से मुल्क में कल-कारखाने खुलें, लड़ाइयों के लिये सभी हथियार तैयार हो सकें और जिन्दगी के लिये रोज की जरूरी चीजें इतनी बनें कि रहन सहन ऊंचा हो सके।

(७) मुल्क की बाहरी हिफाजत और भीतरी अमन के लिये जनता की फौज तैयार करके उसे हथियार दे।

(८) सभी तरह के दमन और दबाव डालने और सताने वाले हुक्म और आर्डिनेन्स हटा ले।

(९) किसानों पर जो लगान और टैक्स का नामुनासिब बोझ है उसे कम कर दे ताकि उनके दिलों में जोश हो और इस तरह यह लड़ाई जीतने की ताकत उनमें बढ़े।

(१०) देहातों या शहरों में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें चटपट आराम पहुँचाने के ख्याल से मंहगी का भत्ता दिया जाय और गल्ले की सस्ती दुकानें खोली जावें।

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

यह कौंसिल इस मुल्क की कांग्रेस, मुसलिम लीग, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन आदि जमातों से भी जोरदार शब्दों में अपील करती है कि ऊपर लिखी माँगों की बुनियाद पर मुल्क में बड़े से बड़ा एका हासिल करे और इन्हें चटपट हासिल करने के लिये मिलजुल कर काम करे। इसी सिलसिले में वर्धा में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में पास हुए प्रस्ताव के जो मानी निकलते हैं उससे इस कौंसिल को इसलिये खुशीहै कि अब तक जो हालत थी उसमें कुछ तरक्की तो हुई— वह कुछ सुधरी तो सही। उसमें जो यह माना गया है कि इस लड़ाई से दुनिया को खतरा है और जो व्यक्तिगत (शख्सी) सत्याग्रह को भी बन्द कर दिया गया है यह बात ठीक ही हुई है। लेकिन कौंसिल यह महसूस करती है कि सरकार क्या करती है सिर्फ इस बात पर नजर लगाने के बजाय कांग्रेस को चाहिये था कि कोई ऐसा रास्ता निकालती जिससे मौजूदा राजनैतिक झमेला मिट के कोई समझौता हो जाता। खास कर मुल्क की सबसे बड़ी राजनीतिक जमात होने के नाते कांग्रेस से यह कौंसिल दरख्वास्त करती है कि इस मामले में खुद आगे बढ़े और मुस्लिम लीग के साथ, हिन्दुस्तान की और सभी सूबों की भी सरकारों को बनाये जाने के बारे में कोई सुलह समझौता कर डाले ताकि मुल्क में यहां की लोगों की अपनी सरकार कायम न होने देने में ब्रिटिश सरकार के लिये आज जो बहाना मौजूद है वह जाता रहे क्योंकि इस कौंसिल का यकीन है कि सभी दलों की मिलीजुली जो सरकारें भारत में और इसके सभी सूबों में कायम होंगी और टिकने से काम करेंगी वही इस मुल्क के लोगों और यहाँ की सभी चीजों को अच्छी तरह संगठित और तैयार कर सकती हैं जिससे भारत की रक्षा की जा सके, यह लड़ाई

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

कामयाबी के साथ चलाई जा सके और फासिज्म का सत्यानास तेजी से हो सके।

इसके सिवाय किसानों और किसान-कार्यकर्त्ताओं से भी जोर देकर यह कौंसिल कहती है कि वे नीचे लिखी निहायत जरूरी बातों पर ध्यान दें।

(१) इस प्रस्ताव में लड़ाई के मुतल्लिक कही गयी बातों का प्रचार करना।

(२) रूस और चीन को सभी तरह की मदद पहुंचाना और सोवियत के दोस्तों की मण्डली और गिरोह जगह जगह कायम करना।

(३) ऊपर लिखी राष्ट्रीय माँगों का लोगों में प्रचार करने में सभी लोगों के साथ मिल जुल कर काम करना।

(४) जगह जगह की हालतों के मुताबिक मालगुजारी, लगान, कर्ज और दूसरी वसूलियों में छूट आदि के जरिये लोगों को आराम पहुँचाना।

(५) देहातों में अमन और शान्ति बनाये रहने के लिये कांग्रेस और दूसरी जमातों से मिलकर गांव, तालुका और जिले में पंचायतें बनाना और जनता के स्वयं-सेवकों का तैयार करना।

(६) को-आपरेटिव सोसायटियां कायम करना ताकि लोगों को उधार पैसे मिल सकें, उनकी पैदावार नफे से कम न सके और जरूरत चीजें आसानी से सस्ते में मिल सकें।

(७) भीतरी अमन और हिफाजत के लिये सभी जातियों और वर्गों के बीच दोस्ती और मेल बढ़ाना।

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

(८) खाने की चीजों, दूध, खेती, गोशालों की और भी चीजों की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करना।

(९) जगह जगह पुराने कारबारों को फिर से जगाना और जिलाना।

(१०) इस खतरे के बख्त सभी कामों में अपने ऊपर भरोसा करना।

अन्त में यह कौंसिल भारत के किसानों पर जोर देती है कि मुल्क के इतिहास में किस्मत का फैसला करनेवाली इस घड़ी में मर्दानों और बहादुरों जैसा काम करें और कुछ देहातों नें फैले खौफ और घबराहट की हालत को दूर करें। उन्हें अपने घर-बार की हिफाजत के लिये कन्धे से कन्धा भिड़ा के खड़ा हो जाना चाहिये। फासिस्टों के जरिये फैलाये गये वहशियाना और पाशविक दहसत के सामने भी चीन और सोवियत रूस के मर्दों और औरतों ने जिस निराली हिम्मत और बहादुरी का सबूत दिया है उसे हमें अपने दिलों में बैठा लेना होगा, अपने मुल्क की हिफाजत और रक्षा के लिये हमें अपने दिमाग को ठीक करना होगा, दिल को इस्पात बनाना होगा और धुन को और भी जबरदस्त कर पक्की बनाना होगा ताकि हम मुस्तैदी के साथ ठिकाने से यह काम कर सकें क्योंकि जो किसान मजबूत और हिम्मतवाले हैं और अपने मुल्क और जमीन के लिये अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हैं वही आजादी के बेशकीमत विरासत और उत्तराधिकार को हासिल करके उसे बचा सकते हैं।

ओरिएण्ट प्रेस, पटना।

jGuru Math; Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

१३ वां

बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन

बेरमो (हजारीबाग)

ता० २९, ३० जून १९४६ ई०

सभापति

स्वामी सहजानन्द सरस्वती

का

भाषण

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

झारखंडी बन्धुओ,

मैं आपको और आपके सेवकों को धन्यबाद देता हूं कि विहार प्रांतीय किसान सम्मेलन इस झारखंड (छोटानागपुर) में करने का निश्चय करके आपने इसे पूरा कर छोड़ा, हालांकि हजार बाधायें आईं। विहार प्रांतीय किसान सभा की जिन्दगी सोलह साल से ज्यादा की हो गई। इस दर्म्यान इस सम्मेलन के जलसे विहार के प्राय: सभी जिलों में हो चुके। किन्हीं-किन्हीं जिलों में तो ये जलसे कई बार हुए। मगर आपके झारखंड को, जिसमें संथाल परगने को भी मैं शामिल करता हूं, ऐसा अवसर कभी न मिला था। यह पहलाही मौका है कि आपने सम्मेलन करने की हिम्मत की। सोभी ऐसे समय में जब जीवन की सभी जरूरी चीजें दुर्लभ हो रही हैं और भोजन मिलना भी कठिन है, खासकर आपके इस पहाड़ी इलाके में। इसीलिये आपकी हिम्मत की प्रशंसा करना ही पड़ता है। सदा से शोषित, दलित और भयंकर गरीबी के शिकार इस झारखंड के लिये यह बहुत बड़ी बात है—अनहोनी सी है। इसीलिये हमारा मस्तक आपके सामने झुक जाता है।

झारखंड के निवासी

हमारे दकियानूस समाज ने झारखंड के निवासियों के लिये मनुष्य की जिन्दगी बिताने की कोई चिन्ता नहीं की। प्रत्युत इन्हें विवश किया कि पशु-वत् जीवन गुजारें। ये पढ़ें लिखें और इन्हें अक्ल आये इसकी फिक्र किसने की? इन्हें पेट भरने को अन्न और तन ढंकने को वस्त्र मिले यह किसने सोचा? इनका विकास हो और सभ्य कहे जाने वाले लोगों के मुकाबिले में ये लोग डट सकें, बैठ सकें यह खयाल किसे हुआ? इनकी अपनी भाषा पढ़ाने के स्कूल खुलें जिनमें इनके बच्चे पढ़ें यह विचार क्या कभी हमारे

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

दिमाग में आया ? हिन्दी, बंगला, रोमन और अंग्रेजी सिखाने की जो धुन लोगों पर सवार थी वही धुन मुंडारी, संथाली आदि भाषाओं के प्रसार के लिये क्यों न हुई, कौन बतायेगा ? लिखना पढ़ना तो आमतौर से इनके लिये "काला अक्षर भैंस बराबर" ठहरा। फिर भी इनपर शासन करने और इन्हें हुकूमत के शिकंजे में कसकर बांधने के लिये बनाये गये कानून ठेठ अंग्रेजी में हैं। यहां के निवासी कितने वकील, बेरिस्टर, डाक्टर और प्रोफेसर बने हैं, कौन बतायेगा ? और अगर उनकी संख्या आज भी नगण्य है तो इसका जिम्मेवार कौन है ? सरकार और समाज यदि दोषी नहीं हैं तो हैं कौन ? इन भोले लोगों को भाषा में कानून की बातें छापकर अगर इन्हें समझाया नहीं जाता तो क्या यह छोटा अपराध है ? यदि इनकी भाषा पढ़ाने की कहीं कोशिश भी होती है तो गैरों के ही अक्षरों में। इनके अपने अक्षर अबतक बने ही नहीं। इसीलिये कभी रोमन और कभी देवनागरी या बंगाली अक्षरों का धावा इनपर हुआ करता है। अगर मराठी भाषा की पुस्तकें देवनागरी में लिखी होने पर भी उसकी अपनी लिपि है, अपने अक्षर हैं जिनमें पत्र व्यवहार आदि होते हैं तो झारखंडियो के भी अपने अक्षर क्यों न होंगे, क्यों न हो सकेंगे, यह समझ से बाहर की बात है। मगर इसके लिये दूसरों को पड़ी क्या है ?

भीषण शोषण

यह सब इसीलिये है कि गैरों को काफी मौके मिलें इनके गहरे शोषण के लिये। यदि ये जग जायें, इनमें स्वाभिमान पूर्णरूपेण आ जाय और ये अपना हक तथा कर्त्तव्य अच्छी तरह पहचानने लगें तो दूसरे लोग इनका निर्दय शोषण कैसे कर पायेंगे ? तब मारवाड़ी, साहुकार, वकील, मुखतार, मिशनरी, धर्मोपदेशक, जमींदार, सरकारी अफसर इन्हें लूट कैसे सकेंगे ? झारखंड में लोहे, कोयले और अबरक के रूप में अपार निधि छिपी पड़ी है। यह भूमि स्वर्ण भण्डार है। जंगलों की कीमती लकड़ियों और पत्थरों का क्या कहना ? घासपात और जड़ीबूटियों की भी बात निराली ही है। दर

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

असल यह भूमि रत्नगर्भा है। फिर भी यहाँ के निवासी नंगधड़ंग और दरिद्र हैं। गंगा की मध्यधारा में रहने पर भी ये लोग प्यासे मर रहे हैं। खूबी तो यह कि बाहरी लोग भारतवर्ष एवं इस झारखंड के औद्योगिक विकास के नाम पर यहाँ से अपार धन ढो रहे हैं। यदि यहाँ के निवासी शिक्षित, संगठित और हर तरह से तैयार रहते तो यह बात कदापि हो नहीं पाती। यही है अबतक इन्हें पिछड़े तथा असभ्य बना रखने का रहस्य। और तो और। कोयले काटने और कारखानों में काम करने—कुलीगिरी करने—वालों को मनुष्य जीवन गुजारने भर के लिये भी वेतन ये शोषक लोग नहीं देते। उनके पिट्ठू और दलाल ठेकेदार लोग तो और भी गजब करते हैं, खासकर इसी बेरमो में। देहातों में जाइये तो पानी पीने के लिए कुएं भी नदारद। किसानों को धान के खेतों से या नदी-नालों से ही बरसात में भी पानी पीना पड़ता है।

जंगल के कष्ट

खूंखार जानवरों से घिरे घोर जंगलों के बीच रहने पर भी यहां के लोगों को जंगलात के कानूनों के करते अपार कष्ट भोगने पड़ते हैं। यदि जंगल के छुटभैये नौकरों की पूजा ये लोग न करें तो नाहक ही इनके मवेशी कानी हौसों में डालकर इन्हें तबाह किया जाता है। पानी के झरने ज्यादा-तर रिजर्व जंगलों के भीतर ही होते हैं जहाँ पानी पिलाने के लिये मवेशियों को ले जाना जरूरी होता है। मगर जंगल के रक्षक लोग यह बात बर्दाश्त नहीं करते और पशुओं को कानी हौस में खामखाह डाल देते हैं। यह तो आये दिन की बात है। यह कोई नहीं सोचता कि आखिर इन्हें और इनके जानवरों को पानी तो पीना हीं है और उसे उन झरनों के सिवाय और कहीं ये पा नहीं सकते। पारसनाथ के पहाड़ की तली में चालू झरनों पर जबसे अहिंसक जैनी सेठों का अधिकार हुआ तबसे तो गजब हो गया। बिना पैसा दिये न तो उनके पानी से सिचाई हो सकती है और न दूसरा काम: कहा जाता है कि सर्वे खतियान में जो हक किसानों का नहीं है वह

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

कैसे मिले ? मगर सर्वे खतियान क्या इनसे पूछकर बनाया गया था ? क्या इन्हें पता भी था कि खतियान क्या बला है और उसमें क्या लिखा जा रहा या लिखा गया है ? एक ओर तो इन्हें उसकी जानकारी के योग्य बनाया न गया। दूसरी ओर उन्हीं एकतर्फा खतियानों के बलपर इनके सनातन अधिकार छीने जाते हैं ! यह बर्दाश्त के बाहर की चीज है और जितना शीघ्र ऐसे कागज पत्र सर्वसम्मति से जला दिये जाएँ उतना ही है अच्छा।

सालभर खाने के लिये यहां अन्न तो पैदा होता नहीं। सरकार और जमींदार इसकी कोशिश भी नहीं करते कि आवपाशी वगैरह का प्रबंध करके पैदावार काफी बढ़ाई जाय। ऐसी हालत में जंगली महुवा, गेठी, केना वगैरह खाकर ही यहां वालों को गुजारा करना पड़ता है। मगर जमींदारों ने उनपर भी रोक लगा रखी है और विना पैसा दिये उन फल फूलों के नजदीक इन लोगों को जाने नहीं देते ? यह फौरन खत्म होने की चीज है। जंगल के कानून में नए सुधार होने के कारण काठ बांस आदि लेने में और भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसी ही हजार कठिनाइयाँ हैं। इसीलिये बिहार प्रांतीय किसान सभा ने यहां के निवासियों के लिये कुछ चुनी मागें पेश की हैं। उनकी पूर्त्ति अविलम्ब हो जाने से इन्हें कुछ आराम मिल सकता है। वे मांगें आगे लिखी हैं।

झारखंडी किसानों की खास मांगें

(क)—घर गिरस्ती तथा जीविका चलाने के लिए उन्हें जंगलों और पहाड़ों से फल, फूल, कंद, मूल, साग तरकारी, शहद वगैरह रस, पत्थर, बालू, लकड़ी, बांस, कांट, कुश, जलावन, पत्ते, घास वगैरह लाने का पूरा अधिकार हो और उसमें कोई रोक टोक न कर सके। खेतों या जंगल में लगे महुवा के फूल और फल बेरोक चुनने का उन्हें हक हो और एतदर्थ उन्हें कुछ भी देना न पड़े।

(ख)—किसानों के खेतों या उनकी सीमापर लगे कुसुम, बेर, पलास, वगैरह पर लाह लगाने और चुनने का पूरा हक बिना और कुछ दिये किसानों

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

को हो और इसके विपरीत सर्वे वगैरह में लिखी बातें रद्द कर दी जायँ।

(ग)—टंगकर, बनकर, पतकर, चुल्हकर, खरचरी, भैसौंधा आदि के नामों से लगे कर या होनेवाली वसूलियां नाजायज करार दे दी जायँ।

(घ)—किसानों और उनके पशुओं के पीने वगैरह के लिए शुद्ध जल का जरूरत के अनुसार स्थान स्थान पर कुएँ आदि के जरिये पूरा प्रबंध किया जाय। सोते, झरने आदि जहाँ कहीं भी हो वहाँ उन्हें और उनके पशुओं को बेखटके आने जाने की पूरी व्यवस्था कर दी जाय और रास्ता बना दिया जाय।

(ङ)—एकएक करके सभी कानीहौस, अड़गड़े या कैटल-पाउंड जल्द हटा दिये जायँ।

(च)—कोड़कर और उटकर जमीनें तैयार करने का निरावाध हक किसानों को रहे और इस वारे में जो भी शर्त्तें या रोक अबतक हों सभी रद्द कर दी जायँ।

(छ)—संथाल परगने के दामिन कोह इलाके के पहड़िया किसानों के लिए कुरांव या झूमचास की पूरी आजादी बराबर कायम रहे और उसमें जो भी रुकावटें हों वे फौरन उठा ली जायँ।

(ज)—कोड़कर और उटकर जमीनों के तैयार हो जाने के कम से कम पांच साल बाद ही उनका लगान तय हो और वह आसपास की सबसे कमजोर जमीनों के लगान से ज्यादा हर्गिज न हो। आमतौर से वह आधा ही हो।

(झ)—यहाँ का लगान सरकारी मालगुजारी से ३०-४० गुना होने के कारण वह वहुत ही कम कर दिया जाय।

(ञ)—यहाँ का कास्तकारी कानून बिहार कास्तकारी कानून जैसा ही हो और उसमें आदिवासियों के खास लाभ की ही बातें विशेष रूप से जोड़ी जायँ। मगर जमींदारों के लिए कोई भी खास अधिकार न रहे।

(ट)—सेवकाई, कमिऔती, कमिया आदि नामों से प्रचलित गुलामी-प्रथा का नामो-निशान सख्ती के साथ मिटा दिया जाय।

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

(ठ)—आदिवासियों और पिछड़े लोगों की अपनी भाषा में उनको शिक्षित करने के लिये स्कूल वगैरह खोले जायँ और हर तरह की ऊँची शिक्षा मुफ्त देने का प्रबन्ध किया जाय।

(ड)—आदिवासियों एवं पिछड़े लोगों की भाषा तथा रस्म रिवाजों के जानकार हाकिम हीं उनके केसों का फैसला करें ऐसी व्यवस्था की जाय और कचहरियों में काम करने वाले वकील-मुखतार आदि पर ऐसा नियंत्रण रखा जाय कि वे उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी में न डाल सकें।

(ढ)—इनके लिए जो कानून या व्यवस्था बने उसका मुस्तैदी के साथ उनमें बखूबी प्रचार करके उन्हें अच्छी तरह समझाने का प्रवन्ध हो।

(ण)—अबरक को चुन तथा खोद-निकाल कर जीविका करने वाले ग्रामवासियों के रास्ते की सभी रुकावटें फौरन हटा ली जायँ और कोयले की खानों के ऊपर की जमींनों की खेती-बारी में होनेवाली किसानों की सभी दिक्कतें दूर कर दी जाएँ।

(त)--एक से ज्यादा जुडिशियल कमिश्नर मुकर्रर किए जायँ ताकि मुकदमों के फैसले में ज्यादा देर न हो।

मजदूरों की बात

आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ के कारखानों और खानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में भी दो चार शब्द कह देना चाहते हैं। ये मजदूर बहुत ही शोषित और पीड़ित हैं। न तो इनके रहने का ठिकाना है और न खाने का। खानों के मालिक और ठेकेदार इन्हें नर्क की जिन्दगी गुजारने के लिये विवश करते हैं। गिरिडीह, बेरमो, तातानगर, झरिया सर्वत्र एक ही बात है। एक तो वेतन कम है। फिर हजार बहाने बाजी करके उसमें कटौती की जाती है। ओवर टाइम काम के लिये मजदूरों को हर तरह से विवश किया जाता है। महँगाई के भत्ते को जैसे तैसे करके मैनेजर और ठेकेदार हड़प लेते हैं। कहते हैं कि ग्रेनशौप में अन्न कम तौला जाता है। दूकान पर भीड़ इतनी होती है कि कोई ले नहीं सकता। मजदूर परीशान हो जाते

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0: In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

हैं। तेल, साबुन और चीनी का तो मिलना ही कठिन है। पानी की भी दिक्कत होती है। क्योंकि काफी नलों और टंकियों का प्रबन्ध नहीं रहता। हमेशा कोशिश यही रहती है कि सस्ते मजदूर भर्त्ती किये जायँ। प्रतिदिन चार छे आना देकर भी इस महँगी के जमाने में काम करवाने का यत्न होता ही रहता है। ऐसी ही हजारों मुसीबतें हैं।

उनके दूर करने का एकही उपाय है कि मजदूरों की यूनियनें स्थान स्थान पर बनें, उनमें हरेक मजदूर अवश्य शरीक हो और मेम्बर बनें और इस तरह यूनियनें खूब मजबूत बनाई जायं। जो यूनियन पहले से बनी है वह मजदूरों का गढ़ है, किला है। उनका कर्त्तव्य है कि उसे अभेद्य, अच्छेद्य बनायें और उसके हुक्म पर मर मिटने को तैयार हों। मजदूरों और किसानों का एकही बल है और वह है उनकी अपार संख्या। यदि एक सूत्र में बंधकर काम करें तभी वह संख्या उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति दिलायगी। इसलिए हमेशाही "दुनिया के किसान मजदूरो एक हो जाओ" का नारा उन्हें बुलन्द करना होगा और उसी के अनुसार अमल करना होगा।

जमींदारों की होली

मगर यह बात नहीं है कि सिर्फ झारखंडी किसान हीं कष्ट में हैं। किसानों की सर्वत्र एक ही दशा है और सभी दुखिया हैं। खासकर बिहार के हर जिले के किसान बेहद पामाल और परीशान हैं। जमींदारों ने इन्हें कसकर बेरहमी से लूटा है और वह लूट बराबर जारी है। ये जमींदार किसानों की जान, माल और इज्जत के साथ बराबर होली खेलते रहे हैं। बेशक सन् १९४२ ई० के अगस्त के बाद यह होली भीषण हो गई है। इसमें सबूत की जरूरत नहीं है। कोई भी निष्पक्ष और सहृदय आदमी गांवों में जाकर तथा ये शर्मनाक और दर्दनाक बातें जानकर अपना कलेजा मसोस देगा। अगर ये जमींदार किसानों को भी इन्सान समझते तो यह बात न होती। मगर उनकी नजरों में—नहीं नहीं उनके मामूली से मामूली अमलों की नजरों में भी—ये किसान कीड़े मकोड़ों से भी गये गुजरे हैं।

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

इनमें भी तथा कथित छोटी कौम के किसानों का तो कुछ कहिये मत। उनकी तो सारी कमाई लूट ही ली जाती है हजार बहाने करके। हरी, बेगारी, दूध, दही, तरकारी, पाठी, पाठा के रूप में उनका खून बराबर ही नश्तर के जरिये निकाला जाता है। फिर वे सर उठायें तो कैसे? मगर पाप का घड़ा भर चुका है और ये किसान एक दिन खामखाह जम के सर उठायेंगे, सो भी जल्दी ही। फिर तो जालिमों की अंतड़ी ही सूख जायेगी याद रहे। दुनिया का इतिहास यही बताता है। फ्रांस और रूस में ऐसा ही हुआ है। सोलहवें लुई और जार निकोलसको देवता तथा खुदा को तरह मानने वाले किसान-मजदूर ही उनके खून के प्यासे बन गये! क्यों? इसी निर्दय शोषण से ऊबकर ही तो? और वही शोषण यहां भी चालू है।

जमींदारी का खात्मा

निराशा की काली घटा के बीच आशा की किरण झलक रही है और वह यह है कि अब सबों ने मान लिया है कि जमींदारी प्रथा हमारे देश के लिये भारी अभिशाप है, बला है, प्लेग है, महामारी है, टी० बी० है और न जानें और क्या क्या है। यह बात घुमा फिरा के, तथा सीधे भी, अंग्रेज बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं, कारखानेदार बोलते हैं और कांग्रेस भी बोलती है। एक समय था, जब हम किसान सभा वाले ही "जमींदारी प्रथा नष्ट हो" का नारा लगाते थे, जिससे हमारे नेतागण चिढ़ते थे और जमींदार मुंह बना देते थे। इस बात की मखौल उड़ाई जाती थी कि ये लोग जमींदारी मिटाने चले हैं! मगर आज तो हवा ही बदल गई है। सभी लोग इस पाप से मुल्क का पिंड जल्द छुड़ाना चाहते हैं। यह हमारी और किसानों की बहुत बड़ी जीत है। ऐसा कहने सोचने वाले मानने लगे हैं कि यदि यह जमींदारी कलम की नोंक से न मिटाई गई तो तलवार की नोंक से मिटाई जायगी जरूर।

सर्वसोखन सिंह

जमींदारों को मैं सर्व सोखन सिंह और कुंभकर्ण कहा करता हूं; क्योंकि उनका पेट कभी भरता ही नहीं, चाहे जितना भी मिले। मगर जमींदार

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0: In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

इससे चिढ़ते हैं। मैं उनसे अदब से कहूंगा कि वे और खासकर इस झारखंड के जमींदार बिहार सरकार की सन् १९३०-३१ वाली रिपोर्ट पढ़ें जिसके ८० वें पृष्ठ में लिखा है कि "छोटानागपुर के जमींदार प्रतिवर्ग मील सिर्फ सात ही रुपये सरकार को माल्गुजारी देते हैं"—"but in Chota Nagpur, where the permanently-settled estates cover 24000 square miles, the revenue is only Rs. 7 to the square mile". क्या गजब है ! इन जमींदारों ने इस स्वर्णमयी भूमि के पूरे चौबीस हजार वर्गमील पर दखल जमा रखा है और अबरक, कोयला, लोहा, पहाड़, जंगल से करोड़ों रुपये नोचते हैं। मगर सरकार को देते हैं मुश्किल से केवल डेढ़ लाख के करीब ! फिर भी ये यदि सर्व सोखन सिंह और कुंभकर्ण नहीं हैं, तो आखिर हैं क्या ? खुशी की बात यही है कि इनकी यह लूट जल्द मिटने को है, जमींदारी जल्द ही मिट जाने को है।

मुआविजा देकर ?

कहा जाता है कि कीमत या मुआविजा देकर ही इस जमींदारी को मिटाया जायगा। अच्छी बात है। मिटाया जाए। मगर हमारी तो बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि यह कैसे संभव है। अबतक इस मसले पर जिनने विचार किया है उनकी बातें हमने जानने की भरपूर कोशिश की है। उससे हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसा करने में पचासों साल—हां, पचासों साल—लगेंगे। "जमींदारी का खात्मा कैसे हो" पुस्तिका में, जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में छपी है, हमने यह बात दिखाई है। खूबी तो यह कि उसके लिये पचीसों अर्ब रुपये चाहियें। तभी समस्त भारत से यह जमींदारी की बला भागेगी। और इतने रुपये ऋण लेकर यह काम करने में शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार आदि की सारी योजनाएं योंही पड़ी रह जायंगी। जिन लोगों ने इसकी तह में घुसकर विचारा है हम उन्हीं की राय बता रहे हैं, नकि अपनी। हमारा अनुरोध है कि जमींदारी मिटाने के प्रेमी सज्जन हमारी वह पुस्तिका प्रान्तीय किसान सभा के ओफिस, कदम कूआं,

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

पटना से छे आने में खरीद कर जरूर पढ़ें । हम मानते हैं कि बिना मुआविजा दिये कानून के जरिये जमींदारी मिटाई नहीं जा सकती है। यह विकट समस्या है जरूर। मगर इसका सीधा और आसान रास्ता हमने उसी पुस्तिका में सुझाया है। हालाँ कि हमतो जमींदारों के लिये एक पैसा भी मुआविजा देना पाप मानते हैं। किसान ही जमीन के असली मालिक हैं। उन्हीं के हाथ में जमीन थी। लार्ड कार्नवालिस ने ब्रिटिश सत्ता और कारबार को मजबूत करने के लिये जमींदारों का वर्ग पैदा किया और किसानों की जमीन बेरहमी से छीनकर उन्हें दे दी। न्याय का तकाजा है कि हम भी मौका पाते ही फिर उसे छीन लें। यदि उन्हें मुआविजा दें तो अंग्रेजों को भी अपनी सल्तनत यहां से हटाने के लिये मुआविजा क्यों न दें ? अगर जमींदारों ने लगातार डेढ़ सौ साल तक किसानों की जमीनों पर बलात् कब्जा रखा है तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर दो सौ साल तक जबर्दस्ती अधिकार रखा है। इसलिये कीमत और मुआविजे की बात वाहियात है।

बकाश्त-संघर्ष।

चाहे जमींदारी मिटे या न मिटे और चाहे इसमें कितनी हीं देर क्यों न हो। मगर एक बात बड़ी तेजी से हो रही है और होके रहेगी। जिन जमीनों पर किसानों के दखल कब्जे का कागजी सबूत नहीं है उन्हें बड़ी तेजी से ये जमींदार छीनने लगे हैं। शिकमी और बकाश्त जमीनों के सम्बन्ध में यह बात हो रही है और इसकी खबरें चारों ओर से आ रही हैं। अभी अभी गया जिले के हसुवा थाने के सिनुवारी मौजे में जो एकाएक किसान-जमींदार संघर्ष छिड़ गया है और जिसकी खबर हमें पीछे से लगी, उसका भी यही रहस्य है। बंगाल के फ्लाउड कमिशन ने जमींदारी मिटाने का प्रश्न तेजी से छिड़ने पर इस बात का होना लाजिमी बताया है कि बटाई-दारों की जमीनें छीन ली जायंगी। इसलिये यह कोई नई बात नहीं है। जमींदारी मिटाने का अर्थ यही है कि जो जमीन जमींदार खुद नहीं जोतता वह उससे छिन जायगी। इसीलिये शिकमी और बकाश्त जमीनों के बारे

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

में जमींदारों की कोशिश है और होगी कि वह किसानों से निकल जाय। फलतः बकाश्त संघर्ष बड़ी तेजी से छिड़ेंगे, चाहे हम उनके कितने विरोधी हों। आखिर किसान जमीनें छोड़ दें तो जायं कहाँ और खायें क्या? कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों को यह ठोस सत्य मद्दे नजर रख कर ही कुछ कहना करना होगा। केवल किसान सभा को बदनाम कर देने से काम न चलेगा। बदनाम करने से तो अच्छा है कि वह जमीनों की छीना झपटी के रोकने का उपाय समय से पहले कर दें। सभा ऐसा कर रही है या किसान नाजायज कर रहे हैं, ऐसा कहने मानने से पहले जरा ये नेता और मंत्रीगण सोच तो लें कि ऐसी परिस्थिति में यदि वे खुद किसान होते और उनकी जमीन छिनी जाने लगती जिससे पूरे खान्दान को फाके की नौबत आती, तो क्या करते। बकाश्त जमीनों पर सपरिवार जा डंटते और संघर्ष छेड़ते या नहीं? यदि यही प्रश्न हम सबों की आंखों के सामने नाचता रहे तो इस मामले में किसानों या किसान सभा को कोसने से लोग बाज तो जरूर ही आयें। किसान सभा के बारे में हम साफ कह देते हैं कि वह लुका चोरी खेलना नहीं जानती। वह तो जब इसमें पड़ती है तो ताल ठोंक के। आज जो कुछ जमींदार कर रहे हैं यदि वह रोका न गया तो हमें और सभा को इसमें मजबूरन पड़ना हीं होगा। क्योंकि हम किसानों को रही सही जमीनों की बेदखली और जमींदारों की ज्यादती देखकर आँखें मूंद नहीं सकते और न किसानों को दर दर के भिखारी और डाकू चोर बनने दे सकते हैं। जमीनें छिन जाने पर आखिर वे और करेंगे ही क्या?

काश्तकारी कानून की काया पलट

आज काश्तकारी कानून की हालत यह है कि किसान विवश हैं और जमींदार मनमानी घर जानी करते हैं। किसान कुछ कर नहीं सकते। खासकर भावली के किसान तो लुट जाते हैं। जो जमीनें रेहन में किसी महाजन को देते हैं वे उनसे आखिरकार प्रायः छिन ही जाती हैं। दफा ६९ से भावली वालों की जरा भी रक्षा नहीं होती। यह रोज का अनुभव है। दफा

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

१७१ के अनुसार महाजन खेत की पैदावार भी खाता है और उसका पावना किसान के मत्थे सूद के साथ बढ़ता जाता है। यदि खड़ी फसल को जमींदार खेत या खलिहान में ही सड़ा डाले तो किसान कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह की हजार दिक्कतें हैं। इसलिये कांग्रेस मंत्री और सरकार उसकी कायापलट कर डालें, सो भी जल्द से जल्द। तभी खैरियत है। एतदर्थ कानून का नया मस्विदा ऐसे वकीलों की एक कमिटी के पास भेजा जाना जरूरी है जिनने किसानों की दृष्टि से इस कानून की बुराइयों को अच्छी तरह देखा है। वह कमीटी जो राय दे उसी के अनुसार कानून बनना चाहिये। मगर हर हालात में भावली को कानूनन नाजायज करार देना ही होगा। हमारा यह भी पक्का विचार है कि समस्त विहार के लिये अब एक ही काश्तकारी कानून चाहिये। उसीमें झारखंडी किसानों के लिये कुछ आवश्यक बातें दी जायँ जिससे उनकी विशेष रक्षा हो सके।

ऊखकी कीमत

विहार में धीरे धीरे चीनी की मिलें बन्द होने लगी हैं। एक दो बन्द हो चुकी हैं। एकाध मरण शय्यापर पड़ी ऊर्ध्व साँस ले रही हैं। चीनी की पैदावार क्रमशः घट रही है। इसीलिये कि काफी ऊख मिलों को नहीं मिलती। क्योंकि आज जब गल्ले को घोर महंगी है ऊख की कीमत फी मन दो रुपये से कम नहीं चाहती थी। मगर सरकार ने एक रुपया भी नहीं रखा और उसमें भी दो आने मन की कटौती करने की नादानी की थी। नतीजा सामने आया। किसान सभा यही बात बराबर रटती थी। पर सुने कौन? खैर कांग्रेसी सरकार इस भारी भूल को सुधारे, ऊख का दाम दो रुपये नई फसल बोने के पहले ही घोषित करे और एक कमिटी बनाकर उसके सामने यह प्रश्न रखे कि वह हमेशा ऊख की कीमत वैज्ञानिक ढंग से तय की जाने का आधार बताये। मनमाने ढंग से दाम रखना खतरनाक है। वह कमिटी ऐसी हो जिसमें किसान सभा का विश्वास हो और जिसमें उसके प्रतिनिधि हों।

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

मंत्रि मिशन की घोषणा

इंगलैंड से भारत में पधारे मंत्रिमिशन पर हमारा कभी विश्वास नहीं रहा है और न है। हम मानते हैं कि आजादी छीनी जाती है, लड़कर वापिस ली जाती है। न कि किसी की दया, नेकनीयती और दूरंदेशी से मिलती है। राजनीति में नेकनीयती और ईमानदारी को स्थान नहीं है, यह कटु सत्य हम जितना शीघ्र मान लें उतना ही अच्छा। इसलिये हम मानते हैं कि ब्रिटिश मंत्रियों की घोषणा के जाल से बचने में ही भारत का कल्याण है। घोषणा का जो अन्तिम रूप गत १६ वीं जून को हमारे सामने आया है वह तो कांग्रेस की फांसी और मिस्टर जिन्ना की गद्दी है। यह हमारी पक्की धारणा है। हमने निहायत ही गौर से सारी बातें शुरू से आजतक पढ़ीं और विचारी हैं। हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिना लड़े कुछ होने जाने का नहीं, हमारे प्रभु हमें कुछ दे नहीं सकते—"सूच्यग्रं नैव दातव्यं विना युद्धेन केशव"। अतः हमें उसी की तैयारी अभी से करनी है। आशा है हमारे राष्ट्रीय नेता इस भारी धोखे से बचेंगे और हमें ठीक राह दिखायेंगे। कांग्रेस बड़ी है, महान है और वह हमेशा ही ऐसी ही रहेगी, ऐसी हमारी धारणा है।

किसान सभा

किसान सभा एक है, अखंड है। यह किसानों का किला है। इसे हर तरह से तन, मन, धन से दृढ़ बनाना हर किसान का पहला और पवित्र कर्त्तव्य है। हर बालिग स्त्री पुरुष एक आना पैसा देकर इसका सदस्य बने, गांवों से लेकर ज़िले और प्रान्त तक इसकी शृंखला कायम करके खुद उसी शृंखला में बंध जाय और इस तरह इसे अजेय और अभेद्य बना छोड़े। युवक स्त्री पुरुष किसान सेवक दल में लाखों की तादाद में भर्त्ती हों और किसान-कोष में अन्न धन के रूप में अपार निधि जमा करें। फिर वे देखेंगे कि किसान-मजदूर राज्य शीघ्रही कायम हो जयगा, पंचायती राज्य स्थापित हो जायगा, शोषण मिट जायगा और इनकिलाब हो जायगा, क्रान्ति हो जायगी। इनकिलाब जिन्दाबाद; किसान सभा जिन्दाबाद, जय हिन्द।

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

मुद्रक—रामेश्वर सिंह,
ओरिएण्टल प्रेस, पटना

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

६ वां

बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन

सभापति

स्वामी सहजानन्द सरस्वती

का

भाषण

शेरघाटी, गया।

५, ६ अप्रैल ४२

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgac

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

हमारे साथी—ये और वे !

किसान बन्धुओ,

आज दो साल के बाद आपके सामने खड़े होने में जो खुशी हो रही है उसे आपको कैसे बताऊं, आपके सामने कैसे जाहिर करूं ? मुझे क्या पता था कि एकाएक आपकी इस कान्फ्रेंस का अध्यक्ष, इसका सदर मुझीको होना होगा ? मैं तो सोचता था कि जेल की पथरीली चहार-दीवारी के भीतर बैठे बिठाये ही इसकी खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलेंगी। क्योंकि मेरी तीन साल की मीयाद तो अभी तीन चार महीनों के बाद ही पूरी हो पाती। मगर अचानक रिहाई ने यह हालत पैदा कर दी ! रिहाई के बाद भी मैं इस काम से भागता था और चाहता था कि आपके वही सेवक यह बोझ बर्दाश्त करें जो मेरी और बहुत से मेरे साथियों की गैरहाजिरी में आपकी खिदमत अपनी ताकत भर करते रहे हैं और जिनने बिहार प्रान्तीय किसान सभा का शानदार झंडा झुकने नहीं दिया है। पिछले दो साल न सिर्फ मुल्क और दुनिया के इतिहास में, उसकी तवारीख में, बल्कि किसान सभा के इतिहास में भी, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण रहे हैं। हमारी उस प्यारी सभा को इस दर्म्यान भीतरी और बाहरी—दोनों ही—

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

जोरदार हमलों का सामना करना पड़ा है। जबकि मेरे साथ ही यदुनन्दन शर्म्मा, कार्यानन्द शर्म्मा और राहुल सांकृत्यायन जैसे आपके तपे-तपाये सेवक आपसे और हमारी सभा से बेरहमी के साथ अलग कर दिये गये थे, ठीक उसी समय हमारे कुछ गिने-चुने पुराने साथियों ने एक ही साथ सभा पर और इसलिये आप पर भी धावा बोल दिया। पहले जमाने में यह अनहोनी बात मालूम पड़ती थी कि तपे-तपाये किसान-सेवकों के साथी किसान सभा और किसानों पर धावा बोल दें। यह बात कुछ उलटी भी मालूम पड़ती है। मगर यह जमाना ही ऐसा है कि अनहोनी होके ही रहती है। आखिर साथी भी तो सभी तरह के होते हैं न? कौन जानता था कि ये साथी ऐसे बगुला भगत हैं जो समय पर धोखा देंगे? अगर वे थे ऐसा मौके की ताक में कि जब हमारे ऊपर बताये साथी आपसे अलग हो जायं तो वे अपनी असली सूरत जाहिर कर दें। उनने यही किया भी। मगर खुशी यही है कि कामयाब न हो सके। आपने और आपके बचे-खुचे सच्चे सेवकों ने उन्हें फौरन पहचान लिया, जिससे उनके चकमे में आ न सके। मुझे इस बात का सचमुच फख्र और गर्व है कि जिस किसान सभा के बनाने में हमने, हमारे सच्चे साथियोंने और आपने अपने खून को पानी बनाया वह ऐसी नाजुक घड़ी में भीतरी और बाहरी सभी तरह के दुश्मनों के हमलों को मुस्तैदी से बर्दाश्त करके इस मुद्दत में धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ती ही गई। यह सोचके आपके और उन साथियों के भी सामने हमारा

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

सर झुक जाता है जिनने इस दुहरे हमले और तूफाने-बदतमीजी का- बेहूदी हरकतों का—सामना शान के साथ बहादुराने ढंग से किया है। मैं तो इसी यकीन के साथ जेल गया था कि मेरी गैरहाजिरी में भी हमारी किसान सभा आगे बढ़ती ही जायगी। अखबारों के लिए मैं ने यही बयान दिया भी था। मुझे बेहद खुशी है कि मेरा यह यकीन सच्चा साबित हुआ और दुश्मनों और गद्दारों के मंसूबों पर पानी फिर गया।

इसी लिए बाहर आने के बाद भी मेरी दिली ख्वाहिश थी और मंसूबे बांधता था कि शंघघाटी में उन्हीं बहादुरों में किसी के सर पर सदारत का सेहरा बंधे, गले में अध्यक्षता का माला पहराई जाय और मैं दिल में इसकी खुशी मनाऊं। मेरे लिए कितने फख्र की बात होती और दुश्मनों का इसमें कितने तमाचे पर तमाचे लगते! मगर अफसोस कि मेरा यह दिली अरमान पूरा न हो सका और साथियों ने मेरा मजा किरकिरा कर दिया। एक-एक करके सबों ने, मेरी रिहाई के बाद ही, इससे साफ इनकार करने के साथ ही मुझी पर जोर दिया कि इस बार मैं ही सभापति बनूं। इसके लिए उन्हें कोसूं, शाबाशी दूं या क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। उनके इस निराले ख्याल ने, "नान-को आपरेशन" ने एक अजीब हालत पैदा कर दी। उनकी इस अनोखी गुट्टबन्दी ने मुझे मजबूर कर दिया और लाचार मैं आपके सामने खड़ा हूं। यही नहीं कि उनने इस अध्यक्षता और सदारत से साफ इनकार कर दिया

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

बल्कि फौजी हुकुम और मार्शल आर्डर भेजा कि मुझी को यह काम करना ही पड़ेगा। इसीलिये इनकार भी नहीं कर सकता था। क्योंकि तबतो "कोर्ट मार्शल" होता, जिसके लिए मैं तैयार न था। मुझे यह साफ कबूल करने में जरा भी हिचक नहीं कि आपके इस फौजी हुक्म, साथियों के निराले नान-कोआपरेशन, विचित्र असहयोग और सबों की दिली मुहब्बत के सामने सर झुकाने के अलावा मेरे लिये दूसरा चारा थाही नहीं। ऐसे साथी दुनिया में शायद ही किसी खुश-किस्मत को मिलते हैं जो मेरे जैसों को इस तरह अपना गुलाम बना लें। ऐसी हालत में अगर सभापति बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद नहीं देता और आपका शुक्रिया अदा नहीं करता तो इसके लिए मैं कसूरवार कतई नहीं हो सकता। क्योंकि आप इसके हकदार हईं नहीं। हां, एक बात के लिए बेशक मैं सबों को और खासकर अपने साथियों को तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनने सर्व-सम्मति और मुत्तफिक आवाज से मुझे जबर्दस्ती इस जगह पर खड़ा करके हमारे नये और पुराने दुश्मनों के उस हौसले पर पाला डाल दिया जो अभी अभी उनके दिलों में ताजा-ताजा ही होने लगा था यह खयाल करके कि किसान सभा में फूट और दल-बन्दी होने जा रही है। उफ, आज उन बेचारों के दिलों पर कैसी गुजरती होगी?

हम क्या करने जा रहे हैं?

गुजश्ता दो-तीन साल के भीतर दुनिया कहां से कहां चली

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

गई ! कितने मुल्कों के नक्शे बदल गये ! कितनों की आजादी छिनी ! कितने मिट्टी में जा मिले ! और कितने के सर गुलामी और पामाली की 'बला की नंगी तलवार कच्चे धागे में बंधी लटक रही है, उस पर तेज हवा के झकोरे पर झकोरे लग रहे हैं और अब गिरी तब गिरी की हालत हो रही है। ये तो ठोस बातें हैं, आंखों देखी और कानों सुनी चीजें हैं। मगर इस दर्म्यान हमने क्या कुछ कम सबक सीखा है ? इतना सीखा है जितना पहले के जमाने में शायद हजारों साल में भी नहीं सीख पाते ! फिनान्स कैपिटल और उसकी नंगी सूरत फासिज्म, नात्सीज्म और मिलिटरिज्म, 'या यों कहिये कि कोरी और सोलहों आना जंगी हुकूमत क्या बला है इस बात की करारी जानकारी हमें इसी मुद्दत में हो सकी है। सब से ताज्जुब की चीज तो है इसका जादू जो हमारे सर पर सवार है। इस फासिज्म का जवाल और सत्यानाश हमारे सामने खड़ा है और हमें निगल के हमारी हस्ती मिटाने पर तुला बैठा है। फिरभी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। इसी को कहते हैं कि जादू वही जो सर पर चढ़के बोले। माफ करना मेरी साफ बातों के लिए। हममें बहुतेरे आज जोरों से चिल्ला चिल्ला के आसमान फाड़ते हुए कहते पाये जाते हैं कि "साम्राज्यवाद, शाहंशाहियत या इम्पीरियलिज्म और फासिज्म बराबर हैं, अगर दूसरा बुरा है तो पहला भी कम खराब नहीं है"। अगर इसके ये मानी हों कि हम दोनों से ही सजग रहें क्योंकि दोनों ही हमारे लिए खतरनाक हैं और हमें धोके में डालने की उनमें लासानी ताकत हैं, तबतो ठीक ही था। इस बात में तो दो

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

जायें हो सकती हैं नहीं। हमें तो दोनों को ही मिटाना है। सवाल सिर्फ है आगे पीछे का। मेरा तो ख्याल है कि फासिज्म के मिटाने के लिए जो जंग हम करेंगे वही साम्राज्यवाद को भी मिटानेवाला होगा। मगर बेहद तकलीफ तो हमें तब होती है जब इसके कहने का मंशा यह होता है कि हमारा सारा गुस्सा जो आज से पहले दोनों के ही खिलाफ था अब सिर्फ इम्पीरियलिज्म के खिलाफ हो जाये और फासिज्म को हम इस वक्त एक तरह से भूल जायें। अगर साफ लफ्जों में कहना हो तो इसके मानी यह हैं कि हम चर्चिल की हुकूमत की जगह हिटलर, मुसोलिनी या तोजो की हुकूमत पसन्द करें। ज्यादे से ज्यादा इसके यही मानी हैं कि हम सिर्फ यही सोचें कि ऐमरी और चर्चिल की सरकार चाहे जैसे हो यहां से नेस्तनाबूद हो जायें, और इसके बाद क्या होगा इसकी जरा भी परवाह न करें। यह बात सोचने की इस समय जरूरत समझें ही न। मगर है यह निहायत ही खतरनाक बात। यह तो ठीक जलते चूल्हे से निकल के जलती आंच की भट्ठी में जाने की बात है।

यही गलतफहमी न हो इसलिए साफ कह देना चाहता हूं। चर्चिल की सरकार यहां से चली जाय इसमें भला किस बदबख्त को मुखालिफत हो सकती है? हम बीसियों साल से इसीलिए तो बलिदान और कुर्बानियां लगातार करते आये हैं। फिर आज यह बात एकदम भूली या छोड़ी जा सकती है कैसे? मगर इसके बाद क्या हो, यही तो असली सवाल है? आजतक कांग्रेस

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

लीडरों से हम इसीलिए तो लड़ते हैं कि "इसके बाद क्या हो" का जवाब वे गोलमटोल देते रहे हैं, जिसका मतलब हमने ठीक ही यही लगाया है कि वे हिन्दुस्तान के जमींदारों और सरमायेदारों —पूँजीपतियों—की ही सरकार यहां कायम करना चाहते हैं। हम इस बात को न तो बर्दाश्त कर सके हैं और न करते हैं। हमें यह खयाल ही बागी बनाये डालता है। यह वजह है कि हमने खुले आम बराबर इस बातको मुखालिफत की है, जिसके चलते हममें जाने कितने ही कांग्रेस के बागी करार दिये गये हैं। फिर भी हमने पर्वाह नहीं की है। इसीलिए कहता हूं कि हमारे सामने दर असल अहम सवाल यही है कि इसके बाद क्या हो। और अगर अबतक चर्चिल की सरकार की जगह हमने हिन्दुस्तानी मालदारों की हुकूमत का खयाल तक बर्दाश्त नहीं किया है, तो आज क्या हो गया है कि हिटलर और ताजो की नादिरशाही का स्वागत और इस्तकबाल करने को, फिर चाहे छिपे लुके और चोरी चोरी ही क्यों न हो, तैयार हो जायें? क्या वजह है कि हमसे इसकी उम्मीद भी की जाये? क्या हमने आज तक ईमानदारी से काम नहीं किया था, जिससे हमसे ऐसा सोचने की उम्मीद की नादानी की जाती है? और अगर हमसे कोई यह कह दे कि आज चर्चिल के बाद यहां हिटलर या तोजो न आयेंगे तो हम यही कहेंगे कि या तो वही पागल है या हमी। जो ऐसा सोचते हैं वह दूरकी कौड़ी लाते हैं। जिस चर्चिल को हम बावजूद अपनी पचासों साल की सर तोड़ कोशिश और कशमकश के हरा न सके, यहां से हटा न

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

सके, उसीको हटाके, हरा के यहां ताजा ताजा ही आनेवाले हिटलर या तोजो को हम पचास या सौ साल में भी हरा सकेंगे, यह कोरी अफीमची की पिनक है ! कोरिया और फारमोसा वालों से ही क्यों नहीं पूछ के हम अपनी अक्ल दुरुस्त कर लेते कि चीन के मंचू राजाओं को हटाके वहां जा धमकने वाले तोजो और उसके मुरिसों से पल्ला छुड़ाने का खयाल करना भी कितनी बड़ी नादानी है ? मैं तो यही समझता हूं कि कांग्रेस के जरिये बृटिश सरकार को हटाके जिन जमींदारों और मालदारों की सरकार यहां हो सकती थी उससे लाखगुनी खतरनाक और खूंखार जमींदार-मालदारों की सरकार ही यहां बनेगी अगर चर्चिल को तोजो ने हटा पाया। फिर हमारा दिल-दिमाग उसे सोचे भी कैसे ? जब तक सिर्फ मिटाने की बात हम सोचते हैं तब तक तो नहीं, मगर ज्योंही कुछ बनाने की बात सोचते हैं त्योंही यह पहेला हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हां, पहेली नहीं, पहेला। और मैं चाहता हूं कि हम इस पर अच्छी तरह गौर करें। मैं साफ कहे देता हूं कि यह सिर्फ बृटिश सरकार के मिटाने का सवाल न होके कहीं बड़ा और अहम मसला है, उसकी जगह कुछ बनाने का सवाल है और इसी "कुछ" में खतरा है, जोखिम है। क्योंकि हम इस नये सिरे से बनने या बनाये जानेवाले "कुछ" से पूरे बेखबर हैं।

कहते हैं कि एक सीधा सादा माता की मुहब्बत वाला देहाती नानिहाल जाने लगा तो उसकी मां ने उसे कुछ पैसे

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

देके कहा कि रास्ते में भूक लगने पर कुछ खरीद के खा लेना। और उसे रवाना कर दिया। चलते चलते दोपहर के वक्त उसे तेज भूक लगी। इतने में एक बड़ा बाजार आ गया। खुशी-खुशी वह एक हलवाई के पास गया और पूछने लगा कि तुम्हारे पास कुछ है जिसे मैं खा सकूं। दूकानदार ने उत्तर दिया कि पूड़ी, मिठाई वगैरह सभी चीजें हैं, जो चाहो लेलो। इस पर निराश होके दूसरे के पास गया, यही सवाल किया और जवाब भी उसे यही मिला। लाचार वह तीसरे, चौथे वगैरह सभी के पास एक के बाद दीगरे गया और सभी जगह एकही सवाल-जवाब होता रहा। वह बेचारा भूक से परीशान था और उसे सूझता ही न था कि क्या करे। इतनेमें एक काइयां दूकानदार को शैतानियत सूझी। वही आखिरी था जिसके पास वह देहाती गया। उसे उम्मीद तो कतई थी ही नहीं कि खाने को कुछ मिलेगा। मगर उसके अचम्भे का ठिकाना न रहा जब उस काइयां ने चटपट कह दिया कि हाँ, जरूर कुछ है। फिर क्या था ! उस देहाती का चेहरा खिल उठा और उसने पास के पैसे आगे बढ़ाये। दूकानदार ने पैसे लेके जमींकन्द के कई टुकड़े उसे दिये और कहा कि यही कुछ है, लेजाओ और खाओ जब उस बेचारे ने लेजाके कहीं अलग उसे खाने की कोशिश की तो कच्चा जमींकन्द उसके गले को काटने लगा और भारी जलन पैदा करदी। नतीजा यह हुआ कि उसे फेंक के रवाना हो गया और जैसे तैसे नातेदारी जाके घर लौटा। लौटने पर मां से कहने लगा कि मां, तुम्हारी मुहब्बत के करते तुम्हारी बातें

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

मानके मैंने सिर्फ "कुछ" ही खरीदा। मगर वह तो बड़ा ही खराब था। पूछताछ करने पर मां को असलियत मालूम हो गयी और उसने अफसोस किया और कहा कि मैं तुम्हें ऐसा नादान नहीं जानती थी; नहीं तो 'कुछ' न कहके पूड़ी मिठाई वगैरह खास चीजें बता देती। मुझे डर है कि यहां हम भी देहातों के 'कुछ' की तरह गला काटने वाली चीज बनाने जारहे हैं। फर्क यही है कि यहां 'हमारी मां' तो अफसोस करने वाला है नहीं, हां जिसमें मुरव्वत है। इसलिए हमें खुद ही पछताना पड़ेगा, ऐसा अन्देशा मुझे है।

किसान सभा क्या चाहती है?

इधर अखबारों में बड़ा वावेला मचा है, कुहराम मचा है और कुछ पढ़े-लिखे नादान दोस्तों और दाना-होशियार-दुश्मनों को अच्छा मौका हाथ आ गया है कि हमें और हमारी सभा को बदनाम करें। बात यों हुई है कि आल-इंडिया किसान सभा की कार्यकारिणी ने जिसे सेंट्रल किसान कौंसिल कहते हैं, नागपुर में १३ फरवरी को इस मौजूदा लड़ाई और जंगे आजादी के मुतल्लिक एक लम्बा रेजोल्यूशन, बड़ा-सा प्रस्ताव पास किया। उन दिनों मैं हजारीबाग जेल की चहार-दीवारी के भीतर बन्द था। हमारी और आपकी सब से बड़ी बदकिस्मती तो यह है कि वह पूरा रेजोल्यूशन किसी भी अखबार में निकला तक नहीं और उसके जो चन्द चुने-चुनाये टुकड़े छपे उनसे सारी बातों की जानकारी हो सकी नहीं, हो सकती न थी। इसीसे

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgac

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

फायदा उठाके हमारे दुश्मनों ने हमारी सभा के खिलाफ जहर उगलना और हमें बदनाम करना शुरु कर दिया। उनको इस चाल में किसान सभा के कुछ सच्चे सेवक और सिपाही भी आगये। हालत यहां तक पहुंची कि हम और हमारी किसान सभा को ब्रिटिश सरकार का गुलाम और एजेन्ट तक करार देने की हिम्मत की गई और की जारही है। लोगोंने तो यहां तक कह डालने की जुर्रत की कि मैं खुद सरकार से माफी मांग के और उसकी मदद करने का वादा करके जेल से बाहर आया। इन भले मानसों को इतनी मोटी बात भी नहीं सूझी कि अगर दो साल लगातार रहके मैंने सरकार के सामने सर नहीं झुकाया तो सिर्फ तीन-चार महीनों के ही लिए ऐसा क्यों करता? उनने यह भी मुनासिब न समझा कि हजारीबाग जेल के ऑफिस या सरकार के दफ्तर में पूछकर देखें तो सही। सिर्फ एक अखबार ने पूछा और उसे यह बात गलत मालूम हुई तो उसने माफ़ी भी दी। मगर यार लोग फिर भी वही पुराना ताल-सुर अलापते ही रहे और हैं। मेरी रिहाई के हुक्म में साफ ही लिखा है, "फौरन बिना किसी शर्त्त की रिहाई" "Immediate and unconditional release"। आज भी जेल ऑफिस में पूछा जा सकता है। मगर जब असलियत जानने की नीयत हो तब न? इस बेहूदे और झूठे लोगों की शैतानियत पर मुझे हँसी भी आती है और गुस्सा भी होता है। उन्हें खातिरजमा रखना चाहिये कि मुझमें अभी इतनी हिम्मत बाकी है कि अगर ऐसी कोई भी बेहूदा, बदतमीजी वाली और मुल्क के साथ गद्दारी

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

की बात मैं करता तो साफ क़बूल कर लेता। उन्हें जान रखना चाहिये कि राजनीति, सियासत और पालिटिक्स न तो मेरा पेशा है और न इससे मेरी या मेरे लोगों की रोजी ही चलती है।

हां, तो अब जरा नागपुर के उस रेजोल्यूशन को देखें। उस की चार बातें ज्यादा अहम और महत्त्वपूर्ण हैं। पहली यह कि उसने साफ कह दिया कि फासिज्म, नात्सीवाद या जापान की फौजी हुकूमत को दुनिया से मिटाने के लिए किसानों को बेखटके रूस, चीन और उनके पक्षकी प्रगतिशील शक्तियों—उनकी तरक्की पसन्द दोस्त ताकतों—की कतार में खड़ा हो जाना चाहिये—"The Council, therefore, has no hesitation in exhorting the kisans of India to align themselves on the side of Russia, China and the allied progressive forces in waging a relentless war for the final extermination of Fascism."

इसमें रूस और चीन की मददगार सरकारों या मुल्कों का भी जिक्र न होके सिर्फ तरक्की पसन्द ताक़तों—"Progressive forces"—का ही जिक्र है और यह तो मानना ही होगा कि इंगलैंड और अमेरिका में भी प्रगतिशील शक्तियां या तरक्की पसन्द ताकतें हुईं जिन्हें किसान, मजदूर वगैरह कहते हैं। गोकि कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडरों तक ने इंगलैंड और अमेरिका या उनकी सरकार तक को प्रगतिशील और तरक्की पसन्द कह दिया है बमुकाबले फासिस्ट ताकतों के, फिर भी

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

हमारा रेजोल्यूशन तो यह भी नहीं कहता है। वह तो उन मुल्कों और उनकी सरकारों का नाम भी इस सिलसिले में नहीं लेता। फिर हमारे सर यह इलजाम थोपा जाता है कि हम तो अंग्रेजी सरकार की मदद करने की सलाह किसानों को देते हैं। जो लफ्ज हमारी जबान पर न हों और जो खयाल हमारे दिमाग में सपने में भी न हो उन्हें हम पर लादना ईमानदारी और भलेमानसी की हद है।

यही तो है हमारे रेजोल्यूशन का वसूली पहलू या सिद्धान्त का पक्ष जो इस लड़ाई के बारे में है। तो क्या हमारे दुश्मन यह चाहते हैं कि हम किसानों को रूस, चीन, और उनकी मददगार दुनिया की तरक्की चाहनेवाली ताकतों की कतार में खड़ा होकर फासिज्म और नात्सीज्म के खिलाफ जेहाद बोलने की राय न दें? यदि हां, तो हम यह बात न मानने को लाचार हैं, और यहाँ हमारा और उनका मेल ठीक उसी तरह गैरमुमकिन है, जैसे जमीन के उत्तरी-दक्खिनी ध्रुवों, पोलों या किनारों का।

अब रहा इस लड़ाई के मुतल्लिक हमारा अमली पहलू, हमारी व्यावहारिक, "प्रैक्टिकल" बात। क्योंकि वसूल और सिद्धान्त की सभी बातों पर हर वक्त अमल होना गैर मुमकिन होता है। असल में जुदी जुदी हालतों में जुदे जुदे काम हो सकते हैं। इसीलिए मौजूदा हालत में हम अमली तौर पर

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

या व्यावहारिक रूप में क्या कर सकते हैं इसके बारे में रेजोल्यूशन के आखिर में दस बातें लिखी गई हैं, जिनमें पहली बात है कि इस लड़ाई के मुतल्लिक जो किसान सभा का ऊपर लिखा वसूल है उसका प्रचार और प्रोपैगैंडा किसानों में किया जाय,— "Propagation of the new view of war outlined in this resolution." हम यह कह देना चाहते हैं कि लड़ाई के बारे में ऊपर लिखे वसूल की मजबूती के लिए बहुत सी बातें रेजोल्यूशन में हैं। इसलिए हमें उन सबों का प्रचार करना होगा। इसके अलावे दूसरी बात यह कही गई है कि रूस और चीन को जो भी मदद हम से मुमकिन हो, पहुँचायें और सोवियट रूस की दोस्ताना जमातें और मित्र मंडलियां जगह जगह कायम होने और करने में मदद करें–"Render all possible aid to Russia and China and help to organise the "Friends of the Soviet Union." इससे साफ हो जाता है कि असली काम में रूस चीन के अलावे उन बाकी तरक्की पसन्द ताकतों को भी छोड़ दिया गया है जिनका जिक्र वसूली बातों के सिलसिले में पहले आया है और सिर्फ रूस और चीन की सभी तरह की हो सकनेवाली मदद की बात कही गई है। फिर भी कुछ मुसलमान इसमें अंग्रेजी सरकार को मदद देने की बात जाने कहां से लाके हमें और किसान सभा को बदनाम करना चाहते हैं। खूबी तो यह है कि इसमें "मित्र मंडलियां" बनाने की बात सिर्फ

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

रूस के ही लिये रही गई है और इस बारे में चीन को भी छोड़ दिया गया है। क्योंकि किसान-मजदूर राज्य पूरी तौर से रूस में ही तो है, चीन में तो वह अधूरा ही है न?

इसपर यह दलील की जाती है कि आखिर रूस और चीन को मदद देने में भी तो अंग्रेजी सरकार की मदद हो जाती है न? अगर इसका जवाब 'हाँ' दिया जाय तो लोग नाक-भौं सिकोड़ बैठते हैं और ठोस हालत पर गौर करना चाहते ही नहीं। वह हर्गिज नहीं सोचते कि अगर अंग्रेजी सरकार पर होनेवाले गुस्से के चलते हम या दुनिया के लोग रूस और चीन की भी मदद न करें तो नतीजा क्या होगा। तब तो अंग्रेजी सरकार के साथ ही न सिर्फ रूस और चीन हारेंगे, बल्कि हिटलर और जापान की जालिमाना हुकूमत, जो अंग्रेजी हुकूमत से हजार गुना खतरनाक है, हमारी छाती पर आ धमकेगी। अंग्रेजी सरकार के ऊपर होनेवाली हमारी सख्त नाराजी के चलते उसे खतम करने के लिए रूस और चीन की भी मदद न करना ठीक वैसा ही है जैसा दुश्मन के बदसगुन के लिए अपनी नाक काट लेना या उसकी एक आँख फोड़ने के लिए अपनी दोनों फोड़ लेना। इस गुस्से में हम यह बात जाने क्यों भूल जाते हैं जिसे बराबर दुहराते रहे हैं और आजभी दूसरे लोगों पर बक डालते हैं कि फासिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों ही सगे भाई हैं और बुरे हैं। इसका तो सीधा मतलब यही है कि उन दोनों की दोस्ती या कभी हो भी

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

सकती है, वे दोनों कभी किसी शर्त पर मिल भी सकते हैं; मगर हमारी दोस्ती अगर इम्पीरियलिज्म के साथ नहीं हो सकती तो फासिज्म के साथ तो वह हजार गुना गैर-मुमकिन है। वह तो हमें कम से कम सैकड़ों साल के लिये खत्म करकेही छोड़ेगा। क्योंकि फिलहाल हमतो उसे खत्म कर सकते नहीं और दोनों एक साथ चल सकते नहीं। आज की हालत में अंग्रेजी सरकार की दुश्मनी के चलते हिटलर और तोजो को आजादी दे देना—कि वे अंग्रेजी सरकार को सर करें—ठीक वैसाही है जैसा कि अपने साथ एकही कूएँ से पानी पीनेवाले अपने दुश्मन को मार डालने के खयाल से उस दुश्मन के दुश्मन को उसी कूएँ में जहर डालने का मौका देना और इस तरह अपनी भी मौत बुलाना या यों कहिये कि जब अपने दुश्मनको जीते जी मार न सकें तो गुस्सेमें अपने आपको सिर्फ इसलिए जहर खाके मार डालने की बन्दिश करना कि पीछे भूत होके उसे सतायेंगे और खत्म करेंगे या कम से कम पुलिस हमें जहर देनेका झूठा मुकद्दमा तो उसपर चलायेगीही। मगर मैं इसे महज नादानी मानता हूं।

बदकिस्मती या खुशकिस्मती से हालत ऐसी होगई है कि जब रूस और चीन जीतेंगे तो हिटलर और जापान हारेंगेही और अंग्रेजों की भी जीत होगी ही। इसे हम किसी तरह रोक सकते नहीं। ऐसा रास्ता हई नहीं कि रूस और चीन जीतें, अंग्रेजी सलतनत हार के यहां से मिट जाये और जापान

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

या हिटलर की हुकूमत यहां कायम न होके हमारी सलतनत कायम होजाय। हमें और किसान सभा को ऐसा रास्ता सूझता ही नहीं। लेकिन अगर कोई दिमागदार ऐसा रास्ता सुझाये तो हम खुशी-खुशी उसी पर चलेंगे। मगर जब तक वह रास्ता मिलता नहीं, तब तक तो हम इसी रास्ते पर खामखा चलेंगे। हमारे लिए दूसरा चारा है नहीं।

इस पर जो लोग कहते हैं कि "तो फिर साफ ही क्यों नहीं कहते कि अंग्रेजी सरकार की मदद करेंगे? घुमा-फिराके नाक क्यों पकड़ते हैं?" उनसे हमारा पूछना है कि साफ कहने के क्या मानी हैं? यह सवाल आताही क्यों है? अंग्रेजी सरकार तो खुद रूस और चीन की मदद कर रही है और इसी का पल्ला पकड़ के पार पाने की उम्मीद करती है। अमेरिका से लौटते ही चर्चिल ने रूस और चीन दोनों की ही बहादुरी की भरपूर तारीफ की और इन्हीं दोनों पर अपनी उम्मीद बताई। ऐसी हालत में क्या हमारा यह फर्ज नहीं होता कि हम भी रूस और चीन की जितनी होसके मदद करें? हम तो पहले सेही चिल्लाते आरहे हैं कि रूस की मदद करो, चीन की मदद करो, अबीसीनियां की मदद करो, स्पेन की मदद करो और फासिस्टों से इन्हें बचाओ। हमने ऐसा न करने के लिए अंग्रेजी सरकार को जाने लाखों गालियां दी हैं। तो क्या अब हमारे लिए यही मुनासिब है कि,—चाहे मजबूरी में ही क्यों न हो, और मजबूरी सेही तो सभी ऐसा काम करते हैं—आज जब अंग्रेजी

iGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

सरकार फासिस्टों के खिलाफ रूस और चीन की मदद कर रही हैं तो हम "काफिर जो कहे आर करे उससे उलटा कहना वो करना" वाले वसूल के मोताबिक इन दोनों को मदद करने से इनकार कर दें ? और अगर अंग्रेजी सरकार पर होने वाले हमारे गुस्से के चलते इसमें हमें दिक्कत मालूम होती है तो इसके लिए कसूरवार चीन और रूस तो हैं नहीं कि उन्हीं पर हम अपना यह गुस्सा उतार। इसके लिए जवाबदेह अगर कोई हैं तो जर्मनी और जापान जिनने सिर्फ अंग्रेजी सरकार से ने लड़के रूस और चीन पर भी धावा बोल दिया और ऐसी पेचीदी और नाजुक हालत पैदा कर दी। अगर वे ऐसा न करते तो किसे फिक्र थी कि कौन कहां लड़ रहा है ? तब हमें कहां कोई पर्वा थी ? यह पर्वा तो इन दोनों की करतूतों नेही जबर्दस्ती पैदा करदी। ऐसी हालत में तो इन खूँखारों पर ही हमारा सभी गुस्सा खामखा उतरना चाहिये और इन्हें मटियामेट करने का तरद्द हमें कर लेना चाहिये। मगर ऐसा न करके अगर हम रूस और चीनकी मदद नहीं करते तो यह निरा अंधेरखाता ही होगा। हां, अगर फासिस्टों के खिलाफ मदद देने की हमारी अब तक की बातें केवल ब्रिटिश सरकार को कोसने के बहाने के तौर पर ही रही हों, न कि हम ईमानदारी से यह बात मानते रहें हों तो बातही दूसरी है। मगर इसका जाहिरा सबूत तो कोई हैं नहीं। हां, जान या अनजान में, हममें कुछ लोगों की मौजूदा हरकतों से ऐसा अन्दाज करने का मौका हमारे मुखालिफों

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

को जरूर लग सकता है कि हम कहते कुछ और करते कुछ हैं। तो क्या ऐसा मौका देना हमारे लिए मुनासिब है ?

यहां कुछ लोग ऐसा भी कह बैठते हैं कि जब हालत की पेचीदगी के चलते रूस और चीन को मदद पहुंचाने से भी बृटिश सरकार और अंग्रेज कौम को भी मदद मिल ही जाती है, तो हम यही बात साफ साफ क्यों न बोलें और घुमा फिरा के बातें क्यों करें ? इस चालबाजी से क्या फायदा है ? मगर दरअसल यह दलील कोई गुंजाइश रखती नहीं। मदद किसे, कब और कैसे की जाय और कौन किसकी मदद करे यह बात हर हालतमें एकसी नहीं होती। इसमें कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनके सामने हमें झुकना ही पड़ता है। मदद करना तो कन्धे से कन्धा भिड़ाना है और यह मुमकिन नहीं कि हम चाहे जिसीके कन्धे से अपना कन्धा भिड़ालें। पालकी की सवारी को ढोनेवाले कहारों में अगर एकभी गायब हो जाय या न रहे तो वह चल नहीं सकती। इसीलिए उसे चलने में मदद हो इसके लिए एक कहार की खामखा जरूरत होती है। यह भी ठीक है कि आम तौर पर उस कहार के लिए कोई खास जगह या खास कन्धा मुकर्रर नहीं होताकि उसीसे वह जुटे। फिर भी उसको दो मजबूरियाँ होती हैं जिनके चलते उसे एक खास कंधे से ही निराले ढंग से जुटना पड़ता है। गोकि आगे, पीछे या बीच में कहीं भी जुट जाने पर सवारी के आगे बढ़ने में वह मददगार होता ही है फिर भी अपनी इन दो मजबूरियों से लाचार होके

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

वह किसी खास कन्धे से ही अपना कन्धा भिड़ाने पर ही मदद कर पाता है और ऐसा न करने पर मददगार होने के बजाय उस सवारी के लिए रुकावट ही पैदा करता है। उन दो मजबूरियों में पहली तो यह है कि जिस कन्धे से उसके कन्धे का मेल हो उसीसे जुटे। बेमेल कन्धे से जुटने में परीशानी और भी बढ़ती है। दूसरी यह है कि जिस कन्धे से जुटे वह अगर दायें लगा हो तो अपना बायां लगाये। बस, इन्हीं दो बातों का खयाल करके ही किसान सभाने फैसला किया है कि हमारा कन्धा रूस और चीन के कन्धे से ही जुट सकता है, उसी के साथ इसका मेल खाता है। सोवियट रूस के ही दोस्तों की जमातें और मंडलियां कायम करने की ही बात कहके चीन का नाम जो इस बारे में नहीं लिया गया है वही हमारी दूसरी मजबूरी की ओर इशारा करता है। वहां किसान-मजदूर राज्य कायम हो जाने के कारण उसी ओर हमारा खिंचाव आदतन और कुदरतन होता है, और हम इसे रोक नहीं सकते।

यही वजह है कि इस हकीकत को कबूल करने के साथ-साथ हमारी सभा ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा होते हुएभी यह हर्गिज नहीं हो सकता कि हम इस लड़ाई को टुकड़ों में बांट सकें। यहतो एकही है। इसके टुकड़े हो नहीं सकते और अगर इसे कई हिस्सों या एक दूसरे से उलटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई तो वह महज बनावटी बात होगी न कि ठोस और असल चीज–"War like peace is indivisible and

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

no artificial distinction could now possibly be drawn between the wars of Russia, China and the Allies who fight together on a world-wide front". रूस पर हमला होने के बाद ही स्तालीन ने कह दिया था कि हम एक दूसरे की मदद करने की दोस्ती करें। इसीलिए ब्रिटेन और रूस की जो आपसी दोस्ती कायम हुई है, वह इसी ख्याल से और अमेरिका के साथ मिलके आखिरकार तय पाया कि सबोंकी ताकतें मिलाके जहां जिस चीज की जरूरत हो वहीं वह पहुंचाई जाय। ऐसी हालत में किस मुल्क की कौनसी गोलागोली, कौनसी टैंक, कौनसे हवाई जहाज वगैरह कहां जायंगे और लड़ाई में काम आयेंगे यह कहा नहीं जा सकता है। सबों की ये चीजें पंचायती करार देदी गई हैं। रूसकी कितनीही चीजें इंगलैंड और अमेरिका जारही हैं और वहां की रूस आरही हैं। फिर इस लड़ाई को ऐसे टुकड़ों में क्योंकर बांटा जा सकता है जो एक दूसरे से कोई मेल नहीं रखते हों? ऐसा करना तो ठोस असलियत से आंख मूंदना और अपने आपको धोका देना होगा।

इसीके साथ एक बात और भी है। जानें किसकी बदबख्ती की वजह से हममें बहुतेरे ऐसे हैं जो रूस और चीनकी मदद की बातें करते हुएभी अंग्रेजी सरकार से बेहद रंज होने के कारण हिटलर या जापान की जीत भीतरही भीतर या तो चाहते हैं, या कमसे कम अनजान में ही ऐसा सोचते, बोलते

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

और काम करते हैं जिससे इन दोनों की जीत रुक नहीं सकती। इस तरह जान या अनजान में इस लड़ाई को कई बनावटी या नकली हिस्सों में बांटके धोका खाते हैं। यह तरीका बड़ाही खतरनाक है और हमारे सामने इसीसे बचने के लिए इस मामले में हमारा और किसानों का दिमाग साफ करने पर जोर देते हुए कहा है कि इस लड़ाई का हर्गिज टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते, यहतो एकही है।

इस रेजोल्यूशन में चौथी बड़ी और काम की बात यह है कि इसने साफ कह दिया है कि जहां रूस और चीन में यह लड़ाई सोलहों आने जनता की-अवामकी-लड़ाई होचुकी है, तहां इङ्गलैंड, अमेरीका और दूसरे दोस्ताना मुल्कों में तेजी के साथ वैसी बनती जारही है। लेकिन हिन्दुस्तान में तो दर असल इसे अवाम और जनता की लड़ाई की सच्ची और असली व्यावहारिक शक्ल तभी मिल सकती है जबकि उसे यहांकी कौमी और राष्ट्रीय सरकार चलाये और सभी लोग दिलसे उसमें मदद करें और पड़जायें। "It is such a people's war that is being so successfully waged by Russia and China. In England, America and other Allied countries the present war is rapidly assuming the form of a People's war for freedom. Similarly this war can effectively be converted into an Indian People's war only

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

when it is fought under the leadership of a National Government and with the willing and hearty co-operation of the people of India". यही वजह है कि आगे चलके कह दिया कि अगर अंग्रेज कौम और अंगरेजी सरकार ईमानदारी और नेकनियती से जर्मनी और जापान की हार चाहती है तो वह फौरनही यह साफ साफ एलान करदे कि हिन्दुस्तान को पूरी आजादी का हक है और लड़ाई के बादही फौरनही वह अपनी हुकूमत का ढांचा खुद तैयार करेगा, वह हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय और कौभी सरकार कायम करे, किसानों और मजदूरों की मांगें पूरी करे, सभी पोलिटिकल और किसान-मजदूर कैदियों को छोड़दे वगैरह, वगैरह। क्योंकि बिना ऐसा हुए लोगों का फटा हुआ दिल इस ओर खिंच सकता नहीं। हम नहीं समझ पाते कि किसान सभा इससे ज्यादा और क्या कर सकती है। यह ठीक है कि यह बात उसने सौदे के रूपमें नहीं कही है और यही मुनासिब है। हमतो सौदेकी बातमें यकीन रखतेही नहीं, यह हमारी मजबूरी है। इसीके साथ हम एलान कर देते हैं कि हमतो हर तरह से इसे अपनी लड़ाई बनाने को तैयार हैं और जितना हो सकता है इसके लिए काम करते भी हैं, करते रहेंगेभी। मगर हमारी तैयारी और कोशिश बेकार होगी अगर अंग्रेज कौम और सरकार ने यहां के लोगों के दिल-दिमाग को इसमें न खींचा और इस तरह अपनी नेकनीयतीका सबूत न दिया। इस तरह तो उसपर औरभी दबाव पड़ता है कि हमारी मांगें

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

जल्द से जल्द पूरा करे। सौदा करने में यह बात नहीं हो सकती, यह हम मानते हैं।

इसी सिलसिले में दो एक बातें और भी कह देना जरूरी है। लड़ाई में शर्त्त या बिना शर्त्त के मदद देने की बात बार-बार उठाई जाती है। यह ठीक है कि किसान सभा के प्रस्ताव में शर्त्त के रूप में कोई भी बात नहीं रखी गई है। हालांकि जिस ढंग से बातें रखी गई हैं वह शर्त्त के मुकाबिले में हजार गुना ज्यादा काम करती है। मगर इसके खामखा यह मानी लगाना कि किसान सभा बिना किसी शर्त्त के मदद की बात कहती है, किसान सभा को जी-हजूरों की चीज बनाने की बदतमीजी करना है। दरअसल बात यह है कि सभा शर्त्त या बिना शर्त्त के झमेले से हजार कोस दूर है। ये झमेले उसके पास फटकने पाते नहीं। लेकिन इस पर यह कहना कि जब शर्त्त नहीं तो खामखा बिना शर्त्त की बात आ जाती है, दूर की कौड़ी लाना है। यहां हमें एक बात याद आ जाती है। मिस्टर मैकडानल्ड के कम्यूनल अवार्ड के बारे में कांग्रेस ने "न तो उसकी मुखालफत करने और न उसे मानने" "Neither support nor oppose" का रास्ता अखतियार किया था। मगर इसके यह मानी किसीने भी नहीं लगाया कि जब वह मुखालिफ नहीं है तो उसे खामखा मानती है, या अगर नहीं मानती तो मुखालिफ है। यही बात किसान सभा के मुतल्लिक शर्त्त या बिना शर्त्त के बारे में भी

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

लागू हो सकती है। और जब हम रूस या चीन के कन्धे से हो कन्धा भिड़ाते हैं, भिड़ाना चाहते हैं, भिड़ा सकते हैं न कि दूसरों से, तो फिर शर्त्त या बिना शर्त्त का सवाल उठता ही कहां है ? सरकार भी इन्हीं दोनों को मदद देरही है ताकि सबकी जान बचे और हमभी उन्हीं दोनों को देते हैं, देना चाहते हैं। बस इतनाही हमारे और सरकार के एक साथ मिल जाने का मतलब है, न कि ज्यादा या कम। मुझे यह बात भूलतीही नहीं जब गांधीजी ने खुद बिहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी में १९३४ में रेजोल्यूशन दिया था कि हम सरकार से मिलने के लिए उसके मुतल्लिक इज्जत रखते हुए मिलने को हाथ बढ़ाते हैं, "We extend our hand of respectful co-operation towards the Government". मैंने इस इज्जत वाली (respectful) बात पर उज्र किया था और उन्हें लिखा भी था। मगर वे इसपर डटे रहे। क्यों ? शायद इसीलिए कि वह दरअसल इस तरह सरकार को यकीन दिलाके लोगों की खिदमत करना, करवाना चाहते थे। हालांकि मेरे जानते फिरभी (respectful) कहने की जरूरत न थी। मगर किसान सभातो ऐसा कुछभी कहतीही नहीं। अगर वह आज ऐसा बोलती तो शायद वही लोग हमारी जबानें अहिंसा के के नाम पर खींच लेते ! फिरभी यह नाहक का वावेला मचाया जाता है। यहभी नहीं कि १९३४ में सरकार दूसरा थी और आज दूसरी और उस समय हमारा गुस्सा उसपर कम था।

njGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

इसी तरह इस लड़ाई के साम्राज्यवादी होने का भी सवाल उठाके इनकिलाब के नाम पर गलतफहमी फैलाई जाती है। मार्च के रूसी इनकिलाब के बाद अगस्त, सितम्बर १९१७ में करेंस्की की सरकार रूस में थी। वह करीब करीब ताना-शाह हो चुकने के साथ ही सरमायदारों का गुलाम था, लेकिन दब्बू था। इसीसे उसे मिटाके अपनी तानाशाही कायम करने के खयाल से कार्निलोफ नाम के प्रधान सेनापति और सिपह-सालार ने उसपर धावा बोल दिया था। उसे खड़ा करनेवाले भी पूंजीपति ही थे। इस तरह दोनों तरफ एक ही तरह के लड़नेवाले थे। मगर लेनिन और उसकी पार्टी ने क्या किया? यह समझके कि दोनों ही सरमायादारों के कठमुल्ले लड़ रहे हैं जिससे यह लड़ाई साम्राज्यवादी है, क्या उसने किनाराकशी और तटस्थता की? नहीं, हर्गिज नहीं। करेंस्की के सामने किसानों को जमीनें देने, दकियानूस ड्यूमा (पार्लियामेंट) को तोड़ देने और जनता की सरकार कायम करने की मांगें पेश जरूर की गईं ताकि मिल-मिलाके कार्निलोफ से लड़ा जाय। मगर उसने टका-सा जवाब दे दिया और एक बात भी न मानी। फिर भी लेनिन और उसके साथी सब से पहले आगे बढ़े और जरा भी हिचक न रख के कार्निलोफ के पछाड़ने में जा लगे। करेंस्की तो लगा था ही। अन्त में लेनिन की पार्टी की ही मदद से कार्निलोफ पछाड़ा जा सका। तो क्या ऐसा करने में लेनिन सनक गया था? क्या वह इतना भी सोच नहीं सकता था कि उन दोनों की लड़ाई साम्राज्यवादी है या नहीं? क्या

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

वह यह भी सोच न सका कि इस तरह करेंस्की जो उसका और उसकी पार्टी का जानी दुश्मन था, इस तरह काफी मजबूत हो जायगा, जिससे पीछे पछाड़ने में बड़ी दिक्कत होगी ? दरअसल यह कुछ भी न था। वह सारी बातें समझता था और उस लड़ाई को हर तरह से अपनी—लोगों को—लड़ाई समझता था। उसने सवाल करनेवालों से कहा कि हम दरअसल करेंस्की को मजबूत करने के बजाय उसकी कमजोरियां इस तरह लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे बिना अब वह कुछ कर नहीं सकता। इसपर जब उसके कुछ साथियों ने कहा कि "तो आइये, करेंस्की की पुरानी बातें भूल जायं," तो उसने कहा कि ऐसा करना भारी भूल होगी। हम उन्हें भूल तो सकते नहीं मगर इस समय ज्यों को त्यों छोड़ उनसे ज्यादा जरूरी काम करने जा रहे हैं। उसने यह भी कहा कि करेंस्की देर से मारने वाली खांसी वगैरह जैसी बिमारी (Chronic disease) है और कर्निलोफ चटपट मारनेवाले हैजा जैसी ((Acute disease) है। इस लिए इस समय अगर हम पुरानी बीमारी की ही दवा में लगे और भूले रहें तो चटपट वाली बीमारी हमें खत्म ही कर देगी। इसलिए पहले इसेही खत्म करने में ही अक्लमंदी है। क्या यही बात ब्रिटिश साम्राज्यवाद और फासिज्म के मुतल्लिक हू-बहू लागू नही हैं ? जो यह बात नहीं मानते उनके इनकिलाब से हम डरते हैं, उसमें खतरा है। क्योंकि हम लेनिन से बढ़के इनकिलाबी अपने आपको मानने की नादानी कर नहीं सकते।

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

बात असल यह थी कि अगर कार्निलोफ जीतता तो केरेंस्की को तो खत्म करताही उसी के साथ ही लेनिन और उसकी पार्टी को भी खत्म करता और इस तरह किसान-मजदूर की आजादी का सवाल बहुत दिनों के लिए खत्म होजाता। इसीलिए लेनिन ने दूरंदेशी से काम लेके पहले उसे खत्म किया, हराया। ठीक यही बात यहां है। रूस और चीन पर हिटलर और जापान की जीत से वे दोनों और उन्हीं के साथ अंग्रेजी सरकार भी तो हारेगीही। मगर दुनिया और हिन्दुस्तान में भी उसी के नतीजे के रूप में जो फासिज्म की फौजी हुकूमत कायम होगी वह कार्निलोफ की हुकूमत से हजार गुनी खतरनाक होगी और किसान-मजदूरों के हकों और हमारी आजादी की बात हवा में मिल जायगी। अगर यह बात न होती और हिटलर खुद रूस पर हमला करके चीन को हमेशा के लिए हड़प जाने के लिए जापान को न उभाड़े होता तो यह खतरा इस समय सामने नहीं होता। यही वजह है कि इससे पहले हमें कोई फिक्र न थी और हम अपनें काम में लगे थे। मगर रूस पर हमला होते ही सारी हालतही एकाएक बदल गई और हमें इस लड़ाई के बारे में अपने रुख को नये सिरे से सोचने और तय करने को मजबूर होना पड़ा। किसान सभा के प्रस्ताव में भी यही बात साफ लिखी है। मैं मानता हूं कि इससे पहले ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई भी मुनासिब वजह न थी, कोई सामान न था। नागपुर के पहले पारसाल अक्तूबर में पकाला (आन्ध्र) में जो आल इंडिया किसान कमेटी की बैठक हुई थी उसने भी

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

यह बात साफ कबूल की थी और लोगों पर जोर दिया कि सोवियत रूस की सभी तरह की मदद करने के साथ ही नात्सी जर्मनी के खिलाफ लड़ी जानेवाली लड़ाई के सभी मोर्चों को जबरदस्त बनाने का काम करें—"to render all possible help to the U. S. S. R. and work for the intensification of the war against the Nazi Germany on all fronts". और नागपुर में किसान कौंसिल ने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा है। यह ठीक है कि सारी बातें उसने बड़ी खूबी और सफाई से पेश की हैं जो आईने की तरह झलक रही हैं। मगर इसके लिए किसान सभावालों को उसपर रंज होने या बिगड़ने की तो कोई वजह मैं नहीं देखता। हमारी सभा के रूल और कायदे के मुताबिक जिस समय उसका खुला जलसा न होता हो उस समय आल इंडिया किसान कमिटी को ही उसके सभी अख्तियार और हक हासिल होते हैं जैसा कि VIII (F) "The A. I. K. C. shall be the highest authority when the Sabha is not in session and shall exercise all its powers" से साफ है। इसीलिए अगर पलासा वाले जलसे के फैसले के खिलाफ पकाला में उसने नई हालत को देखके नया फैसला किया तो ठीक ही किया।

इतना ही नहीं। पलासा में तो खुद सालाना जलसे में ही एक रेजोल्यूशन के जरिये सेन्ट्रल किसान कौंसिल को ही सभी अख्तियार दिये गये थे कि नई हालत आजाने पर वह सब कुछ

aiGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

कर सकती है चाहे कायदे-कानून में ऐसा करने का उसे हक न भी क्यों न हो। यही बात पलासा में किसान कमिटी ने भी की और वही रेजोल्यूशन फिरसे उसने दुहरा दिया। वह यों है "In view of extra-ordinary conditions, political and otherwise, resulting from the war, the A. I. K. C. resolve to authorise the C. K. C. to take all necessary steps to carry on the work of the Sabha and to meet any kind of emergency that might arise, any contrary provision in the constitution notwithstanding". ऐसी हालत में तो किसी भी तरह यह सवाल उठ सकताही नहीं कि सेन्ट्रल किसान कौंसिल को कोई हक था नहीं कि वह पलासा के फैसले के खिलाफ कुछभी तय करे।

अब एकही सवाल और रह जाता है। कुछ दोस्तों ने यह कह डाला है कि जेलमें रहते हुए मुझे कोई हक न था कि अपने खयाल अपने साथियों पर जाहिर करूं। मगर यह चीज मेरी समझ में आ न सकी। अगर जेलमें रहतेही मुझे उन्हीं साथियों ने पलासा मेंही आल इण्डिया किसान सभा का प्रेसिडेन्ट चुना तो क्या इसका मानी यह था कि मैं महज नुमाइशी प्रेसिडेन्ट बनाया गया? और अगर यह बात नहीं थी तो माननाही होगा कि सभाकी पालिसी के बारेमें अपनी राय सबों पर जाहिर करूं ताकिवे खूब सोच समझ कर फैसला करें।

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

वैसी हालत में अगर वह फैसला मुझे पसन्द हो तो ठीक, और अगर पसन्द न हो तो इस्तीफा देदूँ। आखिर मैं बुद्ध प्रेसिडेन्ट तो बनने को तैयार हो सकता नहीं।

लेकिन मैंने आखिर किया क्या? मेरा हक तो था कि किसान कमिटी और कौंसिल के सभी मेम्बरों और सेक्रेटरी को अलग अलग साफ लिखदूं कि मैं क्या सोचता और चाहता हूँ और किस हालत में सभाका सभापति और सदर रह सकता हूं। उसका नतीजा यही होता न कि अगर वे लोग मेरी बातें मानते तो मैं सभापति बना रहता और अगर न मानते तो इस्तीफा दे देता या इन्कार करता? तो क्या यह बात नामुनासिब होती? यही तो सभी जमातों और संस्थाओं का तरीका है। मगर मैंने ऐसे नाजुक वक्त में ऐसा कुछ भी न करके चुप्पी मारली। हां, जब किसान सभा के मेरे शुरू के साथी और सिपाही इन्दु लाल याज्ञिक ने दिसम्बर के आखिर में जेल से रिहा होने पर, चिट्ठी लिखके खुद अपनी राय साफ साफ जाहिर की और मेरी भी साफ राय लड़ाई के बारे में पूछी तो मैंने जवाब दिया और अपने खयाल जाहिर किये। बस, तो क्या मेरा यह काम गलत था? क्या लोग चाहते थे और चाहते हैं कि मैं जवाब भी नहीं देता?

एक बात और। आखिर हमने याज्ञिक की चिट्ठी में लिखा भी क्या था? अफसोस कि यह चीज लोगों को बताई ही न गई और बे-बुनियाद तूफान खड़ा कर दिया गया। हमने चिट्ठी में

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

चाहे हजार दलीलें दीं मगर लड़ाई के मुतल्लिक अपनी आखिरी राय यही लिखी कि "ऐसी हालत में हमारी सभाने पकाला में जो फैसला इस लड़ाई के बारे में किया वही मुनासिब है, हमें उसी पर अमल करना चाहिये और सरकार क्या करती है क्या नहीं इसकी पर्वा जराभी नहीं करना चाहिये"—"In the circumstances our Pakala formulations to "render all possible help to the U. S. S. R. and work for the intensification of the war against Nazi Germany on all fronts", are the only logical and proper ones and we must act upto them regardless of what the Government do or do not do". और पकाला वाला फैसला तो हमारे उन्हीं दोस्तों और साथियों ने किया था जो आज नागपुर के फैसले के लिए मुझको कसूरमंद ठहराते हैं। तो क्या उनकी मंशा यह है कि मैं पकाला के फैसले को भी पसन्द नहीं करता और ठीक बताता यह तो अजीब बात है।

खैर, इन बातों की ज्यादा उधेड़-बुन करना फिजूल है। हमें असली बात पर आना चाहिये और वह है इस लड़ाई के बारे में हमारा किसान सभा और किसानों का रूख। अबतक हमने जो कुछ कहा है उससे यह सवाल काफी साफ हो गया है। एक ही बात और कह देना है। रूस पर हिटलर का हमला होने के बाद ही जेल में हमने जो नज्जारा देखा और

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

बाहर से जो खबरें मिलीं इनसे न सिर्फ हमें तमाचे लगे, बल्कि हमारा क्या फर्ज, कर्त्तव्य और अमल होना चाहिये यह तय करने में आसानी हो गई। उस समय कई सौ चुने-चुनाये जमींदार, मालदार, उनके दोस्त वगैरह हजारीबाग जेल में थे। हमें यह जान के ताज्जुब हुआ और धक्का भी लगा कि हिटलर के हमले से उनमें बड़ी खुशी है सिर्फ इसीलिए कि रूस खत्म होगा सो तो होगा ही, ये किसान सभावाले हिन्दुस्तान में देखें, अब किसान-मजदूर-राज्य कैसे कायम करते हैं। यह एक नई बात थी। यह नहीं कि दोई चार लोग ऐसे थे। हमने बहुतों को ऐसा ही पाया। किसान-मजदूर-राज्य कायम न हो इसके लिए हिटलर और मुसोलिनी का स्वागत और इस्तकबाल हिन्दुस्तान में वे लोग करने को नजर आयें या ऐसी बातें करें जो अपने को आजादी के दीवाने मानते हों। सचमुच ही यह नई बात थी जिसके लिए मैं तैयार न था। चाहे उनका ऐसा खयाल नासमझी सेही क्यों न हो और रूस पर हिटलर की जीत का नतीजा क्या होगा यह बात वह बखूबी समझते भले ही न हों; मगर मैंने तो उसी वक्त तय कर लिया कि हिटलर और उसके साथियों को मिटाने के लिए हमें और किसानों को सारी ताकत लगाना ही होगा। हमें उन दोस्तों वाली आजादी खतरनाक जँची।

मैं मानता हूं कि जब तक सारे मुल्क के लोग दिलोजान से इस काम में न पड़ जायेंगे तबतक तोजो और हिटलर को

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

हराना गैरमुमकिन है। चीन में च्यांग-कै-शेक की सरमायेदार और पूंजीबादी पार्टी अकेली कुछ न कर सकी और जापान ने एकके बाद दीगरे चीन के जाने कितने ही सूबे हड़प लिये। वहां की कम्यूनिस्ट पार्टी भी चियांग-कै-शेक का मुकाबिला करने और उसके दांत खट्टे करने में कामयाब होने पर भी फ़ासिस्टों को हरा न सकती थी। इसीलिए वहां हारकर दोनों का समझौता होके संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ा जिससे आज जापान को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। उसे पता लग रहा है कि किसी भी मुल्क की सम्मिलित और मजमूई ताकत किसे कहते हैं। मैं तो मानता हूं कि हमारे सामने चीन की ही मिसाल इस मामले में रहनी चाहिये और वही हालत पैदा करने में हमें लग जाना चाहिये। इसीलिए नागपुर में किसान कौंसिल ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि हमारे मुल्क की छोटी बड़ी सभी जमातें मिल जायें। सबसे बड़ी सियासी और राजनीतिक जमात होने की ही वजह से इस मामले में कांग्रेस ही आगे बढ़े और मुस्लिम लीग वगैरह से मिल मिलाके कोई रास्ता जल्द निकाले ताकि हम एक खयाल और एक आवाज से यहां राष्ट्रीय और कौमी सरकारें सूबों में और हिन्दुस्तान में भी कायम करने में कामयाब हों। अंग्रेजी सरकार को भी गर्ज है, वह भी मजबूर है। उसकी मजबूरी चियांग-कै-शेक से कम नहीं है ऐसा मैं मानता हूं। उसके ऊपर न सिर्फ ब्रिटेन के लोगों का ही दबाव पड़ रहा है, बल्कि रूस और चीन का भी। असल में हिन्दुस्तान को अपने साथ

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

किये बिना. ब्रिटेन, रूस, चीन वगैरह सभी को भारी खतरा है, सभी के सामने सत्यानाश खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे मौके पर हमारी एक और मिली आवाज यहां नैशनल गवन्मैंट कायम करके ही रहेगी जिससे हम सारी ताकत से जापानी और हिटलर के खूँखार गरोह का मुकाबिला कामयाबी से कर सकेंगे। मेरा तो यह भी पक्का यकीन है कि बिना गैर-मामूली ताकत हासिल किये हम जापान के खतरे का सामना कर नहीं सकते और जब ऐसा कर चुकेंगे तो हमारी वही ताकत ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को बात की बात में मिटा छोड़ेगी अगर फिर भी मिटाने की जरूरत रही। "जरूरत रही" की बात इसलिए कि इस लड़ाई की दौरान में ही, हो सकता है, साम्राज्यवाद की भी कचूमर फासिज्म के साथ ही निकल जाय और वह सर उठाने की हिम्मत कर न सके। आखिर फासिज्म साम्राज्यवाद की हीतो आखिरी खूंखार और गुंडानुमा सूरत है।

हां, जहां एक ओर हम कौमी और राष्ट्रीय सरकार फौरन से पेश्तर कायम करने में लगजायें वहां देहातों और शहरों के लोगों में नाहक फैले हुए खौफ और आतंक कोभी मिटा देने का पक्का इरादा करलें और उनमें ऐसी हिम्मत लादें कि वह चोर डाकुओं का और जरूरत होनेपर जापानी शैतानों काभी डटके मुकाबिला कर सकें जैसाकि रूस और चीन के लोग कररहें हैं। हमें यह न भूलना होगा कि आज इस नाजुक घड़ीमें हमारी हरेक बात तौलकेही बोली जाय। नहीं तो अंग्रेजी सरकार का

jGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

नुकसान करनेके बजाय हम अपनीही बर्बादी कर बैठेंगे। जोशमें हमारे ऐसा लेक्चर देनेसे कि "सरकार लड़खड़ा रही है" हमें स्वराज्य तो कभी शायद ही मिले या उसके लिए लड़ने की हिम्मत लोगोंमें शायदही आये, मगर चोर डाकुओंकी हिम्मत जरूर बढ़ेगी और डाकेजनी चोरी बगैरह बढ़ेंगी। खासकर देहातों में सभी पार्टियों, जमातों और लोगोंकी पंचायतें और वालंटियर कोर एक रायसे बनें जो दिनरात उनकी हिफाजत करें। इसकीही आज जरूरत है, नकि अलग-अलग अपनी डफली बजाने और वालंटियर कोर या ब्रिगेड कायम करनेकी। ऐसा करने में धोका होगा यह मैं मानता हूं। इसीलिए आज अलग किसान-सेवक-दल नये सिरे से बनाने की बात मैं नहीं पसन्द करता। पहले के बने सेवक-दल रहें जरूर, मगर वे औरों से मिलके एक जनता का वालंटियर दल (People's Volunteer Corp) की सूरत में तबतक के लिए बदलजायें जबतक लड़ाई जारी है। अगर हम बद-अमनी नहीं चाहते और नहीं चाहते कि किसानोंकी फसलें और उनके घरवार लुट जायें तो यही करना होगा। दूसरा रास्ता हई नहीं। नहींतो अगर हमारी गैर-जिम्मेदारी के करते चारों ओर गोलमाल फैलनेमें रोकके बजाय मदद मिलीतो नतीजा न सिर्फ यह होगा कि लोग लुट जायेंगे, गरीब पामाल होजायंगे, बल्कि हमारी आजादीकी उम्मीदभी लुट जायेगी।

किसानों की लड़ाई

जेल से बाहर आतेही मेरे सामने यह सवाल बार-बार लाया गया है कि किसानों की बकाश्त की या दूसरी लड़ाइयों

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

का क्या हो—यह चालू रहें, जारी हों या बन्द कर दी जाय ? सवाल तो ठीक और मौजूं हैं। मगर इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हमने इस सिलसिले में लड़ी हैं उनसे चाहे आपने कुछ सीखा हो या नहीं, मैंने न सिर्फ बहुत सीखा है, बल्कि आगे के लिए बहुत कुछ तयभी कर लिया है कि कैसे लड़ी जायें। मौका मिलते ही साथियों से उनपर राय-सलाहें करके आखिरी फैसला किया जायगा। लेकिन इतना कहने में तो मुझे जरा भी हिचक नहीं कि इन लड़ाइयों का अबतक का तरीका हमें छोड़ के कुछ नया ढंग अखतियार करना होगा। नहीं तो नतीजा बुरा होगा और हम कुछ कर न सकेंगे। आपमें बहुतेरे यहतो जानते ही हैं कि रेवड़ा की ही लड़ाई हमने सबसे ज्यादा मुस्तैदी के साथ लड़ी थी और दुश्मनों की कमर तोड़ दी थी। मगर क्या उसका झमेला अभी तक खत्म हुआ ? किसी न किसी सूरत में वह रह रह के सर उठाता रहता ही है। जमींदारी ऐसी डायन है कि वह मरती ही नहीं और सताती रहती है जब तक उसे भागने को मजबूर न किया जाय। जमीदारों को तो आसानी से हम पकड़ सकते हैं, मगर जमींदारी तो हवाकी और दिमागी चीज है और लड़ना है उसी के खिलाफ। इसीसे दिक्कतें बढ़ती हैं। इसलिए हमें ऐसी तदबीर करनी है कि उसे मात करदें। यही नहीं। अगर हम पहली जैसी ही लड़ाइयां चलाते रहे तो जमींदारों के हौसले बढ़ जायँगे और वह ठठेरे वाली बिल्ली बन जाएँगे। इसीलिए

a Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

थोड़ी देर भलेही हो, फिरभी जल्दबाजी हर्गिज नहीं करनी चाहिये और खूब सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। आखिर अगर अबतक किसान लुट न गये और कायम हैं तो थोड़े दिनों तक और भी जमींदारों की नादिरशाही बर्दाश्त करें। यकीन रखें, इससे हमारी और उनकी ताकत बढ़ेगी, जबकि जल्दबाजी के करते खामखा घटेगी। लड़ाई के चलते सरकार भी यह हर्गिज न चाहेगी कि उसकी ताकत इन लड़ाइयों में खर्च हो। इसीलिए फौरन ही ऐसी लड़ाइयां चाहे जैसे हो खत्म करा देना चाहेगी ही। ऐसी हालत में हमें गैर-मामूली और आले दर्जे की तैयारी करनी होगी और उसके लिए समय चाहिये। लेकिन याद रहे कि डिफेन्स ऐक्ट के सामने कोई तैयारी टिक नहीं सकती। वह नंगी तलवार है। फिर नाहक हम क्यों अपनी ताकत जाया करें? इसीके साथ हमें यह भी तो सोचना है कि फासिज्म के बवंडर को हमारे काम मदद न पहुंचायें।

इसलिए एकतो हमें साफ साफ अपनी बातें सबों से कह देना है कि हम खामखा लड़ना नहीं चाहते, हमें परीशान करके किसानों की लड़ाई में घसीटा न जाये। इसीके साथ जहां एक ओर मजबूती के साथ हम यह कहदें कि बर्दाश्त की भी कोई हद होती है जिसके बाद हमें इसमें जरूर ही पड़ना होगा और इसकी जंवाबदेही जमींदारों और सरकार पर ही होगी, तहां दूसरी ओर किसानों को भी यकीन दिला देना चाहिये कि

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

घबरायें न, हिम्मत और बर्दाश्त से काम लें। नतीजा अच्छा होगा और अगर आज जमींदार बकाश्त को छोड़ने को राजी नहीं है तो इसीके चलते कल उन्हें जमींदारी से ही हाथ धोना होगा। हमें एक और भी काम करना होगा। जहां जहां ऐसे झमेले हों वहां वहां की पूरी और ब्योरे वार रिपोर्ट प्रोविन्शल किसान सभा के दफ्तर में भेजना होगा, ताकि पूरी जांच के बाद सारी बातें सरकार और जमींदारों के पास आखिरी बार बाकायदा रख दी जा सकें और उन्हें एक और मौका दिया जा सके कि संभल जायें। इससे हमारा काम आसान हो जायगा। मुझे साफ साफ ऐसा कहने में जराभी हिचक नहीं है कि अबतक यह काम हमकहीं भी ठीक ठीक कर सके हैं नहीं। योंही गोल मटोल बातें करते और लड़ते रहे हैं। इसीसे ज्यादा ताकत लगाने पर भी नतीजा वैसा अच्छा नहीं हुआ है। हम बखूबी समझ लें कि यह काम बकाश्त की लड़ाई की तैयारी को ही पूरा करनेवाला है, न कि और कुछ।

इसी मौकेपर हमें यह कहते हुए निहायत खुशी होती है कि किसान सभा पर जब आफतों पर आफतें ढाई जारही थीं और इसके ज्यादातर रहनुमा आपसे अलग थे उसी समय आपने डुमरांव में उस बेहूदे और जालिमाना बेयाई टैक्सके खिलाफ सीधी लड़ाई लड़के उस इलाके के लोग को जितना आराम पहुंचाया, किसान सभाका सर ऊँचा जिस कदर किया, जमींदारी जुल्मके खिलाफ बाक़ी सभी लोगोंके संयुक्त मोर्चे

a Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

और यूनाइटेड-फ्रन्ट की जो जिन्दा मिसाल पेशकी और लाठी-राज कायम करनेमें अपनी मिसाल नहीं रखनेवाले डुमरांव महाराज को जो बुरीतरह नीचा दिखाया, हराया और ठंढा किया वह हमारे आन्दोलन और कशमकस की एक लाजवाब और बेमिसाल चीज है। डुमरांव की लड़ाई में बहुत खूबियां हैं जो यहां कही जासकती हैं नहीं। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और मेरासर आपके सामने झुक जाता है।

ऊख और किगना फसलें।

ऊख वोनेवाले किसानों पर बीते दोसालके भीतर कौन कौन मुसीबतें गुजरीं यह किससे छिपा है? मैंनेतो इस मसलेपर बहुत कुछ कहा और लिखा है। जबतक किसान अपना निजी ऊख-संघ सूबेभर में किसान सभाकी मातहती में कायम नहीं करलेते, ऊख की खेती कम नहीं करते और गुड़ बनाने को हरदम तैयार नहीं होजाते तबतक उनकी तकलीफें बनीही रहेगी। सरकारी ओरसे ऊखवालों की सोसाइटियां बनाई जाती हैं उनमें किसान हर्गिज न जायें जबतक हमारी दो मांगे पूरी न हो जायँ। एकतो सोसाइटी में जानेवाले किसानों को आजादी रहे कि गुड़ महंगा होनेपर भी मिलोंमें ऊख देनेको वे मजबूर न हों और गुड़ बनासकें। दूसरे मिलवालों पर दवाव डालके ऊखकी कीमत बढ़ाने के लिए हड़ताल करनेकी आजादी उन्हें रहे, जब कभी इसकी जरूरत आजाये। इन्हीं दो शर्त्तों के पूरा होने परही किसानों

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

का हक मुनहसिर है, निर्भर है। इन दो शर्त्तों के विना सोसाइटियों में जानेपर उनकी तबाही बढ़तीही जायगी। चीनीकी मिलोंके मजदूरों की तकलीफें, मिलोंके चलते फैलनेवाली गन्दगी, बीमारी और मच्छरों की फौज से होने वाली मुसीबतें और शुगर सिंडिकेट की नादिरशाही वगैरह बातें ऐसी है जिनके बारे में कुछ न कहनाहीं अच्छा है। जब तक यह सिंडिकेट तोड़ न दी जायगी न तो किसान, न मजदूर और न चीनी खाने वाले ही आराम से रह सकेंगे या उनके साथ इन्साफ हो सकेगा। ऊख के दाम के बारे में भी जब तक खास तौर से सरकार ऐसी जांच न करे जिसमें किसान सभा को काफी मौका मिले कि खेती के खर्च का पूरा सबूत पेश करे और जांच कमिटी के फैसले पर पूरा असर डाल सके तबतक हमेशा अन्धेर-खाता और अटकल-बाजी ही चलेगी। मुख्तसिर यह है कि ऊख और चीनी के बारे में बुनियादी बातों की जरूरत है जो अभी हो नहीं सकी हैं।

इस कारबार को कामयाब बनाने के लिए हर इलाके में किसानों के लिए किराने की दो दो फसलों (money crops) का इन्तजाम सरकार को करना ही पड़ेगा। दूसरा चारा नहीं है। नहीं तो हमेशा तूफान जारी ही रहेगा। इन फसलों, गुड़ और आम तौर से दूसरी फसलों की पैदावार के लिए किसानों को काफी पैसे मिल सकें इसके लिए गोले का प्रबन्ध (marketing) सरकार को खुद करना होगा। नहीं तो लगान

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

और मालगुजारी न मिलने की शिकायतें घटने के बजाय बराबर बढ़ती ही जायँगी और नतीजा बुरा होगा।

खेतों के मजदूर।

अगर हम गावों की असली हालत की जांच करें तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में हर साल कम-वेश दस लाख किसानों की जमीनें लगान, मालगुजारी और कर्ज में छिनी जाती हैं, वे बिना जमीन के होते जाते हैं और इस तरह खेती के मजदूरों की तायदाद बढ़ती जाती है। यह बड़ी ही खतरनाक बात है। हमने जेल में बैठे बैठे इस सवाल पर बहुत छान बीन की और एक किताब भी लिखी है। सरकारी और दूसरी रिपोर्टों की बिना पर ही हम यह बात कह रहे हैं। अगर यही रवैया जारी रहा तो ज्यादे से ज्यादा सत्तर-अस्सी साल में वे सभी किसान बिना जमीन के हो जायँगे जो अपनी जमींनों में खेती करते हैं और उनकी जमीनें सिर्फ लगान पर जीनेवाले लोगों के पास जा धमकेंगी। इधर वे खुद मजदूर बन के मारे मारे फिरेंगे! इसीलिए खेत-मजदूरों का सवाल न तो अछूत या हरिजन कहे जाने वालों का है और न कुछ खास जातियों का। इस गरोह में तो आज वे सभी जाति वाले और धर्म वाले शामिल हैं और तेजी से होते जा रहे हैं जिनकी जमीनें धड़ाधड़ छिन रही हैं। वे यातो गैरों के खेतों में ही काम करके जैसे तैसे आधा चौथाई पेट खा पाते हैं या शीकमी और बटाई जमीनें. जोत-जात के गुजर करते हैं। अगर मुझसे कोई सच

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

पूछे तो मैं तो उन्हींको दर असल किसान मानता हूं। दूसरे किसान भी आज नहीं तो कल उन्हीं की कतार में जाने को मजबूर होंगे। यही वजह है कि किसान सभा उन्हें छोड़ नहीं सकती, उनकी ओर से आंखें मोड़ नहीं सकती और उनके सवाल को अपना सवाल बनाए बिना रह नहीं सकती। नहीं तो वह खतम हो जायगी और उसकी जरूरत रहेगी ही नहीं। मौजूदा खेत-मजदूरों के साथ इज्जत और भाईचारे का सवाल, उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात और उनके और हकों के मसले तो इस असली मसले के सामने फीके पड़जाते हैं। जब जमीन हमारे पास रहेगी ही नहीं तो मजदूरी बढ़ाने का क्या सवाल? जब किसान के पास खुद खाने को नहीं रहेगा तो वह खेत-मजदूर को क्या देगा? इसलिए ऊसर, चौर वगैरह की जमीनों को खेती के लायक बना के और उन्हीं जमीनों में बड़े बड़े जमींदारों की जिरात को भी मिलाके ऐसी जमींनें सब से पहले उन्हीं लोगों को दी जायँ जो खेत-मजदूर या निहायत गरीब किसान हैं। तभी यह सवाल थोड़ा बहुत हल हो सकता है। यों तो जब तक मुल्क में कल कारखाने काफी नही बढ़ते दिक्कतें रहेंगी ही।

मैं बहुत ढूँढ़-खोज के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जबतक जमींदारी का खात्मा बिना मुआविजा या कीमत दिये दियेही नहीं किया जाता—हां, जमींदारों के अच्छी तरह खानेपीने वगैरह का इन्तजाम तो करना ही होगा और वे कुछ

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

न कुछ काम करें इसका भी इन्तजाम जरूरी है—और जबतक कमसे कम अस्सी फी सदी किसान मालगुजारी, लगान या कर्ज की वसूली से कतई बरी नहीं करा दिये जाते जिनके पास गुजर बसर से ज्यादा पैदावार की जमीन नहीं है तबतक खेत-मजदूरों और किसानों का सवाल हल नहीं होगा—उसके हल का रास्ता साफ न होगा। अस्सी फी सदी से ज्यादा किसान अपनी जमीनों से बड़ी मुश्किल से जैसे-तैसे गुजर कर पाते हैं यह बात मैं ने वहीं साबित की है।

झारखंड के किसान।

छोटा नागपुर के पांच जिले और संताल परगने को मिलाकर छओं को झारखंड कहते हैं। यहांके किसान कातो मालूम पड़ता कोई भी पुसाँहाल है नहीं। अभी तक वहां जब्ती-कुर्की के जरिये लगान वसूल होता है जबकि बिहार में यह बात है नहीं। भावली जमीनों के बारे में जो कानून कांग्रेसी मिनिस्ट्री ने बनाये वह वहां अमली तौर पर आम तौर से लागू हुएही नहीं, यों तो कहने के लिए भलेही लागू करा दिये गये। पहाड़ी जमीनें काटके वे पहले बे-रोक खेत बना लेते थे जिन्हें 'कोड़कर' और 'उटकर' कहते हैं और बहुत साल के बाद जमींदारों को मामूली लगान देते थे। मगर अब यह बात नहीं रही और ऐसी दिक्कतें पेश कर दी गई हैं कि यह काम बन्द-सा है। पलास, बेर और कुसुम के पेड़ों से लाह पैदा

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

करने में उन्हें कोई दिक्कत न थी। मगर अबतो अपने खेतों में लगे पेड़ों में भी वे ऐसा कर पाते नहीं। महुवे का फल उनके गुजर की खास चीज है। मगर अब उसपर भी आफत है। जेल डिपार्टमेन्ट और कानीहौस के चलते वे हाय मार के रह जाते हैं और लुट जाते हैं। उनके बच्चों को उनकी अपनी जबान (भाषा) पढ़ाने का अबतक कोई भी इन्तजाम किया नहीं गया है और यह कैसा अन्धेर है। संताल परगने के पहाड़िया लोगों परतो आफत का पहाड़ ही टूट पड़ा है। वे अबतक जंगलों को काट-काट के एकतरह के बिना हल बैल की खेती करते और गुजर करते थे जिसे झूमचास या कुरांवचास कहते हैं। अब वह ऐसा कर पाते नहीं। कानूनी रोक डालदी गई है और वह दूसरी तरह जीविका करना जानते नहीं। यह है उन झारखंडियों की सैकड़ों तकलीफों में केवल दोई-चार। लोग कहते हैं दुनिया में न्याय है, खुदा है, भगवान है। मगर उसका पता कहां है ? इन तबाह और पामाल झारखंड-वालों से कोई पूछे तो क्या इसका जवाब मिलेगा ?

किसान सभा का संगठन।

आखिर में मैं किसान सभा के संगठन पर आपका खयाल लाना चाहता हूँ। हम और आप बहुत घमंड करते हैं कि हमारे यहां की किसान सभा काफी मजबूत है। दूसरे सूबे वाले भी ऐसा ही समझते हैं। मगर मुझे यह सुनके दर्द होता है, शर्म आती है, तकलीफ होती है। सूबे के सोलह ज़िलों में

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

तीन सौ से ज्यादा थाने हैं। भला आप कह सकते हैं कि कितने जिलों की किसान सभायें बाकायदे जबर्दस्त आफिस रखती हैं और काम करती हैं? अगर जिलों में कुछ को छोड़ ज्यादातर में जैसे तैसे आफिस हों भी और वे काम भी बुरा-भला करते हों तो भी कितनी थाना किसान कौंसिलें ऐसी हैं? हरेक ने साल में कितने मेम्बर किसान सभा के बनाये, अपने चन्दे का कोटा जिले और सूबे को भेजा, बाकायदा रिपोर्ट भेजी और बकाश्त या जंगल वगैरह की लड़ाइयां लड़ीं? जब हम ठिकाने से कागजी घोड़े भी नहीं दौड़ा सकते तो मौके पर किसानों की लड़ाई के समय सरकार या जमींदारों के असली घोड़े जब किसानों की छाती पर दौड़ना चाहेंगे तो उन्हें रोकेंगे कैसे? जब हमने बाकायदा किसान सेवक दल बनाके उसे तैयार नहीं किया और किसान-कोष में पैसे वगैरह जमा नहीं ही किये तो बकाश्त की लड़ाई लड़ेंगे क्या खाक? और जब हमारे पास एक हफ्तेवारी अखबार भी नहीं है तो किसान सभा की ताकत की डींग फिजूल है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम चल नहीं सकते, रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते।

बातें तो बहुत ज्यादा हैं और उन्हें कहने को दिल भी चाहता है। मगर लम्बा पोथा जो हो गया। इसकी तोंद आखिर कितनी बढ़ाई जाये? कागज भी तो मिलता नहीं कि सभी बातें छापी जा सकें। इसलिए आज इतने से ही सब

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

करना ठीक है। उम्मीद है, आप भाई यहां से जाने के पहले कुछ ऐसा तय करके जांयगे जिससे किसान सभा का झंडा ऊँचा फहराता रहे, किसानों का पेट भरे, उनका तन ढँके, उन्हें सर उठाके इज्जत के साथ जिन्दगी गुजारने का मौका मिले, हमारा मुल्क आजाद हो, यहां किसान-मजदूर-राज्य कायम हो।

इन्किलाब जिन्दाबाद। नात्सीवाद मुर्दाबाद।
फासिज्म का नाश हो। पूंजीवाद खत्म हो।
जमींदारी प्रथा चौपट हो।

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

PRINTED BY
GOPAL LAL
AT THE RAJESHWARI PRESS,
GAYA.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra
ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

PEASANTS' REVOLTS

(1845-1875)

Compiled by

INDULAL YAJNIK

Joint Secretary, All-India Kisan Sabha

21 DALAL STREET, BOMBAY.

Price one anna—(Eight annas a dozen).

Printed by K. K. Pathak at the Karmavir Press, Jubbulpore.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgac

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Preface.

I have great pleasure in publishing the second edition of this pamphlet that was issued under the title "Agrarian Disturbances in India" about two years ago.

Two minor changes have been made in revising the first edition. The section about the condition of the Halis (agrarian serfs) in Bombay Presidency has been omitted because its importance demands separate treatment. And an instructive extract from the minute submitted by Mr. Auckland Colvin on the Deccan Riots has been added to the reports. Besides the various sections have been rearranged in a chronological order.

It is intended to add authentic reports of later peasants' revolts as these become available.

These records of revolts against the Sahukars (money-lenders) shed a lurid light on the oppressive burden of peasants' debts that is being discussed today throughout the country. The pamphlet must serve as a lesson and a warning to all Governments and politicians to deal promptly and effectively with the Sahukari terror that snuffs out the life and happiness of the millions of Kisans.

Jubbulpore,
27th February 1939.

Indulal Yajnik.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

PEASANT'S REVOLTS

In view of the current discussions on the ever-increasing debts piling on the bent backs of the Indian peasantsy, and the sporadic agrarain disturbances often directed against the village money-lenders in all parts of the country, it would be instructive to study the course of similar events since the advent of British rule in India.

A wave of agrarain riots swept through the villages of Poona and Ahmednagar districts in 1875. The Commissioners appointed by the Government to inquire into the genesis of these disturbances submitted a heavily documented report on its course and causes and made several recommendations for the protection of the peasants that were afterwards incorporated in the Deccan Agriculturists' Relief Act.

The Commission the also gave a brief resume of similar disturbances that had happened before in the Bombay Presidency and reproduced a whole chapter on the Santhal Rebellion of 1855, as an appendix, from Sir W. W. Hunter's *Annals of Rural Bengal.*

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgac

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

The facts about these disturbances dating from 1845 to 1875 are briefly reproduced below from the above sources.

I.

1845—1874.

In 1845 the Bheel Chief Raghoo Bhangrin headed a large body of plundering Bheels, whose practice it was to cut off the ears and noses of Marwari sowcars wherever they could find them.

The Kolis of the hill ranges between the Poona and Thana districts have from time to time organized gangs which have employed themselves chiefly in the plunder, often in the murder and mutilation, of money-lenders.

In a remarkable letter of Sir G. Wingate to the Bombay Government in 1852, the following passage occurs :—

"These two cases of village money-lenders, murdered by their debtors almost at opposite extremities of our Presidency must, I apprehend, be viewed not as the results of isolated instances of oppression on the part of creditors, but as examples in an aggravated form of the general relations subsisting between the class of money-

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

lenders and our agricultural population. And if so, what an amount of dire oppression on the one hand, and of suffering on the other, do they reveal to us? What must be the state of things which can compel cultivators, proverbially patient and long-suffering, accustomed to more or less of ill-usage and injustice, all the time, to redress their wrongs by murder and in defiance of an ignominions death to themselves? How must their sense of justice have been violated? How must they have been bereft of all hopes of redress from law or Government before their patient and peaceful natures could be roused to the point of desperation required for such a deed?"

The Santhal Rebellion

The Santhal rebellion of 1855 is, so far as we are aware, the only other instance in the history of British India of a wide-spread disturbance arising out of the relations of the agricultural and money-lending classes.

The following detailed account is culled from Hunter's *Annals of Rural Bengal*:—

Along the skirt of the Santhal country, from the ring-fenced colony on the north to the high-

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

land valleys of Beerbhom, (Bengal) Hindu hucksters settled upon various pretences, and in a few years grew into men of fortune.

They cheated the poor Santhal in every transaction. The forestor brought his jars of clarified butter for sale, the Hindu measured it in vessels for salt, oil, cloth and gun-powder; the Hindu used heavey weights in ascertaining the quantity of grain, light ones in weighing out the articles given in return. If the Santhal remonstrated, he was told that salt, being an excisable commodity, had a set of weights and measures peculiar to itself. The fortunes made by traffic in produce were augmented by usury.

The Hindu dealer gave them a few shillings worth of rice, and seized the land as soon as they had cleared it and sown the crop. Another family, in a fit of hospitality, feasted away their whole harvest, and then opened an account at the grain-dealers, who advanced enough to keep them above starvation during the rest of the year. From the moment the peasant touched the borrowed rice, he and his children were the serfs of the corn merchant. No matter what economy the family practised, no matter what

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

effort they made to extricate themselves, stint as they might, toil as they might, the Hindu claimed the whole crop, and carried on a balance to be paid out of the next harvest.

Year after the year Santhal sweated for his oppressor. If the victim threatened to run off into tha jungle, the usurer instituted a suit in the Courts, taking care that the Santhal should know nothing of it till the decree had been obtained and execution taken out. Without the slightest warning, the poor husbandman's buffaloes, cows. and little homestead were sold, not omitting the bronze household vessels which formed the sole heirloom of the family. Even the cheap iron ornaments. the outward tokens of female respectability among the Santhals were torn from the wife's wrists.

A mitigated serfdom like this is indigenous in every country where the people increase aud the means of subsitence stand still. It represents the last resource of labour when placed by over-population completely at the mercy of capital. The labouring man, toil as he may, can earn at the most a bare subsistence; a bare subsistence is

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

the least that the master can give to his slave. Between 1838 and 1851, the population within the pillars increased from 3,000 to 82,795, besides 10,000 on the outskirts: and the landless Santhals, finding himself seldom worse off as a serf than as a free labourer, acquiesced in his fate.

But in 1854, events occurred that completely altered the relation of capital to labour in Bengal. The Government had determined to give Railways to India, and the line skirted the Santhal country for two hundred miles. High embankments, heavy cuttings, many arched bridges, created a demand for workmen such as had never been known in the History of India. Some years later, twenty thousand were required in Beerbhoom alone: and the number along the sections running through or bordering on the Santhal territories amounting to one hundred thousands men, or more than the whole overflowing of the Santhal race during a quarter of a century.

It was then that the distinction between the slave and the free man began to make itself felt. The entire free population who had not land of their own went forth with their women and

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

children, their bows and arrows in their hands, and the national drum tatooing in the front, to work for a few months on the railway, and then to return and buy land, and give feasts to their clansmen. The slaves, who were compelled to remain working for their masters at home, contrasted their own lot with that of the prosperous adventurers. Running away became common: and the Hindu masters had recourse, in self-defence, to a much stricter and more vigilant system than they had ever before practised. The same causes that had made the slave eager for freedom had rendered him more valuable to his master, and it became clear that the great issue would soon have to be tried, whether it was possible, in the second half of the present century, under British laws, to keep men slaves when it was worth their while to be free.

During the cold weather of 1854 and 1855 the Santhals appeared to be in a sttange, restless state. They had gathered in an excellent crop, and the influx of capital had enhanced the local price of agricultural produce. Nevertheless the highlanders continued excited and discontented,

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

The truth was that the rich Santhals had determined to be no longer the dupes of the Hindus, who intercepted these high prices; the poorer agriculturists had determined to be no longer their serfs, and the day-labourers had determined not to be their slaves.

To a people in this frame of mind, leaders are seldom wanting. Two brothers, inhabitants of a village that had been oppressed beyond bearing by Hindu usury, stood forth as the deliverers of their countrymen, claimed a divine mission, and produced heaven-sent tokens as their credentials. The god of the Santhals, they said, had appeared to them on seven successive days, at first in the form of a white man in a native costume, next as a flame of fire, with a knife glowing in the midst: then as the perforated slice of a sal trunk which forms the wheel of the Santhal's bullock-cart. The divinity delivered to the two brothers a sacred book, and the sky showered down slips of paper, which were secretly spread throughout the whole Santhal country. Each village received a scrap without a word of explanation, but with an imprecation, as it would avoid the wrath of the national god, to forward it without a moment's pause to the nearest hamlet.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

The brothers found that they had raised a storm which they could not control. A general order went through the encampment to move down upon the plains towards Calcutta, and on the 30th June 1855 the vast expedition set out. The body-guard of the leaders alone amounted to 30,000 (thirty thousand!) men. As long as the food which they had brought from their villages lasted the march was orderly, but unofficered bodies of armed men roaming about, not very well knowing where they are going, soon became dangerous: and with the end of their own stock of provisions, the necessity for plundering or levying benevolences commenced. The leaders preferred the latter, the rabble the former.

On the 7th of July, a Native Inspector of Police heard of the entrance of a vast body of hill-men, with the two brothers at their head, into his jurisdiction: and the Hindu usurers, becoming uneasy, bribed him to get up a false charge of burglary against the band, and apprehend their leaders. He went out with his guards, but was met half-way by an embassy from the Santhals, with instructions to escort him into their camp. The two brothers ordered him to

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

levy a tax on every Hindu family in his jurisdiction, for the subsistence of their followers and were about to dismiss him in peace, when some one discovered that he had come out with the intention of getting up a false complaint. At first he denied the charge, saying he was on his way to investigate an accidental death from snake-bite, but afterwards confessed the usurers had bribed him to get up a false case of burglary, and bring in their leaders bound. The two brothers said, "If you have any proof against us, take us and bind us." The fooldardy Inspector, presuming on the usually peaceable nature of the Santhals, ordered his guards to pinion them, but no sooner were the words out of his mouth, then the whole mass rushed upon, and bound him and his minions. After a hurried trial the chief leader Sidu slew the corrupt Inspector with his own hands, and the police left nine of their party dead in the Santhal camp.

From this day—7th of July—the rebellion dates. At the time of their setting out, they do not seem to have contemplated armed opposition to the Government.

When all was over, their leaders, who in other respects at any rate disdained equivocation

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

or falsehood, solemnly declared that their purpose was to march down to Calcutta, in order to lay the petition which the local authorities had rejected at the feet of the Governor-General; and the truth of this statement is rendered probable by the fact that their wives and children accompanied them. Indeed, the movement could not be distinguished at first from one of their great national processions, headed by the customary drums and pipes. Want drove then to plunder, and the precipitate outrage upon the Inspector of police changed the whole character of the expedition. The inoffensive but onlf half-tamed highlander had tasted blood, and in a moment his old savage nature returned.

About the 25th July, Government finding that it must take severer measures, placed the reduction of the rebels in the hands of an experienced commander, with instructions that amounted to delivering over the disturbed districts to the military power.

The details of border warfare, in which disciplined troops mow down half-armed peasants, are unpleasant in themselves, and afford neither glory to the conquerors nor lessons in the military art. After a lapse of thirteen years, the

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

officers who reduced the Santhals can hardly be brought to dwell minutely on the operation. "It was not war" one of them has said to me. "It was execution; we had orders to go out whenever we saw the smoke of a village rising about the jungle. The Magistrate used to go with us. I surrounded the village with my sepoys, and the Magistrate called upon the rebels to surrender."

II.

Slavish Condition of the Khandesh Bhils

The Commissioners appointed by the Government of Bombay to inquire into the course and causes of the Deccan Peasant's Riots in 1875, took great pains to examine the relations between the poor peasants and the rich money-lenders in the Deccan, Gujerat and other provinces of India Special attention was naturally devoted to the miserable condition of the half-naked Bhils though they had so far shown no signs of unrest.

The following extracts from the reports submitted by Mr. Pritchard, First Assistant Collector of Khandesh in 1870, throw lurid light on the chains of slavery in which the Bhil.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

Peasants were then held by the Gujars, Wanis and other money-lenders.

THE OFFICIAL REPORT ON BHILS IN 1870.

" A few years ago written agreements with Bhils were almost unknown. They are unknown, to this day, in the adjacent *parganas* of Nawapur and Akhrani, and in the neighbouring Mehwasi States. The first form these writings took was that of " Salkhuts " or agreements for service for a fixed period in consideration of a sum of money paid in advance. The enforcement of such contracts was by Act XIII of 1859 entrusted to the magistrates, to whom the law allows discretion and liberty to decline to pass orders in cases in which they may not be satisfied that the alleged contract is just and proper. The *Guzur* found that those papers were useless for oppression, the purpose they were intended to serve, unless it were shown that the consideration mentioned in the Salkhut was really made over to the Bhil, and that his maintenance was provided, for no magistrate would compel him to perform service.

So Salkhuts were put on one side. Plentiful as they were three years ago, there is hardly one

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

to be found throughout these districts. Now every *Guzur* has a bond on stamped paper purporting to be executed by his servant, acknowledging the loan of a sum of money the man can never by any chance repay. Directly an *Awtya* (serf) shows a disposition to leave a *Guzur's* service, his master files a suit agains thim in the Civil Court for amount set forth in the bond. The Bhil, knowing he has no chance of success does not appear to defend the suit. The Court accordingly decrees against him, and a distress warrant follows: the poor wretch's few household goods are seized, any little ornament his wife may passess is taken from her, and he himself is arrested and carried off a prisoner to the Munsiff's Court.

There his master, having reduced him to a state of utter helplessness, offers him his choice of returning to work or going to the Dhulia Jail. He returns to service, with the liabilities increased by the cost of the suit, of his own arrest, etc., and with no proper agreement with his master. It is no part of the duty of the Court, even then, to see that his master is bound down to treat him fairly. He serves on for a few more month, or perhaps years,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

on a pittance of grain and the smallest quantity of clothing that will cover him until, tired out, he again strikes work: again his master rushes off to the Court and this time the Bhil is not even invited to have his say: the former decree is still unsatisfied, and another distress warrant is issued without further inquiry. The first the Bhil hears of it, perhaps, is from the sepoy who has come to arrest him. And so it goes on from year to year.

What is this man but a slave? What hope has he? What redress is there for him? He cannot appeal to the Judge, besides the Judge's Court is 80 miles away, and months must pass before his complaint can be heard even if his friends manage to provide the money necessary, as he did not defend the suit originally brought in the Munsiff's Court. He is a mere chattel to be disposed of whenever his master may want money. It is a common occurrence for one *Guzur* to sell his Awtya to another, under the pretence of a transfer of the Awtya's debts. A well-encumbered Bhil with a decree of the Civil Court out against him is a more valuable commodity in the West than one whose liabilities are smaller.

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

Another from of fraud commonly practised by *Guzurs* in their dealings with Bhils, and one even more fatal to the latter than that described above, is the following:—A *Guzur* advances Rs. 40 (say) to a Bhil wherewith to buy a bullock on the understanding that the Bhil and his bullock are to work on the lender's farm, the Bhil becoming a *Gowandya* (or partner) in the concern to the extent of half a plough. A bond is made out for the amount advanced, *plus 25 per cent.* premium, *plus* very likely a further amount on account of old debts unjustly claimed. Interest at the rate of 24 per cent. is charged on the whole amount entered, and at the rate of 50 per cent. on the grain advanced for the Bhil's food till harvest time.

The *Guzur* has besides the advantage of the Bhil's labour *free* for his share of the plough. He keeps the accounts and manages the sales, and cheats the Bhil to his heart's content in the division of the produce. So much so, that in all the cases I have gone into, I only remember *two* in which a Gowandya's debt was not *increased* at the end of a year according to the *Guzur's* accounts, though none of them ever had more than food and clothes from the partner.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

At the end of the year there is a pretence of adjusting accounts. The first year the Bhil is put off with the argument that he has to pay for his bullock: next year, too, he gets nothing but clothes and food, and is told he has still to pay something. He asks for a settlement of his account, and as a preliminary he is sent to fetch a new stamped paper. His master and two or three "responsible" *Patels* meet and talk his affairs over. A few soft words are said to him, and he is given money to buy his wife a new saree and a little liquor for himself. A new bond is made out, the contents of which he does not understand in the least, and he goes back to his work hoping for a bumper crop and a better luck next year.

He struggles on for another year or two, and then feeling that the state of things is very unlike what partnership in a profitable farm ought to be, he determines to leave. Then for the first time he realizes the fact that his partner or master rather, has acceptance for Rs. 200, or more: that the bullock he had toiled for all these years is not his; and that he and all he has is at his master's mercy. The Civil Court is resorted to and, as in the case of the Awtya

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

described above, all his goods are seized and sold and he perforce becomes the Guzur's slave.

I need hardly describe the tactics pursued by the professional money-lenders. They are the same here now as 30 years ago prevailed all over the Presidency, and have been often described before. The Bhil is a very easy victim, and the Khandesh Wani is as merciless and unscrupulous as Shylock.

"The subject appears to me one of the greatest importance. The Western Bhils are more oppressed than ever, and their complaints are louder every year. I am confident that unless a remedy is soon provided, they will learn to believe that Government does not intend to help them, and will trust to their own resources for relief. It may be well to remember that the Santhal rebellion arose out of a state of things precisely similar to that now existing in the west of Khandesh, and that though no indications of an approaching outbreak may have presented themselves here, neither did the Santhals give a word of warning before they burst on the plains of Bheerbhoom with an army 30,000 strong to avenge themselves on the usurers who had robbed and enslaved them under the tacit sanction of our Civil Law........."

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

III

Deccan Riots.

The Commission appointed to report on the Deccan agrarain riots of 1875 did not refer to any instances of lawlessness directed against money-lenders between 1855-1871.

No doubt there were periodical revision settlements and consequent additions to the Government demand of land revenue. But the American Civil War of 1865 brought a boom in the cotton market and a harvest of gold to the cotton growers and other peasants of the Presidency.

But the boom period suddenly ended with the Civil War in about 1870, and the unwary peasants, who had borrowed extensively on the strength of their illusory prosperity, found themselves literally crushed under heavy burdens of debts in the seventies of the last century.

Let us now follow the narrative of subsequent disturbances as given by the Deccan Riots Commission.

1871—1875.

In Kaira.—From April 1871 to July 1875 moneylenders were the victims in the following

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

offences:—murders 9 ; grievous hurt and wounding 10 ; arson 7 ; assaults 24 ; assaults with a view to rescue property attached or taken for debts 12 ; thefts 3 ; trespass by re-entry into property taken under attachments 4. There were besides 3 suicides of debtors on account of debt, and 2 cases of Traga (self-inflicted hurt) for the same reason. Total 79 offences in four years and three months.

In Ahmednagar

From April 1871 to October 1874, money-lenders were the sufferers in the following cases:—murders 2 ; dacoities (including one case of mutilation) 5 ; house-breaking with theft of property and bonds, etc., 7 ; riots 3 ; arson 1. Total, 18 offences in three years and six months.

In Poona

In the years 1872 to 1874, money-lenders were the sufferers in the following case:—murder 1 ; robbery 7 ; mischief 8 ; thefts 24 ; hurt 29 ; criminal force 8. Total offences in 5 years, 71.

The Police Reports of the Presidency for 1874 show two murders and four dacoities, of which money-lenders were the victims, in the districts of Ratnagiri, Sitara, Sholapur, and Ahmedabad,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gra

THE RYOTS' PREMONITORY DISTURBANCES

The first open indication of the spirit of hostility against the Marwari money-lender which led to the riots, was shown by the inhabitants of the village of Kardeh, in the Sirur Taluka of the Poona Collectorate, at the end of 1874. A Deshmukh (district hereditary officer) of good family and some influence, who had accumulated a fortune in the service of His Highness Scindia, to whom he is related, had settled in the village, and, having spent his fortune, had fallen deeply in debt. Two of his creditors, Kalooram and Bhugwadas, Marwaris, got decrees against him and Kalooram took out a warrant of arrest. The Deshmukh gave Kalooram personal ornaments, and the warrant was not executed. About four months afterwards some ornaments and property belonging to the temple of Vithoba at the Deshmukh's house were attached, but at the instance of the villagers, Kalooram allowed the attached property to remain in deposit with a third party for two months. At the end of that term, as the Deshmukh had not paid the value of the property, it was taken possession of by Kalooram. A third execution was issued on Kalooram's decree, and

ajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgao

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

the Deshmukh's house and lands were attached and sold for a song, there being no bidders against the Marwari decree-holder.

The villagers who combined against these Marwaris did not confine themselves to a passive hostility. Besides refusing service as water-carriers, barbers, household servants, etc., they subjected the Marwaris to annoyance by throwing the carcases of dogs and other filth into their premises, and generally showed such a spirit of personal hatred, that the money-lenders, on retreating to Sirur for the protection of the police of the taluka headquarters, petitioned the Magistrate, representing that they were in bodily fear of the villagers. The Magistrate considered the spirit shown by the people to be of a dangerous nature, and reported it to the Police Commissioner accordingly.

The Outbreak

The first actual outbreak occurred at Supa, a large village of the Bhimthari Taluka of Poona, on the 12th May 1875. The victims of the rioters were the Guzerathi Sowcars, of whom there are a large number in Supa. Their houses and shops were attacked by a large mob princi-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

pally recruited from the hamlets round Supa, who had assembled ostensibly to attend the market on bazar day. The houses and shops were gutted of every thing that the rioters could find, and one house was burnt down, but no violence to persons was committed. The rapidity with which the example was followed, through the whole area affected, shows that everywhere the same influences had brought the villagers to the same readiness for resort to force.

Within twenty-four hours of the riot at Supa, the leading Marwari Sowcar of Kheirgaom, a village about 14 miles distant, had his fodder stocks burnt down and his house attacked with fire, and during the following days riots occurred in four other villages of Bhimthari and were threatened in seventeen more. The contagion spread to the neighbouring districts of Indapur and Purandher, in the former of which a disturbance, which would have been serious from the number assembling, was averted, as were the riots threatened in the seventeen villages above noted, by the promptitude of the police. A detachment of native infantry having arrived at Supa, the police were relieved and available for other duty, and order was quickly restored.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

In the meantime riots commenced in the Sirur Taluka. The first violence was committed at Navra, where a Marwari, who had left the village for safety, was mobbed and prevented from removing his property to the place whither he had himself retreated. An uncle of this Marwari had some two years previously been murdered by his debtors. Other villages of Sirur followed the example, Kardeh being one: at Damareh a Marwari had his leg broken and was saved from death by some of the rioters dragging him out of his burning house. Altogether fifteen villages of Sirur Taluka and three of Haveli Taluka were the scene of riot or threatened disturbance. The Regiment of Poona Horse, which has its headquarters at Sirur, supplied parties to assist the Assistant Magistrate and the police in restoring and maintaining order.

While these disturbances were going on in the Poona District, similar outbreaks were occurring in the neighbouring talukas of Ahmednagar, and during the fortnight following the riot at Supa on 12th May, riots took place in the talukas of Shrigonda, Parner, Nagar and Karjat, and beside actual rioting there were numerous gatherings which were prevented from proceeding

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection, Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

to violence by the timely arrival of police or military. A detachment of native infantry was moved to Shrigonda, and parties of the Poona Horse were active in patrolling the villages in the west within reach of their headquarters as Sirur.

THE EXTENT OF THE RIOTS

In Poona disturbances more or less serious took place in five villages of Bhimthari Taluka, and six villages of Sirur Taluka.

Disturbances were threatened but averted by the arrival of the police in:

17	villages	of	Bhimthari
10	,,	of	Sirur
3	,,	of	Haveli
1	village	of	Indapur

In Ahmednagar disturbances took place in :–

6	villages	of	Parner Taluka
11	,,	of	Shrigonda
4	,,	of	Nagar Taluka
1	village	of	Karjat

Disturbances were threatened in many other villages.

The following shows the number of persons arrested in connection with the disturbances and the results of the trials held:

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

In Poona

Persons arrested 559, of whom 301 were convicted and 258 discharged.

In Ahmednagar

Persons arrested 392, of whom 200 were convicted and 192 discharged.

Punitive police posts, mustering a total of 98 men, were established at the expense of the inhabitants among the disturbed villages. As was to be expected, the greatest difficulty was experienced by the Magistrates in obtaining trustworthy evidence against the rioters.

The riot at Supa was singular in the whole-sale plunder of property, and that at Damareh in the murderous assault upon the money-lenders. In a few other instances, personal violence was used, and in several places stacks of produce belonging to money-lenders were burnt; but as a rule the disturbances were marked by the absence of serious crime. The object of the rioters was in every case to obtain and destroy the bonds, decrees, etc., in the possession of their creditors: when these were peaceably given up to the assembled mob, there was usually nothing further done. When the money-lender refused

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

or shut himself up, violence was used to frighten him into a surrender or get possession of the papers. In most places, the police interfered during the first stage of assembling and threatening, and so prevented violence. From many villages, the Marwari sowcars fled on the first news of the outbreak. In other villages, they opened negotiations with their debtors for a general reduction of their claims, and in some cases propitiated their debtors by easy settlements. In almost every case enquired into the riot is stated to have commenced, on news arriving of money having been extorted in some neighbouring village, with the usual story which will be noticed hereafter that the Government approved of the proceeding. The Marwari and Gujur sowcars were almost exclusively the victims of riots, and in villages where sowcars of the Brahmin and other castes shared the money-lending business with Marwaris, it was usual to find that the latter were only molested. There were, however, exceptions where the leading or only sowcars were of the Brahmin caste, as in the case of the village of Ghospuri.

The last of the connected series of outbreaks occurred at Mundhali in Bhimthari Taluka on

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

the 15th June, but there were subsequently two isolated cases in Poona, which showed that the warning conveyed by the long catalogue of convictions and punishments and the imposition of punitive police posts, had not extinguished, but only repressed, the violent temper of the cultivator.

On 22nd July, seven men of the village of Nimbut, Taluka Bhimthari, besides committing a robbery of documents, cut off the nose of a man who was enforcing a decree of the Civil Court, which had put him in possession of land belonging to one of the perpetrators of the outrage. On 28th July, the villagers of Karhati, Taluka Bhimthari, broke into the house of a Marwari sowcar and took away grain which was stored there. He had refused them advances of grain except on terms as to the renewal of his bonds or settlement of his debts, to which they were unable or unwilling to agree.

Besides these two cases in the Poona District, etc., sequels as it were of the general movement, the following case must be noticed. On the 10th September in the village of Kukrur, in the South-West of the Collectorate of Satara, a riotous outrage was committed by the rioters of

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

Poona and Ahmednagar. About 100 or more of the villagers attacked, plundered and burnt the house of a leading Gujur sowcar, collected all papers and accounts which they found in the house, destroyed them, and then dispersed. The cause of the riot was declared by the rioters who were arrested to be the harsh proocedings of the sowcar against his debtors: the Magistrate in charge of the Taluka reports that " news of the doings in Poona and Nagar Districts had no doubt reached all parts of the country some time ago, and probably suggested the idea to the people of Kukrur." Kukrur is more then 100 miles from the nearest part of the disturbed District in Poona.

The Moderation of the Peasants

In reviewing the character of the disturbances generally, the most remarkable feature presented is the small amount of serious crime. A movement which was a direct appeal to physical force was over a large area usually restrained within the limits of a mere demonstration: the few cases which show the vindictive spirit usually displayed in agrarain disturbances, are probably to be accounted for by the presence of other element besides the ordinary Kunbi peasantry.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

This moderation is in some measure to be attributed to the nature of the movement itself. It was not so much a rebellion against the oppressor, as an attempt to accomplish a very definite and practical object, namely the disarming of the enemy by taking his weapons (bonds and accounts), and for this purpose mere demonstration by force was usually sufficient.

IV.

Mr. Auckland colvin's minute on the Deccan riots

18. The Kumbi, especially if a headman, is occasionally prosperous and able to invest his little capital in petty loans: more often he is involved in the commencement or the midcourse of difficulties, the issue of which every day's observation of his fellow may teach him: and in a large number of cases, he either is in or is about to occupy the curious position which seems likely to be the outcome of all the expenditure in surveys. The position is that of a man recorded as occupier of his holding, and responsible for the payment of revenue assessed on it, but virtually reduced by pressure of debt to a tenant-at-will, holding at a rack-rent, and sweated by, his Marwari creditor. It is in that creditor's power to eject him any day by putting in force

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

any one of the decrees he had against him: and if allowed to hold on, it is only on condition of paying over to his creditor all the produce of his land not absolutely necessary for next year's seed grain or for the support of life.

The peasant is indebted on an average to the extent of sixteen or seventeen years' payment of the Government revenue. He has nothing to hope for, but lives in daily fear of the final catastrophe. Under a so-called ryotwary system it is gradually coming to this, that the ryot is the tenant and the Marwari is the proprietor. It is a zemindari settlement: but it is a zemindari settlement stripped of all the safeguards which under such a settlement in Upper India are thought indispensable to the tenant. The proprietor is irresponsible, the tenant unprotected. *It promises to become not a ryotwari, but a Marwari settlement.* The settlement is more and more between the Government and the Marwari, though neither declares the position. While the Marwari has no wish to possess himself of the land, but of its produce only, the Government, so long as the Kumbi is recorded as proprietor, hesitates to look below the surface. Hence the survey which found him thirty years

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

ago in debt, but with thousands of waste acres to fall back upon, returns to him and finds him more in debt than ever, but with little or no reserve of waste acres. Nevertheless, it calls on him for largely increased payments: and the Marwari, on whom the increased payments fall, replies to the call not by remonstrating against the assessment, but by squeezing fresh bonds or by taking his debtor into court. The Kumbi's last state is worse than his first, and from all sides the pressure is increasing on him.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gran

OTHER PUBLICATIONS

	Rs.	As.	Ps.
Modern Indian Peasant	1	0	0
Kisan Speaks	1	0	0
Kisan Hand Book	0	8	0
Kisan Movement	0	8	0
Kisans and Congress	0	8	0
Kisan Githavali (Hindi)	0	2	0
Tribes of Nilgiris	0	8	0
Economic Conditions of Zamindari Ryots (Andhra)	1	0	0
Labour in South India	1	8	0

SHORTLY TO BE PUBLISHED

Guide to Village Economic Surveys	0	2	0
Peasant Fact Book			

ALL INDIA KISAN PUBLICATIONS

23, STRINGER ST., MADRAS G. T.

First six publications to be had also from:

EDITOR, A. I. KISAN BULLETIN,

21, DALAL STREET FORT BOMBAY,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

C-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

भारतीय

संयुक्त समाजवादी सभा

लक्ष्य तथा कार्यक्रम

सभापति

बिहार प्रांतीय संयुक्त-किसान सभा

कदमकुआँ, पटना

[मूल्य एक आना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा

लक्ष्य तथा कार्यक्रम

भारत के विभिन्न वामपक्षी, समाजवादी एवं प्रगतिवादी दलों तथा संगठनों ने जिनकी संख्या २० से अधिक थी, मिलकर सर्वसम्मति से 'भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा' की स्थापना अभी हाल-ही में नेताजी-भवन, कलकत्ता, में की। इसमें बहुसंख्य ऐसे व्यक्तियों और विद्वानों ने भी योग दिया, जो समाजवाद एवं साम्यवाद में विश्वास रखते हुए भी किसी वामपक्षी या समाजवादी दल के सदस्य नहीं हैं। विभिन्न दलों और संगठनों के प्रतिनिधि भारत के सभी प्रांतों से आए थे। शायद ही कोई प्रांत बचा हो। जिस संयुक्त समाजवादी सम्मेलन में यह महान कार्य संपन्न हुआ, उसमें उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या प्रायः तीन सौ थी। श्री शरच्चंद्र बोस ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। उद्घाटन भी उन्हींने किया। २८, २९, ३० अक्तूबर १९४९ को यह सम्मेलन क्रमशः स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री शंकरराव मोरे और जनरल मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा (United Socialist Organisation of India) के अध्यक्ष श्री शरच्चंद्र बोस चुने गए। सम्मेलन में शरीक सभी दलों के दो-दो प्रतिनिधियों को मिलाकर अस्थायी जेनरल कौंसिल (General Council) बनाई गई, जिसके लिए देश भर से १० प्रतिनिधियों को सभापति उन व्यक्तियों में से नामजद करेंगे, जो किसी दल से संबद्ध न होते हुए भी जन-प्रतिनिधित्व की हस्ती रखते तथा सम्मेलन के मन्तव्यों को मानते हैं। इस प्रकार कम-बेश ५० सदस्यों की वह कौंसिल होगी, जिसकी पहली बैठक कलकत्ते में ४ दिसंबर, १९४९ को होगी। उसीमें मंत्रियों आदि का चुनाव होगा। वही कौंसिल भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा का विधान भी तैयार करेगी, जो उस सभा के अगले खुले अधिवेशन में स्वीकार होने के लिए पेश होगा। यह अधिवेशन अगले मार्च-अप्रैल तक होगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

सम्मेलन में श्री मावसेतुंग के नेतृत्व में चीनी जनता की विजय, वहाँ जनता की प्रजासत्ताक सरकार की स्थापना एवं च्यांग कैसेक के शासन के ध्वंस पर खुशी जाहिर की गई और चीनी जनता तथा उसकी नवीन सरकार को बधाई दी गई। भारत सरकार उसे फौरन मान ले, यह माँग भी की गई। कांग्रेसी सरकारों के द्वारा जो दमन की चक्की चालू है, उसकी निंदा भी इस सम्मेलन ने की। भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा के लक्ष्य, नाम तथा कार्यक्रम के संबंध में नीचे लिखी घोषणा तैयार की गई :—

'द्वितीय विश्व-युद्ध के खत्म होते-न-होते पूर्वी एशिया तथा यूरोप की जनता में भीषण क्रांतिकारी उफान नजर आया। क्रांति और नई सामाजिक व्यवस्था संभव हो गई। पश्चिमी यूरोप में साम्राज्यवादियों के सीधे हस्तक्षेप एवं चंद वामपक्षी राजनीतिक दलों के आगा-पीछा तथा वर्ग-सामंजस्य वाली चालों के फलस्वरूप किसी हद तक क्रांति का काम रुका सही; फिर भी दूसरे देशों में साम्राज्यवादी पूँजीवादी प्रणाली को निश्चित रूप से धक्का लगा। फलतः जनता के प्रयत्नों से राजनीतिक एवं सामाजिक बातों में मौलिक परिवर्तनों का श्रीगणेश संभव हो गया। यह भी बात है कि दक्षिण-पूर्व एशियावालों के विप्लवों और हाल की चीन के स्वातंत्र्य-आंदोलन की विजय ने पाश्चात्य साम्राज्यवादी प्रभुत्व को खोखला कर दिया है। समाजवाद तथा जनतंत्र का पलड़ा बेशक भारी हो गया है।

'वर्षों के युद्ध के करते जीर्ण-शीर्ण तथा आर्थिक दृष्टि से छिन्न-भिन्न ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके स्थिरस्वार्थ जो भारत एवं एशियाई देशों में फैले हैं, अपनी हस्ती की सबसे बड़ी उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। यूरोप तथा एशिया में सोवियत रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव और संसार के बाजार पर अमरीका का प्रभुत्व, ये दोनों ही इसे दोनों ओर से कतरने लगे। ऐसी दशा में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने ठीक ही महसूस किया कि अपने लूट-खसोटवाले व्यापार के विशेष क्षेत्र के रूप में भारतीय बाजार को किसी भी मूल्य पर बचाना होगा; फलतः अमेरिका के संसार-व्यापी प्रभुत्व तथा सोवियत रूस के पूर्व-पश्चिम (दोनों ओर) फैलनेवाले प्रभाव के विरुद्ध भारतीय पूँजीपतियों के साथ साठ-गाँठ अनिवार्य रूप से आवश्यक है। भारतीय जनता के क्रांतिकारी विचारों में वृद्धि देखकर भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

अच्छी तरह मान लिया कि उसकी अपनी हस्ती के लिए भी भारतीय पूँजीवादियों से सट्टा-पट्टा एक ऐतिहासिक आवश्यकता है और इसके लिए, जितना शीघ्र हो, अनिवार्य कदम बढ़ाना ही होगा।

'कांग्रेस तथा मुसलिम लीग के नेताओं एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच सौदे के फलस्वरूप १९४७ के अगस्त में शासन-सत्ता हस्तांतरित करने की रस्म-अदाई हुई। इस प्रकार एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरी ओर भारतीय पूँजीवादियों को मिलाकर एक मोर्चा भारतीय जन-क्रांति के विरुद्ध तैयार हुआ। नेहरू-सरकार, जो भारतीय स्थिरस्वार्थों की सरकार है, अपने वर्ग-स्वभाव के करते ही उन समस्याओं को सुलझा नहीं सकती, जो भारतीय जनता के सामने खड़ी हैं। भारत में विद्यमान पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था के रहते भारतीय जनता को गरीबी और भूख के पंजों से त्राण नहीं मिल सकता। नेहरू और पटेल की सरकार तो स्थिर स्वार्थों की है। अमीरों के हाथों गरीबों की लूट को यह सरकार क्षमा प्रदान करती है। उद्योग-धंधों के राष्ट्रीयकरण को इसने पाँवतले रौंद दिया है। जमींदारों के द्वारा चुराई गई चीज (जमीन) को उनसे उगलवाने—जमींदारी को मिटाने के लिए मुआविजा देने के ख्याल से यह सरकार किसानों से रुपए के रूप में उनका खून निचोड़ रही है। अमीरों पर जो अतिरिक्त-आय-कर लगा था, उसके भार को यह कम कर रही है। लेकिन, श्रमजीवी वर्ग के द्वारा गुजारे लायक मजदूरी की माँग को इसने बेरहमी से दबा दिया है। शरणार्थियों एवं विपन्न मध्यमवर्गियों के सभी प्रतिवाद आंदोलनों के उभड़ने को इसने बर्बरतापूर्ण वहशियाना कामों के द्वारा दबा दिया है। जनता के स्वतंत्र भाषण तथा आजाद संगठन के आदरणीय अधिकारों को इसने लूट लिया है और विशेष आईन-कानूनों के द्वारा शासन जारी कर दिया है।

'यह सरकार पूँजीपतियों, चोरबाजारियों तथा भ्रष्ट पुलिस अफसरों के, जो खुफिया विभाग के बैरकों में राजबंदियों के साथ अमानुषिक बर्ताव संबंधी साम्राज्यवादी परंपरा को जारी रखना चाहते हैं, उखाड़ने पर लोगों को गिरफ्तार करती है। इसने आजाद हिंद फौज एवं दूसरे फौजियों के साथ, जिन्होंने बहादुरी से भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, अपमानजनक व्यवहार किया है। जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद आज राष्ट्रसंघ के बुर्के के नीचे मौजूद है, उसके सामने इसने-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

आत्मसमर्पण किया है। नेहरू-सरकार ने जो मुद्रा के मूल्य को घटाया है, वह ग्रेट ब्रिटेन के पूर्ण पिछलग्गू बनने का सबसे ताजा और जबर्दस्त नमूना है। यह चीज हमारी सारी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए घातक है। नेहरू-सरकार ब्रिटिश अमरीकी गुट्ट का अर्दली बन गई है।

पूँजीवादियों, चोरबाजारियों, कंपनियों के हिस्सेदारों और जमींदारों की इस स्थिरस्वार्थवाली सरकार को खत्म करना होगा तथा इसकी जगह किसानों, मजदूरों एवं विपन्न मध्यवर्गीयों की सरकार स्थापित करनी होगी। जनतांत्रिक जनता की यह सरकार ही भारतीय राष्ट्रीय स्वार्थों की प्रगति कर सकती है। सिर्फ वही एक-एक करके सबों को खाना, कपड़ा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य निश्चित रूप से दे सकती है। केवल वही हमारे देश के जन-समूह का सर्वांगीण उद्धार कर सकता है।

(इसी दृष्टि से) भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा नीचे लिखे लक्ष्य तथा कार्यक्रम के संबंध में अपने-आपको संकल्पबद्ध करती है। यह लक्ष्य एवं कार्यक्रम भारतीय जनता के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपनाता है :—

नाम—इस संस्था (संगठन) का नाम होगा, 'भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा' (युनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनिजेशन ऑफ इंडिया)।

लक्ष्य—(अ) 'भारत में समाजवादी प्रजासत्ताक राज्यों के संघ की स्थापना इसलिए करना कि यहाँ वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाए, जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण लापता होगा और यह सिद्धांत मान्य होगा कि 'हरएक से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए', यही इस सभा का लक्ष्य होगा।

(ब)—समाजवादी प्रजासत्ताक राज्यों के इस संघ की बुनियादी रूप-रेखा यही होगी कि उत्पादन, वितरण तथा विनिमय के साधनों पर समाज का अधिकार होगा और अन्यान्य बातों के सिवाय यह संघ फौरन ही आदेश जारी करेगा कि:—

(१) बिना मुआविजा जमींदारी (भूमि का आधिपत्य) खत्म हो।

(२) पूँजीवादी ढंग का शोषण खत्म हो तथा बुनियादी, विस्तृत एवं मूलभूत उद्योग-धंधे समाज की संपत्ति हों।

(३) जनता के उपयोग के सभी विभाग समाज के हाथ में हों।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(४) जमीन जोतने-कोड़नेवालों (किसानों) की ही हो। इस संबंध में नही गैर उतने ही बंधन हों, जो राष्ट्र तथा जोतने-कोड़नेवालों के हित-साधक हों।

(५) खेती संबंधी सभी ऋण माफ हों।

(६) बैंक तथा ऋण देनेवाली अन्य संस्थाएँ समाज की हों।

(७) विदेशी कारबार पर राष्ट्र का एकाधिपत्य हो।

(८) देश के भीतरी कारबार और रोजगार के लिए नियम-कायदे राष्ट्र (सरकार) बनाए।

(९) मौजूदा विदेशी स्थिर स्वार्थ मिटा दिए जाएँ।

(१०) जनता के निवास-स्थान की व्यवस्था सरकार करेगी।

(१२) खानें, खनिज पदार्थ, जंगल, नदियाँ और समुद्री किनारे के जल जैसे प्राकृतिक पदार्थों पर राष्ट्र (सरकार) का अधिकार होगा।

(१२) शक्ति के मूलभूत साधन विद्युत शक्ति, कोयले, तेल एवं शक्तिदायक आसव (शराब) तथा इस शक्ति के उत्पादक कल-कारखाने राष्ट्र (सरकार) के हाथों में होंगे और वही उन्हें चलाए तथा नियंत्रण में रखेगा।।

(१३) जन-स्वास्थ्य-संबंधी सभी विभाग समाज के हाथ में होंगे और सबों के लिए दवा-दारू का पूरा प्रबंध होगा।

(१४) सबों को पूरा काम मिलेगा, भिखमंगी न रहेगी और ऐसी व्यवस्था होगी कि यदि दैवात् बेकारी हो जाए; तोभी आराम का जीवन गुजरे। बुढ़ापे, बीमारी, शारीरिक अयोग्यता, संतानोत्पत्ति की दशा तथा अनाथ बच्चों के लिए भी वही व्यवस्था हो।

(१५) सभी शिक्षा-संस्थाएँ समाज के हाथ में हों, जिनमें धार्मिक शिक्षा न दी जाए। सबों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो।

(१६) सबों को सोचने-विचारने ए' पूजा-पाठ की पूर्ण स्वतंत्रता हो।

(१७) समाजवादी राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल सबोंको सांस्कृतिक बातों में पूर्ण स्वतंत्रता हो।

(१८) अस्पृश्यता एवं इसी तरह के जाति-भेद और ऊँच-नीच आदि के खयालों के नामोनिशान को बखूबी मिटा दिए जाने की व्यवस्था हो और सबोंको समान अधिकार हो।

(१९) स्त्री-पुरुषों के बीच पूर्ण समानता हो।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(२०) सभी नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण हो।

काम—भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा का काम होगा साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के सभी अवशेषों और पूँजीवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष चलाना, ताकि अप्रजातांत्रिक, अधिनायकवादी एवं प्रतिगामी भारतीय स्थिर स्वार्थों की सरकार की जगह मजदूरों और किसानों की सरकार स्थापित हो।

कार्यक्रम:—भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा के संघर्ष का कार्यक्रम यों होगा कि वह—

(१) प्रतिनिधित्व-शून्य एवं अजनतांत्रिक मौजूदा विधान-परिषद् के द्वारा निर्मित तथाकथित भारतीय विधान को अमान्य ठहराने के लिए जनता को ललकारेगी और कहेगी कि जनता की विधान-परिषद् बुलाई जाए, जो सार्वजनिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी जाए और भारत में समाजवादी प्रजासत्ताक राज्यों के संघ के लिए विधान बनाए, ताकि (अ) सरकार के संचालन में मजदूरों एवं किसानों को वाजिब स्थान मिले; (ब) संघ में सम्मिलित सभी भागों को पूर्ण स्वतंत्रता हो और (स) भाषा के आधार पर सभी प्रांतों के भू-भागों का फिर से बँटवारा हो।

सभा मांग करेगी कि

(२) भारत ब्रिटिश राष्ट्रसंघ से पूर्ण संबंध-विच्छेद कर ले।

(३) ब्रिटिश अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ कोई सट्टा-गट्टा न होगा।

(४) अँगरेजों के हाथों निर्मित साम्राज्यवादी नौकरशाही तथा फौजीयंत्र के रूप में मुल्की, फौजी और पुलिस-विभाग की जो नौकरियाँ हैं, उन्हें खत्म कर के नए ढंग से शासन-व्यवस्था के यंत्र का निर्माण हो तथा भारतीय परिस्थिति एवं जनता की भावना के अनुसार जनता का फौजी दल तैयार किया जाए।

(५) अनिवार्य फौजी शिक्षा दी जाए और हथियार-कानून खत्म हो।

(६) आजाद हिंद फौज के सभी सिपाहियों को फिर से भर्त्ती किया जाए और उन्हें बसाया जाए।

(७) कल-कारखानेदारों ने जो युद्ध में नफा कमाया है, वह और चोरबाजारियों तथा सट्टेबाजों की संपत्ति जप्त हो।

(८) फौरन ही वे दमनकारी कानून और ऑर्डिनेंस (फर्मान) रद्द किए जाएँ, जो बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमा चलाए नजरबंदी, नागरिक स्वतंत्रता में बंधन तथा हड़ताल के हक पर रोक की आज्ञा देते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-

(९) राजबंदियों और नजरबंदों की फौरन ही बिना शर्त्त रिहाई हो।

(१०) सभी राजनीतिक दलों एवं मजदूर-किसान संगठनों पर लगे बंधन हटाए जाएं।

(११) सभी मीटिंगों और जलूसों की रोक हटाई जाए, ताकि बोलने एवं संगठन की पूरी आजादी हो।

(१२) सभी प्रकार की जमींदारियों तथा किसान एवं सरकार के मध्यवर्त्ती सभी प्रकार के स्वार्थों का खात्मा बिना मुआविजा किया जाए।

(१३) खेती-संबंधी-ऋण माफ किए जाएँ, खेती की उन्नति के लिए सस्ते कर्ज तथा अन्य प्रकार की सरकारी सहायता की व्यवस्था हो और अलाभकर जमीनों से लगान न लिया जाए।

(१४) किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य निश्चित हो, जिसमें खेती के खर्च के अलावे (अ) उचित मुनाफा भी शामिल हो, (ब) खेत-मजदूरों की गुजारे लायक कम-से-कम मजदूरी निश्चित की जाए, और (स) किसानों के जीवन एवं खेती के लिए आवश्यक चीजों का मूल्य घटाया जाए।

(१५) कल-कारखाने के मजदूरों को गुजारे लायक वेतन मिले।

(१६) कानून के जरिए ४० घंटे का हफ्ता और ७ घंटे रोज काम करना तय हो।

(१७) लोगों को काम पाने का हक हो, नहीं तो, बेकारी का भत्ता मिले।

(१८) हड़ताल करने का हक हो।

(१९) सामाजिक सुरक्षा का हक सबको हासिल हो, जिसमें कोई भूखा-नंगा न रहे।

(२०) ठेकेदारी पर काम करना उठा दिया जाए।

(२१) सबों को भोजन, वस्त्र, निवास और दवा-दारू मिलने की गारंटी हो।

(२२) मैट्रिक्युलेशन तक की शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य हो।

(२३) चोरबाजारी, जीवन की जरूरी चीजें जमा करके छिपा रखने और शासन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त-से-सख्त दंड आदि की व्यवस्था हो।

(२४) शरणार्थियों तथा अपने स्थानों से हटे-हटाए अन्य लोगों के लिए जमीन, मकान और काम देकर सहायता पहुँचाने तथा बसाने का प्रबंध हो।

ओरिएन्ट प्रेस, पटना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-C

uru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalg

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Gr

Guru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalga

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.